



LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Thursday, February 7, 2019/ Magha 18, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 7, 2019/ Magha 18, 1940 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
OBITUARY REFERENCE	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 61-66)	1A-31
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 67-80)	32-45
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 691-920)	46-275



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, February 07, 2019/ Magha 18, 1940 (Saka)

(Please see the Supplement)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 07, 2019/Magha 18, 1940 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	276
PAPERS LAID ON THE TABLE	277-87
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 46 th Report	288
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES Statement	288
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES Report of Study Visit	289
STANDING COMMITTEE ON LABOUR 46 th to 52 nd Reports	289-90
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS 24 th and 25 th Reports	291
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 216 th to 219 th Reports	291-92
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 320 TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS - LAID Dr. Jitendra Singh	293

MOTION RE: SIXTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	294
SPECIAL MENTIONS	295-11
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	312-20
Shri Abhijit Mukherjee	313
Shri K. Ashok Kumar	314-15
Dr. K. Gopal	316-17
Shri Balabhadra Majhi	318
Shri Rahul Shewale	319
Shri N. K. Premachandran	320
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS	321-
(Contd. - Concluded)	
Shri Mallikarjun Kharge	321-45
*Prof. Richard Hay	346-47
*Dr. Ratna De (Nag)	348-48F
*Shri Nishikant Dubey	349-49C
*Shri Harishchandra <i>Alias</i> Harish Dwivedi	349D-49E
*Shri Krishna Pratap	350-50F
*Adv. Narendra Keshav Sawaikar	351-51B
*Shri Vishnu Dayal Ram	352-52G
*Shri Kamakhya Prasad Tasa	353-55
*Shri A.T. Nana Patil	356-56D
*Shri Bidyut Baran Mahato	357-57E
*Dr. Yashwant Singh	358-58A

***Laid on the Table**

*Dr. K. Gopal	359-59A
*Dr. Thokchom Meinya	360-60A
*Shrimati R. Vanaroja	361-61B
*Shri Thangso Baite	362
*Adv. Joice George	363-63C
*Shrimati Darshana Vikram Jardosh	364-64B
*Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	365-65GGG
*Dr. Kirit Somaiya	366
*Shri Rajeshbhai Chudasama	367-67C
*Shri P.R. Sundaram	368-68B
Shri Anandrao Adsul	369-76
*Shri Dhananjay Mahadik	377
*Shri Alok Sanjar	378-79
Shri Dinesh Trivedi	380-88
*Shri P. Nagarajan	389-89B
*Shri Gajanan Kirtikar	390-90C
*Shri Badruddin Ajmal	391-99
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	400-12
*Shri R. Dhruvanarayana	413-13B
Shri Jayadev Galla	414-24
*Shri Lakhan Lal Sahu	425-25G
*Shrimati Aparupa Poddar	426-27

***Laid on the Table**

*Shri Md. Badaruddoza Khan	428-28A
*Shri Harishchandra Chavan	429-29B
*Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	430-30B
*Shri S.P.Muddahanume Gowda	431-31C
*Shri Rabindra Kumar Jena	432-32E
Shri Mohammad Salim	433-39
Dr. Kirit P. Solanki	440-43
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	444-45
Shri Prem Singh Chandumajra	446-47
Shri Virender Kashyap	448-49
*Shri B. Vinod Kumar	450-50B
Shri N.K. Premachandran	451-54
Shri H.D. Devegowda	455-66
*Shrimati Anju Bala	467-67F
*Prof. Chintamani Malviya	468-68C
*Shri Shivkumar Udasi	469-69B
*Shri Harinarayan Rajbhar	470
*Dr. Prabhas Kumar Singh	471
*Dr. Sunil Baliram Gaikwad	472-73
*Shrimati Riti Pathak	474-75
Shri Kalyan Banerjee	476-82
*Shri D.K. Suresh	483-83B
*Dr. A. Sampath	484-84D
*Kumari Shobha Karandlaje	485-85G

Shri Ram Kumar Sharma	486-87
Shri P.K. Kunhalikutty	488-89
Kunwar Haribansh Singh	490-91
@Shri K. Parasuraman	492
Shri Asaduddin Owaisi	493-98
Shrimati Sushma Swaraj	499
*Kumari Sushmita Dev	500-500B
*Shri Rahul Kaswan	501
\$Shri Saumitra Khan	502
Shrimati Meenakshi Lekhi	503-13
*Shri Devji M. Patel	514-14A
*Shri Nalin Kumar Kateel	515-15A
*Shri Anurag Singh Thakur	516-16A
*Shri Rodmal Nagar	517
*Shri Vinayak Bhaurao Raut	518-18A
*Kunwar Pushpendra Singh Chandel	519
*Shri Ajay Mishra Teni	520

***Laid on the Table**

@For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri K. Parasuraman in Tamil, please see Supplement PP No. 492A-492D

\$For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Saumitra Khan in Bangla, please see Supplement PP No. 502A-502D

*Shri Bhairon Prasad Mishra	521
Shri Ramdas Athawale	522-24
*Shri Jugal Kishore	525-25A
*Shri Rameshwar Teli	526-26A

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**

***Laid on the Table**

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, February 07, 2019/ Shravana 18, 1940 (Saka)

S U P P L E M E N T

<u>CONTENTS</u>		<u>PAGES</u>	
XXX	XXX	XXX	XXX
Xxx	xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xxx	xxx
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS		492A-92D	
		502A-02D	
		527-60	
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri K. Parasuraman		492A-92D	
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Saumitra Khan		502A-02D	
xxx	xxx	xxx	xxx
Shri Narendra Modi		527-59	
Amendments –Negatived		560	
Motion – Adopted		560	

XXXX

(1100/RPS/RCP)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री बुन्देला वर्ष 2003 से 2008 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला का निधन 60 वर्ष की आयु में 3 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने साथी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

(प्रश्न 61)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 61, श्री डी. के. सुरेश – उपस्थित नहीं।

श्री नलीन कुमार कटील – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): मैडम, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं है। ठीक है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 62, श्री अशोक महादेवराव नेते ।

(प्रश्न 62)

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): अध्यक्ष महोदया, आज भी देश के आदिवासी एवं दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट नहीं आते हैं। इसमें मेरा संसदीय क्षेत्र, जो महाराष्ट्र में है, आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर् भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का आदिवासी एवं दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषतः नक्सल प्रभावित संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर् में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्पष्ट प्रसारण हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाकर, उसे शीघ्र क्रियान्वित करने का विचार है?

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, भारत का 99 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र और आबादी को रेडियो सिग्नल्स कवर करते हैं। साथ में, अब टेलीविजन के सिग्नल्स डायरेक्ट-टू-होम सेटेलाइट ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं। सेट टॉप बॉक्स के अन्दर कुछेक चैनल्स ऐसे भी हैं, जिन पर आप रेडियो को सुन सकते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, अब हमने रेडियो ट्रांसमिशन, पूरे भारत के जितने भी आल इंडिया रेडियो चैनल्स हैं, उनको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड किया है। यदि किसी के पास कोई फोन हो तो वह उसके ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकता है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमुर् संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका चामोर्षि में मार्कण्डा देवस्थान एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा काशी देवस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है।

(1105/RAJ/SMN)

इस धार्मिक स्थल का बड़ा महत्व है। इस मंदिर के निकट से पवित्र वेणगंगा गुजरती है। वेणगंगा नदी के किनारे स्थित पवित्र मार्कण्डा देव, भगवान शंकर जी के नाम से जाने जाते हैं। यहां

हेमाडपंथी मंदिर भी है, जो मार्कण्डेय ऋषि की तपस्या से पावन है। इसी क्षेत्र में कछाड़गढ़ तालुका सालेकसा जिला गोंदिया में लिंगोचंगों जो आदिवासियों के देवता हैं, उनकी एक प्रमुख एवं अति प्राचीन गुफा और मंदिर है। यह देश के आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां पर महाराष्ट्र राज्य से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा सहित अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदिवासी संस्कृति भारतीय संस्कृति की विरासत का एक महत्वपूर्ण अटूट अंग है।

अतः इस संदर्भ में मंत्री जी से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों की धार्मिक एवं पर्यटनीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन एवं एफ.एम. सेन्टर के माध्यम से आदिवासी धार्मिक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रसारण करने हेतु प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, ट्राइबल एरियाज के अंदर जो कल्चर है, वहां का धर्म है, वहां की संस्कृति है, उसको न केवल मजबूती देना बल्कि पूरे भारत और विश्व में लेकर जाना, इसके लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो लगातार काम करते रहते हैं। मेरा माननीय सांसद से निवेदन है कि अगर वह एक लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वहां पर लगाएं तो उसके लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट उनकी मदद करेगा। उसमें जो ट्राइबल एरिया है, उसी लोकलाइज्ड जगह पर उनको अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को बढ़ावा और मजबूती देना आसान हो जाएगा।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Madam, Doordarshan and All India Radio are the most prime organisations which are helping the rural masses in all the activities. Today, competing with the other channels, Doordarshan and All India Radio have been neglected. The prime slot has been given to the private channels. Doordarshan and All India Radio are the most important

Government channels and these channels have reached the common people and rural masses of this country.

I think it has been neglected for the last ten years; I am saying not only now. May I know from the hon. Minister whether he is giving prime slot to these channels so that they can reach the rural masses in a proper manner?

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): Madam, the mandate of the Prasar Bharati, Doordarshan and All India Radio is to be able to communicate all the information that is required by the citizens of our country and also to entertain them and also to keep up our traditions and our culture alive. There are programmes that the private channels may not show because of commercial reasons. Nevertheless, Prasar Bharati emphasises on showing those programmes. Our primary concern is not of revenue generation but serving our countrymen. I can assure the hon. Member that the maximum numbers of subscribers in our country are there on our DTH platform. Our programmes cover a very large spectrum of issues thereby providing the right sort of information to the citizens of our country. We are also ensuring that quality programmes are there on the Doordarshan and on the All India Radio. This is a continuous effort of not only increasing our reach but also ensuring that the programmes are better.

(1110/MMN/IND)

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Though the telecast audience of Doordarshan and Akashvani is different, with the growing private channels in the field, there is a need to make Akashvani and Doordarshan more relevant,

impactful, informative, and at the same time, entertaining both in the urban and rural, in the rarest, areas of our country. Otherwise, both Doordarshan and Akashvani would fade away in due course of time in future. Madam, having said that, would the Minister briefly state about the educational programmes being telecast across the country and the efforts made by the Ministry in the last four years to take Doordarshan and Akashvani internationally by popularising the telecast programmes of popular and informative programmes? Thank you.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.): Madam, the point that the hon. Member has made is, of course, valid and very well taken. Like I mentioned, the entire Prasar Bharati, which involves Doordarshan and, of course, the All-India Radio, is continuously in the process of making their programmes better. There is a competition with private channels. However, like I mentioned a little while earlier, our main concern is to be able to serve the country and keep all cultures and all traditions alive, and for all sorts of art forms to be provided a platform.

In terms of reaching out internationally, of course, we have DD India, and we are also ensuring to make DD India stronger. There are collaborations with other countries as well. Keeping in mind what the hon. Member has said, we will continue to work to ensure better quality.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने आकाशवाणी को “मन की बात” से पूरे देश में बहुत पापुलर किया है।... (व्यवधान) यही पॉपुलेरिटी है।... (व्यवधान)

महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूँ, हमें वहाँ “मन की बात” देखने में या सुनने में हमेशा समस्या होती है। “मन की बात” को देखा भी जाता है। वर्ष 2014 में मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा में हाई पावर ट्रांसमिशन रिले सेंटर आकाशवाणी का सैंक्शन हुआ था। मैंने संसद में नियम 377 के अंतर्गत और जीरो ऑवर में मंत्री जी को पत्र लिखकर लगातार अपेक्षा की कि यह कार्य पूरा हो जाएगा। मंत्री जी ने मुझे दिसम्बर, 2017 का टारगेट दिया और फाइनल टारगेट मार्च, 2018 का दिया और कहा कि मार्च, 2018 में गोड्डा की रिले ट्रांसमिशन लाइन चालू हो जाएगी। मैं आज फरवरी, 2019 में बात कर रहा हूँ। आपने अमीरों के इलाके में बहुत काम किया है, लेकिन यह क्वैश्चन गरीब के इलाके का है। ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस और पत्र के माध्यम से गरीब के इलाके के लिए आपका कमिटमेंट है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गोड्डा में आकाशवाणी की रिले ट्रांसमिशन लाइन कब शुरू होगी?

महोदया, देवघर के बारे में भी कमिटमेंट था कि तीन एफएम का स्टेशन जून, 2018 में शुरू हो जाएंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह कब चालू होंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जहाँ 50 काम हुए हैं, वहाँ एक काम रह गया, ऐसा हो जाता है।

...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने पहले उत्तर में बोला है कि पूरे देश के अंदर we are covering 99.2 per cent of the population, and, therefore, I am sure that this area is covered by radio. However, I bring it to the notice of the Member that डीटीएच हमारा सेटअप बॉक्स है और सेटेलाइट सर्विस है, उसमें रेडियो स्टेशंस भी अवेलेबल हैं। अब हमारे रेडियो स्टेशंस मोबाइल फोन्स पर अवेलेबल हैं। जहाँ भी साधारण मोबाइल का सिग्नल आता है, वहाँ लोग “मन की बात” और रेडियो सुन सकते हैं। जहाँ तक और विस्तार की बात है, उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो के भी ट्रांसमिटर्स लग रहे हैं और हम कई जगह अलग-अलग फेज़ेज में प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टर्स भी लग रहे हैं। योजना के तहत इसका विस्तार होता रहेगा।

(इति)

(1115/VR/IND)

(Q. 63)

HON. SPEAKER: Question No.63 – Shri C.N. Jayadevan.

Shri C.N. Jayadevan – Not present.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में देश के सम्पूर्ण विद्युतीकरण के साथ प्रत्येक परिवार को वर्ष 2009 तक बिजली उपलब्ध करा देने का एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन वर्ष 2014 तक उस काम को पूरा नहीं कर पाए। जब हमारी सरकार आई, तो वर्ष 2014 में हमने जहां सारे गांवों के विद्युतीकरण का काम पूरा किया, वहीं जब हमने उसका सर्वेक्षण कराया, तो 4 करोड़ परिवार ऐसे थे, जिनके घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने तय किया था कि मार्च, 2019 तक हम सारे परिवारों को सौभाग्य योजना के माध्यम से कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे। सरकार ने पूरे प्रयास किए और लोगों के घर तक जाकर प्रचार-प्रसार के माध्यम से ऐसा प्रयास किया कि सभी लोगों को कनेक्शन दिए जाएं। इस दिशा में तेजी से काम हुआ और कनेक्शन देने के समय के लक्ष्य को घटाकर हमने दिसम्बर, 2018 किया। दिसम्बर, 2018 तक हमने उन सभी परिवारों को जो बिजली का कनेक्शन लेना चाहते थे, उन्हें कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। देश में अभी भी शेष 30 लाख परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार के बहुत सारे प्रयासों के बावजूद अभी तक बिजली के बिल के कारण, क्योंकि वे समझते हैं कि कहीं बिजली का अधिक बिल न आ जाए, इस वजह से सरकार के बहुत प्रयासों जैसे कैम्प लगाना, प्रचार करना आदि, के बावजूद भी इन परिवारों ने बिजली के कनेक्शन नहीं लिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सभी 30 लाख परिवारों तक भी बिजली के कनेक्शन पहुंच जाएं, क्या सरकार इसके लिए ऐसा प्रयास करेगी कि सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन के लिए एक मैक्सिम बिल तय कर दिया जाए या उन्हें डायरेक्ट

बेनिफिट के माध्यम से बिल में सब्सिडी देने का काम या कोई ऐसी नई स्कीम बनाए, जिससे प्रेरित होकर उन 30 लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली पहुंच सके?

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदया, आज के दिन देश में दो राज्यों को छोड़ कर, बाकी सभी राज्यों में जितने इच्छुक घर थे, उन्हें विद्युत का कनेक्शन दे दिया गया है। जो दो राज्य बचे हैं, वे कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण बचे हैं। एक राज्य छत्तीसगढ़ है, जिसके बस्तर इलाके में कठिन परिस्थितियां हैं, वहां विद्युतीकरण करने के लिए करीब 20 हजार घर बचे हुए हैं, वहां कठिनाई है। दूसरा राज्य राजस्थान है, जहां दूर-दराज ढाणियां बसी हुई हैं। वहां कुछ कठिनाई है। इन दो राज्यों को छोड़कर बाकी शेष राज्यों ने मुख्य सचिव के माध्यम से लिखित सूचना भेजी है कि हमने जितने इच्छुक घर थे, सभी को कनेक्शन दे दिया है। उत्तर प्रदेश ने भी यही काम किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घर ऐसे थे, जो कि बिना लेजिटिमेट कनेक्शन लिए बिजली का उपयोग कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि वे चोरी कर रहे थे या कुछ भी ऐसा कर रहे थे। उन्हें बिजली का कनेक्शन लेने में हैजिटेशन था और वे बिजली का कनेक्शन नहीं लेना चाहते। उन्हें परसुएड किया गया है और यह भी बताया गया है कि जहां भी चोरी पकड़ी जाएगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रांतों ने तो योजनाएं भी चलाई हैं कि चाहे पहले के बकायेदार भी हों या बिजली चोरी का केस भी हो, तो हम कम्पाउंड कर दे सकते हैं, आप बिजली का कनेक्शन ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी यह प्रयास जारी है और यह प्रयास जारी रहेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता करेंगे कि हम कुछ और कंसेशन दे सकते हैं, तो हम देंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, मेरा प्रश्न इसी प्रश्न के साथ जोड़ दीजिए, ताकि मंत्री जी एक साथ रिप्लाई दे सकें।

माननीय अध्यक्ष : आप इसी प्रश्न में सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, ठीक है, मैं इसी प्रश्न में सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछता हूँ।

Madam, the question that I asked was: 'Whether an estimated 3.4 crore rural households are still without electricity and majority of such villages are in Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Jharkhand, Odisha, etc.'

Madam, the reply that has been given is: 'As informed by the States, there are only 21.30 crore households in the country; of these 21.29 crore households have been electrified up to 27.01.2019; the remaining 83,015 un-electrified households are in Chhattisgarh and Rajasthan.'

(1120/PC/SAN)

अभी मंत्री जी ने बताया कि केवल छत्तीसगढ़ में ही यह समस्या है।

श्री आर. के. सिंह : मैंने राजस्थान का भी नाम लिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इस देश में, आपको मालूम है कि 6,50,000 विलेजेज़ हैं। हैमलेट्स को जोड़कर, उनमें से केवल 18,000 देहातों को इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं पहुंची थी, वह पहुंचने में थी। इस हाउस में हमेशा कहा जाता है 60 सालों में क्या किया?

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : 6,32,000 विलेजेज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : 6,32,000 विलेजेज़ को हमने इलेक्ट्रिफाई किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भाषण देना है, अभी आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मैं भाषण तो दूंगा, लेकिन ये कैसी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ... (व्यवधान) हमेशा ... (Not recorded) बोलकर अपनी बात को रखते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो छोटे-छोटे विलेजेज़ हैं - हैमलेट्स, हट्टीज़ और वाडीज़, क्योंकि वहां पर भी, उस हाउसहोल्ड तक भी इसे पहुंचना है। ये कब तक इसे पूरा कंप्लीट करेंगे? क्या इसके लिए राज्य सरकार से कोई सब्सिस्टेंस अलाउंस या कोई सब्सिडी आप देंगे?

श्री आर. के. सिंह : मैडम, मैं दो बातें कहूंगा। पहले तो आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि इन्होंने अपने समय में इतने गांवों में काम किया और आपने सिर्फ 18,300 गांवों में काम किया।

मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय खड़गे जी को और सब को भी यह जानकारी है। ये दो बातें हैं। एक तो, जो गांव बचे हुए थे, वे एकदम बिलकुल जितने कठिन दूर-दराज के इलाके थे, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या कारगिल हो, ये सब बचे हुए थे। राजस्थान की ढाणियां भी बची हुई थीं। इनको हमने कंप्लीट किया। गांव का मतलब है - सेंसेस विलेजेज़। जितने टोले थे, वहां भी हम पहुंच गए हैं। अब देश में सिर्फ दो राज्य बचे हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ। सिर्फ दो राज्य बचे हैं, जहां हम हर इच्छुक घर तक नहीं पहुंचे हैं। एक है राजस्थान और दूसरा है छत्तीसगढ़। इन दोनों के विशेष कारण हैं। विद्युतीकरण राज्य सरकार के माध्यम से ही कराते हैं। पैसा हम देते हैं, लेकिन काम हम राज्य सरकार के माध्यम से ही कराते हैं। हमारा यह काम अच्छा चल रहा है।

आदरणीय खड़गे जी का पूछना है कि बाकी जितने हैमलेट्स और घर बचे हुए हैं, उन्हें कब तक पूरा कर देंगे। हमारा टारगेट 31 मार्च, 2019 का है। हम उससे पहले वहां कार्य पूरा कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो दो प्रांत हैं, उनके बारे में भी मेरा यह कहना है कि वहां भी हम 31 मार्च, 2019 से पहले कार्य पूरा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : जयदेवन जी आ गए हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए।

SHRI C. N. JAYADEVAN (THRISSUR): Madam Speaker, in the reply, the hon. Minister has not stated the target fixed under the scheme. The Minister has

also not mentioned the number of households which remain to be electrified. Without these numbers, this reply is incomplete.

I would like to ask the Minister what was the target and how many more households are yet to be electrified.

श्री आर. के. सिंह : आदरणीय महोदया, जिस समय हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया, यह योजना प्रारंभ की थी, उस समय सभी राज्यों ने अनुमानित आंकड़े भेजे थे, क्योंकि उन्होंने सर्वे नहीं किया था। सर्वे करने का टाइम नहीं था। अनुमानित आंकड़े थे कि तीन करोड़ अस्सी लाख के आसपास या चार करोड़ के आसपास घर बाकी हैं। ये अनुमानित आंकड़े थे, क्योंकि घरों में जाकर सर्वे नहीं किया गया था। जब उनकी टीमों गांवों में पहुंची, तो पाया कि जहां पर उनका अनुमान था कि 100 घर बाकी हैं, वहां पर 60 घर ही बाकी थे इत्यादि। इस तरह से जैसे-जैसे गांवों में पहुंचते गए और कार्य करते गए, वैसे-वैसे आंकड़े सही होते गए। आज के दिन में हमने 2 करोड़ 48 लाख 619 घरों का विद्युतीकरण कर दिया है। अभी छत्तीसगढ़ में 20,134 घर बाकी हैं। राजस्थान में 4 लाख 11 हजार का उन्होंने आंकड़ा दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनका सर्वे पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये आंकड़े भी घटे-बढ़ें, जैसे-जैसे उनकी टीमों गांवों में पहुंचें।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 64, श्री प्रसून बनर्जी।

(1125/SPS/RBN)

(Q. 64)

SHRI PRASUN BANERJEE (HOWRAH): Madam Speaker, thank you for giving me a chance to raise my question. मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल इण्डिया रेडियो और आकाशवाणी हमारे जन्म लेने से पहले से हैं। इस बारे में ज्यादा क्या बोलूँ, पूरी दुनिया में सब लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैडम, इसके बारे में मैंने जो थोड़ा-बहुत देखा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मामले को बीस साल हो गए और अब नई सरकार भी आने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ कि डी.पी.सी. यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनी ही नहीं है। कुछ लिटिगेशन जरूर हैं। प्रमोशन कमेटी नहीं बैठी है, कोई एक प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। उसी वजह से मेरा कहना है कि मिनिस्टर साहब जरूर कुछ करें, बहुत मुसीबत हो रही है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ गया हूँ। इसमें खुशखबरी है और इसमें अच्छी बात है। इसका बैक ग्राउण्ड मैं बताता हूँ कि प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव्स का रिक्रूटमेंट तकरीबन वर्ष 1990 में हुआ और यू.पी.एस.सी. ने रिक्रूटमेंट किया। उसके बाद दो प्रमोशंस हुए, लेकिन फिर कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने यह कहा कि यह जो प्रमोशंस की प्रक्रिया थी, उस पूरी एक्सर्साइज को आप वापस देखिए। उसके बाद यू.पी.एस.सी. ने मना कर दिया कि हम रिक्रूटमेंट भी नहीं करेंगे और प्रमोशंस भी नहीं करेंगे। वह मैटर काफी लम्बे समय तक चलता रहा। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। उसके बाद यू.पी.एस.सी. एग्री हुआ और सहमत हो गया कि हम इस पर रिक्रूटमेंट करेंगे। मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 तक जितने भी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होने थे, वे हमने किए और 221 प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव्स को हमने नेक्स्ट पर प्रमोट किया। अभी उसका एक्जिक्यूशन होना बाकी है। उसका कारण भी यह है कि अभी कोर्ट के अंदर लिटिगेशन चल रहा है और मैटर

पेण्डिंग है। जैसे ही वहां से निर्णय आएगा, सारे डिपार्टमेंट प्रमोशंस हो चुके हैं, हमने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, सिर्फ एक्जिक्यूशन बाकी है।

HON. SPEAKER : Is there any Supplementary?

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्समैन हैं। पहले ऑल इण्डिया रेडियो में स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम होते थे। अभी दूरदर्शन बना है। पहले घर-घर में खेलों की बात चलती थी, जो कॉमेंट्री होती रहती थी, वह अब कम हो गयी। हमारी यह बात नहीं है, मन की बात प्राइम मिनिस्टर जी को जरूर करने दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को और ज्यादा ऑल इण्डिया रेडियो में करें। सबके पास टी.वी. नहीं होता है, गांव-गांव में हमने देखा है।

माननीय अध्यक्ष : हो गया, यह तो प्रमोशन का था।

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा): मिनिस्टर साहब भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं। इसलिए उनसे कहना है कि छोटे स्पोर्ट्स चाहे कबड्डी आदि हों, छोटे-छोटे स्पोर्ट्स भी घरों में भेजने चाहिए। इसके लिए उनसे विनती है। ... (व्यवधान) मन की बात तो होने दीजिए, चिल्लाए किसलिए? मन की बात ठीक है। जिसकी मन की बात है, वे देते हैं, सुनने दीजिए। हमारा बोलना है मन की बात चलने दीजिए। हमारा कहना है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के लिए उनसे विनती है, उनको यह जरूर करना चाहिए।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, हालांकि जो प्रश्न पूछा है, उसका संबंध इस प्रश्न से नहीं है। लेकिन खुद प्रसून बनर्जी साहब एक स्पोर्ट्समैन हैं तो मैं जरूर इसका उत्तर दूंगा। अगर कॉमेंट्री अलग-अलग खेलों की हो तो उससे सभी देशवासियों को बहुत लाभ होगा। अभी हमारी नेगोसिएशंस चल रही हैं कि जिस तरह से दूरदर्शन के अंदर जिस तरह का एंगेजमेंट रहता है, रेशियो रहता है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, उसके ऊपर हमारी अभी चर्चा चल रही है। क्रिकेट वालों से भी चल रही है और दूसरे जो खेल हैं, उनके साथ भी चल रही है। मुझे यकीन है कि इसके ऊपर जल्दी ही काम होगा और क्रिकेट की कॉमेंट्री और सभी खेलों की कॉमेंट्री भी आने वाले समय में हम देख पाएंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): धन्यवाद अध्यक्ष जी। ऑल इण्डिया रेडियो जिस स्थिति में माननीय मंत्री जी आपको मिला होगा, वह मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि पिछले चार वर्षों से इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को चाहे कैजुअल हो या पर्मानेंट एम्प्लॉइज हों, उनकी लगातार एक मांग रही है कि दिल से काम कैसे करें? एक तरह से आप चाहते हो कि इसकी रीच बढ़े, पॉप्यूलैरिटी बढ़े। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम अधिकतर काम करवा पा रहे हैं। टैक्नीशियंस हमारे पास ज्यादा हैं, इंजीनियर्स ज्यादा हैं, प्रोग्रामर्स कम हैं। लेकिन जितने एम्प्लॉई हमारे पास हैं भी, उनका कितने वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ है, तीस-तीस वर्ष। अगर एक संस्था में बैठा व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठा हुआ है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। कैजुअल एम्प्लॉइज पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है तो वह संस्था आगे कैसे बढ़ेगी?

(1130/MM/SM)

पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, उनका भारत की सीमा में प्रसारण हो जाता है। अगर हमारे यहां के चैनल्स की रीच बढ़ानी है, उनसे और अच्छा काम करवाना है तो कोर्ट केसेस की दुहाई देने की बजाय इस मसले का कहीं न कहीं हल किया जाना चाहिए। इसमें हजारों इम्प्लॉई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध रहेगा और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह से छः सरकारें चली गयीं, लेकिन उन कैजुअल इम्प्लॉईज का अभी कुछ नहीं हो पाया है और उन एग्जिक्यूटिव्स का भी कुछ नहीं हो पाया है। उनको किस तरह से आगे प्रमोशन मिल पाए, आप इस दिशा में क्या कदम उठाने वाले हैं, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि यह वर्षों पुरानी समस्या है। उन्होंने यह बात भी कही कि एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी सरकार आती है, लेकिन यह मोदी सरकार है। हमने प्रमोशन्स किए हैं। हमने वर्ष 2018 में प्रमोशन्स किए हैं। यह जो समस्या है, इसका हल निकाला जा रहा है। जहां तक कैजुअल्स की बात है, तो यह नीति हमारी सरकार में नहीं बनी है, यह पहले की बनी है कि प्रसारण

को जारी रखने के लिए कैजुअल्स लिए जाते हैं ताकि उनकी सैकिण्ड इनकम हो सके। उनको एक महीने में केवल सात दिनों का ही काम मिलता है। इस से अलग-अलग लोगों को रेडियो और दूरदर्शन पर आने का अवसर मिलता है। इससे प्रसारण का इग्जिक्यूशन भी पूरा हो जाता है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष जी, अनुराग जी ने अभी कहा कि पाकिस्तान के चैनल्स का तो प्रसारण हो रहा है, लेकिन हमारे चैनल्स का प्रसारण नहीं हो रहा है। तो यह कहीं न कहीं सरकार की फैल्योर है कि पाकिस्तान के चैनल्स का प्रसारण हो रहा है और हम हमारे चैनल्स का प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि इस समय प्राइवेट एफएम चैनल्स का ज़माना चल रहा है। ऑल इंडिया रेडियो ने प्राइवेट चैनल्स पर अंग्रेजी और हिन्दी में न्यूज़ बुलेटिन अलाऊ किए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, कोई कर्नाटक से है। मराठी, कन्नड़, बंगाली आदि रीजनल भाषाएं हैं, उनके बुलेटिन दिन में कभी न कभी होते हैं, लेकिन क्या आप रीजनल भाषा में बुलेटिन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की तरह ही अलाऊ करेंगे ताकि क्षेत्रीय भाषी लोग भी उसको समझ सकें?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) : महोदया, माननीय सदस्य ने एक अच्छा पॉइंट उठाया है। एफएम रेडियो बेसिकली लोकल रेडियो होता है और आम तौर से उसी क्षेत्र की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, हालांकि आजकल देश के सभी एफएम रेडियोज़ पर चाहे वे साउथ, ईस्ट कहीं के भी हों, उनमें हिन्दी और लोकल लैंग्वेज का मिक्स बोला जाता है। अभी तक प्राइवेट रेडियो स्टेशनस पर खबरें अलाउड नहीं थीं, सरकार ने नीति बनाकर उसको शुरू किया है। उसमें हमने यह कंडिशन रखी है कि आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ हू-बहू लीजिएगा। यह हाल ही में शुरू हुआ है और इसको शुरू हुए मात्र दो हफ्ते ही हुए हैं। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, We have noted it. मैडम, हम एनश्योर करेंगे कि इसकी क्वालिटी भी बेहतर होती जाए और इसकी अड्रेसिबिलिटी लोकल लोगों के लायक बने। We will ensure that they get this done.

माननीय अध्यक्ष : यह अच्छा है, क्योंकि लोग रेडियो को भूल गए थे, अब फिर से सबने इसको याद करना शुरू कर दिया है।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity because I was a casual announcer in the All India Radio some 35 years back.

माननीय अध्यक्ष : यह कितनी अच्छी बात है कि आप कैजुअल अनाउंसर के बाद पार्लियामेंट मैम्बर बने।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): With the mercy of the people and also with your mercy. I would like to ask a question to the Hon. Minister, Col. Rajyavardhan Rathoreji. Two questions have been asked: one by Shri Ashok Mahadeorao and the other by Shri Prasun Banerjee. As I have told you, Madam Speaker, I am a person who has some home sickness or nostalgia with the Akashvani as well as with Doordarshan.

(1135/AK/SJN)

Now, many of the TV-relay Centres of our nation are being closed down. As regards the local TV-relay Centres in my own State, in Adoor and Punaloor, they have already been closed down; and another one in Devikulam in my learned friend Adv. Joice George's Constituency is going to be closed down.

As regards the FM coverage, I hope that the learned Minister may also agree with me that even though we all accept and know the importance of FM media, the coverage of FM is only 52 per cent. Many of the hon. Members have said that if the FM coverage is not increased, we will not reach the

people. There has been an allegation from various quarters that it is all motivated to help the private TV channels.

Madam Speaker, Akashvani is the mother of all audio media of this nation, and Doordarshan is the mother of all visual media of this nation. So, I would like to ask this, through you, Madam, from the hon. Minister. यह सवाल मेरे दिल से आ रहा है। This is not a speech, but यह सवाल मेरे दिल से आ रहा है। Will the Minister take appropriate steps at the earliest? Honestly, he can take steps to strengthen Akashvani as well as Doordarshan. Otherwise, we will be at the mercy of some other nation, and we will be at the mercy of the private channels. Thank you, Madam Speaker.

HON. SPEAKER: Yes, his suggestions may be well taken. That is all.

... (*Interruptions*)

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.) : Madam Speaker, the Question was on Departmental promotions. However, since the hon. Member has asked from 'dil se', if you allow me, I will answer it.

माननीय अध्यक्ष : एक-दूसरे के दिल को इतना पहचानेंगे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा।

...(व्यवधान)

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.) : Madam, you will find casual announcers from all walks of life. I am not surprised, and in fact, I am happy that we have an hon. Member who has been a casual announcer.

Madam, I will clarify about the 52 per cent that he mentioned. It is 60 per cent of population that is covered by FM, and 45 per cent of geographical mass that is covered by FM. However, it is a collaborative effort, namely, All

India Radio FM Stations and private FM Stations collaborating to reach the entire country.

He also spoke about the closing down of some of the transmitters and relay stations. We are closing down the analogue terrestrial transmitters for the reason that every transmitter is able to relay only one channel. We are now digitizing it, and when we digitize it, every single transmitter, first, gives better clarity of the broadcast and secondly, it carries 10 channels. Therefore, we have a larger number of channels that can be carried. We have realised that there are very few people who are actually receiving signal on an analogue transmitter, and most people have the Set-Top Boxes and take the service from DTH. It is our continuous effort -- as a person who has been associated with the broadcast industry -- that we are not giving in to private operators, but we are collaborating with them so that the Indian population has better services available to them.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सारे दूरदर्शन रिले केन्द्र बंद कर दिये गये हैं। जहां पर एफ.एम. रेडियो की शुरुआत करनी थी और जो घोषणा हुई थी, जैसे मेरे लोक सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर में वह अभी तक नहीं चले हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्र बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की सारी की सारी फ्रीक्वेन्सी राजस्थान में आ रही है। दूरदर्शन रिले केन्द्र को दोबारा चालू करने के लिए मंत्रालय का क्या विचार है? यह मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा।

(1140/BKS/SPR)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैडम, मैं यह बात दोहरा देता हूँ कि यह प्रश्न डिपार्टमेंटल प्रमोशंस पर था, लेकिन फिर भी यह बात बार-बार आ रही है कि पाकिस्तान से सिग्नल्स हिंदुस्तान में आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत किसी के सिग्नल्स रोकना नाजायज है, गलत है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनके जितने सिग्नल्स हमारे यहां आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे सिग्नल्स उनके देश के अंदर जा रहे हैं। जहां तक बॉर्डर एरियाज की बात है, वहां सैटेलाइट के कारण हमारे पूरे भारत की कवरेज है। सैटेलाइट का जो फुटप्रिंट है, वह पूरे भारत में है, कोई भी सीमावर्ती एरिया खाली नहीं है।

जो आपके क्षेत्र की बात है, माननीय सांसद मुझसे बाद में मिल लें, मैं उनकी मदद कर दूंगा।

(इति)

(प्रश्न 65)

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय मंत्री से कहना चाहूंगा, उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है, इसमें परियोजना के नाम से इतना अच्छा लगता है – भारत माला परियोजना। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, आप इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आपने हमारे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में दिया, लेकिन आपने अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया, शायद उसका कोई अलग कारण है। लेकिन मैं उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में सिटिजन अमेंडमेंट बिल (सी.ए.बी.) में जो डिक्लेरेशन हुआ था, तब पूरा असम बंद हुआ था। उसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर हम पूरब या पश्चिम से जाना चाहते थे तो वह पूरा रास्ता बंद हो जाता था। एक ही लिंक है, जिसे हम पी.एल.टी. रोड कहते हैं, पासीघाट, लेडन, तेने रोड, जो जिरडो और दारिंग को जोड़ता है, सिर्फ एक वही लिंक बचा हुआ है। पासीघाट से राइट अप टू जो सीमावर्ती इलाके चांगलांग और तिरप तक हम जा सकते हैं, लेकिन हम ईटानगर तक नहीं जा सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी परसों शायद ईटानगर जाएंगे, उस समय आप यह घोषणा करा दीजिए कि इस रोड को भी हम पूरा कर देंगे, ऐसा एक आश्वासन हमें दीजिए।

महोदया, मेरा यही प्रश्न है कि इस विषय में आपने ईस्ट-वैस्ट हाइवे जो पहले ही एनाउंस किया हुआ है, उसमें आप अमाउंट ऑफ सैंक्शन कब तक दे सकेंगे?

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, भारत माला जो प्रोजेक्ट है, यह भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। In this, total Economic Corridor Development, Inter-corridor and Feeder road, National Corridor Efficiency Improvement, Border and International Connectivity Road, which we have provided in Arunachal Pradesh; after that, Coastal and Port Connectivity Roads, Greenfields Express Ways, and balance road works under NHDP. Along with this, roads under

existing schemes, that is, LWE, ACRDP (North-East), and Setu Bharatam and Char Dham.

इसमें 83677 किलोमीटर टोटल लैथ भारत माला परियोजना में कवर की गई है, इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिला है और उसकी कीमत 6,96,92,320 करोड़ रुपये है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें टोटल 137 प्रोजेक्ट्स 6532 किलोमीटर हैं और इसमें 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के कांटेक्ट्स हमने अवार्ड कर दिए हैं और कार्य की शुरुआत हो गई है। जो डीपीआर बन रहा है, वह 21210 किलोमीटर में है और यह एक ऐतिहासिक बात हुई है कि इसमें 25 हजार हैक्टेअर रोड के लिए जो लैंड है, उसका 3डी इस साल में पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कुछ कहने के बजाय आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको वहां रोड का काम दिखेगा, वह इस बात का परिचय देगा।

जहां तक अरुणाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्ट की बात है, हमने दो लाख करोड़ रुपये के काम मंजूर किए हैं। आपको पता है कि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी, एविएशन कनेक्टिविटी नार्थ-ईस्ट में इतना काम हो रहा है, जो इसके पहले नहीं हुआ।

(1145/GG/UB)

नॉर्थ-ईस्ट में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में ही केवल 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कार्यों को हमने मंजूरी दी है। बीच में मैं वहां गया था। अभी हमने यह प्रोग्राम फिक्स किया है, इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। अगर कोई नया एड करना चाहते हैं तो मुझे फिर कैबिनेट में जाना पड़ेगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि और किसी प्रोग्राम में अगर हो सकता है तो मैं कोशिश कर के देखूंगा। परंतु अब इस प्रोग्राम में एड करना मुश्किल होगा। जो डिकलेयर किया है, क्योंकि यह टोटल प्रोग्राम जो है, वह 83 हजार 677 किलोमीटर है और इसकी कीमत 6 लाख 92 हजार 324 करोड़ रुपये है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सन् 2022 के पहले अगर यह प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो देश के रोड नेटवर्क की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए आज इसमें कुछ नया एड

करने की बजाय, जितना मिला है, उतना पूरा करेंगे और आपने जिसका उल्लेख किया है, अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिक रोड के बारे में जो डीटेल्स हैं, वह मुझे आप एक बार डीटेल में दे दीजिए, और किसी योजना में उसमें मार्ग निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐड करने के लिए कैबिनेट में जाना पड़ेगा, वह संभव नहीं होगा।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर): अध्यक्ष महोदया, मैं डिवीज़न क्रमांक – 260 से बोलने की अनुमति चाह रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे देश में रोड नैटवर्क की जो तस्वीर बदली है और उसमें मध्य प्रदेश में भी विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। भारत-माला परियोजना के तहत जो 65 हजार किलोमीटर की अनुमानित लंबाई पर काम हुआ, उसमें मध्य प्रदेश को 5850 किलोमीटर से जोड़ा गया, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सेंट्रल रोड फंड से मंदसौर संसदीय क्षेत्र को विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने जोड़ने का प्रयास किया है। मंदसौर चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, देश भर में विशेष रूप से उल्लेखित रहा है कि किसानों की मांगों के संबंध में मंदसौर एक जागृत स्थिति में भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद के साथ एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं देश में रोड नैटवर्क को ले कर लागू की गई हैं, आज वे देश ही नहीं दुनिया के सामने उल्लेखनीय हैं। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से विशेष धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रोड बनने जा रही है, जिसमें मेरा क्षेत्र जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, उसमें कृषि उत्पादों को देश के मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए एक अभिनव प्रयोग होगा, उसमें 85 किलोमीटर तक मंदसौर संसदीय क्षेत्र को जोड़ा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि यह विशेष परियोजना देश को कितने समय में समर्पित होगी? मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर से विशेष धन्यवाद माननीय मंत्री जी को मैं देना चाह रहा हूँ।

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, यह देश की सबसे महत्वपूर्ण रोड है। इसकी विशेषता यह है कि यह दिल्ली और मुंबई के बीच में एक नया द्रुतगति महामार्ग बन रहा है। इसकी जो विड्थ है, वह 120 मीटर है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है, दिल्ली से अहमदाबाद,

सूरत, वडोदरा, मुंबई, इसके बजाय हमने नई अलाइनमेंट ग्रीन हाइवे की सिलैक्ट की है। यह गुड़गांव से शुरू होता है और यहां से सवाईमाधोपुर, अलवर, रतलाम, झाबुआ से हो कर वडोदरा और वहां से मुंबई जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इससे बैकवर्ड एण्ड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, बैकवर्ड एण्ड ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बैकवर्ड एण्ड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा का पूरा पिछड़ा क्षेत्र विकसित हो रहा है। मैडम, इसमें मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरे डिपार्टमेंट में दस लाख करोड़ रुपये के काम हमने अभी तक अवार्ड किए हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी मंत्रालय के पास आना नहीं पड़ा। ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री काम हुआ है। इस एक ही रोड में हमने लैण्ड एक्विजिशन में 16000 करोड़ रुपये देश के बचाए। यह डिस्टेंस 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक आप कार में बैठ कर 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरा कर सकेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैडम, इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके काम भी शुरू हो गए हैं। वडोदरा से मुंबई 44000 करोड़ रुपये के काम अवार्ड हो गए हैं। गुड़गांव से ले कर जो मध्य प्रदेश की बात इन्होंने की थी, मध्य प्रदेश में 240 किलोमीटर, राजस्थान में 400 किलोमीटर, गुजरात में 250 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 250 किलोमीटर, यह लगभग काम, अभी हमारा लैण्ड एक्विजिशन लगभग पूरा हुआ है। मैंने पीयूष गोयल जी को प्रस्ताव दिया कि हमारे पास 120 मीटर की विड्थ है। आप चाहो तो मैं बुलेट ट्रेन के लिए भी जगह देने के लिए तैयार हूँ।

(1150/KN/KMR)

अब लैंड पूरी तैयार हो गई है। काम शुरू हो गया है। प्रधान मंत्री के हाथ से भूमि पूजन कर रहे हैं और इनके क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में सम्मानित सदस्य ने जो कहा, लैंड एक्विजिशन का काम बहुत अच्छी प्रोग्रेस में हुआ है। मध्य प्रदेश में इनके क्षेत्र में बहुत विकास होगा। दिल्ली के लिए जो वडोदरा या सूरत या अहमदाबाद तक जो डेवलपमेंट्स डीसेंट्रलाइज हुए थे, उसका डीसेंट्रलाइजेशन होगा। इस रोड पर लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा और ट्राइबल सेक्टर में नया रोजगार निर्माण होगा। देश के लिए नया ग्रोथ इंजन होगा। इसका काम लगभग शुरू हुआ है। यह प्रयास है कि ढाई साल के अंदर यह पूरा हो और काफी काम अब अवार्ड

भी हुआ है। आने वाले 10-15 दिन में इसके भूमि पूजन करने के लिए प्रधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमारे नेशनल हाइवे का नेटवर्क वर्ल्ड में प्रथम क्रमांक पर पहुँचा है। यह एक्सप्रेस हाइवे जो दिल्ली से मुम्बई का है, जो केवल 1 लाख करोड़ रुपये का एक हाइवे है, यह भी मुझे लगता है कि वर्ल्ड के इतिहास का एक रिकार्ड होगा और इसके कार्य का शुभारंभ लगभग होगा।

माननीय अध्यक्ष : इतने पैसे बचाए हैं तो मंदसौर के पास इंदौर-मंदसौर भी जुड़ सकता है क्या?

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR): Madam Speaker, I am really happy to mention here that the Road Transport and Highway Ministry under the leadership of Mr. Gadkari has really done commendable work throughout India and in the State of Maharashtra particularly.

Madam, in my Constituency there is one important road going through National Highway No.60 where Mr. Gadkari had announced and done Bhumi Pujan in July 2017. That work is pending just because of contractor's fault, the contractor has gone to the court, not because of a mistake from the Ministry. I would request the hon. Minister to intervene and ask the contractor to complete the work. This is about Pune-Nashik road of ILFS. The other work which was announced and sanctioned was Pune-Nagar road. These two roads are important from traffic point of view in my State Maharashtra. So, I would request the hon. Minister to intervene and instruct the contractor to complete the tender work. Thank you.

श्री नितिन गडकरी : मैडम, आईएलएंडएफएस को जो काम मिला था, आपको पता है कि अभी वह काम करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पाँच बाईपास हैं और सम्मानित सदस्य के आग्रह पर पाँचों का टेंडर निकाला गया है। डिपार्टमेंट ने यह तय किया है कि अब आईएलएंडएफएस काम नहीं

कर सकती है तो हम अपने पैसे से काम करेंगे। लगभग टेंडर निकल गया है, टेंडर रिसेव हुआ है। केवल एक आईएलएंडएफएस के एनओसी की बात है। मैंने उनसे बात की है। उनका एनओसी लेकर पन्द्रह दिन, महीने भर में यह काम शुरू हो जाएगा। जो अहमदनगर से पूना के बारे में बात है, उसका अभी डीपीआर बन रहा है। अभी मैं उसके बारे में आश्वासन नहीं दे सकता। मैडम, एक मेरी विशेषता अच्छी है, मैं इसके लिए भाग्यवान समझता हूँ कि हर पार्टी का एमपी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वह यही कहता है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा और अच्छा काम हुआ है। These are good compliments. I really thank you. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील जाखड़, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए।

श्री सुनील कुमार जाखड़ (गुरदासपुर): स्पीकर मैडम, आपके थ्रू सबसे पहले मैं गडकरी साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अभी कुछ रोज़ पहले पंजाब आए थे। गुरुनानक जी के 550वें प्रकाश पर्व पर इन्होंने डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहब के हाइवे का नींव पत्थर रखा। मैं इनका आभारी भी हूँ और इनसे आशा करता हूँ कि उसके ऊपर हो रही देरी को लेकर, जहाँ यह स्पष्टीकरण देंगे, वहीं पर मेरा एक सवाल इनसे है कि क्या अमृतसर डेरा राजा सांसी से लेकर डेरा बाबा नानक तक स्टेट हाइवे 25 को इस भारतमाला में जोड़कर फोर लेन फ्रीवे बनाने पर कंसिडर करेंगे?

श्री नितिन गडकरी : आप करतारपुर वाली बात कर रहे हैं?

श्री सुनील कुमार जाखड़ (गुरदासपुर): जी सर। करतारपुर से डेरा बाबा नानक, क्योंकि राजा सांसी से लेकर करतारपुर तक जितने भी अनुयायी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए आएँगे, अमृतसर से लेकर राजा सांसी एयरपोर्ट या अमृतसर से लेकर डेरा बाबा नानक तक जो स्टेट हाइवे 25 है उसको फोर लेन फ्रीवे बनाने का अनुरोध है।

(1155/CS/SNT)

श्री नितिन गडकरी : महोदया, करतारपुर का जो रोड बनने वाला है, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, चूँकि प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग पहले काम शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान उधर

से काम शुरू करने वाला था, हमने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नियम हो, उसके ऊपर तुरन्त निर्णय करके काम करने का अधिकार दे दिया गया है। केवल भूमि अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। उसमें थोड़ी गति देकर उन्हें यह कहा गया है कि टेंडर निकालकर, क्योंकि उसी कान्ट्रैक्टर से यह काम भी पूरा कराने के हमने आदेश दिए हैं और यह काम पूरा होगा। भूमि अधिग्रहण के बारे में “श्री ए” नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार में जारी हुआ है और मुझे लगता है कि लैंड मिल जाएगी, तो यह काम पूरा होगा। जो उसे आगे तक करने की बात माननीय सदस्य ने कही है, उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिया है, मैं उसके ऊपर जाँच करके जो कुछ भी हो सकता है, वह करने की कोशिश करूँगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह, आप बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। जैसा आपने माननीय मंत्री जी से बोला कि मंदसौर से लेकर जो रोड इंदौर जाता है, मैं भी उसी मालवा के क्षेत्र से आता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जब से अपना विभाग संभाला है, इन्होंने राजस्थान और पूरे देश में रोड का जो जाल बिछाया है, उससे पूरे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो रोड कोटा से चलते हुए, जो भारतमाला रोड है, जो रोड मंदसौर से जाती है, जो रोड झालावाड़ से जाती है, वह रोड कब तक बनेगी और महोदया आगे जो आप बोल रही हैं, वह आपके क्षेत्र से निकलते हुए दक्षिण भारत तक कब तक बनेगी। मंत्री जी, आप मुझे इसके बारे में बताएं।

श्री नितिन गडकरी : महोदया, यह प्रश्न तो भारतमाला तक ही सीमित है। अब देश के सभी रोड्स की जानकारी तो अभी एकदम मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरी जानकारी ठीक होगी तो शायद यह फॉरेस्ट के क्लियरेंस के लिए फंसा हुआ रोड है। क्या यह वही रोड है?

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : नहीं, सर। यह रोड भवानी मंडी का है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट में है। यह एक्सप्रेसवे है।

माननीय अध्यक्ष : आप इसे लिख लेना।

श्री नितिन गडकरी : मैं इसके ऊपर तुरन्त उनसे बात करके और इंदौर तक है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपको इंदौर से जोड़ने का काम मैं पक्का जल्द से जल्द कर दूँगा।

(इति)

(प्रश्न 66)

माननीय अध्यक्ष : निशंक जी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि देश की आजादी के 70 वर्षों में जितने कुल राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड की धरती पर नहीं बने थे, इन 4.5 वर्षों में आपने उससे भी ज्यादा दिए हैं। उत्तराखंड की सारी आर्थिकी तीर्थाटन और पर्यटन पर ही निर्भर करती है। मैं प्रधान मंत्री जी और नितिन गडकरी जी का इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जहाँ उन्होंने 12,500 करोड़ रुपये की लागत से चार धाम बद्दीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए महायोजना बनाई है, वहीं कर्णप्रयाग तक 16,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली रेल लाइन भी अलग से दी है। 12 महीने, 24 घंटे सुरक्षित चारधाम यात्रा की यह जो महायोजना है, जिसमें लगभग 12,500 करोड़ रुपये व्यय होने हैं और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1,800 करोड़ रुपये उसमें व्यय भी हो गए हैं।

महोदया, मैं विनम्रता से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ भारी बर्फबारी, भू-स्खलन और जिस तरीके से बाढ़ आदि में वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, तो क्या पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण की दृष्टि से इस बड़ी योजना में कोई अलग से प्रावधान किया गया है? यदि कोई प्रावधान किया गया है, तो वह क्या है और कब तक यह पूरा हो जाएगा? उसी में जो यात्रा मार्ग मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून है, हमने कई बार आग्रह किया और आपने युद्ध स्तर पर उसको क्रियान्वित भी किया, वह कब तक पूरा हो जाएगा, यह मैं जानना चाहता हूँ।

(1200/RV/GM)

श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, केदारनाथ, बद्दीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कहीं भी आप पूरे साल भर जा सकते हैं, इस तरह से नई एलाइनमेंट तैयार की गयी है।

स्पीकर महोदया, आपको पता है कि उत्तराखण्ड में जब हादसा हुआ था, तब काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए, स्विट्ज़रलैंड से और पूरे विश्व से इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को बुलाकर

इसका पूरा अध्ययन करने के बाद इसकी डी.पी.आर. बनाई गयी। जब मैं मंत्री बना तो उस समय यह काम, विशेष रूप से उस हादसे का ही परिणाम था। इस पूरे काम को इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर ध्यान देकर किया गया है। इसकी लम्बाई 889 किलोमीटर की है, 12 हजार करोड़ रुपये इसकी कीमत है। इसमें टू-लेन पेव्ड शोल्डर का है। इसमें 25 मेजर ब्रिजेज, दो टनेल्स, तीन वायाडक्ट्स हैं। इसके साथ-साथ इसमें करीब 107 माइनर ब्रिजेज हैं, 16 रि-एलाइनमेंट बाइपासेस हैं और 3,890 कल्वर्ट्स हैं। यह पूरी तरह से नया रोड है। इसलिए इसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की पूरी चिंता करते हुए इसका प्लान किया गया है।

दूसरी बात यह है कि यह सब करते समय हमने विशेष रूप से ऑल-सीजन रोड के हिसाब से रोड के बगल में छोटी-छोटी एमेनिटीज रखी है। उसमें बैठने की सुविधा रहेगी। ये घटनाएं जो होती थीं, जैसे पहाड़ गिर गया था, बादल फट गया था, लेकिन अब इस प्रकार की एलाइनमेंट बनी है कि अब कोई भी संकट आएगा, तब भी एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी और कभी भी ट्रैफिक नहीं रुकेगा। इसलिए Rock bolting, Soil nailing, Reinforcement of earth wall, Bio-engineering measures, ये सब हमने उसमें दिए हैं। एक बात जरूर है कि यह जो प्रोजेक्ट है, इसमें स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. के पास 436 किलोमीटर की 27 प्रोजेक्ट्स हैं, बी.आर.ओ. के साथ 328 किलोमीटर की 18 प्रोजेक्ट्स हैं और एन.एच.आई.डी.सी.एल. के पास 125 किलोमीटर की 8 प्रोजेक्ट्स हैं।

मैडम, इसमें एनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट की पूरी चिंता करने के बाद भी इस काम को बहुत बार कोर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया। पहले नैनीताल कोर्ट ने इसे बंद कर दिया। फिर उससे निकल गए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है। पर, इसमें एक बात है कि 100 किलोमीटर तक एनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं लगता है। चार धाम योजना, यह एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें छोटे-छोटे 58 प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलग-अलग डी.पी.आर. बने हुए हैं। पर, जो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि यह एक ही प्रोजेक्ट है और इसलिए इसके लिए एनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट का क्लियरेंस लिया जाए।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां बाकी बातें क्लियर होंगी। पर, अभी उन्होंने काम करने की अनुमति दी है। मुझे लगता है कि इसमें भी पॉजिटिव निर्णय हो जाएगा। कोर्ट केसेज और लिटिगेशन में एक साल का विलम्ब हुआ है। पर, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2020 के पहले यह प्रोजेक्ट पूरा होगा।

इसमें मैं सबसे अच्छी बात यह बताना चाहता हूं कि जब मैं बी.जे.पी. का अध्यक्ष था और निशंक जी मुख्यमंत्री थे, और जब मैं बद्रीनाथ-केदारनाथ के दर्शन करने जा रहा था तो उस समय लोग बहुत नाराज होते थे और मुझसे कहते थे कि देखिए कैसी अव्यवस्था है, यहां रोड्स इत्यादि नहीं हैं। मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ। फिर मैंने निशंक जी से कहा था कि आप सरकार तंत्र को छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही, अपने कुछ लोगों के साथ प्राइवेटली ही जाऊंगा, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते थे। अब मुझे इस बात की खुशी है कि गंगा नदी और बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री-यमुनोत्री की स्थिति ठीक हो गयी है। स्पीकर महोदया, आप इस समय प्रयाग जाइए।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, मैं देखकर आई हूं। वह साफ है।

श्री नितिन गडकरी: पहली बार, इस बार, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि वहां का जल शुद्ध और स्वच्छ है। अविरल और निर्मल गंगा है।

माननीय अध्यक्ष: हमारा आशीर्वाद है।

श्री नितिन गडकरी: गंगा नदी अच्छी हुई है। वहां पूरे विश्व से लोग तीर्थाटन करने आते हैं। वर्ष 2020 के पहले ऑल-सीजन रोड्स तैयार हो जाएंगे। आप साल भर कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी एलाइनमेंट बनी है कि चाहे कितना भी बड़ा बादल फटे, कितनी भी बड़ी बाढ़ आए, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा और आप बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री के दर्शन कर सकेंगे। यह काम वर्ष 2020 के पहले पूरा हो जाएगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: बहुत बढ़िया। आज बहुत अच्छे मूड में क्वेश्चन आवर हो गया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, अब आप चिंता न करें।

...(व्यवधान)

QUESTION HOUR OVER

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें धन्यवाद दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। अब आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, मैं तो धन्यवाद देने के लिए कह रहा हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप तो आशीर्वाद दीजिए।

...(व्यवधान)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1204 hours

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. जितेन्द्र सिंह जी।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर (स्पेशल ग्रेड), (ग्रेड-I), (ग्रेड-II) और (ऑर्डिनरी ग्रेड) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 384 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2018 जो 27 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1239(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2019 जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-6/2017-एनएसएल-॥ में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 21 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 11) जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2018-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(1205/RK/CP)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Annual Accounts of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the years 2016-2017 and 2017-2018, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the years 2016-2017 and 2017-2018.
- (4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

- (1) Review by the Government of the working of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2017-2018.
- (2) Annual Report of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963: -

- (i) G.S.R.1208(E) published in Gazette of India dated 14th December, 2018, approving the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018.

- (ii) G.S.R.1143(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2018, approving the Paradip Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018 containing corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. No.7(E) dated 4th January, 2019.
 - (iii) G.S.R.6(E) published in Gazette of India dated 4th January, 2019, approving the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (2)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2017-2018.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2017-2018.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) सेंटर फॉर मैटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर मैटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989: -
 - (i) The Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.278(E) in Gazette of India dated 26th March, 2018.
 - (ii) The Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Second Amendment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.1205(E) in Gazette of India dated 14th December, 2018.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table: -

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Air India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Air India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2017-18.

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):
 - (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (3) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table: -

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956: -

- (i) S.O.6111(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.222 (New NH 61) (Kalyan to Nirmal Section) in the State of Telangana.
- (ii) S.O.6112(E) published in Gazette of India dated 11th December, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.365 (New) (Mangalwarpet to Mallampalli Section) in the State of Telangana.
- (iii) S.O.6248(E) published in Gazette of India dated 21st December, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.113 (Padhi-Dahod Section) in the State of Rajasthan.
- (iv) S.O.6249(E) published in Gazette of India dated 21st December, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.13 (Solapur-Bijapur Section) in the State of Karnataka on Design, Build, Finance, Operate and Transfer Basis (DBFOT) Toll Basis.

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
46वां प्रतिवेदन**

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
Statement**

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to lay on the Table the Final Action Taken Statement (Hindi and English versions) of the Government on the recommendations contained in Chapter I of the Twentieth Report (16th Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes pertaining to the Ministry of Petroleum & Natural Gas on Action Taken by the Government on the Tenth Report (16th Lok Sabha) on 'Status of implementation of Reservation Policy in those companies who have 50% Government and 50% Private equity like Petronet LNG Ltd.'

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
Report of Study Visit**

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): I beg to lay on the Table the Report (Hindi and English versions) of the Study Visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Ranchi, Hyderabad, Pune and Mumbai during September-October, 2018.

**श्रम संबंधी स्थायी समिति
46वां से 52वां प्रतिवेदन**

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा कौशल विकास पहल योजना' के बारे में समिति के 33 वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।
- (3) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

- (4) गृह मंत्रालय से संबंधित 'एनडीएमसी में स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु अनुबंध/नैमित्तिक/स्वच्छता कर्मियों की तैनाती' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (5) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।
- (6) विदेश मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'महिला कर्मियों, जिसमें उपचारिकाएं और सेविकाएं शामिल हैं, की विदेशों में नियुक्ति, मुद्दे तथा विनियामक ढांचा' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (7) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती और जमा तथा स्रोत पर कर कटौती (आयकर, आदि) के विहित प्रावधानों का अनुपालन' संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
24th and 25th Reports

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:-

- (1) Twenty-fourth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in their 18th Report on 'Tourism Promotion and Pilgrimage Circuit'.
- (2) Twenty-fifth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in their 21st Report on 'New Railway Catering Policy, 2017'.

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
216th to 219th Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

- (1) 216th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Eleventh Report on the Cyclone Ockhi- its Impact on Fishermen and Damage Caused by it.

- (2) 217th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Ninth Report on Demands for Grants (2018-19) of the Ministry of Home Affairs.
- (3) 218th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Tenth Report on Demands for Grants (2018-19) of the Ministry of Development of North Eastern Region.
- (4) 219th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Thirteenth Report on Security situation in the North Eastern States of India.

(1210/PS/SK)

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 320TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS—LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 320th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Department of Space.

**MOTION RE: SIXTY- FIRST REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to move:

“That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 5th February, 2019.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 5th February, 2019.”

The motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

1213 hours

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Madam Speaker, Coimbatore is called the Manchester of South India and considered as the 2nd biggest city and number one industrial city in Tamil Nadu. Coimbatore has been selected as one of the Smart Cities in the country. Now, Coimbatore is a fast-growing city with all-round development in employment, education, health, agriculture, etc.

Coimbatore Airport caters to the needs of nearby districts and cities namely, the Dollar City of South India of Tirupur; Steel city of Salem in Tamil Nadu, Textile City of Erode; Nilgiris in Tamil Nadu; and Palakkad and some other districts of Kerala. Further, a large volume of goods from both industrial sector and agricultural sector are being exported from Coimbatore through highways and airways to other cities in the country and abroad.

At present, there are around 14 lakh people who travel annually to and from this airport. About 7000 tonnes of cargo per year is handled here. Due to shortage of flight service, both for domestic and international operations, the textiles and knitting industrial units and agricultural sector are facing a lot of problem. The farmers who are producing perishable goods like vegetables, fruits and flowers, are now compelled to go to the far away airports of Chennai, Trichy, Bengaluru and Kochi, to export their goods resulting in a huge loss of money and time. Further, Coimbatore airport was conferred with international status in the year 2012. It must get more air connectivity.

In view of this, I request the Union Government to take necessary action for the expansion of the existing Coimbatore Airport.

HON. SPEAKER: Dr. Kulmani Samal, Shrimati V. Sathyabama and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Nagarajan.

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर है जो कि यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही कई जिले दिल्ली एनसीआर में हैं। एनसीआर के नजदीक और राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद यहां बहुत सी व्यवस्था की चीजें नहीं पहुंची हैं, चाहे ट्रेन हो या अच्छे रास्ते हों।

अध्यक्ष जी, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहां से प्रदेश की राजधानी लखनऊ 515 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 615 किलोमीटर दूर है जबकि पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट नजदीक है, जो कि 482 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और सामली है।

(1215/MK/SNB)

ये सारे जिले दिल्ली से लगे हुए हैं और राजधानी का हिस्सा भी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजधानी से सटे हुए हैं, उनको दिल्ली प्रदेश में जोड़ लिया जाए ताकि उनका विकास हो। ये जिले पूरे दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत सारा रेवेन्यू भी देते हैं। दिल्ली के लिए दूध, सब्जी, फल आदि सारी चीजें सप्लाई करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh -- Not present

Shri Ravindra Kumar Pandey -- Not present

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Madam Speaker, in the mid-80s, Jawahar Navodaya Vidyalayas were set up with the stated objective of providing quality education to rural poor.

Madam, in an unjustified move, the Government has recently decided to increase the fees of students up to class IX of Jawahar Navodaya Vidyalayas from Rs. 200 to Rs. 600. The monthly fees for these students have been trebled. Further, fees for students of classes IX to XII, which includes children of Government employees and also children belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have been increased to Rs. 1500 per month.

Madam, this is highly unjustified because this hike in the fees will make the Navodaya Vidyalayas inaccessible to rural poor. Furthermore, a fee of Rs. 1500 per month will not only make the Navodaya Vidyalayas inaccessible to rural poor but also is the beginning of doing away with reservation in these schools. This is not only unjustified but also highly unacceptable and condemnable.

Madam, through you, I would like to request the Government to withdraw this hike in fees immediately. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री तारिक अनवर, डॉ. कुलमणि सामल और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री एम.बी.राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, यह बहुत ही गंभीर मामला है। लगातार केंद्र और बिहार झगड़े में एन.एच.ए.आई और रेल की जो भी परियोजनाएं हैं, वे कम्प्लीट रूप से ठप पड़ गयी हैं। मेरे यहां एन.एच-106 रोड का टेंडर आई.एल.एफ.एस. कंपनी ने लिया था। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस वहां गये, तो हाई कोर्ट ने सुओ-मोटू नोटिस भी लिया था। लगातार डेट-पर-डेट दी जा रही है। हाई

कोर्ट के चीफ जस्टीस ने भी कहा था कि हमने इतनी गंदी रोड आज तक नहीं देखी। हमारे यहां एन.एच-106 एवं एन.एच.-107 रोड है। मैडम, सहरसा में एक ओवर ब्रिज है, जिसको बनाने के लिए पुल निगम को कई बार पैसे दिये गये, लेकिन बिहार सरकार इस पर कम्प्लीट रूप से ध्यान नहीं दे रही है। उंचेट स्थान से तारा स्थान होते हुए सिंहेश्वर स्थान खुर्दा से एन.एच-107 में फुलोंद और बेड़ों का टेंडर का होना था, इसके लिए बिहार सरकार जमीन अधीग्रहण नहीं कर पा रही है। आप इसको लगातार देखेंगे। इसमें मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि बिहार सरकार को एक निर्देश दिया जाए कि दोनों पुल का टेंडर के लिए सब कुछ हो गया है, लेकिन एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है। आई.एफ.एफ.एस. कंपनी एन.एच-106 रोड के लिए कार्रवाई तुरंत करे और साथ-साथ पुल निगम को निर्देश दिया जाए कि सहरसा ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य जल्द पूरा करे।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैडम, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मोदी जी की सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी योजना चलाई है और देश की जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की हैं। भारत सरकार ने अमृत फार्मेशियों के कैंसर और कार्डियो वैस्कुलर बीमारियों की दवाओं के साथ-साथ कार्डियाक इम्प्लांट की दवाएं वर्तमान बाजार दरों के मुकाबले 60 से 90 प्रतिशत की रियायती दरों पर बेची हैं। भारत सरकार द्वारा संचाचित एवं गैर-संचारित रोगों को समूल समाप्त किये जाने के बावजूद भी भारतवर्ष में प्रतिवर्ष तम्बाकू से पैदा होने वाली और दूषित पर्यावरण के कारण पैदा होने वाली बीमारियों से वर्ष 2018 में 317928 महिला व पुरुष कैंसर से मर गये हैं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया है। भारत में कैंसर से प्रतिदिन 2500 लोग मर रहे हैं। हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर रही है। 2 ब्रेस्ट कैंसर से मर रही हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. के ताजा आंकड़ों के अनुसार कैंसर रोग के सही समय पर पता न लगने के कारण यह रोग घातक स्टेज पर पहुंच जाता है। विश्व में 9.6 मिलियन लोग प्रतिवर्ष कैंसर से मर रहे हैं।

(1220/RPS/NKL)

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश में पैथोलॉजी सर्विस के दायरे को और बढ़ाया जाए और कैंसर की रोकथाम के लिए अधिक अभियान चलाए जाएं।

मैं मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल अम्बाला में दिया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, Shri Gaurav Gogoi.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, Speaker Madam.

Madam Speaker, the NRC process is being updated in the State of Assam. This process has cost a lot of money and still now, many genuine Indian citizens are left out of this draft NRC. The Supreme Court has been monitoring this exercise and recently has pulled up the Government for delaying the NRC process. It shows the lack of seriousness on the part of the Government and the Supreme Court used some very harsh words. I request the Government to speed up the implementation of the NRC and also keep in mind the present situation in the North East and the entire India regarding the Citizenship Amendment Bill. If passed, it will violate the entire NRC process; and it will violate the Assam Accord. They are protesting across India against this Bill which is unconstitutional. I hope, the Government would keep in mind that the Assam Accord says that after 25th March, 1971, any illegal migrant who enters India, should be detained and deported immediately. The sanctity of the Assam Accord must be kept. Overall, in India, there is an absence of laws to deal with important things. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, Shri P.K. Kunhalikutty and Shri E.T. Mohammad Basheer are permitted to associate with the issue raised by Shri Gaurav Gogoi.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

महोदया, मैं आज शून्य काल में, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। साक्षर भारत मिशन के तहत जिला स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में लगभग साढ़े पांच लाख साक्षर भारत मिशन कर्मियों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है। वर्ष 1999 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक इन लोगों ने मात्र 2000 रुपये के मानदेय पर काम किया। 2000 रुपये के मानदेय पर लगभग 19 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक 31 मार्च, 2018 के बाद उनकी सेवा अवधि समाप्त कर दी गई है। उनसे साक्षरता के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कार्य लिए गए ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आपकी बात आ गई है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): अध्यक्ष महोदया, उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे, पल्स पोलियो, कुष्ठ उन्मूलन, पीडीएस सुपरवाइजर, मतदान कार्य, योजना बनाओ अभियान, मनरेगा कार्य, स्वच्छ भारत मिशन आदि लिए गए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आपकी बात आ गई है, इतना लम्बा मत बोलिए।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध है कि विभाग उनके बारे में विचार करे, क्योंकि 19 वर्ष कार्य करने के बाद वे किसी लायक नहीं रहते हैं। विभाग उन पर विचार करे, उनकी सेवा अवधि का विस्तार करे और उनके मानदेय को भी बढ़ाने का काम करे। मैं सरकार से यह करने का आग्रह करता हूँ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी – उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत ।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत व्यथित अन्तःकरण से खड़ा हूँ। पिछले चार वर्षों में आपने मुझे सुना होगा कि मैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बीएसएनएल की सेवाओं के बारे में बार-बार कहता हूँ। अगर आप उनकी कॉलर ट्युन्स सुनेंगे तो वह है – 'मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।' यह एमटीएनएल की कॉलर ट्युन है और वह खुद गढ़े में जा रहा है। इस सारी स्थिति में सुधार के लिए मैं बार-बार प्रयास कर रहा हूँ। यह इतनी दर्दनाक बात है कि पिछले तीन महीने में उनको समय पर तनखाह भी नहीं मिलती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संक्षेप में बताइए।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): वर्ष 2008 में इनकी सरकार ने जो घोटाले किए, उनकी वजह से यह कंपनी घाटे में गई। ...(व्यवधान) उस वक्त से लेकर कर्मचारी कितना त्याग कर रहे हैं। ...(व्यवधान) कर्मचारियों ने पिछले दस वर्षों में बोनस नहीं मांगा। उनको नई वेतन श्रेणी अभी भी नहीं मिल रही है। इतना सब त्याग करने के बाद भी, अगर सेवाओं में सुधार हो जाए तो कंपनी उभर कर आएगी। मैं एक-एक मिनट में दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूँ। एक मुद्दा मैंने रखा था, हाल ही में आपने देखा कि एयर इंडिया ने अपने सुधार के लिए अपने लैण्ड बैंक का इस्तेमाल किया और पैसे जमा किए। हमारे पास भी लैण्ड बैंक है, उसका मॉनेटाइजेशन कीजिए। अपना कॉल सेंटर बनाएं, ये सभी सुझाव मैंने दिए हुए हैं। उन सुझावों पर काम करें।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ओर से सरकार को कहें कि इन दोनों कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल और श्रीमती वी. सत्यबामा को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका संरक्षण चाहूँगा क्योंकि यह एक विशेष और गंभीर किस्म का प्रकरण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस) संचालित है, जहां मेडिकल चलता है और रिसर्च का काम होता है। इस अस्पताल में बिलासपुर के साथ-साथ

आस-पास के जिलों जैसे कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर आदि के साथ ही मध्य प्रदेश के बहुत से हिस्सों जैसे अनूपपुर, शहडोल, ढिंढोरी, मंडला आदि क्षेत्रों से गरीब और अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं।

(1225/RAJ/SRG)

अध्यक्ष महोदया, पूर्ववर्ती सरकार, बीजेपी की सरकार ने इन वर्गों के लिए मुख्य मंत्री 'स्वास्थ्य कार्ड बीमा योजना' के माध्यम से 50 हजार रुपये तक निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' का भी वहां पर संचालन हो रहा था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकार बनी है, उसने इन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया है।

अध्यक्ष महोदया, 22 जनवरी को इस अस्पताल में आगजनी की घटना हुई थी और इस आगजनी की घटना में पांच शिशुओं की मौत हो गई। इन मौतों की जांच करने की बजाय वहां की सरकार दोषी व्यक्तियों को बचा रही है। वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके कारण वहां पर असंतोष की स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आगजनी की घटना में जिन पांच बच्चों की मौत हुई है, उसकी जांच की जाए और केन्द्र सरकार की एजेंसी द्वारा जांच की जाए। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो, उसकी व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. कुलमणि सामल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड): अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में लोग बंदूकें रखते हैं। इस क्षेत्र में डकैती की समस्या के कारण यह जरूरी था। केवल भिंड जिले में ही लगभग 25 हजार गन लाइसेंस हैं। अब इस क्षेत्र में डकैती की समस्या समाप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र के युवाओं को हथियार सहित होने पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल जाती है। चम्बल क्षेत्र के युवा निर्भिक और बहादुर होने के कारण पूरे भारत में सुरक्षा गार्ड के रूप में पसंद किए जाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने

युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष जोर दिया है। इसके लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया गया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को शस्त्र संचालन में कुशलता के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। ये तीन-चार महीनों की ट्रेनिंग से एक शानदार काम कर सकते हैं, पुलिस और सेना के सहयोगी बन सकते हैं। केवल भिंड जिले में ही एक वर्ष के अंदर 10 हजार लड़कों को रोजगार मिल सकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Speaker Madam, there are nearly 104 million elderly persons in our country and their number is increasing steadily. It was found that 71 per cent of elderly population resides in rural areas while 29 per cent in urban areas. Of these 104 million elderly people, it was found that more than 51 million of them live below poverty line. We need immediate intervention by the Central and the State Governments. The issue of elder abuse highlights a national shame. It requires both introspection and action from society at large. Many elderly persons are being subjected to abuse within their own families by their own sons and daughters.

Madam Speaker, with the changing family patterns and younger people migrating to cities in search of work, a large number of elders are being left alone at their old age. In urban areas, adults find themselves so pre-occupied with work and the stress of city life that they leave elder persons unattended at home.

Another cause for worry is that the number of homeless elderly is also increasing. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama. Is Sathyabama present here?

... (*Interruptions*)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Madam, I am about to complete it.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। एक मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

...(व्यवधान)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I am just concluding.

HON. SPEAKER: Then complete it.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, कृपया मुझे बोलने के लिए आधा मिनट का समय दें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I urge upon the Government, due to the high degree of sickness of senior citizens, they should be provided more financial assistance, monthly pension of Rs. 3000 and free treatment facilities for the welfare of senior citizens. Thank you Madam.

HON. SPEAKER: Advocate Joice George, Dr. P.K. Biju, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri M.B. Rajesh and Shrimati V. Sathyabama are permitted to associate with the issue raised by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher

*SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Hon. Madam Speaker, Vanakkam. An environment friendly Zero Liquid Discharge method is being used by 300 dyeing Units and 18 Common Effluent Treatment Plants situated in Tiruppur District of Tamil Nadu. Around 9 Crore litres of Water allocated to these dyeing Units, thus saved, is also provided for the additional use of common public every day. I request that the GST on Common Effluent Treatment Plants should be brought down from 12 per cent to 5 per cent. Moreover, I request that GST on Waste Water Treatment Equipments used in these Common Effluent Treatment Plants should also be brought down from 18 per cent to 5 per cent. I request the Union Government to take immediate action in this regard. Thank you.

(1230/IND/RP)

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह – अनुपस्थित।

श्री राजू शेड्डी - अनुपस्थित।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): अध्यक्ष महोदया, मेरे दिंडोरी क्षेत्र में अंगूर, अनार, मुनक्का और प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत से, विशेषकर मेरे दिंडोरी क्षेत्र से बांग्लादेश को अंगूर, अनार और मुनक्का काफी मात्रा में निर्यात होता था। देश में प्याज के बढ़ते उत्पादन में से विदेशों को ज्यादा निर्यात किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 5 प्रतिशत हो रहा है। वर्ष 2016-17 में 38358 मिट्रिक टन का निर्यात किया गया था, जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा भारत को मिली थी, किन्तु बांग्लादेश सरकार ने सौ प्रतिशत की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, यानी सौ रुपये के माल का निर्यात हुआ, तो सौ रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी ली जाती है, जिसके कारण भारत के अंगूर, अनार और मुनक्का का निर्यात घटकर 2017-18 में 5134 मिट्रिक टन रह गया है। निर्यात में करीब 85 प्रतिशत

की कमी आई है। अंगूर, अनार एवं मुनक्का का निर्यात महाराष्ट्र से अधिकतर होता था, निर्यात में कमी की वजह से महाराष्ट्र के किसानों की आय में कमी हुई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र के किसानों के हित में एवं विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से अनुरोध करे कि अंगूर, अनार एवं मुनक्का पर से इम्पोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके में चिट फंड कह लीजिए, अनरेग्युलेटेड डिपोजिट कह लीजिए या पोंजी स्कीम कह लीजिए, उससे हम लोग ग्रसित हैं। चाहे रोज वैली स्कैम हो, शारदा स्कैम हो, चाहे बासिल हो। तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर वे हमारे यहां डिपोजिट ले रहे हैं। वर्ष 2011 में बंगाल में एक सरकार बन जाने के कारण “जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का” इस वजह से बहुत तेजी से ये चिट फंड कम्पनियां बढ़ीं। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से पालिटीशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार मिलकर इस कम्पनी को बढ़ाते हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि नारदा और शारदा घोटाले में जब राजनेताओं को सीबीआई बुलाती है, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद जेल चले जाते हैं या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यदि एक ब्यूरोक्रेट, जिसकी नाभी में सारी जानकारी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गणेश सिंघानिया के यहां रेड होती है, तृणमूल कांग्रेस की जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे जो सांसद हैं, उनके बारे में जानकारी होती है, उसे छुपाने के लिए, केवल राज को छुपाने के लिए, सांसद के लिए कभी परेशानी नहीं हुई, कभी वे धरना पर नहीं बैठीं और आज एक ब्यूरोक्रेट के लिए धरने पर बैठीं। यह कितना बड़ा तार है, आप इसे देख सकती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जितनी चिट फंड कम्पनियां हैं, उसमें से गणेश सिंघानिया के यहां जो रेड हुई है, जो अनरेग्युलेटेड

स्कीम के सारे पैसे जो तृणमूल कांग्रेस के मुख्य मंत्री और उनके रिश्तेदारों का है, इसकी सीबीआई इन्क्वायरी हो, उन्हें जेल भेजा जाए और इन कम्पनियों को बैन किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शिव कुमार उदासि, श्री देवजी एम. पटेल, श्री गणेश सिंह, डॉ. संजय जायसवाल श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और प्रो. रिचर्ड हे को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से देश की महत्वपूर्ण समस्या, जो किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, बल्कि पूरे देश में कुपोषण और बच्चों में विकलांगता के बारे में कहना चाहता हूँ। यह विशेषकर गरीब परिवार के बच्चों और जच्चा, दोनों के लिए बड़ी गंभीर समस्या है। हाल की एक रिपोर्ट है, उसमें दर्शाया गया है कि देश में गरीबों की संख्या घटी है, लेकिन यह समस्या केवल गरीबी के कारण नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के दो जिले नक्सलवाद प्रभावित जिले होने के कारण सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण मेरे क्षेत्र में यह समस्या कुछ अधिक है। गर्भवती माताओं में नॉन स्टेपल खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाने का अनुरोध मेरी तरफ से है। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तीसरा लैंगिक समानता और चौथा राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता होनी चाहिए। ये सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन इन पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, ताकि विकलांगता और कुपोषण की समस्या नियंत्रित हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, कोल इंडिया की सीसीएल इकाई के क्षेत्र में लगभग दो हजार सैलरी मजदूरों को दस साल से स्थायी सर्विस नहीं मिली है और उनका मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। बहुत-से लोगों का नौकरी न मिलने की वजह से देहांत भी हो गया है और वे

रोजगार की योजना से जुड़ नहीं पाए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि यह सैलरी मजदूरों का मामला है, अतः इस समस्या का अविलम्ब निष्पादन कोल इंडिया की तरफ से किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1235/PC/RCP)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगा। इस समय देश में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि यूनिवर्सिटी को इकाई न मानकर, विभाग को इकाई मानकर आरक्षण देने का जो रोस्टर बनाया है, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा- माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां हैं- कि इसका कोई न कोई निजात होना चाहिए। न्यायपालिका कानून का काम कर रही है। हम लोग पार्लियामेंट में बैठकर क्या कर रहे हैं? हमने ज़्यादा कानून सुप्रीम कोर्ट बनाने का कार्य कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप बस अपनी बात रखिए।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : महोदया, इसके ऊपर कुछ किया जाए। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट गरीब विरोधी, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। ये जातिवादी संस्था बन गई है। ये भाई-भतीजेवाद की संस्था बन गई है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं श्री गणेश सिंह को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बात रखिए। रमेश बिधुड़ी जी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। दिल्ली में 30 लाख लोग अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं। वे नारकीय जीवन जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर 48 हजार करोड़ रुपये का फंड है। वर्ष 2014 में जब केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो दिल्ली में किस का शासन लागू था? उन 9 महीनों के दौरान जल बोर्ड के माध्यम से 1,20,000 हजार करोड़ रुपये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की सीवर के लिए सैंक्शन कराया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पानी की निकासी को लेकर गंभीर नहीं हैं। जब लोग वहां जाकर उनसे कहते हैं, तो वे बार-बार कहते हैं कि केंद्र सरकार मेरे काम को रोक रही है। मैडम, वे स्वयं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि शहरी विकास मंत्रालय इस मामले में ऑनरेबल लैफ्टिनेंट गवर्नर को इंटरफेयर करने की इजाजत दे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से इंटरफेयरेंस कर ही रहे हैं। 30 लाख लोग दिल्ली के अनार्की मुख्यमंत्री के कारण नारकीय जीवन जी रहे हैं। उन कॉलोनीयों में न पानी है, न पानी की निकासी है, न सीवर का काम चल रहा है। मैडम, इस तरफ ध्यान दिलवाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पूरे देश भर के कई राज्यों में किसानों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए किसान मित्र एवं किसान दीदियों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन उनसे तकनीकी, जैविक संबंधी जानकारी के साथ-साथ फसल बीमा, भावांतर भुगतान योजना, कृषक भ्रमण, मृदा परीक्षण आदि की संबंधित जानकारी उन किसानों तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इनको जो मानदेय दिया जा रहा है, वह बहुत

कम है। इनका मानदेय बढ़ाने के लिए सभी राज्यों से प्रस्ताव भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में आए हैं। मैं मांग करना चाहता हूँ कि इन पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रंजीत रंजन जी। आप अपनी बात आधे मिनट में पूरी कीजिए। ज़्यादा समय नहीं है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : मैडम, मैं अपनी बात बोलती हूँ। इसी सदन में बालिका गृह कांड, बलात्कार कांड, जो 37 बच्चियों के साथ हुआ था, उसका मामला उठा था। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि न ही सरकार ने उस पर कोई अच्छा कदम लिया, न प्रशासन ने कोई कदम लिया। इसके कारण जो डिमांड हम लोग सदन में रख रहे थे, आज उसको दिल्ली साकेत में शिफ्ट कर दिया गया।

मैडम, आपने उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उन बच्चियों के लिए यह पूरा सदन गंभीर हुआ था। मेरी रिक्वेस्ट है कि 13 और जो संस्थाएं थीं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। सी.बी.आई. उनकी जांच क्यों नहीं कर रही है? इसके साथ ही मैं आप से मिली थी। आपने कहा था कि हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें। यह बात निकल रही है, मैंने खुद जाकर शेल्टर्स में देखा है। अन्य शेल्टर्स की बहुत बुरी हालत है। जो क्रायेटेरिया अपनाया गया है, उस क्रायेटेरिया को एन.जी.ओज़. नहीं मानते हैं, न ही प्रशासन और सरकार, जिसकी भी हो, उसको गंभीरता से लागू करने के लिए उनको कहती है।

मैडम, आश्चर्य की बात है कि जो 22 हजार का किराए पर घर लेना है, वे उसमें 10 हजार में कर रहे होते हैं। वे कह रहे थे कि डेढ़ साल से सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। यह विचित्र सी बात है कि एन.जी.ओज़. को डेढ़ साल से हर महीने की पेमेंट नहीं मिलती है। इसके बावजूद वे शेल्टर हाउस चलाने में इंटेस्टेड क्यों रहते हैं? मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि यह सोलहवीं लोक सभा का अंतिम सेशन है। एक महिला होने के नाते उन बच्चियों की खातिर मैं आपसे और इस पूरे सदन से आग्रह करूंगी कि इस देश के जो तमाम बालिका गृह और बालक गृह हैं, उनकी स्थिति बहुत नाज़ुक

है। कई जगहों पर सैक्सुअल हरेसमेंट भी होता है। उनके साथ एक तरह से काम के साथ भी हरेसमेंट होता है। मैडम, प्लीज़ एक टीम बनाई जाए। वह एक ऐसी टीम हो, जो नॉन-पॉलिटिकल हो और वह सारे शेल्टर होम्स की जांच करे। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. बी. राजेश, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्रीमती सुप्रिया सुले को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1240/SPS/SMN)

माननीय अध्यक्ष : अब जो बचे हैं, वे सब कल।

...(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले-सभा पटल पर रखे गए

1240 बजे

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन जिन सदस्यों ने सभा पटल पर ये दिए हुए हैं, उनको सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को मामले उठाने हैं, वे तुरन्त सभा पटल पर 20 मिनट के अंतर्गत रखें। अगर निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, उनको माना जाएगा। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Additional attempts to UPSC Civil Services aspirants

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Due to frequent and sudden changes in the examination pattern of Civil Services Examination conducted by UPSC, the candidates, especially from the Rural India have lost precious years and attempts. The Civil Services Aptitude Test (CSAT) has given advantage to the candidates with education from English medium over candidates from the Rural India.

I would like to draw the attention of the Department of Personnel and Training (DOPT) to address this difficulty faced by students predominantly from the Rural India by providing two (02) additional attempts to the candidates irrespective of their age and attempt restrictions from the exam cycle 2019 onwards with a preparation period of minimum one year so that they have a fair chance to compete with the other candidates.

(ends)

Re: Guidelines for Post-Matric Scholarship for Scheduled Caste students

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): The Government of Tamil Nadu has a strong belief that Social and economic upliftment of under privileged sections of the society would be possible and sustainable only by ensuring their educational progress especially in the field of higher education and hence Tamil Nadu Government has been implementing the Centrally Sponsored Scheme of Post-Matric Scholarship to students belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in its true letter and spirit.

I would like to draw attention to the recent revision of guidelines for the Scheduled Castes Post-Matric Scholarship scheme, wherein it has been stated that the fees claimed against the Management quota/Spot admission seat in any institutions / Universities will not be reimbursed with effect from April, 2018. In Tamil Nadu, large number of Scheduled Castes students belonging to poor economic background who are not able to get admission under the government quota on merit, have been availing the benefit under the Post-Matric Scholarship scheme under management quota seats in self-financing colleges. As a result, the number of Scheduled Castes students joining the Higher and Technical Education Institutions in the State has increased tremendously. In fact, this scheme has largely benefitted the State to achieve a higher Gross Enrollment Ratio of more than 45%. Non-reimbursement of fees for management quota seats under the new guidelines will create a huge setback in achieving the goal of social equity and social justice as it will deny opportunities to the poor

Scheduled Castes students in the fields of higher and technical education. This may cause serious resentment and unrest among the Scheduled Castes community.

Another important issue is the sharing pattern between the Center and State for funding the scheme. Presently the expenditure under scheme at the end of the five years (plan) period is taken as the committed liability of the state for the next five years. While the committed liability of Tamil Nadu was Rs. 353.55 crore in 2011-12 with effect from 2017-18, it has risen to Rs. 1526.46 crores. This puts an unbearable burden on the State Government finances for its high performance in the last 5 years. It also results in a situation, where this Central sector scheme will be largely (if not fully) funded by the *State* from its own resources. Therefore, it is requested that in line with other Central Schemes, the scheme may be funded with a sharing pattern of 60:40 between the Centre and the State.

Further the release of funds by the Government of India to the State Government under this scheme over the years has been both delayed and inadequate. Up to 2017-18 the State is yet to receive arrears of Rs. 1579.58 crores from the Government. of India. It is requested that the release of this arrear amount to the State of Tamil Nadu may be expedited, to release the strain on the State Government's finances.

(ends)

Re: Welfare measures for fishermen community of Tamil Nadu

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): India has a total coastline of 7,516.6 Km. There are a total of 4 million fisherman comprising of 8,64,550 families. Presently, India ranks second in the world in total fish production with an annual fish production of about 9.06 million metric tonnes.

The fisheries sector contributes to the national income, exports, food and nutritional security and employment generation As per the Central Statistical Organization (CSO), of the Government of India, the value of GDP from fisheries sector at current prices during 2011-2012 is estimated to be Rs 65,541 crores, which is 4.47 per cent of the total GDP of agriculture and allied sectors.

Each fisherman consumes approximately 1200-1,500 litres of diesel per month with the present subsidy of Rs. 6/litre and they get subsidy only for approximately 300 litres which is not enough. The government is now taking steps to make the fishermen pay full price for the diesel and transfer the price equivalent to the subsidy to their bank accounts.

During the Cyclone Gaja on November of 2018 which crossed through the delta district of Nagapattinam has affected the livelihood of almost all the fishermen in the delta district, 151 motor boats were completely destroyed, 1066 partly-damaged and 1137 vallams (country boats) were completely destroyed and 1434 vallams were partly damaged and fishing nets have also been damaged.

The fishermen community of Delta district of Tamil Nadu are still recovering from the devastating effects of the cyclone and presently they are not in a position to pay full price for the diesel.

And I have also addressed the parliament last month and requested relief funds for the delta district of Tamil Nadu from the National Disaster Management Fund which has not been granted. So, I kindly request them once again to please grant the relief fund for the people of the delta district so that they can at least make a partial if not full recovery. The following measures are urgently required to be taken for the welfare of fishermen community of Tamil Nadu: -

- (i) The fishermen 'community of India wants the Government of India to continue giving subsidy on diesel as deduction. while buying the fuel 'and not through Electronic Clearance Service (ECS) and also the government should increase the subsidy for diesel consumed by fishermen to meet the increasing, price of diesel.
- (ii) The Government of India should classify the fishermen community as Schedule Tribes.
- (iii) The Central Government should also develop the fishing harbor in Nagapattinam, Nagore, Pattinacherry area.
- (iv) The Government of India should take steps for establishing a Direct Purchase Center (DPC) for fishes from the fishermen to get a better price in an International Level.

To achieve all this the Government of India should also establish a separate Ministry for fisheries. (ends)

Re: Need to improve BSNL/MTNL mobile/internet services in Nabarangpur parliamentary constituency in Odisha and Delhi

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): For last 7-8 months, especially after the Jio phone made inroads into Odisha, the SIM of BSNL/MTNL is hardly working. Most of the time it is not reachable. Whenever it gets connected, the conversation is one way. Whenever, it is both ways, it gets disconnected within seconds. The mobile phone has become a serious source of tension, irritation, time wasting equipment and so on. It is apprehended that the present deficiency in services by the Government company is a pre-act for its disinvestment. I urge the Government to take corrective action in this regard.

(ends)

Re: Need to waive the loan taken by fishermen of Maharashtra

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र में मछुआरों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। भारी कर्ज में दबे हुए गरीब मछुआरों का जीवन संकट में पड़ गया है। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का समुद्री तट है जिस पर रहने वाले कई मछुआरों के लिए समुद्र ही उनकी रोजी-रोटी है। आजकल कई कारणों से मछली की पकड़ कम हो गयी है। मछली पकड़ने के लिए आवश्यक साधन और सामग्री की कीमतें आये दिन बढ़ रही हैं। डीजल की कीमतों में वृद्धि, मछली के लिए अनिश्चित कीमतें जिसके चलते जिन मछुआरों के पास नौकाएँ हैं उन्हें बड़ी समस्याएँ आ रही हैं। कई मछुआरे अपनी नावों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत ऋण लेते हैं। राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत उनसे 9 प्रतिशत से 15.25 प्रतिशत ब्याज दर वसूल की जाती है। कई चीजों की लागत की अनिश्चितता के कारण उन्हें ऋण का भुगतान करना मुश्किल लगता है। अब बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दर में कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय कल्याण योजना की ब्याज दर बहुत अधिक है जो अनुचित है। मत्स्यपालन व्यवसाय को किसानों का दर्जा दिया गया है जैसे कि व्यापारी किसानों को धोखा दे रहे हैं, वैसे ही मछुआरों को व्यापारियों से गारंटी मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार किसानों की तरह मछुआरों को भी कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार को राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत उठाए गए महाराष्ट्र के मछुआरों के ऋण को माफ कर देना चाहिए।

(इति)

Re: Need to develop Kollam Bypass as a four-lane road

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Kollam Bypass was originally designed as a four-lane road. The land for construction of four lane road was already acquired. Two lane road of Kollam Bypass was constructed and dedicated to the Country. Two lane road is not sufficient for meeting the requirement. In Kerala, road development is delayed due to lack of land. But the land for construction of four lane road for Kollam Bypass is available. This bypass is also crossing two other National Highways. Development of main junctions such as Kallumthazham, Ayathil etc. are also required. Construction of over bridge, underpass, service roads and other developments are essential for the smooth vehicular traffic through the Kollam Bypass.

Hence, I urge upon the Government to initiate immediate steps for construction of four lane road and other developments in Kollam Bypass.

(ends)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – CONTD.

1241 बजे

HON. SPEAKER: Now, we will take up discussion on Motion of Thanks on the President's Address. Shri Mallikarjun Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सर्दी हो गयी है, फीवर है और जुकाम भी है। ... (व्यवधान) तुम्हारे जैसे दस लोग आए तो भी नहीं जाऊंगा।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं अध्यक्ष जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया। लेकिन इस भाषण में सारी चीजें जो प्रधान मंत्री जी ने बाहर कहीं थीं या इस सदन के अंदर पांच साल में उन्होंने जो कुछ भी अपने मुद्दे रखे थे, उन्हीं मुद्दों को राष्ट्रपति जी के मुंह से प्रधान मंत्री जी ने बोलने के लिए लगाया। मुझे कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट, जिस जगह हम सब लोग मिलकर नीति को बनाते हैं और खासकर मोदी जी का जो पांच साल का कार्यकाल था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अब तो आप नए हैं और बी.जे.पी. वाले हैं, जोर से बोलेंगे। ... (व्यवधान) न्यूली कन्वर्टेड लोग बहुत जोर से बोलते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हरेक का उत्तर मत दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा :

“ये हुस्न ओ रुआब तो ठीक है, लेकिन गुरुर क्यों तुमको इस पर है,
मैंने सूरज को हर शाम, इसी आसमां में ढलते देखा है।
किस बात पर तू इतराता है, यहां वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं,
कभी तारों से जगमग आसमान में, सितारों को टूटते देखा है।”

लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने ये जो कहा, यह उन पर लागू होता है, क्योंकि वे हमेशा अपनी ही बात कहते हैं और खासकर दूसरों की बात को मानते नहीं हैं। ये आदत है उनकी। अपनी जो बात है, वही ठीक है।

(1245/MM/MMN)

दूसरा कोई अगर सच्ची बात भी कहता है या इतिहास की सच्चाई को छिपाकर रखने की कोशिश वे करते हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अवसर बहुत ही मान और प्रतिष्ठा का अवसर है। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, वे अपने अभिभाषण के माध्यम से बताते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की उपलब्धियों की तुलना पिछली सरकार से करने का प्रयास किया गया। ऐसा करना हमारे लिए शोभा नहीं देता है और देश के लिए भी शोभा नहीं देता है। उसमें अपने विचारों को रखा जाना चाहिए था। लेकिन राजनैतिक फायदों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का इस्तेमाल करना इस परम्परा को खराब करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि आज की सरकार अपनी गिरती हुई रेंप्यूटेशन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है।

यह प्रश्न बार-बार हम से पूछा जाता है और कहा जाता है कि आपने 60 सालों में क्या किया? यह उनका स्लोगन है। जहां-कहीं भी जाते हैं, जब कभी भी पब्लिक मीटिंग होती है या पार्लियामेंट में आते हैं, पहले तो 70 साल बोलते थे, अब कम करके 55-60 पर आए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसमें छः साल बीजेपी के हैं, तीन साल श्री मोरारजी देसाई के हैं और अन्य नेताओं के भी तीन-चार साल हैं, इसलिए अब वह घटकर 60 साल पर आ गए हैं कि आपने 60 सालों में क्या किया? ऐसा वे कहते रहते हैं। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की

प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत के संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई आस्था नहीं रखती है। उनको कमजोर किया गया और उनकी आजादी खत्म करने की कोशिश रोज-बरोज हो रही है। साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठा रही हैं और बोलने की आजादी भी छीनी जा रही है। दलित, पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। जावड़ेकर साहब ने आज एक स्टेटमेंट भी दिया है। यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन खत्म करने के लिए दो सौ पॉइंट को 13 पॉइंट किया गया। इसमें दलित, बैकवर्डस और कमजोर लोगों को संविधान ने रिजर्वेशन दिया है। उसको सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से छीन लिया गया है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि संविधान के तहत यह सरकार नहीं चल रही है। अभी दस परसेंट की व्यवस्था आपने की है, जिसका हमने भी सपोर्ट किया था। एक तरफ आप रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनको रिजर्वेशन मिली हुई है उनसे आप छीन रहे हैं। हम चार महीने से लड़ रहे हैं। पिछले सत्र में भी यह बात आयी थी तब जावड़ेकर जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसे आठ दिन में ठीक कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किया गया? आप रातों-रात 10 परसेंट आरक्षण का बिल लेकर आए, यहां सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी हैं, उसी दिन उनका अनस्टार्ड क्वेश्चन इसी सदन में था। साढ़े ग्यारह बजे वे उत्तर देते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अनस्टार्ड क्वेश्चन सैम डे आप रिप्लायी देते हैं कि ऊंचे वर्ग के गरीब लोगों को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं वह प्रश्न आपको दे देता हूँ। इसी सदन का प्रश्न है और यहीं से पब्लिश हुआ है।

(1250/SJN/VR)

दूसरे, आधे घंटे में बिल आता है। इसका मतलब क्या है कि इस पर कैबिनेट में भी डिस्कशन नहीं होता है। सीधा, मोदी साहब जो बोलते हैं, वही होता है, दूसरा किसी को भी मालूम नहीं होता है।... (व्यवधान) अगर मालूम होता... (व्यवधान) तो इस अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर ऐसा क्यों आता। उसी दिन क्यों आता और उसी दिन आप छानबीन नहीं कर सकते थे। क्या आपके मंत्री इसको देखते नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसी गड़बड़ी में अपने कानून लाते हैं, होना, लाना,

पास करना, चले जाना और जो जरूरी है, उसको नहीं लाते हैं। मेरा यह कहना है कि कम से कम दूसरों को भी देखिए। हम हमेशा अच्छी चीज को सपोर्ट करते आए हैं। यहां विरोधी पक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी अच्छी चीज आती है, कई एक्ट एकमत से हो गए हैं। एकाध हो सकते हैं, जब बिना अभिप्राय उसके ऊपर अलग-अलग मत हो सकता है।...(व्यवधान)

अब मैं चंद आंकड़े देता हूँ क्योंकि मोदी जी हमेशा युवकों को दिशाहीन करने के लिए और आज़ादी के बाद जो जेनरेशन आई है, उनसे वह हमेशा यह कहते हैं कि 60 साल में तुमने क्या किया है? मैं छोटा-सा, एक चार-पांच कॉलम बताऊंगा कि हमने क्या किया है, क्योंकि वह आपको भी याद रहे। आपको कभी मौका मिले, तो कह दीजिएगा। 60 साल में हमने यह किया – लिट्रैसी रेट आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में 16 प्रतिशत थी। वर्ष 2014 में जब हमने छोड़ा, तब 74 प्रतिशत थी, तो बढ़ी या घटी।

दूसरे, लाइफ एक्सपेक्टन्सी पहले 32 साल थी और आज वर्ष 2007 में 70 साल है।...(व्यवधान) पहले शिशु मृत्यु दर 165 मृत्यु प्रति हजार होती थी और आज 38 है।

इरीगेशन की बहुत बात होती है। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना...(व्यवधान) 'वन ड्रॉप, मोर क्रॉप'। So many drops, more crops. यह रहने दीजिए...(व्यवधान) हरित क्रांति तो हम लाए थे, जिस देश में एक अनाज का दाना नहीं मिलता था, लोग पंक्तियों में...(व्यवधान) हमने उस देश में इरीगेशन प्रोजेक्ट तैयार करके...(व्यवधान) मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1947-51 में 22 मिलियन हेक्टेयर इरीगेशन था, हमने वर्ष 2014 तक 68 मिलियन हेक्टेयर बनाया। उस वक्त फूडग्रेन्स 50 मिलियन टन्स था, 138 मिलियन टन्स तक हम उसे लेकर गए हैं। दूध का प्रोडक्शन (व्हाइट रिवोल्यूशन) 17 मिलियन टन्स था और हमने इसको 138 मिलियन टन्स बनाया। रोड चार लाख किलोमीटर थी, हम 54 लाख किलोमीटर तक लेकर आए। रेलवे 54 हजार किलोमीटर थी, 65 हजार किलोमीटर तक लाए, उसमें हमने 10 हजार किलोमीटर की बढ़ोत्तरी की।...(व्यवधान) इस देश में 500 कॉलेजेस थे।...(व्यवधान) उस तरक्की से तो आप पढ़े

हैं। क्या आप मोदी जी के जमाने में कालेज में पढ़े हैं? चुप बैठिए... (व्यवधान) मैडम, 500 कालेज थे... (व्यवधान) हमने वर्ष 2014 तक 37 हजार कॉलेजस बनाए।

(1255/BKS/SAN)

मैं अभी भी यह लिस्ट पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि सारी चीजें उनको मालूम हैं, लेकिन मालूम होते हुए भी वे लोग यह कहते हैं कि इसको अलग रख दो। चूंकि नये लोगों को मालूम नहीं है तो उनको दिशा भ्रम पैदा करने के लिए ये अपनी बात बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कुछ नहीं किया है, क्या आपने कुछ किया है, ऐसा कहते हैं। उनका हमेशा यह डॉयलाग रहता है। ... (व्यवधान) लेकिन यह हमने किया, ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, वर्ष 2011 की सेंसज के ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

इसके बाद पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहर लाल नेहरू जी इसलिए लाए थे ताकि हमारे देश का एक सिस्टेमिक डेवलपमेंट हो। इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में इकोनोमिक एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स तथा अन्य जो बड़े-बड़े विद्वान थे, उनको उसमें बैठाकर वे कई योजनाएं लाए। जैसे भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, रिहंद डैम, तुंगभद्रा डैम, नागार्जुन डैम हो या टिहरी हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, मैं ऐसे बीसों आंकड़े पढ़ सकता हूँ, ये सब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी और उसके बाद जो कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने ये सब किया है। परंतु आप इनके बारे में कुछ नहीं बोलते। इतने सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हमने किये, ये और किसी ने नहीं किए।

इसके अलावा प्लानिंग कमीशन को आपने खत्म कर दिया। आप उसकी जगह नीति आयोग लाए। नीति आयोग क्या है, यह एक दिखावटी संस्था हो गई है। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अंग हो गई है। इसकी कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। अगर कोई प्लानिंग से संबंधित अपने विचार सामने रखता है तो उसकी बात पर कहीं विचार नहीं किया जाता। इसको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक छोटे से डिपार्टमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अलावा दूसरी चीजें इम्प्लायमेंट जनरेट करने के लिए पब्लिक सैक्टर जो हम लाए, ये सब आपको मालूम है। चाहे भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, सेल, एच.एम.टी., हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स

लि. हो, ये सब हम लाए। यहां तक कि एटोमिक इनर्जी जैसी संस्था हमने बनाई। आर्यभट्ट जैसे सैटेलाइट के लांच से भारत उन देशों में शामिल हो गया, जिनका नाम सैटेलाइट वाले देशों में आज भी है।

1974 में भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण किया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पहली बार एक भारतीय व्यक्ति श्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भेजा गया। इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने कहा – ‘सारे जहां से अच्छा’। यानी ये सब जो काम हमने किये, इनका थोड़ा क्रेडिट तो दीजिए। आपके दिल में क्या है, जब आपके दिल में नफरत है और आपका पूरा शरीर ही अगर नफरत से भरा हुआ है तो कौन क्या कर सकता है। इतने सब काम होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि 60 सालों में आपने क्या किया। हमने ये सब किया। देश को बचाया, खाना दिया, दूध दिया, विद्या दी, पानी दिया, सब कुछ दिया। ... (व्यवधान) हम उसका रिप्लाय देंगे। जब हम काम की बात करते हैं तो आप उल्टी बात करते हो। उसका जवाब देते वक्त हम बोलेंगे। लेकिन जब हमने इतनी तरक्की की तो आपने क्या किया? केवल तालियां बजाकर नौजवानों में दिशाभूल पैदा करने या उनमें भ्रम पैदा करने की बात करेंगे।

(1300/GG/RBN)

आज नहीं तो कल आप जो कह रहे हैं, सत्य से दूर की जो बातें कर रहे हैं, लोग आज नहीं तो कल उनको तुकराएंगे। ... (व्यवधान) मैडम, मैं आपसे यह कहूंगा कि ये लोग जीडीपी की बात करते हैं। मैं पैसों में बोलूंगा कि सन् 1947 में इस देश की जीडीपी मनी वैल्यू में तीन लाख करोड़ रुपये थी। सन् 2013-14 तक 98 लाख रुपये हो गई थी यानी तीन लाख से 98 लाख रुपये तक अगर किसी ने किया तो यह कांग्रेस पार्टी ने किया। ... (व्यवधान) 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश की जीडीपी को लगभग 33 गुना बढ़ाया। कांग्रेस सरकार के सन् 2005-06 और 2007-08 के बीच में भारत की आज तक की सबसे ऊंची 9.6 पर्सेंटेज जीडीपी ग्रोथ रेट दिखायी गई। जब सन् 2008 में सारी दुनिया में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी पक्की थी कि उसको कोई हिला नहीं सका, आगे बढ़ते गए। ये हमारे काम हैं। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। इनके जमाने में 7 या 7.5 पर्सेंट जीडीपी ग्रोथ होने वाली थी, होने का एक अंदाजा था। लेकिन इन्होंने क्या समझा कि अगर 7 पर्सेंट हो गयी तो लोग कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आंकड़ों के बेस बदले गए। बेस जो बदला, उन्होंने नए आंकड़े बनाए और 8 पर्सेंट अपनी जीडीपी को बताने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी तोड़-मोड़ के जोड़ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबको मालूम हो रहा है। आपकी अचीवमेंट क्या है, आप कैसे इसको कितना बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं यह सबको मालूम है। अगर यही जीडीपी ग्रोथ है तो मैं पूछता हूँ कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अगर यही जीडीपी ग्रोथ है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? मैडम, मैं आगे यह भी कहूंगा कि सच यह है कि जमीन से आसमान तक बुनियादी ढांचे से ले कर रॉकेट साइंस तक लड़ाकू टैंक से ले कर मिसाइल तक, अनाज से ले कर दूध के उत्पादन तक आप कहीं भी उंगली रखिए, आपको कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस दिखेगा। ... (व्यवधान) यही मेहनत, देश के लिए कुर्बानी और सफलता की कहानी हमारी नज़र आएगी। हमने दुनिया में एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई। संविधान के तहत लोकतंत्र को मज़बूत बनाया और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी हमने की। ... (व्यवधान)

मैडम, ज़रा उनको चुप बैठने के लिए कहिए। अब मैं डीमॉनेटाइजेशन पर आता हूँ। इनका कहना है कि नोटबंदी को भी हमने सफलता से किया। नोटबंदी से प्रोग्रेस हुई, नोटबंदी से टैरिज्म खत्म हुआ, नोटबंदी से कालाधन वापस आया। नोटबंदी से कर्प्शन खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से फेक करेंसी भी बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें 8 नवंबर, 2016 रात के आठ बजे, खुद ही टीवी पर आकर मोदी जी ने कहीं कि आज से पांच सौ और हजार रुपये के नोट कागज़ की रद्दी के टुकड़े के समान हो जाएंगे, वे सब कचरे के डब्बे में जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन इसका फटकारा किसको मिला? इसका झटका किसको मिला? ...(व्यवधान) उन लोगों को मिला, जिन जो माँ-बहनों ने देहातों में काम कर के अपने पैसे बचाए थे।

(1305/KN/SM)

जो अपने बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, छोटे-मोटे कार्यक्रम के लिए रखे थे, उनके ऊपर मार गिरी है। कोई अमीर आदमी पर मार नहीं गिरी, कोई इनके दोस्तों पर मार नहीं गिरी। जो लोग यहाँ से पैसे लेकर भाग गए, उन पर मार नहीं गिरी। जिन लोगों ने नोट बदल लिए, उन पर मार नहीं गिरी। जिन लोगों की बैंकों के साथ दोस्ती थी, उन पर मार नहीं गिरी। मार किन पर गिरी, खेती में काम करने वालों के ऊपर, छोटे-मोटे व्यापारियों पर और मजदूरों पर मार गिरी। इससे नौकरियाँ भी घट गई हैं, क्योंकि छोटे-मोटे कारोबार भी बंद हो गए...(व्यवधान) ये लोग मेरी बात को नहीं मानते, लेकिन कम से कम जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो आप मानेंगे। उनका कहना क्या है? इस देश के जाने-माने इकॉनोमिस्ट है- डॉ. मनमोहन सिंह जी और वर्ल्ड में भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है...(व्यवधान) उन्होंने यही कहा कि जब नोटबंदी हुई- "It is a monumental mismanagement, failure, and, in fact, it is a case of organised loot and legalised plunder of the country's economy." आज यही सिद्ध हुआ है और उसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम, जो भूतपूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने यही कहा- "Demonetisation was a massive, draconian monetary shock. In one fell swoop, 86 per cent of the currency in circulation was withdrawn. A real GDP growth was clearly affected

by demonetisation. Growth had been slowing even before, but after demonetisation, the slide accelerated.” यह मेरा नहीं है। इकॉनोमिस्ट का कहना है। गवर्नमेंट के एडवाइजर थे। भारत रत्न, नोबल प्राइज विनर अमर्त्यसेन का कहना है- “At one stroke the move declares all Indians — indeed all holders of Indian currency”, मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ, “At one stroke the move declares all Indians — indeed all holders of Indian currency — as possibly crooks, unless they can establish, they are not.” यह उनका कहना है। ऐसे जो वर्ल्ड के रिनॉन्ड इकॉनोमिस्ट हैं, उनका यह कहना है...(व्यवधान) मैडम, आज आरबीआई में, क्या आप सुन रही हैं? कुछ नींद आ रही है शायद।

माननीय अध्यक्ष : शांति से सुन रही हूँ

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, थैंक यू वैरी मचा आरबीआई के 2 अगस्त, 2018 में, यह रिपोर्ट उन्हीं की है। यहाँ के बहुत से नेता लोग, फाइनेंस कमेटी, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, ऐस्टिमेट्स कमेटी, बहुत सी कमेटियों में भी हैं। अब आरबीआई कहता है कि 99.99 परसेंट पैसे वापस आ गए हैं। फिर कहाँ गया आपका कालाधन? उन्होंने कहा कि मैं कालाधन लाऊँगा। हर एक को 15-15 लाख रुपये दूँगा। हर नौजवान को ये बोले कि 15 लाख रुपये आपकी जेब में। कांग्रेस पार्टी ने 80 लाख करोड़ रुपये लूटा, इनके दोस्त रामदेव जी महाराज कहते थे तो इन्होंने भी वही शुरू किया। कम से कम अगर उन्होंने बोला तो प्रधान मंत्री जी को तो नहीं बोलना चाहिए था। प्रधान मंत्री बनने वाले थे क्योंकि इलेक्शन मैनीफेस्टो में था। सब कुछ था, उनको साढ़े 13 साल का चीफ मिनिस्टर का अनुभव था। इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपये डालूँगा। हर साल दो करोड़ नौकरियाँ दूँगा...(व्यवधान) ऐसे गलत प्रोमिसेस करके सत्ता में आकर बैठे हों, फिर भी ... (Not recorded) बोलना छोड़ नहीं रहें। मुझे यही समझ में नहीं आया...(व्यवधान) मैडम स्पीकर, मेरा ही यह कहना नहीं है, यह पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस कहती है। आप बोलते हो, उठिए आप...(व्यवधान)

(1310/CS/AK)

कृषि मंत्रालय ने नवंबर, 2018 में एक रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी के कारण किसानों को बहुत परेशानी हुई।... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।... (व्यवधान) इसके कारण किसानों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उनके पास खाद, बीज आदि के लिए पैसे नहीं बचे थे।... (व्यवधान) बाद में सरकार यू-टर्न हो गई।... (व्यवधान) बाद में बोली कि अगर यह रिपोर्ट दी, तो सरकार की बदनामी होगी, इसलिए फौरन इसको बदलो। ... (व्यवधान) फिर यू-टर्न लिया और यू-टर्न लेकर उन्होंने यह कहा कि नहीं, नहीं, डीमॉनेटाइजेशन से किसानों को बहुत मदद हुई। एक तरफ आपकी रिपोर्ट ऐसा कहती है, आप ही बोलते हैं। दूसरी तरफ आप उसको बदल देते हैं, तो यह आपकी आदत है, आप... (Not recorded) बोलने की आदत से मजबूर हैं, आप क्या कर सकते हैं? ... (व्यवधान)

महोदया, आपने 2 करोड़ नौकरियों के बारे में बोला। ब्लैक मनी के बारे में बोला। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है? वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी की दर 3.8 परसेंट थी और एनएसएसओ के एक पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे के अनुसार वर्ष 2017-18 में यह रेट 6.1 परसेंट हो गई।... (व्यवधान) इस रिपोर्ट को सरकार ने जनता से छुपा कर रखा था। इसीलिए नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के दो सदस्य रूठ गए और चेयरमैन के अतिरिक्त दो मेंबर्स राजीनामा देकर चले गए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिपोर्ट खुद ही यह कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और पहले से भी बढ़ा है। फिर भी आप यह कहते हैं कि इतनी नौकरियां हमने दीं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण कौशल विकास की बात की, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी का रेट वर्ष 2011-12 में 5 परसेंट था। मैं एक बार और पढ़ता हूँ कि एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी का जो रेट वर्ष 2011-12 में 5 परसेंट था, वर्ष 2017-18 में वह 17.4 परसेंट पहुँच गया।... (व्यवधान) ग्रामीण महिलाओं के लिए

अनएम्प्लॉयमेंट का यह रेट उस वक्त 4.8 परसेंट था और अब यह बढ़कर 13.6 परसेंट हुआ है...(व्यवधान) इनके पास नौकरियों की भी कमी नहीं है...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया? आप नम्बर बताइए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदया, प्वाइंट नम्बर 275(3)।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, do not allow this.

...(Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेरे भाषण के बीच में क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है? ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, स्पीच के समय ऐसा नहीं करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदया, प्वाइंट नम्बर 275(3) कहता है कि "The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table:...". जो उन्होंने अभी एग्रीकल्चर का कोट किया, हमने वह रिपोर्ट पेश नहीं की है। यदि उन्होंने वह कोट किया है, तो he is misleading the House. ...(Interruptions) इसलिए या तो उन्हें मॉफी माँगनी चाहिए या उन्हें वह सारी चीजें एक्सपंज करनी चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं देख लूँगी। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, जुलाई 2017 में रेलवे में कम से कम अब तक आपके पास दो लाख 50 हजार वैकेंसीज हैं। एक तरफ रूरल इंडिया में भी और अर्बन इंडिया में भी बेरोजगारी बढ़ रही है और आपके पास वैकेंसीज कितनी हैं- रेलवे में दो लाख 50 हजार वैकेंसीज हैं। मार्च, 2018 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में 55 हजार वैकेंसीज थीं। जनवरी, 2018 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 16 हजार वैकेंसीज थीं।

(1315/MY/SPR)

ए.आई.आर तथा दूरदर्शन में 16 हजार वैकेन्सी है। जनवरी 2018 में सरकार के केवल पाँच मंत्रालयों में लगभग नौ हजार रिजर्व्ड कैटेगरी के जॉब्स वैकेन्ट है। इतनी लाखों वैकेन्सीज़ हैं, लेकिन आप वह भर्ती नहीं करते हैं। नए एम्प्लोएमेन्ट नहीं आ रहे हैं, जो अन-एम्प्लोएमेन्ट बढ़ रही है, उसको मानने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। इससे यही मालूम होता है कि युवकों को प्रोत्साहन देना, नौकरी देना तथा जीडीपी बढ़ाना इस सरकार के बस में नहीं है या वे चाहते नहीं हैं।

उन्होंने चंद आँकड़ें ऐसे बनाए हैं, ईपीएफ तथा ईएसआई में उन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि हमने 55 लाख नौकरियाँ दी है। आपने कहां नौकरियाँ दी? जो लोग थे, उनको ईएसआई तथा प्रोविडेंट फन्ड में लाएं। वहां एज युजूअल ड्राइव रहती है, हर साल ड्राइव रहती है, इस बार जोर से ड्राइव हुई होगी। यह क्रिएटेड तथा जेनरेटेड नहीं है। यह नयी एम्प्लोएमेन्ट नहीं है। यह तो हमने पुराने एम्प्लोएमेन्ट को ईपीएफ एनरोलमेन्ट करके 55 लाख दिया है।

अब दूसरी बात जीएसटी की आती है। जीएसटी के लिए तो सारे सदन ने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन उसकी वजह से हर जगह दिक्कतें आ रही हैं। हमने पहले ही बोला था कि मैक्सिमम 18 परसेन्ट रखिए। उसके ऊपर मत रखिए। इसमें दिक्कत होती है, लेकिन आपने बात नहीं मानी। आपने क्या किया? उस जीएसटी में चार-चार तथा पांच-पांच स्लैब कर दियो। जैसे-जैसे इलेक्शन आते रहते हैं, गुजरात इलेक्शन आया – ‘कम करो’, फिर दूसरा इलेक्शन आया – ‘कम करो’, यूपी का इलेक्शन आया - ‘कम करो’। अरे भाई, पहले ज्यादा करो, फिर बाद में कम करो। इसीलिए, हम बोल रहे थे कि 18 परसेन्ट से ज्यादा मत जाइए। जो तीन स्लैब बनाते हैं, उसे बनाकर रखो और प्रैक्टिकल हो। लेकिन नहीं, हम नहीं मानते हैं। इसकी वजह से पूरा व्यापार खत्म हो गया। एमएसएमई ने खुद ही बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिया है। वे लोग बोलें कि हमारा एक्सपोर्ट आपकी वजह से बंद हो रहा है। कृपया करके इसको ठीक कर दो, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको मदद करने की कोशिश नहीं की गई। जब-जब इलेक्शन आता है, उस वक्त कम होता है और आप वोटों के लिए कम करते जाते हैं।

मैडम, यह जो राफेल डील है, इसको हमने इस सदन में बहुत बार उठाया और बहुत बार बातें की, लेकिन इसके बारे में उनका कोई जवाब नहीं है। अगर आप कम से कम इजाजत देते, वह इस बारे में एक घंटे की चर्चा के लिए तैयार हो जाएं, ... (व्यवधान) मैडम, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो अपने साथ एक आन्ट्रप्रेनर को ले गए और अपना एग्रीमेन्ट करवाया, जिसकी इनसॉल्वेन्सी हुई, जिसने परसों ही 45 हजार करोड़ रुपये की इनसॉल्वेन्सी का पिटीशन दाखिल किया। आप एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर उसको देते हैं, जिसको नट-बोल्ट भी बनाना नहीं आता है। वैसे आदमी को आप राफेल लड़ाकू जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसमें 30 से 35 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। इसको हम बोल रहे हैं, इसलिए आप चर्चा के लिए यहां तैयार होइए। हम सेपरेट चर्चा करेंगे। यहां भाषण में बोलकर चले जाने की बात नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? ये जिस ढंग से प्रेशर लाये और कैसे हुआ। इसीलिए, मैडम स्पीकर, मैं आपसे विनती करूंगा कि इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेन्ट्री कमेटी बैठाइए। यह हम पहले से ही कह रहे हैं। आज भी कहूंगा और जब तक इस समस्या का हल नहीं होता है, तब तक हम इस इश्यू पर लड़ते रहेंगे।

(1320/SK/UB)

एचएएल को 60 साल का एक्सपीरियंस है।.... (व्यवधान) काम कर रहे हैं।.... (व्यवधान) तुम अपनी बात को सही करने के लिए एक अच्छी संस्था को बदनाम करना चाहते हो। (व्यवधान) जो लोग वहां मेहनत करके देश में लड़ाकू जहाजों के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाकर देते हैं, उनकी इन्सल्ट करते हैं।.... (व्यवधान) एक आदमी जो इनसॉल्वेंट है, उसे सपोर्ट करते हो।.... (व्यवधान) यह क्या है? (व्यवधान) डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम है।.... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सीलड कवर में डाला।.... (व्यवधान) वहां क्या ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोला, क्या असत्य बात बोली?.... (व्यवधान) रैफेल मामले के मुद्दे की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोला कि सीएजी और पीएसी दोनों ने राफेल

विमानों की कीमत की जांच की है।.... (व्यवधान) उन्होंने कहा और बाद में करैक्शन एप्लीकेशन डाली। क्यों करैक्शन एप्लीकेशन डाली? (व्यवधान) क्या आपको मालूम नहीं था कि सीएजी रिपोर्ट यहां पेश हो गई थी? क्या पीएसी में इसकी कोई चर्चा हुई थी? क्या सीएजी ने इस कीमत को मानकर रिपोर्ट रखी थी? (व्यवधान) आपने वह ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) आप ने वहां कहा, यानी आप अपने कामों का ध्यान नहीं रखते हैं। (व्यवधान)

मैंने अभी कोट किया कि इस सदन में अनस्टार्ड क्वेश्चन पर आधे घंटे की बात थी। यह वैसा ही है, जो चीजें नहीं हैं उन चीजों को लेकर इन्होंने कोर्ट को भी ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोला, सुप्रीम कोर्ट को ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) बोला और बाद में माफी मांगना चल रहा है।.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी और कितनी देर है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, मैं आधा घंटा और बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आधा घंटा नहीं, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष, अब मैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूं। (व्यवधान) यह मेरे शब्द नहीं हैं, ज्यूडिशियरी- एक जज ने रिटायर होने पर कहा कि हाइएस्ट ज्यूडिशियरी को किसी एक्सटर्नल सोर्सिस द्वारा रिमोट कंट्रोल की तरह चलाया जा रहा है।.... (व्यवधान) आरबीआई के बारे में तो आपको मालूम है।.... (व्यवधान) आरबीआई के गवर्नर एक के बाद एक रिजाइन करते गए, यहां तक कि ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

.... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) भी गए। इसके बाद नीति आयोग के ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) गए, चीफ इकॉनॉमिक एडवाइजर ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) गए, पीएम इकोनामिक

एडवाइजर काउंसिल के सदस्य ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) गए और एनएसएसओ के दो सदस्य भी घर चले गए। इन्होंने सबको एक-एक करके भेजा। (व्यवधान) यह ऑटोनोमस बॉडी की बात हुई।

दूसरा, सीबीआई, सीवीसी, ईडी, आईटी सबके ऊपर दबाव है.... (व्यवधान) अगर उनकी बात कोई नहीं मानेगा या उनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं आती है तो लगाओ सीबीआई को, लगाओ ईडी, लगाओ किसी और एजेंसी को और लगाकर उनकी आवाज बंद करो, उनका गला घोटो.... (व्यवधान) अगर डेमोक्रेसी में यह चीज होती है तो इससे बुरा कुछ नहीं है।.... (व्यवधान)

मैं आपके सामने एक कोट करना चाहता हूं। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था -

“However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However, bad a constitution may be, if those who are implementing it are good, it will prove to be good.”

(1325/MK/KMR)

ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आप कम से कम इसके अनुसार तो चलिए क्योंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर को बार-बार कोट करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी के भाषण में भी उनका कोट हुआ है। इसके साथ फार्मर्स का एक इश्यू है। मोदी जी ने हुकूमत आने से पहले अपनी प्रणाली में खूब बोला था कि मैं किसानों को दुगुना दाम दूंगा और उनकी आमदनी बढ़ाऊंगा, लेकिन अब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 3 परसेंट हो गयी है। अगर आप एवरेज को लें तो जो यू.पी.ए गवर्नमेंट में यह 4 परसेंट थी, अब इनके 2 परसेंट पर आ गयी है। आप एक लाख दस हजार करोड़ रुपये कार्पोरेट वालों का माफ कर सकते हैं, तो आप किसानों के कर्ज को माफ क्यों नहीं करते? ...(व्यवधान) क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए अगर आपके कोई रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो उनको प्रेफरेंस देकर एक लाख दस हजार करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं करते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है, इनको कुछ देना है, ये आगे की बात है। आपने पांच साल में जो वायदे किये, उनमें से आपने एक भी नहीं निभाया। जब आप लोग सत्ता में आए, उस वक्त आप लोगों ने कुछ नहीं

किया, अब जब आगे सत्ता के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए आप नये-नये तरीके ढूँढ़ रहे हैं। आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। किसान समझ गया है कि उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर किसी को थोड़ा फायदा मिलेगा, तो इनकम टैक्स रिबेट वालों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा।

एक एम.एस.पी. का विषय है। पहली बार हुआ कि कॉस्ट को डेढ़ गुना किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो हर लिहाज से इन्वेस्टिगेशन करके बनाते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं बताना चाहता हूँ कि यू.पी.ए.-2 सरकार के समय एम.एस.पी. का एवरेज ग्रोथ 11.28 परसेंट था, जबकि बीजेपी सरकार के समय सिर्फ 4.91 परसेंट है। इसको आप देख लीजिए कि एवरेज क्या है। ... (व्यवधान)

दूसरी चीज, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। इसमें इतना घोटाला है कि कोई भी सरकार आए, इसको तो बदलना चाहिए। मैं आपको आंकड़े के साथ कह रहा हूँ। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में 84 लाख किसानों ने इस बीमा को छोड़ दिया, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ... (व्यवधान) वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018 तक इंश्योरेंस कंपनीज को 48 हजार करोड़ रुपये मिले और किसानों का जो क्लेम था, वह 28 हजार करोड़ रुपये का था। ... (व्यवधान) सीधे 20 हजार करोड़ रुपये इंश्योरेंस कंपनी के खाते में गया। इंश्योरेंस कंपनी की जेब में गया। ... (व्यवधान) आप बड़ी-बड़ी कंपनियों को इस प्रकार के स्कीम्स बनाकर फायदा पहुंचाते हैं और किसानों को छोड़ देते हैं। यह तो दिन-दहाड़े लूट है। इसको बंद करना होगा। किसानों के लिए नये तरीके ढूँढ़ने होंगे। उनको इंश्योरेंस के लिए डायरेक्टली पैसा मिले, ऐसा काम होना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कम्प्लीट कीजिए नहीं तो आपका सेकेंड स्पीकर नहीं बोल पाएगा।

... (व्यवधान)

(1330/RPS/SNT)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ ... (व्यवधान) उन्होंने पांच साल में क्या किया, यह बताना पड़ेगा। ... (व्यवधान) वे हर जगह बताते हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया और हमने क्या किया, मैं यही बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं कहीं बाहर से आंकड़े नहीं ला रहा हूँ, मैं उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) लोगों ने मुझे चुनकर यहां बोलने के लिए भेजा है, पब्लिक में बोलने के लिए नहीं। ... (व्यवधान) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह हर भाषण में कहते हैं कि इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गए और 18 हजार गांवों में बिजली नहीं थी। ... (व्यवधान) लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई, 2018 में उन्होंने कहा कि पांच हजार गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। ... (व्यवधान) अब आपके हो गए 15 हजार गांवा इन 15 हजार गांवों में आपने बिजली पहुंचाई, लेकिन इस देश में 6 लाख 50 हजार गांव हैं, ... (व्यवधान) उनमें से 6 लाख 32 हजार गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन कांग्रेस ने किया और आप 12 हजार या 13 हजार गांवों के बारे में कहते हैं कि मैंने बिजली दी। यह क्या है? ... (व्यवधान) आप आंकड़े देखिए।

मैडम, आज एक प्रश्न था और उस समय जब मैंने प्रश्न पूछा, तब आपने कहा कि नहीं, इसे बाद में पूछिए। जब भाषण करेंगे, उस वक्त लाएंगे। ... (व्यवधान) इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भूल गए कि 60 साल में हमने 6 लाख 32 हजार गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया? ये सब जुमले हैं और जुमलों की सरकार ऐसा ही करती रहेगी। ... (व्यवधान) हम काम करने वाले हैं, वे जुमला बोलने वाले हैं। ... (व्यवधान) अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आते हैं।

मैडम स्पीकर, आपको मालूम है कि 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' की बात आई थी, लेकिन इनके 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' में क्या हुआ? ... (व्यवधान) अगर मैंने लिस्ट पढ़ी तो लोग घबराएंगे कि कितने गांवों में लिंगिंग हुई, ऑर्गेनाइज्ड लिंगिंग हुई – जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गो-रक्षा के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। ... (व्यवधान) अगर दलित शादी करने के लिए घोड़े पर बैठकर जाता है तो उसे उतारकर मारते हैं, लेकिन आप यहां आकर एक लफ्ज़ नहीं बोलते

हैं। अगर कोई 'अछूत' मन्दिर में जाता है, अगर किसी ने जाने नहीं दिया तो उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हैं। ... (व्यवधान) मैं 10 मई, 2015 से लेकर अब तक की घटनाएं पढ़ दूंगा। आप आए थे सबकी रक्षा करने के लिए। आपने कहा कि दलित, वंचित, पीड़ित आदि जितने भी अच्छे शब्द हैं।... (व्यवधान) हमारे साथी यादव जी बहुत अच्छा बोलते हैं, जो सोशियलिस्ट पार्टी के नेता थे, अब वह बीजेपी के नेता बन गए और अपने उसूल को बदल दिया। अपनी लाइफ के तीस-चालीस साल उधर गुजारे और पिछले पन्द्रह-बीस साल से इधर हैं।... (व्यवधान) फिर इसको सेकण्ड करने वाले जगदम्बिका पाल जी, न्युली कन्वर्टेड हैं। ... (व्यवधान) आपकी बातें उन्होंने बहुत जल्दी एडॉप्ट की हैं। ... (व्यवधान) वह हर जगह से घूमते-घूमते यहां आ गए। उन्होंने भी जोरदार तकरीर दी। ... (व्यवधान) उन्होंने इतनी गालियां दीं।... (व्यवधान) हमारी सरकार में दस साल थे। उससे पहले भी वह एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे और पार्टियां बदलते रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जोरदार तरीके से कांग्रेस को गालियां दीं, मोदी जी की तारीफ की और हिन्दी के जितने भी अच्छे-अच्छे लफ्ज थे, उनका प्रयोग करके इसको सपोर्ट करने की कोशिश की।... (व्यवधान)

मैडम, मॉब लिंगिंग इनके जमाने में हुई, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हर जगह छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन संस्थाओं में कर रहे हैं। आपने भी वार्निंग दी कि चाहे वे वीएचपी के हों, गोरक्षक हों, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(1335/RAJ/PS)

लेकिन आपके कहने के बावजूद भी क्यों हुआ और आज तक क्यों हो रहा है?... (व्यवधान)
मैं यह पूछना चाहता हूं।... (व्यवधान)

मैडम, इनको गांधी जी से भी नफरत है।... (व्यवधान) गांधी जी की 150वीं सालगिरह मनाते हैं, जन्म दिन मनाते हैं, लेकिन लखनऊ में जब 30, जनवरी को उनका शहीद दिवस था तो उस दिन उनकी एक फोटो लगा कर, कट-आउट लगा कर ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान) सॉरी... (व्यवधान) ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ।
correct it..... (व्यवधान) ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)... (व्यवधान) ये वहां

पर उसको ठहरा कर, ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को हार पहना कर गांधी को शूट करने का दिखाते हैं...(व्यवधान) गांधी जी को शूट किया...(व्यवधान) आप ने कितने लोगों को अरैस्ट किया?...(व्यवधान) आपने किन को जेल में डाला?...(व्यवधान) यह देश के ऊपर शेम है...(व्यवधान) यह कलंक है...(व्यवधान) गांधी जी की फोटो रखते हैं। ...(व्यवधान) राष्ट्रपिता का फोटो रखते हैं...(व्यवधान) उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन उन लोगों को ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) सपोर्ट करते हैं...(व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनको किसी के प्रति आदर नहीं है...(व्यवधान) हर एक को सताने की कोशिश करते हैं...(व्यवधान) मैं पेट्रोल और डीजल के बारे में कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप कम्पलीट करें।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, मैं थोड़ा बोल कर अपनी बात खत्म करूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिरते गए, लेकिन दाम पहले जितने थे, आप वही रखते गए। जब दाम घटता था या बढ़ता था तो लोगों को राहत देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए पहले की सरकार ने दाम को वैसा ही रखा लेकिन आपने दाम कम होने के बावजूद कंज्यूमर्स को जो फायदा देना था, वह नहीं दी और आपने उसमें कम से कम नौ-दस लाख करोड़ रुपये कमाया। आपने वह पैसा इस्तेमाल किया। वह कहां गया? जो कंज्यूमर्स ने पैसा दिया, उनको रिलीफ क्यों नहीं मिला, मैं यह पूछना चाहता हूँ। आप ये चीजें कर रहे हैं, इससे लोग नाखुश हैं। वे चाहते हैं कि कम से कम ऐसी चीजों में जब राहत देनी चाहिए तब वह देनी चाहिए। आप वह नहीं दे सकते हैं। इनके जमाने में एक्साइज ड्यूटी कम से कम 386 प्रतिशत बढ़ गई और पेट्रोल 126 प्रतिशत बढ़ गया और कंज्यूमर्स से लूट कर बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियों का फायदा कर दिया...(व्यवधान) उनको एक लाख, 10 हजार करोड़ रुपये तक का मुनाफा कर दियो।

मैंने रिजर्वेशन की बात पहले ही कही है, लेकिन मैं महिला बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। आपके जमाने में यह आना चाहिए क्योंकि मोदी जी बहुत क्विक एक्शन लेते हैं। यहां प्रश्न चलता रहता है, लेकिन इमीडिएटली यहां पर दूसरा बिल आता

रहता है। आप कम से कम इसको लाने के लिए कहिए। आपका रिट चलता है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं पूछते हैं। आप यह पूछिए।...(व्यवधान)

पहले जब हम नरेगा की बात करते थे तो मोदी साहब और जेटली साहब हमारा मजाक उड़ाते थे।...(व्यवधान) वह यह कहते थे कि मैं इस मनरेगा को कभी नहीं मिटाऊंगा। यह तो आपकी जीती-जागती स्मारक है। आप ऐसा कहते थे। ...(व्यवधान)

(1340/RC/IND)

अब सरकार कह रही है कि यह गांवों में गरीबी हटाने और खपत बढ़ाने की उत्तम योजना है, लेकिन इस साल के बजट में नरेगा का एलोकेशन 14 परसेंट कम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि यह योजना उत्तम है और कम से कम 15 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, वे ऊपर आ गए हैं, तो आप इस बजट को कम क्यों कर रहे हैं?...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):

अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2014 से लगातार नरेगा का एलोकेशन बढ़ रहा है। इस बार भी 60 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन है। इनके पास कौन-सा कागज है, जिसे देखकर कह रहे हैं कि एलोकेशन कम किया गया है।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I am not yielding.

महोदया, पहले लोगों को साल में सौ दिन का काम मिलता था, लेकिन आज केवल 40-50 दिन का काम मिलता है। मैं दो परसेंट बोल रहा हूँ, आप 59 हजार करोड़ रुपये से 60 हजार करोड़ रुपये कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली आपका परसेंटेज दो परसेंट से गिरा है।...(व्यवधान) पावर्टी इरेडिकेशन के लिए हमने पहले से नरेगा स्कीम चलाई। राइट टू फूड स्कीम चलाई। उसके बाद राइट

टू इनफोर्मेशन, राइट टू एजुकेशन स्कीम चलाई। ये सारी योजनाएं हमने जनता के हित में चलाई थीं, लेकिन इन सभी को कमजोर किया गया।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, “बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ” की बहुत बात कही जा रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बारे में एक शब्द भी नहीं है। करीब 644 करोड़ रुपये इस योजना के लिए रखे गए, लेकिन हर राज्य को केवल 160 करोड़ रुपये रिलीज किए गए।

महोदया, लोकपाल बिल तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। लोकपाल विधेयक के लिए एक भी प्रोविजन नहीं है। यदि रिकग्नाइज्ड ओपोजिशन पार्टी का लीडर नहीं होता है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लीडर को ओपोजिशन पार्टी के लीडर का दर्जा मिलना चाहिए... (व्यवधान) यह बात मेरे लिए नहीं है, कल तुम्हारी हालत भी यही होगी। आप याद रखो, आपकी दो की संख्या थी। मैंने सुषमा जी का भाषण पढ़ा। वह बोलीं कि हमारी संख्या दो से 116 हुई है। क्या मैं आपको वह भाषण दिखाऊं? ... (व्यवधान) उन्होंने भी माना कि हार-जीत होती रहती है। आडवाणी जी ओपोजिशन लीडर थे। उनका भाषण होने के बाद उन्हें चांस मिला। लोकपाल विधेयक में इतना ही अमेंडमेंट लाना है कि ओपोजिशन पार्टी लीडर या लार्जस्ट पार्टी लीडर को ओपोजिशन लीडर का दर्जा मिलना चाहिए। केवल दो शब्द का अमेंडमेंट लाने के लिए चार साल नौ महीने का समय लग गया।

महोदया, यह सरकार नाम बदलू सरकार है। जो कांग्रेस की स्कीम्स थीं, जैसे हमारी बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट एकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और इनकी प्रधान मंत्री जन धन योजना। हमारे निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान योजना बना दिया। हमारी राजीव आवास योजना और इनकी सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग योजना।

(1345/PC/SNB)

इंदिरा आवास योजना हमारा, प्रधान मंत्री आवास योजना इनका। राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण हमारी, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आपकी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्युवल मिशन हमारा, अटल मिशन इनका। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हमारा, सॉइल हैल्थ

कार्ड इनका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी, परंपरागत कृषि विकास योजना इनकी। स्वावलंबन योजना, अटल पेंशन योजना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष। नेशनल लाइवलीहुड मिशन, दीन दयाल उपाध्याय। ये नाम बदलू सरकार है। ...(व्यवधान) ये बोलते हैं कि ये नई स्कीम लाए हैं। ...(व्यवधान) कहां है नई स्कीम? सब पुरानी स्कीम हैं, उनका नाम बदल दिया है। ...(व्यवधान) फॉरेन पॉलिसी और अन्य विषयों पर हमारे बाकी के लोग बोलेंगे। ...(व्यवधान) मैं डॉ. आंबेडकर और बसवण्णा के दो कोट्स बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने सब का समेट लिया। अब कोई नहीं बोलेगा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : राष्ट्रपति जी ने बसवण्णा और डॉ. आंबेडकर को कोट किया है। ...(व्यवधान) ये कोट्स बोलकर मैं बैठ जाऊंगा। ...(व्यवधान) मैडम, अगर आप आगे बोलने के लिए बोलेंगी, तो भी मैं नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान) मैं यह इसलिए कोट इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि यह सबके लिए है। यह मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। बाबासाहेब आंबेडकर ने एक बात कही थी, जब उन्होंने इस देश को यह कांस्टिट्यूशन सौंपा, उस वक्त कहा था:-

“The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with power which enable him to subvert their institutions. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered life-long services to the country, but there are limits to gratefulness as has been well said by the Irish patriot Daniel O’Connell – no man can be grateful at the cost of his honour;

no woman can be grateful at the cost of her chastity; and no nation can be grateful at the cost of its liberty.”

This is the importance. Just because somebody is a great man, somebody is a Prime Minister and you might have got elected in his name but do not subvert. ...(Interruptions) गुलाम मत बनो। ...(व्यवधान) Have your conscience. ...(Interruptions)

“For in India Bhakti, what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul but in politics Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.”

मैडम स्पीकर, हमारे राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण महात्मा बसवेश्वर के वचन से शुरू किया था - ‘दयवे धर्मद मूल व्यया’। आप भी जब कर्नाटक में जाते हैं, तब बसवण्णा के कुछ ने कुछ वचन बोल देते हैं, जो भी लोग आपको बता देते हैं। ...(व्यवधान) बसवण्णा का यह बड़ा फेमस वचन है, जिसे मैं कहूंगा और बैठ जाऊंगा।

‘Kalabeda kolabeda, husiya nudiyalu beda’

मैडम, इसका मतलब है - Do not steal; Do not kill; Do not utter the untruth. इसीलिए, लिंगिंग मत करो। ...(व्यवधान) राफेल में चोरी मत करो और किसानों के साथ झूठ मत बोलो। ...(व्यवधान)

(1350/SPS/NKL)

'Muniya beda, annyarige asahya pada beda'

'Never be angry.' क्योंकि बहुत गुस्से में आते हैं, अभी-अभी। ... (व्यवधान)

'Never be angry; never hate others.'

This is said by Basavanna – what you have quoted – and I am quoting, Madam.

'Tanna bannisa beda, idira haliyalu beda'

'Do not boast yourself, or criticize anyone.'

'Ide antaranga sudhi, ide bahiranga sudhi'

'This is the way to cleanse the soul; this is the way to cleanse the body; this is the way to please our Lord Kudalasangama.'

This is what Basavanna said. मैडम, कम से कम बसवन्ना को आपने कोट किया है। इसके तहत चलेंगे

'Do not steal, do not kill, do not utter untruth;

Never be angry, never hate;

Do not boast yourself, do not criticize anyone;

This is the way to cleanse the soul.'

मैं इतना ही कहूंगा। आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत समय दिया। आपको धन्यवाद है। मेरी वजह से दूसरों को कष्ट न हो, ये भी मैं आपसे विनती करूंगा। आपको बधाई देता हूँ कि मुझे भाषण करने के लिए आपने समय दिया। इतना कह कर सभी को बहुत अटेंटिवली भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुना, कम से कम उठे नहीं। नहीं तो ऐसे तालियां बजाईं कि परसों मोदी, मोदी बोला गया तो दोनों हाथों से मेज बजा रहे थे। फिर मैं एक दिन उनसे मिला, शायद परसों या तरसों, चार दिन पहले। मैंने कहा साहब, जरा अपना हाथ बताइए। मैं फर्स्ट एड को बुलाना चाहता था, क्योंकि

आप ऐसे थपका रहे थे कि कहीं आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी। यही देखना था, इसीलिए मैंने पूछा। मैं यही कहता हूँ कि थपथपाना, उठ कर बोलना, चिल्लाना, जय बोलना ये बात और है। देश को चलाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना ये बात और है। थैंक्यू।

(इति)

*PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): I would like to participate in the motion of thanks to the address of Honourable President of India.

Hon'ble President complimented the Hon'ble Prime Minister led Government of India in the various landmark development schemes intended for the emancipation of the poor and the protection of farmers of the country. The burden of millions of poor who were not able to obtain proper healthcare are provided healthcare through the well-conceived Ayushman Bharat Scheme the largest health scheme in the world. The flagship programme of the Hon'ble Prime Minister to provide every poor family in the country a home by 2022 shows the commitment of the Government of India to provide abode to the homeless. The vision of the Hon'ble Prime Minister to support the Divyags, the hapless women and even infants shows the Government of India's total support to the cause of the weak and the marginalised. The Government of India's multi-pronged approach is to help the youth to achieve their life's mission results in the stupendous schemes of Start-Up India, Make in India and Stand-Up India, and support to MSMEs. The Mudra loans opened avenues of opportunities for both men and women to embark upon small scale business and industries to fulfil their dreams. The farmers have been provided with many a scheme to help them to lead a comfortable life, the farmers being the backbone of the economy. M.S.P, crop insurance, a plethora of schemes route through the KVKs throughout the length and breath of the country.

*Laid on the Table

The attention given to faster development of infrastructure has created records of all sorts- the fastest ever expression in the realm of development of infrastructure by any Government. Modernisation of 100 cities as smart cities in yet another classic example of Government's visionary developments strides.

The building of Nav Bharat by 2022 is reflected in the conception and implementation of other prestigious projects too like GST, OROP, Bankruptcy Laws, Health Schemes, Jan Dhan Yojana, Digital India, LPG subsidies, Urja Ganga, Look East, Demonetisation, Projects for Minorities, Dalits, Vanavasi all remarkable progressive reforms. Even though DBT was promised by others, it is Modi's Government that fulfilled this promise. Through various interventions and innovative practices Ease of Doing Business has become a reality for the first time in India. Now airports, new railway projects, new Highways and new waterways have given an impetus for faster economic growth in such a short period.

New Passport Sewa Kendras, Aadhaar card issued through Post Offices, connecting Indian diaspora by hosting a successful PBD, and sanctioning CGHS at Cochin are all new initiatives of the Government of India.

Our Hon'ble Prime Minister has been able to build better international understanding with a record-breaking number of Countries.

(ends)

*DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY):

*Laid on the Table

*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):

*Laid on the Table

***श्री कृष्ण प्रताप (जौनपुर):**

***Laid on the table**

*ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA):

*Laid on the Table

***श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):**

***Laid on the table**

*SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Speaker Madam, I thank the Hon'ble President of India for the Address delivered to the joint sitting of the two Houses of Parliament.

Our government led by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji led our country towards the fastest growing country in the world in the last only four years.

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji introduced India newly as a super power in all corners, which our country lost its importance in the Congress regime. By celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi we can create a new chapter among the new generation. By introducing Toilets for all by Swachh Bharat Abhiyan in the backward places of Assam, it touches and gives a new dimension to our society. By introducing 'Ujjwala Yojana' people are benefited a lot which is remarkable. By introducing Ayushman Bharat Yojna, now people are getting the benefit. I hereby request you Madam Speaker, our government that it should be extended to the people who are poor but left out from the survey.

By introducing "Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojna", Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Pradhan Mantri Jewan Jyoti Bima Yojna, National Literacy Mission, by establishing AIIMS, PMAGY give benefits to the people which would not have happened if Modi Ji were not be the Prime Minister.

*Laid on the Table

Hon'ble Prime Minister Modi Ji introduced 'Pradhan Mantri Saubhagya Yojna' which is a programme which touches the hearts of the poor people who did not get power even after independence. Congress regime did not care for the people who were deprived from getting power.

Speaker Madam, we the people of Assam are very much happy that our government conferred Bharat Ratna on the Late Dr. Bhupen Hazarika along with other remarkable personalities of India. Only BJP led government can think of that. I on behalf of the people of Assam thank the Hon'ble Prime Minister for taking this decision. Before the Late Atal Bihari Bajpayeeji gave importance and conferred Bharat Ratna on the Late Gopinath Bordoloi which the people of Assam still remember.

We the people of North East especially from Assam thank the Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji as in the last 4 years he opened big projects which were not completed during the Congress regime. "Gas Cracker" project in Dibrugarh, Dhola Sadiya Bridge in Tinsukia, Bogibeel Bridge in Dibrugarh, RGIPT in Sivsagar, Super-speciality Hospital in Sivsagar, extension of four lane to upper Assam which is made possible only in Prime Minister Narendra Modi Ji's regime. Extension of NRL in Assam is a remarkable work done by our Prime Minister.

Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji himself visited many times Assam and other states of North East which created unity among the people. Before we the people of Assam elected Prime Minister of India, but it was a great loss for us.

Countless schemes and reforms have been taken in the regime of our beloved Prime Minister Narendra Modi Ji. Hon'ble President rightly stated that all the projects, schemes and programmes of the government in his speech. I thank the Hon'ble President for his speech.

(ends)

***श्री ए. टी. नाना पाटील (जलगांव):**

***Laid on the table**

***श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर):**

***Laid on the table**

***डॉ. यशवंत सिंह (नगीना):**

***Laid on the table**

*DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM):

*Laid on the Table

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR):

*Laid on the Table

*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI):

*Laid on the Table

*SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR):

*Laid on the Table

*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI):

*Laid on the Table

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):**

***Laid on the table**

***डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):**

***Laid on the table**

*DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST):

*Laid on the Table

***श्री राजेशभाई चुडासमा (जूनागढ़):**

***Laid on the table**

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL):

*Laid on the Table

1352 बजे

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आरदणीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां लाया गया है, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से खड़ा हूं। महोदया, यह संवैधानिक तथा पारंपरिक प्रथा है।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज। यहां पर ये क्या हो रहा है?

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैडम, बजट सेशन शुरू होता है, उसके पहले महामहिम राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कारोबार का लेखा-जोखा देना होता है। थोड़ा मेरे मन में एक संदेह है। जो भी बजट सेशन हुआ, ये फुल-फ्लैज्ड बजट था या इंटरिम बजट था? जहां तक मैंने पढ़ा है, आज तक 70 साल के कार्यकाल में 14 दफा इंटरिम बजट पेश हो चुका है और इसका कारण सामने आने वाला चुनाव है। जो भी चुनाव का कार्यकाल होगा, उस दौरान जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वे सदन में पास करने के लिए एक इंटरिम बजट होता है।

(1355/MM/SRG)

लेकिन इस साल का अनुभव अलग ही है। मुझे इस बार का अंतरिम बजट पूर्ण बजट लग रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार के कार्यकाल की सभी योजनाओं का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। हम भी मानते हैं कि एनडीए सरकार को बहुत अच्छा मेंडेट मिला। नियमानुसार विपक्ष को अपना नेता बनाने का भी मौका नहीं मिला। हम एनडीए के पार्टनर के रूप में शुरूआत के कार्यकाल में बहुत खुश थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक अलायंस पार्टी होते हुए भी हमारे साथ जो व्यवहार होता है, जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसको स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट बोला जाता है। इस लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया समझिए। सत्र के चार वर्किंग डेज़ बचे हैं, उसके बाद चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, उनकी सराहना करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी की पहली घोषणा 'सबका साथ, सबका विकास' थी। हम उस समय साथ थे, आज भी हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है कि हम कल साथ होंगे या नहीं? यह सोचने की बात है। हमारी लोक

सभा में संख्या 18 है, राज्य सभा में हमारे तीन सांसद हैं। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ? इस बात को इस तरफ के लोग भी जानते हैं और दूसरी तरफ के लोग भी जानते हैं। शुरूआती मैडेट के बाद से हम नीचे क्यों जा रहे हैं?

1358 बजे

(डॉ. पी. वेणुगोपाल पीठासीन हुए)

मैं मानता हूँ कि यह आत्मपरीक्षण का समय है। हमने अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम से कुछ गलतियां भी हुई हैं, जिसके बारे में हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हम यही अनुभव आज तक लेते आए हैं। हमारे इधर के साथी दिल से चाहते हैं कि हम भविष्य में भी साथ में रहें। हमारे राज्य सभा में शिव सेना के नेता संजय राउत जी ने आज ही उल्लेख किया जब किसी ने उनसे पूछा कि आप अभी भी सरकार में क्यों हैं? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम सरकार में नहीं हैं, हम एनडीए में हैं। जब श्रद्धेय अटल जी थे, आडवाणी जी अभी भी हैं, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे और हमारे हिन्दू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे थे। हिन्दुत्व की एक विचारधारा थी, जिसके आधार पर हम एनडीए में आए। हम सरकार का साथ देते आए हैं। लेकिन आपको आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है कि हम जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।

(1400/SJN/RP)

अभी तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं। क्या हुआ, हमने क्या पाया और क्यों, यह भी सोचना जरूरी है। अच्छे काम के साथ अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारना भी जरूरी होता है। दुर्भाग्यवश अभी तक हमें इतना अनुभव नहीं आ रहा है, लेकिन सुधार करने का प्रयास हो रहा है। प्रयास तो होना चाहिए। कुछ बातें जरूर हैं, जब हमारी सरकार आई थी, तब पहला नारा हमारे प्रधान मंत्री जी ने दिया था कि 'सबका साथ, सबका विकास'। मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ। 'स्वच्छ भारत अभियान' एक अच्छा नारा दिया गया था, फिर उस हिसाब से काम शुरू हुआ। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया है कि 40 प्रतिशत टॉयलेट निर्माण का काम वर्ष 2014 के पहले हुआ है। हमारे कार्यकाल में उसमें 98 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी जरूर हुई है, उसके आंकड़े हैं, लेकिन टॉयलेट का उपयोग टॉयलेट के लिए होता है या नहीं होता है, यह भी देखना जरूरी है। हम जब भी गांवों में जाते हैं, तो यह देखते हैं कि घरों में पानी के अभाव में टॉयलेट करना मुश्किल हो जाता है। हमारे किसान भाई उसका उपयोग अनाज रखने के लिए करते हैं। आपको यह तो मानना पड़ेगा, यह फैक्ट है। हम जब तक उनको पानी की सुविधा नहीं देंगे, उसकी निगरानी सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक यह बात फायदे की नहीं होगी, जिस कारण से हमने यह डिमांड किया है, जो बहुत-सी बीमारियों का कारण होता है। उद्देश्य अच्छा है और जरूरी है। इसके अलावा हमारी मां-बहनों को ओपन में बैठना पड़ता था, वह एक बेइज्जती की बात होती थी, उसके लिए भी उसकी जरूरत है। अगर योजना लाई गई है, तो उसकी निगरानी भी होनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, वह देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह नहीं हो रहा है। उज्ज्वला योजना की बात चल रही है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं। 14 करोड़ परिवारों को गैस का वितरण किया गया है। ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा यह अनुभव है, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक आदिवासी क्षेत्र भी आता है। हम खुद कभी-कभी अपने वन विभाग के माध्यम से या पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से गैस सिलेंडर का वितरण करते हैं। पहला, गैस सिलेंडर मिलता है। दूसरा, गैस सिलेंडर नहीं मिलता है या उनकी लेने की परिस्थिति नहीं होती है। यह भी देखना जरूरी है... (व्यवधान)

अगर हम गैस सिलेंडर देते हैं, सिगड़ी देते हैं, उसका इस्तेमाल आगे होता है या नहीं होता है। बहुत जगहों पर हमारा अनुभव है कि उसका अमल नहीं होता है। हमारे साथी लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन यह हकीकत आपको भी पता है, जो रूलर एरियाज में घूमते हैं। 'आयुष्मान भारत' की मैं सराहना करता हूँ, जो दुनिया में सबसे अच्छी योजना है। हमारा देश गरीबों का देश है। मैं कभी-कभी यह बात बोलता हूँ कि भारत अमीर लोगों का गरीब देश है।

(1405/BKS/RCP)

सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि अमीर लोगों का गरीब देश है। जब दुनिया में 50 श्रीमंत लोगों की एक लिस्ट बनती है, भारत के उसमें दस लोग होते हैं। यानी दुनिया यह समझती है कि भारत एक श्रीमंत देश है। लेकिन हमारे देश में गिने-चुने श्रीमंत हैं, बाकी सब गरीब हैं, जिनको दो वक्त की रोटी ठीक तरह से नहीं मिलती है। उनको अच्छे वस्त्र नहीं मिलते हैं, न वे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, न उनके सिर पर कोई अच्छी छत होती है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों पर भी गौर से ध्यान देने की जरूरत है।

आयुष्मान भारत के माध्यम से, एक गरीब देश के माध्यम से मैं थोड़ा उधर गया था, भटका नहीं था। लेकिन मैं यह बोलना जरूरी समझता हूँ कि मैं इसे दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम मानता हूँ, अगर उसका अमल सही हो। पांच लाख रुपये के इलाज की सुविधा हर परिवार के लिए, हर साल बीमारी का सामना करने के लिए सरकार की तरफ से मिलेगी।

हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह भी आया है कि आज तक चार महीने में दस लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला है। अगर यह फायदा मिलता रहेगा तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गरीब परिवारों की दूर होगी, यह मैं मानता हूँ। बात यह है कि प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केवल एक महीने में एक रुपया, कुल 12 रुपये और 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा या प्रति दिन 90 पैसे यानी 333 रुपये अगर एक परिवार एक साल में देता है और उस परिवार का मुखिया यदि किसी कारण से मर जाता है या अपंग होता है तो उस परिवार को दोनों योजना के तहत दो-दो लाख रुपये मिलेंगे। योजना अच्छी है, लेकिन इस

पर गौर से अमल मैंने नहीं देखा है। लेकिन इसका अमल अगर सही तरीके से होता है तो हम उसे बिल्कुल अच्छा मानेंगे।

सभापति जी, मैं एक बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से या देश के हिसाब से जिसे मैं एक बहुत अहम् मुद्दा मानता हूँ। जो हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बोला Demonetisation was a defining moment in the Government's war on corruption and black money, इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। डीमोनेटाइजेशन का समर्थन अगर हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं या जो लिखकर दिया, उसके ऊपर भाषण करते हैं और इसकी सराहना करते हैं तो यह बात सरासर गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। कारण यह है कि जो परदेश में हमारा ब्लैक मनी था, उसे वापस लाने का ऐलान चुनाव के दरम्यान किया गया था। मैं उसे ब्लैक मनी मानता हूँ। टैक्स बचाने के लिए अगर बड़े-बड़े लोगों ने अपना पैसा विदेशों में रखा है तो उसे मैं ब्लैक मनी मानता हूँ। लेकिन हमारे देश में हर व्यवहार एक पैरेलल इकोनोमी के तहत चलता है। हमारे यहां बड़े किसान हैं, उनके पास 50 या सौ एकड़ जमीन है और वे मजदूरों को मजदूरी देते हैं तो मजदूरी रोकड़ में देनी पड़ती है, न वे बैंक से देते हैं और न उनके खाते में जमा कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उन्हें हर दिन या वीकली पैसा देना पड़ता है तो रोकड़ा रखना पड़ता है। छोटे व्यापारी जब गांव-गांव में अनाज खरीदने के लिए जाते हैं तो रोकड़ा-पैसा देना पड़ता है। जो छोटे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी मजदूरी रोकड़ा देना पड़ता है। इस तरह से सबको हार्ड कैश रखना पड़ता है।

(1410/GG/SMN)

उनको भी रोकड़ा पैसा रखना पड़ता है, तो इसको हम ब्लैक मनी मानेंगे? 8 नवंबर, 2016 की रात आठ बजे अचानक ऐलान होता है कि पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट चलन से निकाल दिए। जिन सब के पास जितना भी रोकड़ा पैसा था, उसकी कीमत जीरो बन गई। परिणाम यह हुआ कि हमारी इकोनोमी जो पैरेलल चलती थी, न किसान अपने मजदूर को पैसा दे पाया, न छोटा व्यापारी अपने गांव-गांव में किसान को जो अनाज खरीद करता है, उसको पैसा दे पाया, न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन

वाला अपने मजदूर को पैसा दे पाया, छोटे उद्योग की यह हालत हुई कि वे बंद पड़े हुए हैं, और बंद पड़ने के कारण जो बड़े उद्योगों के साथ उनका लिंक होता है, उसके ऊपर भी एक असर हुआ। यह सब कैसा चक्र घुमाया गया, यह देखिए और इसके परिणाम से आज भी हमारा देश पूरे तरीके से नहीं ऊबर पाया है। इसकी सराहना करना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जो गलत है, वह भी स्वीकारना चाहिए। हमारे मंत्रीमण्डल के ही एक मंत्री ने बताया था, जब हमारी जीत होती है तो क्रेडिट कुछ लोग लेते हैं, मगर जब हार होती है तो क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे कारण हार हुई है? वैसे ही अगर गलती की तो की, हमारी गलती हुई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गलती है तो गलती है। अभी पिछले महीने में राज्य सभा में एक सवाल के उत्तर में खुद हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने माना था कि ये हमारी थोड़ी गलतियां हुई थीं, थोड़ी जल्दबाजी हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया। फिर हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह क्यों आया? उसकी सराहना क्यों होती है यह भी एक बहुत बड़ी बात है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, is the BJP boycotting the Shiv Sena?
Only about 10 BJP Members are present. They are the Ruling Party.

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Nothing will go on record.

...(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): हमारे साथ यही व्यवहार होता आया है। उनके साथ हम, उनके बाजू में हमेशा बोलते भी आए हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy, do not disturb him.

...(Interruptions)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सौगत रॉय जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब माननीय शिवसेना प्रमुख जी ने शिवसेना का निर्माण किया, तो बीजेपी के साथ अलायंस कर के हम सत्ता में जाएंगे, इसलिए नहीं किया। खुद की पार्टी उन्होंने अपने बलबूते पर बनाई और हमारे पक्षप्रमुख उद्धव

जी वही दोहरा रहे हैं, हम अकेले भी चला सकते हैं और चलाएंगे। इसलिए कौन साथ में है और कौन साथ में नहीं है, इसकी परवाह हमने कभी नहीं की। हमारी ममता जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। बात है, जब हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में भी थे, तब हमारे 15 सदस्य थे। उनमें से चार मंत्री थे, एक स्पीकर था, वह भी हम तुलना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कुछ योजनाएं कि इस देश को इस बात की जरूरत है, जब एक साइड में अकाल पड़ता है तो दूसरी बाजू में बारिश के कारण नुकसान होता है, तो रिवर कनेक्टिविटी की योजना हमारे श्रद्धेय अटल जी ने शुरू की। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सर, आज सभी का भाषण हो चुका है। अब गिनी-चुनी तीन-चार पार्टियां बची हैं। क्या जल्दबाजी करनी है? आज तो बजट आने वाला नहीं है। बजट का डिस्कशन मण्डे को शुरू होगा, कल फ्राइडे है, हर आदमी एक बजे ही निकल जाता है। आप क्यों चिंता करते हैं, हम हैं न आपके साथ हैं। इनके साथ नहीं हैं आपके साथ हैं।

(1415/KN/MMN)

उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी। हमारे तब के सांसद साथी श्री सुरेश प्रभु को उसका अध्यक्ष बनाया था। एक उद्देश्य बहुत अच्छा था, जैसे हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में रोड डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। हर आदमी आज भी उनके हर सवाल के समय सराहना करते हैं। यह रिवर कनेक्टिविटी वैसी ही बात है। अगर हमने चाहा तो रिवर कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे देश को खेती के लिए पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। जहाँ बारिश के कारण नुकसान होता है, वह टल जाएगा। अकाल के कारण जो नुकसान होता है, वह टल जाएगा और देश समृद्ध होगा। हमारे किसान भाई को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। यह भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सालों से हम सुनते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं तो पहले आता है कि आज दो किसानों ने आत्महत्या की, तीन किसानों ने आत्महत्या की। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात नहीं है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। सभापति जी, और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि कौशल विकास के माध्यम से शुरू-शुरू में तो गलत अनुभव आया। एनजीओ को यह योजना दी गई। हर जवान को जो भी

बेरोज़गार है, जो ट्रेनिंग के लिए आता है तो डेढ़ हजार रुपये उसको स्टाइपेंड देने का भी ऐलान हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से हमने यही अनुभव किया कि यह एक जो रजिस्टर बनाती थी, बेरोज़गार को बुलाती थी, 500 रुपये उसकी जेब में रखती और तीस दिन के सिग्नेचर लेती थी। कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। अभी उसमें थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, जो अभी अनुभव आया। साथ-साथ उद्देश्य यह था कि एक तो उसको जॉब मिले या स्वरोज़गार करे। अगर उनको स्वरोज़गार करना है तो मुद्रा योजना का ऐलान हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया। 10 लाख बिना कॉलेटरल सिक्योरिटी, योजना बहुत अच्छी है। हर पब्लिक सेक्टर बैंक को टारगेट दिया गया। क्या अनुभव लेते हैं हम? एक डीबीडीसी की मीटिंग में हमने देखा, यह अनुभव हमने पाया कि ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Please try to conclude.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आखिरी मुद्दा बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: There are a number of Members. I have got a long list of Members.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Yes, I will conclude. जब हमने देखा कि जो बैंक वालों को टारगेट दिया जाता है तो उनके पास जो बॉरोअर है, जो सही तरीके से रीपेमेंट करता है, उसके घर के मेम्बर को यह लोन दिया जाता है, टारगेट पूरा किया जाता है। सही मायने में बेरोज़गार को नहीं मिलता है। सभापति जी, कन्क्लूड कर रहा हूँ। अगर हर योजना सही मायने अमल होती नहीं है, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए एक यंत्रणा निर्माण करने की ज़रूरत है, यह मैं आपके सामने डिमांड रखता हूँ। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति : श्री दिनेश त्रिवेदी।

*SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR):

***श्री आलोक संजर (भोपाल):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की अभूतपूर्व पहलों व योजनाओं को रेखांकित किया गया है। मुझे भी यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है, कि सरकार के स्वच्छता अभियान की देश में खासी चर्चा है, आज समूचा देशवासी इस अभियान से जुड़ चुका है। खुशी तो तब होती है, जब देखते हैं कि गंदगी करने वालो एवं कचरा फेंकने वालों को हर कोई टोकने के लिए तत्पर होते हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सूक्ष्म परिक्षण करें तो भाषण में आशा की अनेकानेक किरणें आलोकित हो रही है। आज वह गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर माता- बहनें, प्रसन्नचित हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य तो सुधर ही रहा है, साथ ही उनका समय जंगल में लकड़ी काटने व कैरोसीन की लाईन में खड़े होने से बच रहा है।

अभिभाषण में यह स्पष्ट दिख रहा है कि देश एक नयी दिशा पर अग्रसर हो रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश ही नहीं लगा वरन् जड़ मूल से उखाड़ने के लिए सर्वस्व लगाया है। गर्व की बात है कि देश के लगभग 34 करोड़ लोगों के जनधन योजना के तहत खाते खुल चुके हैं, आज देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से सबसे ज्यादा लाभ देश की गरीब माता बहनों को मिला है। देश के गरीब भाई बहनों के लिए पिछली सरकारों में अनेक भाषण सुने लेकिन कही गयी बातें हवा में उड़ गयी है, उसके विपरीत मोदी सरकार ने कही बातों को धरातल पर उतारने का काम सुचारु रूप से किया है। यह भी इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 21 करोड़ गरीबों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक बात यह भी कही गयी है जिसकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है, वह योजना है “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना “- इस योजना के माध्यम से संपूर्ण भारत में आज दिनांक तक 600 से ज्यादा जिलों में लगभग 5000 जन औषधि

केंद्र खोले जा चुके हैं और खुलने भी जा रहे हैं। आज 700 से ज्यादा दवाईयाँ बहुत ही कम कीमत पर गरीबों व सामान्य वर्ग को उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की सभी उपलब्धियों के वर्णन से यह प्रदर्शित होत है कि वास्तव में वर्तमान सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। आज मोदी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों ने यह सिद्ध कर दिया है कि गरीब माध्यम वर्गीय परिवार प्रसन्न हैं, श्रमिक, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के लोग अपने पांव पर सम्मान के साथ खड़े हैं, किसान खुशहाल जीवन जीने के लिये अग्रसर हैं, छोटे-छोटे से व्यवसायी प्रोत्साहित हैं। देश के दिव्यांगों के लिए सरकार ने सार्थक कदम उठाये हैं, जिसकी प्रशंसा सर्वत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि भी इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभिभाषण में कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिये “राष्ट्रीय पोषण मिशन” की बात कही गयी, निश्चित ही आदिवासी व अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। “खेलों इंडिया” अभियान के तहत, देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर व प्रतिभावान खिलाड़ियों को चन्हिति कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर अपना, अपने परिवार, अपने प्रदेश व अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।

मैं अंत में दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को जन जन के मन में प्रवाहित करने के लिए मोदी सरकार एवं माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन का अभिनंदन करता हूँ।

(इति)

1419 बजे

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ, हमारी नेत्री ममता बनर्जी का आभारी हूँ कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। Sir, before I start, I would like to request you that we have got about 40 minutes or so. I am going to speak for 25 minutes. So, I will appreciate a little bit of patience from your side. Sir, having said that, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कष्ट लिया कि दोनों सदनों के सामने बात अपनी नहीं रखी, क्योंकि यह बड़ा पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है। ब्रिटिश का ट्रेडिशन है, जिसको बोलते हैं- 'The Monarch reads the speech of the Queen'.

(1420/CS/VR)

हमारे संविधान के आर्टिकल 87 के तहत बात होती है सरकार की, मगर पढ़ा जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो कंस्ट्रक्टिव और टूथफुल, क्रिटिकल बातें होंगी, वे राष्ट्रपति के अभिभाषण के, उनके प्रति नहीं हैं, सरकार के प्रति हैं। मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमको कसौटी पर रखो, सदन को चलने दो, हमारी जितनी भी बुराइयाँ हैं, उन्हें सामने रखो। आज उसी स्पिरिट के तहत मैं बोलना चाहता हूँ खड़गे जी ने हमारी मुश्किल बढ़ा भी दी और हमारी मुश्किल कम भी कर दी। उन्होंने हमारी मुश्किल बढ़ा इसलिए दी कि जो उन्होंने कहा था, रूबरू वह सच्चाई हमारे समक्ष भी थी। I also wanted to talk about the same points. उन्होंने हमारी दुविधा कम इसीलिए कर दी कि खड़गे जी ने जो कहा, मैं समझता हूँ कि उस तरफ की बात अलग है, मगर सदन में इस तरफ के जितने भी लोग हैं, सभी लोग उनकी बात से एकदम सहमति रखते होंगे। मैं ऐसा समझता हूँ मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ...(व्यवधान) सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है, वह न तो कांग्रेस की होती है, न टीएमसी की होती है, वह आम जनता की होती है। I was very happy that the hon. President talked about the 150th Anniversary of

Mahatma Gandhi. He talked about the Constitution. ...(*Interruptions*) अनुराग जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खड़गे जी की स्पीच सुनकर इतने डीमोरेलाइज हो गए कि मैदान छोड़कर ही भाग गए...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): खड़गे जी, स्वयं मैदान छोड़कर चले गए...(व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): आपने गुरु नानक जी की बात कही, आपने गाँधी जी की बात कही, राम मनोहर लोहिया जी की बात कही और आपने ऐथिक्स की बात कही...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Anurag ji, please sit down. Do not disturb the hon. Member.

... (*Interruptions*)

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने यह कहा, When the hon. President said that prior to 2014 General Elections, the country was passing through uncertainty, मुझे आज भी समझ नहीं आता है कि कौन सी ऐसी अनसर्टेनिटी थी? क्या सरकार नहीं थी, क्या यह पार्लियामेंट नहीं थी, क्या यह संविधान नहीं था? हाँ, अब संविधान पर थोड़ी चोट जरूर आ रही है। यह फ्रेज मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि 'What was the uncertainty?'

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): आप अपनी समझ बढ़ाइए।

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): महामहिम राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया की बात कही, नये भारत की बात कही। इस पर मैं लंबा बोलना चाहूँगा, मगर थोड़ी देर के बाद मैं आपके नये भारत के बारे में बहुत लंबा बोलना चाहता हूँ। यह देश बी.आर.अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, शरद चंद्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, गोविन्द बल्लभ पंत, कोविंद माल्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपालाचार्य और अन्य कितने ही महापुरुषों का है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): गोपालाचार्य कौन हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): आप मुझे बात करने दीजिए। यह देश इन महान व्यक्तियों का देश है। जब हमारा संविधान बना तो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बात कही थी और वह बात थी, "The

spirit of India.” He said that committing suicide is the biggest crime. But the bigger crime is getting away from the spirit of India. मुझे लगता है कि आज उस स्पिरिट ऑफ इंडिया से हम कहीं न कहीं कुछ अलग हट रहे हैं। खड़गे जी ने शायरी से अपने भाषण की शुरुआत की थी।

(1425/RV/SAN)

यह देश हमारे बहुत बड़े पोएट का है। यह देश कविगुरु रविन्द्र नाथ टैगोर का है। यह देश हमारे ऋषि बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का है। इस देश में बहुत सारी फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी यह भी है, जो शायद लागू पड़े, कि वक्त की जब बात आती है।

माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे,
इक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोहे।

वक्त-वक्त की बात होती है। पीयूष जी ने किसी एक पिक्चर की बात की थी। उसी दिशा में, मैं कहूंगा, क्योंकि खड़गे जी ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अभी 'मणिकर्णिका' नाम की पिक्चर आई है। उस पिक्चर में जो था, वह हकीकत ऐतिहासिक है। अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज क्या करते थे? वे आपको डराते थे, धमकाते थे। वे आपके घरों में घुस जाते थे और कहते थे कि आप हमारा साथ दो, वरना हम आप पर आक्रमण करेंगे। आज वही दशा है। आज झाँसी की रानी की याद आती है, क्योंकि यह पिक्चर, जो ऐतिहासिक है, यह झाँसी की रानी पर है। झाँसी की रानी कौन थी? वह एक साधारण महिला थी, जिन्हें लोगों ने चुना था कि आप झाँसी की रखवाली कीजिए। आपने क्या किया? आप आक्रमण करते रहे, यह कहते रहे कि हम आपके पीछे सी.बी.आई. लगाएंगे, आपके पीछे ई.डी. लगाएंगे, आप अपना माथा नीचे कर लीजिए, हमारे साथ चले आइए वरना हम आक्रमण करेंगे और आपने यह किया। बंगाल में अभी जो चंद दिनों पहले हुआ, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट आम जनता के साथ करती थी। फिर क्या हुआ? बंगाल में भी एक झाँसी की रानी है, जिनका नाम है - ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि 'सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं।'

यही है आज की झाँसी की रानी, जो रानी नहीं है, बल्कि एक साधारण महिला है। उन्होंने दिखा दिया कि आप हम पर जितना भी प्रहार करें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता हमारे साथ है।

सर, आपकी शुरुआत हुई थी कि 'अच्छे दिन' आएंगे। बहुत दिनों से हमने इस 'अच्छे दिन' की चर्चा नहीं सुनी है। यह स्लोगन 'अच्छे दिन' पता नहीं कहां गायब हो गया? आज जनता आक्रोशित है। चार चीजें हैं, जो आपको अगले चुनाव में, जहां से आप आए थे, वहां भेज देंगी। ये चार चीजें क्या हैं?

एक तो यह कि आपने डिमॉनेटाइजेशन किया। जैसे कहा गया कि रात को सवा आठ बजे प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं, जैसे मुगल बादशाह ऐलान किया करते थे, कि आज से आपकी 86% की करेंसी रद्द, और आपको अपने पैसे लेने के लिए, अगर मैं यह कहूंगा तो गलत नहीं कहूंगा कि आपको भिखारी बना दिया। आपको लाइन में खड़ा कर दिया, आपके पैसे पर राशन लगा दिया और उसमें बहुत सारे गरीब मारे गए। उसके खून की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? उसी दिन ममता बनर्जी जी ने मुझसे कहा कि 'अच्छे दिन' की बात छोड़ो, इनके बुरे दिन अब चालू हो गए हैं, क्योंकि आम जनता को क्या परेशानी होने वाली थी, वह ममता जी को बहुत अच्छी तरह से पता था।

सर, दूसरी बात, जो आपको खा जाएगी, वह है - unemployment, agricultural crisis and ruining the economy of this country. यदि आपको जानना है कि किस प्रकार सरकार चलानी है और किस प्रकार योजनाएं चलानी हैं तो आप बंगाल की स्कीम्स देखिए, चाहे वह 'कन्या श्री' हो, 'रूपा श्री' हो, 'युवा श्री' हो, 'शिक्षा श्री' हो, 'कृषक श्री' हो। हमारी सबसे अच्छी हेल्थ स्कीम है। आप अपनी हेल्थ स्कीम की बात करते हैं।

(1430/RBN/MY)

मगर हमारे यहां जो 'स्वास्थ्य साथी' योजना है, यह हमारे बंगाल में बनायी गयी है। आज कोई भी जाकर मुफ्त इलाज करा सकता है।

सर, मैं उसकी बात आगे नहीं कहूंगा और अपनी बात को आगे रखते हुए, यह कहूंगा कि जब आपने अन-एम्प्लॉयमेंट की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज अन-एम्प्लॉयमेंट सिर पर

चढ़ा हुआ है। आज जो अन-एम्प्लोएमेंट रेट है, वह चालीस साल के रेट से ज्यादा है। Today, the rate of unemployment is 6.1 per cent, which is much more than four decades of unemployment put together. ILO World Employment and Social Outlook Trend says that 77 of the Indian workers would be vulnerable and 18.9 million people would be unemployed by this year, that is 2019. The MSMEs and traders have registered a huge decline. According to CMIE survey, 3.5 million jobs were lost due to demonetisation. The impact on the labour force was even much more significant. While the job losses were a least 3.5 million, the reduction in the labour force was to the tune of 15 million.

I will now come to demonetisation about which much has already been said. I will only briefly talk about this because the hon. President has made a mention of it. It is said that one of the aims of demonetisation was to fight fake currency. According to the RBI data, यह मैं आरबीआई के डेटा के बारे में कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि 5 लाख 22 हजार से ज्यादा करेन्सी फेक थी और जो पहले थी, उससे ज्यादा हो गई। The RBI has also highlighted in its Annual Report of 2017-18 that the value of banknotes in circulation has increased by 37.7 per cent. सर, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि यही कहना चाहता हूँ कि आपका पूरा डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया है। More than 25 million people, a number greater than Australia's population have applied for about 90,000 vacancies in the Railways. उसका मतलब क्या दिखाता है? आप जीडीपी के जितने भी फेक आँकड़े कीजिए, लेकिन आपका अन-एम्प्लोएमेंट चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 25 million applications have been received for 90,000 jobs.

सर, अभी चार हजार ग्रेजुएट्स ने 14 स्वीपर्स के जॉब की लिए अप्लाई किया है। Your Economic Survey reveals that in the last four years the level of real agricultural

GDP and the real agricultural revenue has remained constant at 1.9 per cent. आप जो डबल की बात कर रहे हैं कि इनकम डबल होगी, आपने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी हमारे बंगाल में कृषि की ट्रिपल इनकम कर दी है। जब वह दिल्ली आएंगी तो पता चलेगा कि किसान की असली देखरेख कौन कर सकता है।

सर, मैं आपको यह कहूंगा कि today the democracy is in danger. Institutions of democracy have been compromised. सर, पार्लियामेंट को ले लीजिए, why did you bulldoze all the legislation? यहां गतिविधि होती है, वेल में आदमी क्यों जाता है। हम सबको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम वेल में जाकर गतिरोध करें। यह जो कांस्टीट्यूशन है, वह हमारे लिए गीता है, हमारे लिए सब कुछ है। जब आप इस कांस्टीट्यूशन को अमेन्ड करते हैं, जब 7 जनवरी की रात को 10 परसेन्ट का रिजर्वेशन देने के लिए आपके कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो दूसरे दिन सुबह 8 तारीख को क्वेश्चन ऑवर के तुरंत बाद कांस्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल हमारे सामने रखा जाता है।

(1435/CP/SM)

यह कहां की इंसाफी है और यह कहां का लोकतंत्र है? आपने इसको मंदिर माना, हम भी मंदिर मानते हैं। आप जब आए, तो आपने माथा नमन किया, मगर हकीकत क्या है? आपने हमें मौका तो नहीं दिया, मगर आम जनता को भी मौका नहीं दिया, तो आपने पार्लियामेंट बिल्कुल भंग कर दी।

Coming to judiciary, “democracy is in danger.” यह हम नहीं कह रहे हैं। 12 जनवरी, 2018 को 4 सीनियर मोस्ट जजेज़ कह रहे हैं, “The way the courts are being run, if it is run like this, democracy would be in danger” और यह भी कह रहे हैं during the news conference, Justice Gogoi told the journalists that the move was partly because of concerns over the death of Justice Loya. This has been reported. क्या होता है? रात को डेढ़ बजे on Wednesday midnight, 25 अक्टूबर दिल्ली पुलिस क्या करती है? It says: “the Delhi Police cordoned off the Lodhi Road building.” मतलब

आधी रात को सीबीआई के मेन काम्प्लेक्स को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। क्यों घेर लेती है, सीबीआई का नंबर वन, उसको आप हटाने जा रहे हैं। It is reported कि आप उनको क्यों हटाना चाहते हैं? आपकी ऐसी कोई कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जिसके तहत आप उनको हटा सकते थे। मगर जो रिपोर्ट में आ रहा है कि शायद वह राफेल डील के बारे में कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। आधी रात को आपने उनको हटा दिया, तो यह कहां की डेमोक्रेसी है? यह जरा हमें बताइए।

मीडिया पर जो दबाव है, वह सब जानते हैं। क्या होता है? The CBI officer dealing with Chanda Kochhar case was transferred after filing FIR. वह ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि हमारे दोस्त अरुण जेटली 22 तारीख को एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह गलत किया, आप इसकी इतनी जल्दी जांच मत करिए। “Professional investigation targets the guilty and protects the innocent. It secures convictions and further public interest. One of the reasons why our conviction rates are poor is that adventurism and megalomania overtake our investigators and professionalism takes a back seat.” यही बंगाल में हुआ कि professionalism took a back seat. आपका मकसद बहुत ही गलत था। जो भी आपके सामने आता है, अच्छे आंकड़े रखना चाहता है, सब को आप घर भेज देते हैं। आप कहते हैं, my way or no way or highway. रघुराम राजन की बात की, उर्जित पटेल की बात की, अरविन्द सुब्रमण्यम, अरविन्द पाणिग्रही सब की बात की, तो मैं उसको रिपोर्ट करना नहीं चाहता हूँ।

सर, मैं 10 मिनट और लूंगा। आप हमेशा महाभारत की बात करते हैं, आप हमेशा श्री राम चन्द्र जी की बात करते हैं, महाभारत, रामायण, राम चन्द्र जी। आप एक दृश्य याद कीजिए कि कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि आपने जो दो वादे किए हैं, आप उन वादों का पालन कीजिए। एक वादा यह है कि आप राम चन्द्र जी को वनवास भेजिए और भरत को आप गद्दी में बैठाइए, तो उन्होंने क्या कहा,

“रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई।”

आपने जो 15 लाख का वचन दिया, उस वचन का क्या हुआ? राम चन्द्र जी की बात करने से बात बनती नहीं है। आपके लिए राम चन्द्र सिर्फ अयोध्या में होंगे, हमारे लिए राम चन्द्र कण-कण में हैं, हर हवा के झोंके में हैं, हर पानी की बूंद में हैं, मैं तो समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अन्दर हैं।

(1440/AK/SK)

अब मैं सीधा आता हूँ जो आप नए भारत की बात कहते हैं। यह कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। Your concept of 'new India' is about destroying democracy; your 'new India' is about destroying institutions; your 'new India' is about destroying Constitution of India; your 'new India' is about sabotaging the new generation; your 'new India' is about creating fear; your 'new India' is about finishing federal structure; your 'new India' is about 'my way or no way'; your 'new India' is about 'me' and not 'us'; and *Après nous, le déluge* मेरे बाद डिल्यूज आ जाएगा। This is your concept of 'new India'.

Further, your 'new India' is about unemployment; your 'new India' is about agriculture crisis; your 'new India' is about largest NPAs; your 'new India' is about destroying RBI to CBI and institutions to Constitution; your 'new India' is about destroying and not recognizing the norms of Parliament; your 'new India' is about bulldozing Bills in the Parliament without discussion; your 'new India' is about 'farzi' data; your 'new India' is about pseudo patriotism; your 'new India' is not to follow *raj-dharam*; your 'new India' is to divide and misrule; your 'new India' is to distort the secular values of Swami Vivekanand; Mahatma Gandhi; Sardar Patel;

Dr. Ambedkar; Netaji; Maulana Azad; Kabir; and Tulsidas; your 'new India' is against the ethos of '*vasudhaiva kutumbakam*'; your 'new India' means destroying our Ganga-Yamuna *tehzeeb* -- जहां ग़ालिब भी है, मीरा भी है, मोहम्मद रफी भी है और लता मंगेशकर भी है; Your 'new India' means destroying the youth; your 'new India' is about lowest farmers' income of 1.9 per cent; your 'new India' is about farmers' suicide; your 'new India' means 77 per cent of Indian workers are out of workforce; your 'new India' means MSMEs are out of business; your 'new India' means not achieving the objectives of demonetization; and your 'new India' is the biggest '*jumla*' for 2019 election whereas your '*jumla*' for 2014 was '*Achhe Din*'. Please understand that you can fool all people some time; some people all the time; but not all people all the time.

मैं यह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपकी एक्सपायरी डेट खत्म हुई, आपकी बात खत्म हुई, लोग आपसे नाराज़ हैं, हमारे लिए – सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। 2019 -- BJP finish!

(ends)

*SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE):

*SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST):

***श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):** मैडम स्पीकर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आपने सन् 2014 में लोगों से बड़े-बड़े वादे किए थे, बड़े-बड़े सपने दिखाए थे और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपके हाथों में हुकूमत सौंपी थी, मगर अफसोस कि आपने आवाम से किए हुए वादे तो पूरे नहीं किए मगर लोगों के लिए बहुत सी परेशानियां पैदा कर दीं, जिससे मुल्क की तरक्की की रफ्तार रुक गई।

महँगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हुई

मैडम, पिछले चार सालों के दौरान हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। गैस सिलेंडर की कीमत दुगनी बढ़ा दी गई है। ट्रेन का किराया बार-बार बढ़ाया गया है।

करप्शन पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई

मैडम, सरकार करप्शन को खत्म करने का वादा कर के आई थी, मगर इस वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। करप्शन के नए-नए वाक्यात सामने आ रहे हैं। नोटबंदी से ब्लैक मनी तो वापस नहीं आई, मगर आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, उनकी जानें गईं। मगर करप्शन लोगों पर लगाम कसने में सरकार बुरी तरह नाकाम रही।

बेरोजगारी में इजाफा हुआ है

मैडम, इस सरकार ने वादा किया था कि वह हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मगर अफसोस कि सरकार का यह वादा भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि पिछले चार सालों में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी पिछले 42 सालों में नहीं हुई थी और यह बात सरकार की गैरशायाशुदा रिपोर्ट कह रही है, जो अखबार में छपी है।

बैंकों के पैसों की लूट-खसोट

मैडम, सरकार ने विदेश से ब्लैक मनी वापस ला कर लोगों के आकाउंट में 15 लाख रुपये डालने का वादा किया था। ब्लैक मनी तो वापस नहीं आई, मगर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग इस मुल्क का वाइट पैसा ले कर जरूर भाग गए और सरकार तमाशा देखती रह गई।

अच्छे दिन नहीं आए, मगर गरीबों के बुरे दिन जरूर आए हैं

मैडम, सरकार ने वादा किया था कि वह लोगों के लिए अच्छे दिन ले कर आएगी। मगर अफसोस कि अच्छे दिन के इंतजार में तकरीबन पांच साल खत्म होने वाले हैं। हाँ गरीबों के बुरे दिन जरूर आए हैं। कभी नोटबंदी के जरिए, कभी जीएसटी के जरिए तो कभी मंहगाई के जरिए गरीबों को परेशान किया गया है।

सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ

मैडम, सबका साथ, सबका विकास भी एक जुमला ही बन कर रह गया है। जब से यह सरकार आई है, तब से अकलियतों को और खास तौर से मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है, उनकी हैसियत को खत्म करने की कोशिश की गई है। उन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में टालमटोल की गई है। उनके साथ तास्सुब के वाकयात में इज़ाफा हुआ है।

सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल

मैडम, सिटिज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो असम के एकोर्ड के खिलाफ है, एनआरसी के खिलाफ है, और हिन्दुस्तान के आईन के खिलाफ है। सरकार इस फिरकापरस्ती वाले बिल को पार्लियामेंट में ला कर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस बिल से पूरे नॉर्थ-ईस्ट की हालत मज़ीद बद्तर हो जाएगी। इसलिए इस बिल के खिलाफ पूरे नॉर्थ-ईस्ट में हंगामा मचा हुआ है। इस बिल को कानून बनाने का मतलब हिन्दुस्तान के लोगों का हक छीनना है। हमारा मुतालबा है कि इस बिल को वापस लिया जाए, और असम एकोर्ड को नाफ़िज़ किया जाए।

तीन तलाक बिल मुस्लिम औरतों के लिए मुसीबत है।

मैडम, सरकार तीन तलाक के खिलाफ़ बिल ला कर मुस्लिम औरतों को इंसाना दिलाने की झूठी बात फैला रही है। हालांकि जो बिल ले कर आई है, वह न सिर्फ़ मुसलमानों के मज़हबी मामलात

और इस्लामी शरियत में मुदाखलत है, बल्कि हिन्दुस्तानी आईन के मिजाज के भी खिलाफ है। यह बिल औरतों के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है क्योंकि इस बिल के मुताबिक तलाक नहीं होगी, मगर शौहर को जेल डाल दिया जाएगा और उस औरत को फिर उसी मर्द के साथ रहना पड़ेगा, जिसने उसको तलाक दे कर अपनी जिन्दगी से निकाल दिया था। हकीकत में यह बिल मुसलमान औरतों और मर्दों दोनों की बर्बादी का सबब होगा। इसलिए इसको फौरन वापस लेना चाहिए।

मस्जिद और मंदिर का मसला

मैडम, जब भी इलैक्शन आता है, इस मुल्क में मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस सरकार ने जब लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो फिर एक मर्तबा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर बहस शुरू हो गई है और लोगों को बहका कर वोट हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई है।

किसानों की परेशानी दूर करने में यह सरकार नाकाम साबित हुई

मैडम, इस सरकार ने किसानों के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिसकी वजह से वे खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। वे अहतजाज करते हैं, मगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स का करोड़ों का कर्ज झटके में माफ कर दिया जाता है। मगर किसानों का कर्ज माफ न करने की हजार मजबूरी बताई जाती है।

मुसलमानों की तालीम के लिए सरकार मुनासिब कदम उठाने में नाकाम साबित हुई है

मैडम, वजीरे आजम ने कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कम्प्यूटर देना चाहते हैं। मगर अफसोस है कि मुसलमानों की तालीमी बदहाली दूर करने के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाए गए। उनके लिए तालीमी इदारे कायम नहीं किए गए। अफसोस तो इस बात का है कि मुसलमानों के जरिए कायम कर्दा जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार को खत्म कर के उसे मुसलमानों से छीनने की शाजिश चल रही है।

बदहाली के बावजूद मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जाता।

सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने वाज़िहा कर दिया था कि मुसलमान इस मुल्क में दलित भाइयों से भी बद्तर हालत में हैं और उनकी हालत को दुरुस्त करने के लिए उन्हें तालीमी इदारों और नौकरियों में रिजर्वेशन देने की सिफारिश की गई। मगर अफसोस कि सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया।

गौ-रक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्ल और सरकार की खामोशी

मैडम, इस मुल्क में गौ-रक्षा के नाम पर अब तक दर्जनों मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया है। ददरी के मोहम्मद अखलाक के बाद राजस्थान के पहलू खान और मोहम्मद अकबर, हरियाणा के हाफिज़ जुनैद और झारखण्ड के अलिमुद्दीन अंसारी समेत कितने ही लोग महज शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए, मगर सरकार इसके खिलाफ कानून बनाने और मुजरिमीन के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम रही।

आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट के काम में सरकारी मदाखलत

मैडम, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारों के कामकाज में सरकारी मदाखलत ने मुल्क की आवाम को तशवीश में मुबतिला कर दिया है। सीबीआई और ईडी वगैराह का गलत इस्तेमाल भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के चार जजों को प्रेस कॉन्फ्रंस करनी पड़ी और आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा

बुनियादी सहूलियतों की कमी पूरा करने में यह सरकार नाकाम

मैडम, आज़ादी के 70 साल बाद भी इस मुल्क में ऐसी जगह है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। सही सड़क नहीं पहुंची है। पीने का साफ पानी लोगों को मयस्सर नहीं है। हमारे असम में कम से कम दस जिले ऐसे हैं, जो आर्सेनिक से मुतासिर हैं। जहां का पानी पी कर लोग अपाहिज हो रहे हैं। हम लोगों ने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया और उन मुतासिरा इलाके के लोगों के लिए पीने का साफ पानी मुहैया कराने की अपील की, मगर ग्राउंड पर कोई काम होता नहीं आया है।

असम में पेपर मिल को बंद कर दिया गया।

मैडम, इलैक्शन से पहले जब हमारे प्रधान मंत्री जी असम गए थे, तो वहां इंडस्ट्री कायम करने का वादा किया था। मगर अफसोस वहां कोई नई इंडस्ट्री कायम नहीं हुई, मगर असम में पहले से मौजूद पेपर मिलों को बंद कर दिया गया, जिससे लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारा मुतालबा है कि पेपर मिलों को माली मदद दे कर उन्हें फिर से शुरू किया जाए

असम में सैलाब से बचाव के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाया गया।

मैडम, असम में हर साल सैलाब से जो तबाही होती है, उससे हम सब वाकिफ हैं। इरोज़न की वजह से तकरीबन 24 लाख हैक्टेयर जमीन दरिया में तब्दील हो चुकी है और तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इसलिए हम इस हाऊस में बार-बार मुतालबा करते आए हैं कि इसको नैशनल क्लैमिटी करार दिया जाए और उसके लिए मुनासिब फंड दिए जाएं और उसकी रोकथाम के लिए संजीदगी से प्लानिंग की जाए। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और सरकार तरह-तरह के बहाने बनाती रही है और थोड़ा बहुत जो फंड दिया गया, उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हालात वैसे ही बने हैं और खतरा अभी भी बरकरार है।

धुबरी फलवारी ब्रिज की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका।

मैडम, मैं धुबरी और फलवारी की तामीर के लिए हमने हर सतह पर मुतालबा किया और बिल आखिर इसकी तामीर का फैसला हो गया, मगर कई सालों से वादे के बावजूद इसकी तामीर का काम शुरू नहीं हो सका।

मैडम, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने मार्केटिंग और रीपैकेजिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इनके वादे महज़ वादे हो कर रह गए हैं।

शुक्रिया

جناب بدرالدین اجمل (دھیری): میڈم آپ نے مجھے اس بل پر بولنے کا موقع دیا میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں، میڈم، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2014 میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے کئے تھے، بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے۔ اور لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں حکومت سونپی تھی۔ مگر افسوس کہ آپ لوگوں نے عوام سے کئے گئے وعدے تو پورے نہیں کئے۔ مگر لوگوں کے لئے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دی جس سے ملک کی ترقی کی رفتار رک گئی۔

(1) مہنگائی پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے

میڈم، گزشتہ چار سالوں کے دوران ہر چیز کی قیمت آسمان چھو رہی ہے، جس سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت لگاتار بڑھ رہی ہے۔ گیس سیلینڈر کی قیمت دوگنی ہو گئی ہے۔ ٹرین کا کرایہ بار بار بڑھایا گیا ہے۔

(2) کرپشن پر قابو پانے میں ناکام ثابت ہوئی

میڈم، سرکار کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ کر کے آئی تھی مگر اس وعدے کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ کرپشن کے نئے نئے واقعات سامنے آئے۔ نوٹ بندی سے بلیک منی تو واپس نہیں آئی، مگر عام لوگوں کو پریشانی جھیلنی پڑی، ان کی جانیں گئیں۔ مگر کرپٹ لوگوں پر لگام کس نے میں سرکار پوری طرح ناکام رہی۔

(3) بے روزگاری میں اضافہ ہوا

میڈم، اس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، مگر افسوس کہ سرکار کا یہ وعدہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ کیونکہ گزشتہ چار سالوں میں اتنی بے روزگاری بڑھی ہے جتنی گزشتہ 42 سالوں میں نہیں ہوئی تھی اور یہ بات خود سرکار کی غیر شائع شدہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو اخبار میں چھپی ہے۔

(4) بینکوں کے پیسوں کی لوٹ کھسوٹ

میڈم، سرکار نے ویدیش سے بلیک منی واپس لا کر لوگوں کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ کیا تھا۔ بلیک منی تو واپس نہیں آئی مگر نیرو مودی اور وجے مالیا جیسے لوگ اس ملک کا وھانٹ پیسہ لیکر ضرور بھاگ گئے اور سرکار تماشہ دیکھتی رہ گئی۔

(5) اچھے دن نہیں آئے مگر غریبوں کے برے دن ضرور آئے ہیں

میڈم، سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کے لئے اچھے دن لیکر آئے گی مگر افسوس کہ اچھے دن کے انتظار میں تقریباً پانچ سال ختم ہونے والے ہیں۔ ہاں غریبوں کے برے دن ضرور آئے ہیں۔ کبھی نوٹ بندی کے ذریعہ تو کبھی جی۔ ایس۔ ٹی۔ کے ذریعہ تو کبھی مہنگائی کے ذریعہ غریبوں کو پریشان کیا گیا ہے۔

(6) سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں ہوا

میڈم، سب کا ساتھ سب کا وکاس بھی ایک جملہ ہی بن کر رہ گیا ہے۔ جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے اقلیتوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ان کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں ٹال مٹول کی گئی۔ ان کے ساتھ تعصب کے واقعات میں اضافہ ہوا۔

(7) سیٹیزن شپ امینڈمنٹ بل

میڈم، سیٹیزن شپ بل جو آسام اکورڈ کے خلاف ہے، این۔آر۔سی۔ کے خلاف ہے اور ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، سرکار اس فرقہ پرستی والے بل کو پارلیمنٹ میں لا کر اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہی ہے۔ اس بل سے پورے نارتھ ایسٹ کی حالت مزید بدتر ہو جائے گی۔ اسی لئے اس بل کے خلاف پورے نارتھ ایسٹ میں ہنگامہ مچا ہے۔ اس بل کو قانون بنانے کا مطلب ہندوستان کے لوگوں کا حق چھیننا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے اور آسام اکورڈ کو نافذ کیا جائے۔

(8) تین طلاق بل مسلم عورتوں کے لئے مصیبت ہے۔

میڈم، سرکار تین طلاق کے خلاف بل لا کر مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کی جھوٹی بات پھیلا رہی ہے۔ حالانکہ جو بل لے کر آئی ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات اور اسلامی شریعت میں مداخلت ہے بلکہ یہ ہندوستانی آئین کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ یہ بل عورتوں کے لئے مصیبت پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اس بل کے مطابق طلاق نہیں ہوگی مگر شوہر کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور عورت کو پھر اسی مرد کے ساتھ رہنا پڑے گا جس نے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ حقیقت میں یہ بل مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کی بربادی کا سبب ہوگا۔ اس لئے اس کو فوراً واپس لینا چاہئے۔

(9) مسجد اور مندر کا مسئلہ

میڈم، جب بھی الیکشن آتا ہے اس ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اس سرکار نے جب لوگوں سے کئے ہوئے وعدے پورے نہیں کئے تو پھر ایک مرتبہ بابری مسجد اور رام مندر پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اور لوگوں کو بہکا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔

(10) کسانوں کی پریشانی دور کرنے میں یہ سرکار ناکام ثابت ہوئی

میڈم، اس سرکار نے نو کسانوں کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہوئے۔ وہ احتجاج کرتے ہیں مگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا کروڑوں کا قرض جھٹکے میں معاف کر دیا جاتا ہے مگر کسانوں کا قرض معاف نہ کرنے کی ہزار مجبوری بتائی جاتی ہیں۔

(11) مسلمانوں کی تعلیم کے لئے سرکار مناسب قدم اٹھانے میں ناکام ثابت ہوئی

میڈم، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دینا چاہتے ہیں۔ مگر افسوس کے مسلمانوں کی تعلیمی بدحالی دور کرنے کے لئے مناسب قدم نہیں اٹھائے گئے۔ ان کے لئے تعلیمی ادارے قائم نہیں کئے گئے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے ذریعہ قائم کردہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو ختم کر کے اسے مسلمانوں سے چھیننے کی سازش چل رہی ہے۔

(12) بدحالی کے باوجود مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیا جاتا؟

سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اس ملک میں دلت بھائیوں سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور ان کی حالت کو درست کرنے کے لئے انہیں تعلیمی اداروں اور نوکریوں میں ریزرویشن دینے کی سفارش کی۔ مگر افسوس کہ سرکار نے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے سے انکار کر دیا

(13) گو رکشا کے نام پر مسلمانوں کا قتل اور سرکار کی خاموشی

میڈم، اس ملک میں گو رکشا کے نام پر اب تک درجنوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دادری کے محمد اخلاق کے بعد راجستھان کے پہلو خان اور محمد اکبر، ہریانہ کے حافظ جنید اور جھارکھنڈ کے علیم الدین انصاری سمیت کتنے ہی لوگ محض شک کی بنیاد پر قتل کر دئے گئے مگر سرکار اس کے خلاف قانون بنانے اور مجرمین کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔

(14) آر بی۔ آئی۔ اور سپریم کورٹ کے کام میں سرکاری مداخلت

میڈم، آر بی۔ آئی۔ اور سپریم کورٹ جیسے اداروں کے کام کاج میں سرکاری مداخلت نے ملک کی عوام کو تشویش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ سی۔ بی۔ آئی۔ اور ای۔ ڈی۔ وغیرہ کا غلط استعمال بھی لوگوں کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چار ججوں کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اور آر بی۔ آئی۔ کے گورنر کو استعفیٰ دینا پڑا۔

(15) بنیادی سہولتوں کی کمی پورا کرنے میں یہ سرکار ناکام

میڈم، آزادی کے 70 سال بعد بھی اس ملک میں ایسی کئی جگہ ہیں جہاں اب تک بجلی نہیں پہنچی ہے۔ صحیح سڑک نہیں پہنچی ہے، پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ ہمارے آسام میں کم سے کم دس اضلاع ایسے ہیں جو آرسینک سے متاثر ہیں، جہاں پینے کا پانی پی کر لوگ اپاہج ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کتنی بار اس مدہ کو

اٹھایا اور ان متاثرہ علاقوں کے لوگوں کے لئے پینے کا صاف پانی مہیا کرانے کی اپیل کی مگر گراونڈ پر کوئی کام ہوتا نظر نہیں آتا۔
(16) آسام میں پیپر مل کو بند کر دیا گیا

میڈم، الیکشن سے پہلے جب ہمارے وزیر اعظم آسام گئے تھے تو وہاں انڈسٹری قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر افسوس کہ وہاں کوئی نئی انڈسٹری تو قائم نہیں ہوئی بلکہ آسام میں پہلے سے موجود پیپر ملوں کو بند کر دیا گیا جس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پیپر ملوں کو مالی امداد دیکر پھر سے شروع کیا جائے۔

(17) آسام میں سیلاب سے بچاؤ کے لئے مناسب قدم نہیں اٹھایا گیا

میڈم، آسام میں ہر سال سیلاب سے جو تباہی ہوتی ہے اس سے سب واقف ہیں۔ ایروزن کی وجہ سے تقریباً 24 لاکھ ہیکٹیر زمین دریا میں تبدیل ہو چکی ہے اور تقریباً 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسی لئے ہم اس ایوان میں بار بار مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اس کو نیشنل کیلیٹی قرار دیا جائے اور اس کے لئے مناسب فنڈ دیا جائے اور اس کی روک تھام کے لئے سنجیدگی سے پلاننگ کی جائے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، اور سرکار طرح طرح کے بہانے بناتی رہی اور تھوڑا بہت جو فنڈ دیا گیا اس کا صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوا جس کی وجہ سے حالت ویسے ہی بنی ہوئی ہے اور خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔

(18) دھیری اور فلباری برج کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا

میڈم، میں دھیری اور فلباری کی تعمیر کے لئے ہم نے ہر سطح پر مطالبہ کیا اور بالآخر اس کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا مگر کئی سالوں سے وعدہ کے باوجود اس کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا۔

میڈم، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار نے مارکیٹنگ اور ری پیکینجنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، ان کے وعدے محض وعدے ہو کر رہ گئے ہیں۔

(ختم شد)

1443 hours

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Thank you, Sir, for allowing me to speak during the discussion in support of the Motion of Thanks on the President's Address.

जब भी किसी चीज की चर्चा हो या डिस्कशन हो, डिबेट में बहुत जरूरी होता है कि एक चीज का कम्पेरिजन होना चाहिए। हम जिंदगी में कोई भी चीज बाजार से लेने जाएं, चाहे गाड़ी खरीदें या कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के बारे में सोचें तो हम वे करते हैं और कम्पेरिजन करते हैं कि यह इससे अच्छा है, उससे अच्छा है। इसी तरह हम कम्पेरिजन करते हैं कि कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की एस्पिरेशन्स हमेशा बढ़ती रहती हैं और बदलती रहती हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई अंत नहीं होता है। सरकारों का काम होता है कि इन एस्पिरेशन्स पर डिलीवर किया जाए। अब कोई कहे कि जो 70 साल में नहीं हुआ वह पांच साल में किया जाए, मैं समझती हूँ कि उन पार्टियों की तरफ से ज्यादाती है जिन्होंने ज्यादातर 70 साल में राज किया है। बड़ी भाषणबाजी, स्लोगन्स, जुमले, क्रोनी कैपिटिलिज्म सारी चीजों के साथ बहुत बड़ी बातें करके टॉल प्रामिसिस, लॉफ्टी प्रामिसिस, टॉल क्लेमस के सिवा they have got nothing that they were able to deliver to the nation, and we all, as MPs, here know how easy it is to make tall and lofty claims.

(1445/MK/SPR)

भाषणबाजी तो सबसे आसान चीज होती है, लेकिन अपनी चीजों को डिलेवरी करना, एक-एक चीज पर कितना मुश्किल होता है, मेरा ख्याल है कि यहां के सारे सांसद इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज कोई खड़े होकर यह कह दे कि यह नहीं, वह नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन, बात कीजिए कि आपने क्या-क्या और इस सरकार ने क्या किया है और तब आंकड़ों पर आइए और उसका नतीजा देखिए। आज मैं कहना चाहूंगी कि मैं अपनी डिस्कशन कम्पेरिजन के साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। पिछली सरकार के सारे लोग जो आज इकट्ठे हो रहे हैं कि पिछली सरकार

का बहुत बढ़िया काम था। मैंने अभी खड़गे जी का भी भाषण सुना है, पता नहीं उन्होंने 70 सालों में क्या तीर-कमान कमा लिये हैं और इस सरकार ने तो पांच साल में कुछ किया ही नहीं है। आप जरा याद कीजिए वर्ष 2014 को। पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार का पूरे देश में, दुनिया में क्या था – besides corruption, crony capitalism, जहां फीयरलेसली देश के खजाने को लूट एंड प्लन्डर किया जा रहा था, निडर होकर जैसे उनका कोई हक है गरीब का पैसा खाने का। कोई ऐसा महकमा, डिपार्टमेंट, मंत्री या कोई ऐसा परिवार नहीं था, जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। यही एक कारण था कि हमारा देश अपने लोगों की निगाहों में और दुनिया की निगाहों में कहीं-न-कहीं एक करप्शन का सिम्बल बनकर रह गया था। हालात ये थे कि इन्फ्लेशन 10.1 परसेंट तक आसमान को छू रहा था। फार्मर्स डिस्ट्रेस की बड़ी बात की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने 60-70 साल राज किया है और किसान के लिए ये हालात पैदा किये हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। केवल किसान के बारे में बोला जा रहा है। जिसकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन आउटपुट कॉस्ट यानी एम.एस.पी. क्या देते थे? कर्जा माफी-कर्जा माफी का केवल एक नारा चल रहा है, जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन एक किसान के हालात में, हकीकत में, जमीनी तौर पर सुधार लाकर, उसको भिखारी की तरह डोल देकर नहीं, लेकिन उनको अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन-सी वे चीजें की गई थीं, उसकी भी चर्चा की जाए। महंगाई की तो ऐसी मार थी कि कौन भुला सकता है कि दाल 200 रुपये किलो, तेल 120 रुपये लीटर और कई और ऐसी चीजें थीं। महंगाई की चर्चा जितनी कम की जाए, मैं समझती हूँ कि आज शायद ही कोई सांसद होंगे, जिन्होंने महंगाई शब्द का नाम लिया हो। पांच साल पहले महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी कि टमाटर और प्याज की कीमतें कहां तक आसमन छू रही थीं। इन सब हालातों में महंगाई की मार हरेक को पड़ती है, लेकिन गरीब को सबसे ज्यादा पड़ती है। गरीब के लिए बहुत सारी नारेबाजी होती थी। There used to be a lot of talk whenever elections are coming. How there would be houses for the poor? How there would be toilet for the poor? तरह-तरह की ऐसी चीजें बोली जाती थीं, on the eve of elections to win the votes. अगर

इन फिगर्स को देखा जाए, तो 70 सालों में फार्मर्स डिस्ट्रेस तो था, लेकिन टॉयलेट्स की बात की जाए, घरों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, मेरे से पहले आप सभी को इन आंकड़ों के बारे में पता होगा कि तब आंकड़े क्या थे और अब आंकड़े क्या हैं। मैं अभी खड़गे जी का भाषण सुन रही थी, जब वे कह रहे थे कि आपने चार साल में 18 हजार गांवों की बिजली दी है तो कांग्रेस पार्टी ने तो 60-70 साल में 6 लाख गांवों की बिजली दी गयी थी। इनके कहने का मतलब क्या है? जब देश का बंटवारा हुआ था, तो पूरा हिन्दुस्तान अंधेरे में था, जब तक ये सत्ता में नहीं आए थे? क्या किसी गांव में बिजली नहीं थी, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आई ? क्या देश को उजाला कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है? मैं तो आंकड़ों के बारे में पूछती हूं, वे तो आंकड़े निकाल लेंगे कि आप जब आए तो गांव में कितने दिन बिजली थी और आपके आने के बाद कितनी बिजली दी। आप देख लें कि आपके पिछले पांच सालों में अगर गरीबों के मकान बारे में बात की जाए तो पांच साल में 25 लाख मकान बने थे, तो इस सरकार ने चार साल में डेढ़ करोड़ के तकरीबन पांच सौ गुना ज्यादा मकान बना दिये हैं। आप टॉयलेट की बात कीजिए। शौचालय न होने के कारण कैसी बीमारियां होती हैं? एक महिला होने के नाते मैं जानती हूं कि अब कैसे गांव बड़े होते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में निकलना पड़ता है, कैसे-कैसे हालत हो रहे हैं। लेकिन, इस बारे में किसको परवाह थी। इन लोगों ने 70 सालों में केवल 40 फीसदी लोगों तक शौचालय दिया है। आज 98 परसेंट लोगों तक शौचालय पहुंचाने का काम इस सरकार ने केवल चार साल में किया है। ये गरीबी हटाओ- गरीबी हटाओ के नारे लगाकर इलेक्शन लूट कर ले गये।

(1450/RPS/UB)

गरीब का यह हाल था कि चाहे कोई गरीब महिला हो, जो अपने घर के लोगों का पेट भरने के लिए, धुएं की सांस फूंक-फूंककर वह अपनी सेहत का क्या हाल करती थी, इसकी परवाह कौन करता था? इनका काम सिर्फ इलेक्शन के टाइम आता है, बाद में उनको भूल जाया जाता है। आज इन सभी के बारे में, चाहे गरीब के घर तक बिजली जाए, उसका घर बने, उस घर में उसका शौचालय हो, उसके लिए सड़क हो, पानी हो, उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, उसकी बहनों-बेटियों की

इज्जत और सेहत को बरकरार रखने के लिए सॉल्यूशन्स हों, उनका बीमा हो, इन सभी चीजों के बारे में और किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। जब देश में हालात इतने बिगड़े हुए थे, तब देश की जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी नुमाइंदगी मिली, जिन्होंने काम करके, तजुर्बे के साथ इस देश को अपने राज्य में दिखाया था। यही कारण है कि इस देश की सवा सौ करोड़ जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुना तो इतने बड़े बहुमत से चुना। यही कारण है कि इन पांच वर्षों में जो न्यु इंडिया का ट्रांसफार्मेशन आया है, आज इन लोगों को कारण ढूंढने पड़ते हैं कि हम किस चीज के बारे में बोलकर, यहां पर रयूमर-माँगरिंग करके इस सरकार को बदनाम करें। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आंकड़े खुद ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो इनकी जुबान वैसे ही बन्द कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि मैं एक प्रधान सेवक बनकर काम करूंगा और देश का चौकीदार बनकर देश के खजाने की रखवाली करूंगा, देश के गरीबों के हकों की रखवाली करूंगा, देश की सरहदों की रखवाली करूंगा और मुहंतोड़ जवाब दूंगा, चाहे वे देश के दुश्मन हों या देश के अंदर देश के खजाने को लूटने वाले धोखेबाज दुश्मन हों, जो अपने देश में बहरूपिया बनकर बैठे रहते हैं। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला। दस साल के मजबूर प्रधानमंत्री के बाद एक मजबूत सरकार आई। I am not going by what my Government says, but let us look at the way the world looks at India. Today, India is being considered the one 'bright spot' in gloomy global economy...*(Interruptions)*

SHRI ANURAG THAKUR: Sir, this is unfair that such comments are coming from the Trinamool Congress Party Members while a lady hon. Member is speaking....*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Hon. Members, keep silence please. Do not disturb the hon. Minister. You may please continue speaking.

... *(Interruptions)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सर, एक पूर्व मंत्री जाकर पीछे बैठकर बात कर रहे हैं, जबकि एक महिला सदस्य बोल रही हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। इससे पता चलता है कि वे महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: ये चाहे जितना शोर मचा लें, today, they cannot deny the fact that India is the fastest growing economy in the world. Today, in the Ease of Doing Business Index, we have reached 77th position after jumping so many positions just within four years which they could not jump in so many years when they were running the Government.

Sir, today, we have left behind big economies whether it is the US, the UK or China, and India is moving at a faster rate in comparison to them. Today, we have the highest investment under Foreign Direct Investment in our country because the world is perceiving India as a new India. Today, we have the highest foreign reserves in our country. Today, in every way, India is growing in a stable and in a positive manner which they could not achieve in ten years of their rule because they were too busy plundering the nation and looting the nation. This is the difference between this Government and the earlier Government.

Sir, I would not like to go into the figures of how we have maintained all our fiscal balances. But I would like to mention here that all the development in our country has taken place and all kinds of welfare schemes have been made; it is despite the fact that we have given higher devolution of Central Taxes to the States. देश के खजाने में से राज्यों को ज्यादा पैसे देने के बाद भी देश की तरक्की में, गरीबों को सहूलियतें देने में यह सरकार ज्यादा कामयाब हुई है, वे नहीं, जो उस खजाने को अपने पास रख गए थे, लूटते थे और इलेक्शन टाइम में बड़े-बड़े वादे करके लूट कर ले जाते थे।

(1455/RAJ/KMR)

सर, मैं ज्यादा न कहते हुए दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। इन पांच सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी देन क्या है? एक, मैं यह कहना चाहूंगी कि बहुत बातें होती हैं कि आपने जन-धन योजना के तहत 23 करोड़ बैंक के खाते खुलवाये, लेकिन क्या यह शर्म की बात नहीं है कि 70 साल के बाद भी हमारे देश में करोड़ों गरीबों के बैंक के खाते तक नहीं थे? यही कारण था कि इनका एक पुराने प्रधान मंत्री बोलते थे कि जब दिल्ली से दस रुपये चलते हैं तो लाभार्थी तक दस पैसे पहुंचते हैं। वे बीच में खाये जाते थे, लेकिन इन्होंने उसको रोकने 70 सालों में कुछ नहीं किया। मोदी जी ने पहला काम किया कि सबका बैंक का खाता खोला ताकि यहां से दस पैसा चले या हजार रुपये चले, वह लाभार्थी के पास पहुंचे, यह सबसे बड़ी देन थी। जिससे हजारों-करोड़ों रुपये के घपले इस सरकार ने रोके हैं।

सर, बहुत सारी योजनाएं हैं। एक रुपये की सुरक्षा बीमा योजना हो या 90 पैसे प्रति दिन की बीमा सुरक्षा योजना हो, मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना' एक ऐसी योजना है, जो इस देश के गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज मैं उस राज्य से चुन कर आई हूँ, जिस राज्य से एक ट्रेन चलती है, जिसका नाम 'कैंसर एक्सप्रेस' है। हमारे इस एरिया में इतना कैंसर है कि ट्रेन भर के लोग यहां से बीकानेर इलाज कराने के लिए जाते थे। कैंसर कैसी बीमारी है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने प्रिय बंधुओं को बचाने के लिए इंसान सब कुछ बेच सकता है। गरीब के घर में जब कोई भयानक बीमारी आती है तो वह सबसे पहले अपने जेवर बेचता है। उसके बाद वह अपना घर बेचता है। उसके बाद वह अपनी जमीन तक बेच देता है और सब कुछ गिरवी रख कर कर्जा लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका प्रिय बंधु बच जाए। इंसान की ऐसी भावना होती है कि वह अपने प्रिय जनों को बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। आज हमारे देश में ऐसे कितने गरीब हैं, जिन्होंने अपने बंधुओं को बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, सब कुछ लुटा लिया है। 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना' ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से पांच लाख रुपये एक परिवार को, तकरीबन 50

करोड़ लोगों को, देश की आधी आबादी को भयानक बीमारियों से बचने के लिए देने की जो योजना बनायी है, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जहां प्रधान मंत्री जी यह पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे राज्य भी हैं, जो इन सहूलियतों से गरीबों को वंचित रख रहे हैं। मेरा राज्य पंजाब है। वहां कांग्रेस की सरकार है। आज वह यहां नहीं बैठे हैं, नहीं तो मैं राहुल गांधी से पूछती कि बताइए तो सही कि दो-ढाई महीने में जहां ग्यारह लाख लोगों ने गोल्डन कार्ड लेकर अपनी जानें बचा ली हैं, पांच लाख रुपये का फायदा उठाया है, क्या कारण है कि पंजाब के एक भी बंदे को, एक भी गरीब भाई-बहन को आज तक पंजाब सरकार ने मोदी साहब का गोल्डन कार्ड नहीं दिया है? उसका क्या कारण है? कारण यही है कि कहीं उनको क्रेडिट न मिल जाए और इनकी सरकार न खिसक जाए, यही वह करते आ रहे हैं।

सर, मैं किसानों की बहुत अहम बात करना चाहूंगी। जितना यह कांग्रेस सरकार बोलती और करती आई है, किसानों के हालात क्या हैं? ...(व्यवधान) आप वहां से बोल रही हैं, मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) देखिए, यहां एक प्रधान मंत्री के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पंजाब में जा कर इतना ढोल बजाया कि पंजाब के किसान का सब कर्जा माफ कर दिया जाए। काश ! मैं व्हाट्सप्प खोल कर आपको सुना सकती। वैसे मेरे पास उनके और उनके मुख्य मंत्री के शब्द जरूर हैं। यह पंजाबी में है, मैं उसे ट्रांसलेट भी कर दूंगी। कइयां दे नाल कइयां दे लोण लेते होणगे कोपरेटिव बैंकों तों। कइयों ने नेशनल बैंक तो कई आढ़तियों तों। कई ऐसे किसान होंगे, वे कहते हैं, मुख्य मंत्री के दावेदार, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कई ऐसे गरीब किसान होंगे, जिन्होंने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया है, कॉपरेटिव बैंकों से कर्जा लिया है, आढ़तियों से कर्जा लिया है। हुण इह तिननों जेहड़े तुहाडे कर्जे ने, असी दिआंगे, पंजाब सरकार देवेगी, तुहानू कोई कर्जा देण दी लोढ़ नहीं हुण, तुहाडा कर्जा साडा कर्जा है।

(1500/SNT/IND)

मतलब आपको कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपका कर्जा नहीं है, यह मेरा कर्जा है। कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो जनवरी, 2017 में लिखा है कि हर तरह का कर्जा कांग्रेस सरकार माफ करेगी। कर्जा माफ करने का कांग्रेस द्वारा सारे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। कर्जा माफ करने के लिए पंजाब के हर घर में एक फार्म भरवाया गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कितना कर्जा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह की फोटो समेत कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इस किसान का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। इसका जो फोटो ब्यॉय बना, जो फेस आफ दि लोन वेवर फार्म बुध सिंह बना, जिसके घर से बहुत धूम-धाम से यह फार्म लांच किया गया कि सभी किसानों का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। उस बेचारे बुध सिंह किसान का बयान तो पढ़िए। न्यूज पेपर में दिए गए बयान की चंद लाइनें आपको पढ़कर सुनाती हूं। “Budh Singh was asked to sign a form. Having done so, he was handed over a receipt. यह रसीद जो मैं आपको दिखा रही थी। “Amid the clicking of cameras, Captain Amarinder Singh went on to assure the farmer that he would be the first in Punjab whose loan would be waived if Congress was voted into power.” अब डेढ़ साल क्या, दो साल का समय निकल गया है। “Fifteen months down the line, Budh Singh is still waiting for his loan. ...(*Interruptions*) When Punjab Government held the function at Mansa to launch the scheme, I thought I would be invited there.” उसने सोचा मेरे क्षेत्र में आए हूँ और कर्जा माफी का ढिंढोरा पीटा है। उसने सोचा मुझे तो जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं तो फेस ऑफ दि लोन वेवर हूँ। “After all, it had all begun from my house. Also, I was promised that I would be the first to benefit from the scheme. But nothing of the sort happened. I only hope my dream of being debt free will not remain shattered.” यह बात वह बेचारा डेढ़ साल के बाद बोल रहा है।

“Buoyed by Captain Amarinder Singh’s assurance, I and my wife, Sarabjit Kaur braved the morning chill to cast our votes for the Congress”, recalls the downcast Budh Singh wondering if he had been taken for a ride. यही राइड है, जो कांग्रेस पार्टी 70 सालों से देश के गरीब, देश के किसान और देश के नौजवानों को दे रही है और आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मॉडल...*(Not recorded)* बोलकर सरकार बनाती है और लोगों को भूल जाती है। यही जुमला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिया। ये कहते थे कि इन राज्यों में सरकार बनेगी, तो दस दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। पंजाब में दो साल निकल गए हैं और इन राज्यों में दो महीने से आपकी सरकार है। इसी तरह से 70 महीने का समय भी निकल जाएगा।

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Thank you, Minister. Please try to conclude.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, बेरोजगारी की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नम्बर-2 पर लिखा था कि हर “घर को नौकरी”। हर घर में नौकरी देने के लिए पंजाब के एक-एक घर से फार्म भरवाया। साठ लाख परिवारों में कहा कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी। दो महीने होने को आए हैं। एक महीने में एक लाख लोगों को नौकरी मिलनी थी, अब दो साल में मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बिट्टू के भाई को छोड़कर, जिसे डीएसपी की नौकरी मिली है, उसके अलावा किसी और को कोई भी नौकरी नहीं मिली।...*(व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Madam, please wind up.

... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude.

... *(Interruptions)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, नौकरी की बात छोड़िए, पंजाब सरकार के मुलाजिमों का खजाना भरने के लिए इन्होंने क्या किया? ...*(व्यवधान)* कर्नाटक में भी इन्होंने यही किया। पंजाब में

इन्हें दो साल हो गए, कर्नाटक में एक साल हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दो महीने हो गए हैं। राहुल गांधी जी यहां आइए और बताइए कि पंजाब में जो वायदा किया था, वह तो पूरा कर दीजिए।

(1505/PC/GM)

HON. CHAIRPERSON (DR. P. VENUGOPAL): Minister, address to the Chair.

...(Interruptions) Please conclude now.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): It is only because of your ... (Not recorded) and *jumlebaazi*. पंजाब की जुमलेबाज़ी से इतना जोश आया कि बाकी देश में भी ये वही बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) कांग्रेस की इस ... (Not recorded) राजनीति से देश की जनता बचकर रहे। ... (व्यवधान) सर, पहली बार देश में हुआ होगा कि किसी सरकार ने, जैसे हमारी सरकार ने सेवेंथ पे-कमीशन लागू किया। ... (व्यवधान) लेकिन इनकी कांग्रेस सरकार ने पे-कमीशन तो क्या लागू करना, पंजाब में बल्कि हर मुलाज़िम के हर महीने 200 रुपये काटने का बजट में ऐलान किया, क्योंकि देश के खजाने में मुलाज़िम के पैसे भरने हैं। ... (व्यवधान) न डी.ए. मिलता है और न प्रोविडेंट फंड मिलता है। ... (व्यवधान) टीचर्स को बोला गया कि तुम्हें रेग्युलर होना है, तो चालीस हजार की तनख्वाह छोड़ दो, हम तुमको दस हजार का रेग्युलर कर देते हैं। ... (व्यवधान) आज टीचर्स भी धरने पर हैं, मुलाज़िम भी धरने पर हैं, नौजवान भी धरने पर हैं। ... (व्यवधान) आज 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ... (व्यवधान) इनकी सरकार को बने 700 दिन नहीं हुए, 700 किसानों ने दो सालों में आत्महत्या कर ली। ... (व्यवधान) ये कहते थे कि हम आत्महत्या करने वाले हर किसान को दस लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देंगे। ... (व्यवधान) 700 किसानों को तो आप आत्महत्या करने के लिए ढकेल रहे हो। ... (व्यवधान) रोज़ एक किसान आत्महत्या कर रहा है।

...(व्यवधान) लेकिन एक भी किसान को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। ...(व्यवधान) कर्जा तो क्या माफ करना था। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : 90 हजार करोड़ का कर्जा माफ करने की बात उन्होंने बोली थी।

...(व्यवधान) आज किसी को 90 रुपये के चैक मिलते हैं, किसी को 15 रुपये के चैक मिलते हैं।

...(व्यवधान) सर, सारे देश से यह इनका बिलकुल बेतुका ... (Not recorded) है। ...(व्यवधान)

सर, आखिर में मैं राहुल गांधी के ग्रोथ और जॉब मॉडल के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी।
 ...(व्यवधान) चलो मैं माफी मांगती हूँ कि उनका नाम ले लिया। ...(व्यवधान) हालांकि, मैं चाहती थी कि इनके ग्रोथ मॉडल के बारे में बात न करूं। ...(व्यवधान) सर, पिछली सरकार में एक इंसान था, जिसके पास इतनी पॉवर, शक्ति और ताकत थी, कि उनकी कैबिनेट और प्रधान मंत्री कोई फैसला ले, तो वह कागज फाड़कर फेंकने की ताकत रखता था। ...(व्यवधान) मैं उस महकमे से आती हूँ, जहां किसानों और नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं हैं। ...(व्यवधान) मैं उस सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इनमें से कुछ योजनाएं बनाईं। ...(व्यवधान) मैं एक योजना के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। ...(व्यवधान) एक मेगा फूड पार्क लगा था, एक बहुत ही शक्तिशाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में, जो पांच सालों से देश से पार्लियामेंट में भूकंप लाने की बात करते हैं। ...(व्यवधान) यहां पर कोई भूकंप तो आया नहीं, लेकिन उनके ग्रोथ मॉडल की बात सुनकर शायद उनकी पार्टी में भूकंप आ जाए। ...(व्यवधान)

सर, आपको हैरानी होगी कि वर्ष 2010 में एक मेगा फूड पार्क उनके क्षेत्र में बनना था।
 ...(व्यवधान) दो सालों में मेगा फूड पार्क बनकर खत्म हो जाता है, जिससे लाखों किसानों का फायदा होता है, क्योंकि मेगा फूड पार्क का रॉ-मैटीरियल किसानों की फसल होती है। ...(व्यवधान) हजारों की गिनती में रोजगार मिलता है। ...(व्यवधान) लेकिन 2010 निकल गया, 2011 निकल गया, 2012 निकल गया और 2013 भी निकल गया। ...(व्यवधान) 2013 में - जिसे मेगा फूड पार्क लगाना था- मुझे उसकी चिट्ठी अपने रिकॉर्ड में मिली। ...(व्यवधान) वह कहता है कि जब तक मुझे सस्ते रेट

पर गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर मैं सब्सिडाइज़्ड रेट्स पर गैस बेस्ड पावर प्लांट बनाना चाहता हूं, जब मुझे वह नहीं मिलेगा तो मैं मेगा फूड पार्क लगाना ही नहीं चाहता हूं। ... (व्यवधान) यह चिट्ठी 2013 में मिली। ... (व्यवधान) लेकिन 2014 के इलेक्शंस से पहले वहां पर लोगों को गुमराह कर के और किसानों को गुमराह करने के लिए वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा भूकंप लाए कि शिलान्यास कर दिया, कि यहां पर मेगा फूड पार्क बन रहा है। ... (व्यवधान) दिसंबर, 2013 में उस मेगा फूड पार्क का शिलान्यास हुआ, जिसका चार सालों में एक ईंटा भी नहीं रखा गया था और जो प्रमोटर ने ही विदड़ा कर लिया था। ... (व्यवधान) यह तो इनका ग्रोथ मॉडल है। ... (व्यवधान) इलैक्शंस से पहले ... (Not recorded) वादे करो, ... (Not recorded) बातें करो और इलैक्शन के बाद सारा कुछ भूल जाओ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, सिर्फ दो मिनट दीजिए। मैं कंकलूड कर रही हूं। हर तरह से बहुत कुछ बोला गया है। ... (व्यवधान) मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूं, क्योंकि यह बात मैं अपनी कम्युनिटी की करना चाहती हूं। ... (व्यवधान) ये कहते हैं माइनोंरिटीज़ इनसिक्वोर हैं, फलां हैं-ढिमका हैं। ... (व्यवधान) जितना अत्याचार इस सरकार ने माइनोंरिटीज़ पर किया है, इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, वह आप हमसे पूछिए। ... (व्यवधान) यह वह सिख कौम है, जिसने देश की आजादी के लिए सब से ज़्यादा खून बहाया। ... (व्यवधान) सब से ज़्यादा लड़ाई लड़ी, सब से ज़्यादा जानें दीं और सब से ज़्यादा जेलें काटीं। ... (व्यवधान) लेकिन एक परिवार ने और एक पार्टी ने इस कौम को खत्म करने के लिए हमारे धार्मिक स्थानों पर टैंको-तोपों के साथ हमले किए, दिन-दहाड़े कत्ल-ए-आम किए। ... (व्यवधान) इस सरकार ने और इस सरकार की लीडरशिप ने कातिलों को और कत्ल-ए-आम करवाने वालों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 34 सालों तक हमें इंसाफ नहीं लेने दिया। ... (व्यवधान)

(1510/SPS/RK)

सर, आज उनको राज्य का मुख्य मंत्री बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्रियां बनाई जा रही हैं और उनको बचाने के लिए हरेक इंस्टीट्यूशन के मिस-यूज की बात करते हैं। मेरे से पूछिए कि पुलिस और सी.बी.आई. का कितना मिस-यूज इन्होंने सिखों के कातिलों को बचाने के लिए किया। आज मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करती हूं, 34 साल के बाद हजारों सिखों के कत्ले आम के दोषियों को जेल में डाला। सज्जन कुमार जैसे मगरमच्छ जेल में गए हैं, वह हमारी सरकार की देन है, जो इंसाफ देना चाहती है। सर, इसके बाद वे जो दूसरे मगरमच्छ हैं, जिनको ये बचाते रहे हैं, जिनको ये मुख्य मंत्री बना रहे हैं। इस देश में माइनोरिटीज़ सेफ रहना चाहती हैं तो उस सरकार का साथ दो, जो आपका साथ देंगे। वे नहीं जो बेइंसाफी के नाम पर इंसाफ बोलेंगे।

सर, आज करतारपुर कॉरीडोर की बात मैं जरूर करना चाहूंगी। सत्तर साल से सिखों की आस्था, सुबह से शाम से इसके लिए पूजा-प्रार्थना की कि हम दर्शन कर सकें। यह कॉरीडोर दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। सत्तर साल में किसने रोका इनको देने के लिए? सिख प्रधान मंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने सिखों के लिए क्या दिया? क्या करके दिया कांग्रेस ने? सिर्फ बातें दी हैं, जुमले दिए हैं और लोगों को गुमराह करके, धोखा देकर, ... (Not recorded) बोलकर, जी हां। Today, a *chowkidar* is the Prime Minister but I would like to tell the Congress Party that he is the *chowkidar* of the country's resources, the country's wealth and health and the *chowkidar* of this country's pride, prestige and sovereignty. ये चौकीदार हैं, जो लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखते हैं और जो ... (Not recorded) जिन्होंने 70 सालों से लूटा है, उन लुटेरों को इस चौकीदार का आज भय है, डर है और इसीलिए ये सारा शोर मच रहा है। मचाइये आप अपना शोर, चौकीदार करेंगे अपनी चौकीदारी और देश की जनता देखेगी कि किस सरकार ने काम किया और किस सरकार ने सिर्फ चोरी और लूटखोरी की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

*SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):

*Laid on the Table

1512 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. Sir, I rise to speak on what I hope to be the last ever Address of the Hon. President scripted by this Modi-Shah regime, a regime which mistakes arrogance for intellect. I am saying this because arrogance, Sir, diminishes wisdom and it ultimately becomes the camouflage of insecurity in which not only the Prime Minister and his Cabinet but also the entire BJP seems to be passing through.

Sir, after losing successive by-elections and the recently concluded State elections, the Interim Budget has shown this regime's desperation to calm the farmers, the middle-class, traders, MSMEs, informal sector and real estate sector who have been badly affected by twin shocks of demonetisation and the poorly-structured and poorly-implemented GST, as well as by the rise in unemployment to a forty-year high. But instead of making long-lasting structural changes, which would lead to their sustainable long-term performance, in other words performing life-saving surgery, the Modi-Shah regime has merely handed out band-aids, and hence, I name this sham of a Budget the Band-Aid Budget, an illegitimate Budget for which this regime has no accountability to deliver.

Sir, I would like to share a saying with my fellow Indians and fellow MPs.

“Fool me once, shame on you.

Fool me twice, shame on me.”

The Modi regime's record of fulfilling their 2014 poll promises is there for everyone to see. They not only fooled me but they also fooled the entire State

of Andhra Pradesh with the promise of giving Special Category Status for ten years. Indeed, they fooled a lot of people who placed their hopes on their words and promises. This 2019 Band-Aid Budget is another set of promises for which they have absolutely no accountability. I do not believe the intent to keep their promises. I will not be fooled twice. My fellow Indians, will you be fooled twice?
(1515/PS/MM)

Sir, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu and the TDP walked out of the NDA and the Government following being totally ignored in the Budget 2018-19. If the Modi regime was able to ignore us while we were partners, we are not naïve enough to expect them to suddenly decide to honour their promises and to deliver on our rights; the twenty-nine items contained in the AP Reorganisation Act as well as the assurances given by the then Prime Minister Shri Manmohan Singh, most importantly, granting AP a Special Category Status with all the benefits of other Special Category Status States.

Mr. Prime Minister, in case you have forgotten, let me remind you once again that in Guntur, Nellore and in front of Lord Balaji in Tirupati, you had promised to build us a capital bigger and better than Delhi. You had promised that if NDA comes to power, you will give Andhra Pradesh a Special Category Status, not for five years, but for ten years.

Sir, I gave a complete account as to what is pending to Andhra Pradesh against our rights as given to us by the AP Reorganisation Act and the assurances given by the then Prime Minister during my one-hour speech opening the No-Confidence Motion during the last Monsoon Session.

Mr. Prime Minister, not only have you betrayed the people of AP, but you also did not bother to respond to a single question that I posed during the No-Confidence Motion. Despite the assurances that you gave to calm us down, during your speech you chose to stick to your pre-written text completely ignoring Andhra Pradesh once again.

Mr. Prime Minister, I can imagine you thinking that your stakes in AP are anyway low, as the BJP vote share is hardly measurable in AP. You may also be thinking that 25 MPs from AP are hardly just about five per cent of the Lok Sabha. But, you have underestimated Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. He has seen many leaders and Governments come and go during his 40-year political career. He has been a key player in many of the national formations, including the National Front, the United Front- I and II, the NDA-I and till recently, was part of the NDA-II. You have underestimated his credibility across the political spectrum and the ripples that it would create across the country among the entire opposition.

You underestimated the power of the Indian democracy. You did not realise that even a State with just five per cent of the population and just five per cent of the Lok Sabha seats, can catalyse a national response to your autocratic ways. The fight for APs rights has grown into a fight to 'Save Democracy'. As a united Opposition, we have been able to expose how this Modi-Shah Regime is making a New India as mentioned by the hon. President in his Address. A New India, indeed! But, a New India in your own image: an autocratic, divisive, invasive, suppressive, coercive, vindictive, Machiavellian, and Fascist regime.

1518 hours

(Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

Sir, there are claims and counterclaims between the Government of Andhra Pradesh, the Government of India, the BJP and the TDP. So, to clear the air, I demand that the Government of India should immediately release a 'White Paper' on what it has done with regard to the implementation of AP Reorganisation Act and assurances given by the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh Ji, in the Rajya Sabha.

Sir, there have been *dharnas, rasta rokos, chakka jaams*, rallies, and many more by farmers in Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and many other States for the last four years. The Modi-Shah regime did not care. The BJP bit the dust in every by-election and also the recently concluded State elections.

Now, instead of waiving off their loans, the Government in the Budget announced that it would give Rs. 17 a day. How does Rs. 6000 a year help a farmer who is in a debt trap? It is only a band-aid for a farmer who is on a life-support. Will it help even one farmer who is in a debt-trap and is contemplating suicide?

Furthermore, they have given Rs. 4 lakh crore write-offs for economic offenders and fugitives, but could not show the same large heart to give just Rs. 1 lakh crore to bring farmers out of financial distress. This clearly shows towards whom this regime is tilting.

Sir, our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu has doubled the farmers' income in Andhra Pradesh in the last four years. The

agriculture growth rate is 11 per cent against the national average of just two per cent. If one looks at the pace of present agricultural growth in the country, which is around two per cent and if you add inflation to that, it will take nearly a half century, not by 2022, to double the farmers' income in India.

(1520/RC/SJN)

One of the aspects which helps in doubling the farmers' income is the recommendation of Dr. M.S. Swaminathan which says that farmers should be given A2 component which is paid out costs such as seed, fertilizer, manure, machine labour, interest on working capital rent, paid for land, etc. plus FL component which is family labour and also the C2 component which includes the imputed rental value of owned land and interest on capital. But, this Government has given just A2+FL! If you give C2, farmer will get MSP as high as 95 per cent more than present MSP, thereby doubling their income. But instead of giving farmers the C2 component, which will make them sustainable, you have given them just Rs. 6,000 an year, or Rs. 17 a day which is actually meaningless for a farmer who is contemplating suicide.

The PM boasted that he would create two crore jobs a year *i.e.*, 10 crore jobs in five years. We are now in the fifth year, leave alone creating 10 crore jobs in five years, crores of people have lost their jobs and livelihood due to demonetization and faulty implementation of GST. There are as many as five lakh Government jobs lying vacant in various departments of Government of India.

Sir, NSSO's latest job survey released a few days ago has compared unemployment figures for 2017-18 with its past surveys since 1972-73. The Report indicates that the country's unemployment rate stood at 40-year high at 6.1 per cent. Now, NITI Aayog is trying hard to push this Report under the carpet because of upcoming elections and to cover up the failure of the Modi-Shah Regime.

Sir, I need a lot more time than what you will allow for me to go deep into the subject of misusing and the weakening of democratic institutions that India has painstakingly built over decades. Many Members have already talked about how institutions like Parliament, the Supreme Court, the Election Commission, the RBI, the CVC, Office of the Governor, CBI, ED, to name a few, are being weakened, or being used as weapons to attack opponents, not to mention the attacks and control of media by this Modi-Shah Regime. I will refrain from being repetitive here since so many people have already spoken about it.

Sir, I would like speak about cultural nationalism which is a very important topic today in India. The Modi-Shah Regime is openly embarking on a path of cultural nationalism and wishes to define a single national identity and culture for India. They are trying to give a very narrow definition of what it means to be an Indian.

Sir, India is not just a Country, and not even just a subcontinent. India is a Civilization that is more than 5,000 years old. In order to understand how our civilization evolved, we have to go back even further. We need to start with a little geological history in order to understand where we came from, how we

interacted and mingled with others who showed up, and how we evolved. Being Indian, did not start in 1947, but evolved over more than 5,000 years not by making everyone the same, but by celebrating our differences, and living in harmony, at least most of the time.

During the continental drift, the Indian Sub-Continent separated from Africa, drifted across the Indian Ocean, and came crashing into Asia, forming the mighty Himalayas, the Hindu Kush and surrounding mountain ranges. These mountain ranges acted as a barrier for entry for millions of years.

As people learned to cross these barriers, migration into India began, and India became the first melting pot in the world. There are only three pure races in this world. Negroid who are the people of Africa and the aboriginals in other parts of the world; the Caucasoid who are people mostly from Europe; and the Mongoloid who are from the far East and the oriental areas of the world.

Indians are not a pure race, but a mix of two in some regions and three in others. If you mix all colours of the rainbow, what do you get? You get brown; and that is what we are. We are a mixed race of brown people.

(1525/SNB/BKS)

Sir, throughout the ages large groups of people have come to India but no group has ever left India *en masse*. I have never heard of the term 'Indian refugees'. People have never had to flee India due to religious persecution in the history of our civilization. They stayed and they continued to mingle and continued to integrate. Hinduism existed even before the concept of religion existed with roots tracing back to pre-historic times over 5000 years ago. It is a

fusion or synthesis of various Indian cultures and traditions. The Hindu synthesis started to develop into a formal religion between 500 BC and 300 BC after the Vedic period during which time Buddhism and Jainism were also founded. Judaism first came to India around 500 BC; Christianity came in 50 AD; Islam came in the early 7th century; Sikhism was founded in India in the late 15th century. This clearly indicates that India has always been prepared to integrate itself with other religions and cultures.

Sir, Central Asians, Greeks, Persians, Romans, Arabs, Mongolians, Chinese, South East Asians and later the European sea powers including the British, French, Portuguese and Dutch all came to India. Our language, our arts and literature, our architecture, our food, our fashion, maths, science, astronomy, even spirituality, in so many areas we have collaborated and mutually benefited with all these cultures. We have been the home for persecuted communities like the Jews, Parsis, Muslims and the Tibetan Buddhists. Being the most diverse country on Earth we are tolerant to each other's ideas, ideals and faith, unless and until some religious or political patriarchic groups intervened to design the differences into conflicts.

Being Indian is not about region, language, religion, caste, being Right or Left, being LGBTQ or not, whether you eat beef or eat pork or you are a vegetarian or vegan. Being Indian is about having the freedom to be all of those, or some, or none, at your own free will. Being Indian is celebrating our continually evolving diversity and valuing our freedom and rights above all else. Indians are not about identity but Indians are about diversity. That is the Indian way.

Sir, I would like to paraphrase Martin Niemoller, a German Protestant Christian, who spent seven years in a Nazi concentration camp for opposing the religious policies of Adolf Hitler. I have taken the liberty of changing the victims to better suit our current Indian context. I inserted Muslims and Christians in place of Trade Unions and Jews.

“First they came for the Communists, and I did not speak out – because I was not a Communist. Then they came for the Muslims, and I did not speak out – because I was not a Muslim. Then they came for the Christians, and I did not speak out – because I was not a Christian. Then they came for me – and there was no one left to speak for me.”

Sir, polarisation strategy is about making people believe that it is not going to happen to them; it will happen only to the `real culprits' or to their rivals. Hence, “let them suffer and be punished” is the mindset that they try to create. This message is for the Majority, who may be influenced by these polarisation tactics. I strongly feel that today it may be the `Others', but tomorrow it will be `you'. There is also a report from the Director of the National Intelligence of the United States saying that there is every possibility of a communal violence before the Indian General Elections this year. This is a direct indictment on the Modi-Shah regime's election strategy of polarisation.

India is the fastest growing internet market in the world. We are the largest internet data users in the world. We are using more data than the US and China combined. More and more essential services are moving online. At this stage it is important for us to understand what our rights are and to what extent the Modi-

Shah regime is protecting or violating our right to privacy. Even Bill Gates has been saying that there has to be a balance between technological innovation and privacy. How can we use data to gain insights into education or health while still protecting people's privacy?

(1530/NKL/GG)

How much technology can we use to improve our lives, and to improve the transparency and efficiency in delivery of services by the Government, and where is the *Laxman Rekha* that stops infringing on our privacy?

HON. CHAIRPERSON (SHRI KALRAJ MISHRA): Please take your seat now.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the Modi-Shah Regime passed an Order on December 20th, 2018, authorising 10 Central Government Agencies to monitor, intercept, and decrypt any information generated, transmitted, received, or stored in any computer source, by any agency, without any approval from any authority of the Government of India. ...(*Interruptions*)

Sir, earlier, the approval of the Joint Secretary was to be taken for any interception or tapping. But it has been done without proper discussion or consensus.

The above Order is a clear violation of privacy, and is a clear-cut example of the rise of the surveillance State. This is against the Nine-Judge Supreme Court ruling, in the Order dated August, 2017, in the case between Puttaswamy vs. Union of India, that Right to Privacy is a Fundamental Right.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KALRAJ MISHRA): You please take your seat. You have already taken more time.

Now, Shri Mohammad Salim.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am just going to conclude.

Before concluding, I only say that there is a thin line between confidence and arrogance. That thin line is humility. The PM is feeling that he is the saviour of India and Democracy. But, with his actions over the last five years, be it relating to AP's rights, demonetisation, improper implementation of GST, and so on, the PM is proving to be a destroyer of Democracy, and not a saviour.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KALRAJ MISHRA): Now, Shri Mohammad Salim.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, in the end, I would like to quote Sardar Patel. He said:

“If your goodness is an impediment in your way, let your eyes be red with anger, and try to fight injustice with a firm hand”

This is what our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu, and the people of Andhra Pradesh are doing. The entire India will have to fight this, Sir.

Thank you very much, Sir.

(ends)

***श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):**

***Laid on the table**

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Speaker Madam, our independence was the result of efforts by thousands of patriotic freedom fighters. Babasaheb Bhim Rao Ambedkar instilled in us the value of human dignity and republic ethic. The key to India's success is its diversity. Our diversity makes us so unique. In this land we find mix of religion, language, cultures, life style. We are so different and yet so similar. Despite that, we have seen in the last four years violence against SC/ST people, incidents of atrocities, mob lynching and communal violence increasing day by day. The President didn't mention about the situation going on all over the country, did not think about the increase in number of farmers' suicides due to crop failure and debt, and didn't take any steps to provide minimum support price to farmers as per the recommendations of Swaminathan Committee Report. Due to demonetisation many have lost their job and how much black money was recovered is not mentioned.

In health sector there is need to improve the doctor-population ratio for providing better medical facilities in the country specially in rural India, where the people suffer a lot. Due to hasty implementation of GST there is an adverse effect on economy, on micro, small and medium enterprises. Each citizen of India is a nation builder and custodian of India's well being and the legacy we will pass to the coming generations. For that, we have to ensure compulsory

*Laid on the Table

and uniform education across the country. Implementation of Kothari Committee and Muchkund Dubey Committee is needed. Government should bring 33% representation for women in Lok Sabha and State Legislature Assemblies with provision for women from Scheduled castes and Scheduled Tribes.

(ends)

*SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD):

*Laid on the Table

***श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी):**

***Laid on the table**

***श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच):**

***Laid on the table**

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR):

*Laid on the Table

*SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):

*Laid on the Table

1532 बजे

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): सभापति महोदय, 31 जनवरी को संसद के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उसके ऊपर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव है। धन्यवाद तो सत्ता पक्ष के लोग 115 पैरा का जो भाषण था, उसमें 115 बार तालियां ठोक कर करते रहे। कभी महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में ऐसे चुनावी मुद्दे भी नहीं आते थे और चुनावी झलकियां भी नहीं देखने को मिलती थीं। वे ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, वह तमाम उसमें समावेश किया गया, जबकि वादा था कि विकास में सबको समावेश करेंगे, समावेशी विकास होगा। आर्थिक स्थिति बहुत ही खतरनाक है। इनका वादा था कि अच्छे दिन ले आएं। मैडम हरसिमरत कौर जो फूड प्रोसेसिंग की मंत्री हैं, उनके भाषण से यह लग रहा था कि पंजाब में उनके जो भी अच्छे दिन थे, वे पांच साल में निकल गए और बुरे दिन हो गए। उनके भाषण में यह झलक रहा था। बाकी देश की भी स्थिति ऐसी ही है। आप अगर देखें तो कंसनट्रेशन ऑफ वैल्थ एक प्रतिशत लोगों के पास 12 आना संपदा जमा हो रही है, जो इनक्रीमेंटल है। पिछले एक-दो तीन साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद उनकी जो संपत्ति है, हमारी जो भी इनक्रीमेंटल इनकम है, उसका 12 आना एक प्रतिशत की तरफ जा रहा है। आज नौ ऐसे हाऊस हैं, जिनके पास हमारे देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा संपदा कंसन्ट्रेटिड है। मैं तमिल में नहीं बोलूंगा, चूंकि तमिल मुझे आती नहीं है, लेकिन ग्रेट त्रिवल्लुवर का जो टू कलर है, उसकी अंग्रेजी प्रति का 385 नंबर वाला जो है, अंग्रेजी में यह है कि For the king, attention to his kingdom's wealth, to fruit, he must guard its source and its produce, even handedly distribute. चौकीदार वे कहे थे, पहरा देना पड़ेगा, उसमें फेल हुए, इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है और दूसरी तरफ वह ईवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, आप देखो कि कितनी अनईवन सोसाइटी बन रही है और कितनी इनईक्वैलिटी और विषमता बढ़ रही है। यह हमारे लिए बहुत घातक होगा और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आम जनता है, जो मेहनत कर रही है, खेत और खलिहान में, खदान में, जो किसान और मजदूर हैं, जिनको अपने अनाज की कीमत नहीं मिल रही है।

(1535/KN/SRG)

आप देखो कि विज्ञापित हो रहे हैं। हमने सब के लिए अच्छा कर दिया, लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लाखों की तादाद में जब पड़ाव लगा रहे हैं, अभी 8 और 9 जनवरी को पूरे देश के 20 करोड़ मजदूरों और किसानों ने इकट्ठा होकर स्ट्राइक की। किस खुशी में, चूँकि उनको जो हक मिलना था, उस हक को छीना जा रहा है। एक तरफ हक को छीना जा रहा है और दूसरी तरफ भीख देने का वायदा किया जा रहा है। वामपंथी सदस्य होने के नाते हम यह चाहते हैं कि हमारा जो बुनियादी मूलभूत अधिकार है, उसका संरक्षण हो। हमें अपने हक मिलें। आज बेरोज़गारी की क्या स्थिति है? यह सरकार यह वायदा करके आई थी कि साल में दो करोड़ बेरोज़गारों को काम देंगे। आपके वायदे का क्या हुआ? आँकड़े सभी लोगों ने रख दिए। अभी वे कहते हैं कि पकोड़े तलो। खड़गे जी ने बोलते हुए कहा कि बाकी लोगों को तो छोड़ो, जो ओबीसी, एससी-एसटी के पद रिक्त हैं, हम अक्सर पिछले 10 साल पहले भी देखते थे, 20-25 साल पहले भी देखते थे कि उन रिक्त पदों को फुलफिल करने के लिए स्पेशल ड्राइव होती थी। आज इस सरकार के दौर में कोई स्पेशल ड्राइव एससी-एसटी, ओबीसी के रिक्त पदों को भरने के लिए नहीं हो रही है। चुनाव के वक्त आकर अभिभाषण में वायदा कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी के बारे में एक शब्द नहीं बोले। आँकड़े छिपा रहे हैं। कहाँ तक आप छिपाएँगे। एक हमारा जो एनएसएसओ का डेटा आता है, उसको आपने प्रकाशन नहीं करने दिया। पहले भी कभी-कभी ऐसा होता था। दरिद्र सीमा के नीचे कौन लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे कौन लोग हैं, कितना उनका आँकड़ा है, जीडीपी का क्या आँकड़ा है? उसको सरकार हमेशा सर्च करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम लोगों ने माँग की थी, तब नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन स्टेच्युटॉरी बॉडी बनी थी। आज 7 सदस्यों के अंदर क्या है? इस्तीफा दे दिया, एक्टिंग चेयरमैन तक ने इस्तीफा दे दिया। दो लोग रह गए। चूँकि उनको रिपोर्ट दाखिल करने नहीं दी जा रही है। आप किसको छिपाना चाह रहे हैं? आरटीआई स्टेटिस्टिक्स के आधार पर, संख्या तत्व के आधार पर खत्म किया। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ। मुझे यह गौरव है, प्रो. प्रशांत चन्द्र महालनोबिस, स्टेटिस्टियन, साइंटिस्ट, वे जब मंत्री बने थे तब हमारे देश के यह स्टेटिस्टिक्स के

आँकड़े इकट्ठा करना, उसको कोलेट करना और उस तत्व को प्रकाशित करना, उसके बारे में प्रोफेशनलिज्म, एक साइंटिफिक डेटा सिस्टम बनाया गया था और पूरे विश्व के अंदर हमारा डेटा सिस्टम स्टेटिस्टिक्स का एक अपना महत्व था, मर्यादा थी। यह सरकार उसको खत्म कर चुकी है। जैसे आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, उसी आँकड़े के आधार पर योजना बनती थी, आप वहाँ नीति आयोग के नाम पर ले आए। इकोनॉमिक्स सर्वे आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। पूरे साल के बजट का भाषण दे सकते हैं, अभिभाषण में पूरे पाँच साल का ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन आप आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। पिछले साल भी आपने एनएसएसओ की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी। यहाँ तक कि शायद संविधान की मान्यता के अनुसार हमारी जो संसदीय परम्परा है उसको भी तोड़ा जा रहा है। प्लीज आपका विभाग है, बोलिये।

THE MINISTER OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI D.V.

SADANANDA GOWDA): Practically, the Government thought that we should come out with Periodic Labour Force Survey as far as urban area is concerned on quarterly basis and for rural area on yearly basis. We started right from July 2017 up to December 2018. We have to collect the data quarterly and we have to come out with the report. For the last two quarters i.e. July 2018 to December 2018 and from October 2018 to December 2018, we are collecting the data and we are processing it. We have not come out with any report. That is a fake report. ...(*Interruptions*). Depending upon the fake report and arguing on the Floor of the House is not fair. ...(*Interruptions*). It is the responsibility of the Government...(*Interruptions*). National Statistical Commission is an autonomous institution. Of course, they are here to guide us how to do the surveys, the formalities and issue the guidelines. Ultimately, the collection of

data and bringing out the report is the responsibility of the Government. We are not hiding anything. We are collecting the data. The process is going on. But simply something has come out in the newspaper and based on that arguing here is not proper.

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र) : प्लीज टेक योर सीट। आप अपनी बात बोलिए।

(1540/CS/RP)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : इसे बोलते हैं the cat is out of the bag. हमने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं बोला था कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। एनएसएसओ की रिपोर्ट के बारे में मैंने नहीं बोला।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आप अपनी बात बोलिए।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : नहीं, आपने उन्हें बोलने की इजाजत दी। जो बात मैंने कहीं नहीं, जो बात बाहर कही जा रही है, मैं उस बात पर आता कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। मैंने आंकड़ा नहीं बोला... (व्यवधान) मैंने कहा कि सर्वे नहीं निकला। वे कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने यह कहा कि एनएसएसओ की रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। उसमें आपने अचानक टिप्पणी देना क्यों शुरू कर दिया? इसे चोर की दाड़ी में तिनका बोलते हैं... (व्यवधान)

महोदय, जो वर्ष 2016-17 के लेबर स्टैटिस्टिक्स का सर्वे था, आपकी सरकार ने वह भी नहीं दिया। वर्ष 2016-17 का अभी तक कलेक्ट कर रहे हैं। आप नोटबंदी के बारे में जानते थे। हम पूछते रहते थे कि कितना रुपया गया, कितना रुपया आया, कितना रुपया सर्कुलेट हुआ, आपका यही जवाब था कि हम अभी आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप एक लाख डिजिटल विलेजेज की बात कर रहे हो और आप सरकार के अंदर डिजिटलाइज्ड नहीं हैं। आपके पास आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। पहले एक साल में ऐसा हो जाता था, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इससे पता चलता है कि सरकार आंकड़े से डर रही है। ये अकड़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े से डर रहे हैं... (व्यवधान) मैं भी बोलूँगा। अभी एक विज्ञापन आ रहा है। आंकड़ा तो नहीं आ

रहा, लेकिन विज्ञापन तो आ रहा है। विज्ञापन में क्या कह रहे हैं, - जैसा होता है, बेरोजगारी के बारे में वे विज्ञापन दे रहे हैं, मैं यह कह रहा हूँ कि ये सिर्फ विज्ञापन तक नहीं रुके हैं। अभी 'आयुष्मान भारत' के बारे में प्रधान मंत्री जी खुद से, जो अगली सदी में लाभार्थी बन सकते हैं, उन्हें भी पत्र लिख रहे हैं। यह नया तरीका हो रहा है। ऐसा हमारे यहाँ भी हो रहा है। पीएमसीएम जो बेनीफिशियरीज हैं, सिर्फ इलेक्शन का सिम्बल नहीं है, बाकी वोट दो बोलकर के, स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप आदि कुछ भी मामला होता है, तो आप उसको पत्र डाल रहे हैं। वह पत्र हमारे क्षेत्र में भी आ रहा है। पत्र क्यों डाल रहे हैं?

दो हजार करोड़ रुपया आपने 'आयुष्मान भारत' के लिए रखा है और पूरे देश में यह पत्र लिखने के लिए प्रधान मंत्री जी का खर्चा 435 करोड़ रुपये का हो रहा है। एक चौथाई पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ विज्ञापित करने के लिए नहीं, पत्र लिखने के लिए और प्रधान मंत्री का नाम घर-घर पहुँचाने के लिए हो रहा है। "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना के आंकड़े हमारे पास हैं, आपके पास नहीं है। 56 प्रतिशत "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" का जो खर्चा है, वह सिर्फ प्रधान मंत्री के विज्ञापन में चला गया। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर इसका विज्ञापन देख सकते हैं। मैं इस तरह के कई उदाहरण दे सकता हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि लोगों को फायदा पहुँचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम विज्ञापित कर रहे हैं। आपके अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी लोग हैं, क्या वे यह नहीं पूछेंगे कि आखिर, आप विज्ञापन में कह रहे हैं कि दशकों में जो नहीं हुआ, वह अभी हो रहा है। लोग अपने अशकों से देख रहे हैं कि 4.5 दशक में जितनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, आज के समय उससे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। आप उस बेरोजगार को धोखा दे रहे हो। स्कूल स्टूडेंट्स स्टाइपेंड्स के लिए लड़ रहे हैं। आईआईएम, आईआईटी के स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। आपने पहले खर्चा बढ़ाया और फिर कहा कि हम स्कॉलरशिप दे देंगे। जब आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, तो जो सबसे पिछड़ा, सबसे दुबला, सबसे गरीब जो हिस्सा है, वह विद्यार्थी इंस्टीट्यूशन से निकल आयेगा, क्योंकि वह पढ़ने के खर्च को सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप यह किसके लिए कर रहे हो? एक गीत है, एक कविता है, अभी एक गाना भी आया है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सलीम जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : 5 साल में क्या हुआ, क्या आपको मालूम है? सोचता था कि वे कितने मासूम थे, देखते-देखते क्या से क्या हो गया। आपने वादा तो यह किया था कि हम देश को बनाएंगे, आपने 56 इंच की छाती दिखाई थी और अभी आप क्या कर रहे हो?... (व्यवधान) नोटबंदी में आपने जो-जो वादा किया था, वह सब एकदम आपके मुँह के ऊपर पड़ा हुआ है। आपके मुँह पर पूरा... (Not recorded) लपेट दिया गया है। जो हमारी बुनियादी जरूरत है, वह पूरी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है।... (व्यवधान) उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ सदस्य सारदा, नारदा कह रहे थे। बिल्कुल, हम पिछले 6-7 साल से, मोदी सरकार आने के पहले से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट वाला संघीय मामला नहीं है, यह न संघ का मामला है, न संघीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह जाँच हो रही है, लेकिन जाँच बहुत धीरे हो रही थी। हम कहते हैं कि भुवनेश्वर में ले जाकर वापस लौटा देते हो। अब आप शिलांग में ले जाकर के घुमाकर लौटा दोगे, यह कोई टूर पैकेज का मामला नहीं है। आम जनता का पैसा वापस करना पड़ेगा। उसी सारदा की तर्ज पर, रोजवैली की तर्ज पर आपने डीएचएफएल में, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इसी तरह से भ्रष्टाचार किया और चंदा इकट्ठा किया है।

(1545/RV/RCP)

यह आप दोनों की नूराकुशती है। आप भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के बारे में क्या कहेगा? आप राफेल के मुद्दे पर जे.पी.सी. नहीं करना चाहते। मुरली मनोहर जोशी जी एस्टीमेट कमेटी के हमारे सभापति हैं। आप भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, कलराज मिश्र जी, ये लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई सामने आएगी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कलराज मिश्र): सलीम साहब, अब कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): सर, आडवाणी जी की अध्यक्षता में नारदा के बारे में एथिक्स कमेटी आज तक नहीं बैठी। क्या आप भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? आप राफेल मुद्दे पर जे.पी.सी. नहीं कर सकते। दुबे जी एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को पारित नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी और जी.डी.पी. के बारे में इस सरकार का जो ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) प्रचार है, वह सब सामने आ जाएगा...(व्यवधान)

(इति)

1546 बजे

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है।

सभापति जी, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के चुनाव को मैं एक ऐतिहासिक चुनाव मानता हूँ क्योंकि इस चुनाव के जरिए देश की दशा और दिशा बदलने का कार्य हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की ओर से वह चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में लोगों को बहुत भरोसा था। अगर हम इसके पहले की बात करें तो इसके पहले यूपीए-1 और यूपीए-11 के समय में जिस प्रकार से शासन हुआ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से सरकारी खजाने की लूट हुई, जिस प्रकार से बैंड गवर्नेंस हुआ, उससे लोगों का भरोसा उठ गया था। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूँ कि लोगों का पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर से भरोसा उठ गया था। मैं हमारे प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे गौरव होता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस चुनाव के जरिए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर लोगों का भरोसा जताने का जो एक कार्य किया है, वह बहुत ही बड़ा कार्य है, क्योंकि काँग्रेस के शासन में जो कार्य हुआ था, मैं समझता हूँ कि उस समय लूट मची थी। उनके करीब आधे से अधिक मंत्री तिहाड़ जेल की कोठी में बैठे हुए थे। उस समय लोगों में भ्रष्टाचार था, कोई शासन नहीं था, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी बात थी। पर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की जनता में आशा की एक नई किरण जगाई और इसकी वजह से देश में हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एन.डी.ए. को करीब दो-तिहाई बहुमत के साथ शासन का अवसर मिला। इसके लिए मैं देश की प्रजा का आभार मानता हूँ और प्रधान मंत्री जी का भी आभार मानता हूँ।

महोदय, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, तो करीब पाँच वर्ष पूर्ण होने के समय पर हम पहुंच गए हैं। हम अपने कार्यों को देखें, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो कार्य किया है, उसे देखें। अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि आप 70 साल और आपके पाँच सालों की तुलना करते हैं। तुलना तो अवश्य करनी पड़ेगी क्योंकि काँग्रेस की सरकार ने इस देश के इतने साल पानी में गंवाए थे। हमारे

प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, वह गरीबों के लिए हुआ है, गाँवों के लिए हुआ है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, वनवासियों, पिछड़े के लिए और युवाओं के लिए कार्य किए गए हैं। इनके समय में जो कार्य हुए थे, मैं समझता हूँ कि उनकी तुलना हमें रत्ती भर भी नहीं करनी चाहिए। आज हमारे प्रधान मंत्री जी का जलवा है। अब दूसरा चुनाव आ रहा है। हमारे कुछ लोग चुनाव के बारे में टिप्पणियाँ कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज भी देश की 150 करोड़ जनता को प्रधान मंत्री पर उतना ही भरोसा है, जितना वर्ष 2014 में था। अब जब चुनाव आ रहा है तो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। ये लोग अपवित्र गठबंधन कर रहे हैं। हमारे गुजरात में एक मुहावरा है कि ऐसे तो हम लोगों को चेहरे से पहचानते हैं, मगर यहां जो गठबंधन करने वाले हैं, ये लोग एक-दूसरे को उनके चेहरे से नहीं पहचानते हैं, बल्कि उनके पैरों से पहचानते हैं क्योंकि आज तक उन लोगों ने एक-दूसरे के पैर खींचने का कार्य किया है। वे एक-दूसरे को चेहरे से नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोग आए हैं।

(1550/MY/SMN)

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कार्य किया है, बहुत ही बड़ा कार्य किया है और प्रजा के लिए निर्णय लिया गया है। मैं 'उज्ज्वला' योजना का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी बहनें, जो पहले धुएँ में रसोई बनाती थीं, तो उनको सांसों की बीमारियाँ होती थीं। उनको लक्ष्य में रखकर प्रधानमंत्री जी ने छह करोड़ से ज्यादा एलपीजी का कनेक्शन दिया है। आज तक पूरे विश्व में इतने बड़े पैमाने पर एलपीजी का कनेक्शन देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आप सभी से यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने आवास योजना दी है। सबको एक छत चाहिए। सबको एक घर चाहिए। सबको एक आशियाना चाहिए। अभी कांग्रेस के एक मित्र कह कर गए कि हमने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन मैं इनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि उनके समय में 25 लाख घर बने थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत एक करोड़ तीस लाख घर बने हैं। यह वास्तविकता है और आज लोगों को छत मिली है। आज लोगों को सम्मान मिला है और उनको आशियाना भी मिला है।

जहां तक गांवों में बिजली का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब शाम के छह बजते थे तो लोग अपने भोजन की क्रिया पूर्ण कर लेते थे, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत पहला प्रयोग गुजरात में किया था और उसकी सफलता के आधार पर यहां भी प्रयोग किया गया। देश के शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी सिद्धि है, क्योंकि 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचायी गई है।

‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’, गरीब के घर में कभी बिजली नहीं होती थी। गरीब के बच्चों को जब पढ़ना होता था, जब उनका इम्तिहान आता था तो उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत करीब 2 करोड़ 47 लाख निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, यह इतिहास में अंकित हुआ है और लोग इसीलिए घबराते हैं। लोग घबराकर ही अनहोली गठबंधन करते हैं। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं। मैं एक सर्जन हूं, इसलिए मैं ‘आयुष्मान भारत’ का जिक्र अवश्य करूंगा।

सभापति जी, जो ‘आयुष्मान भारत’ है, इसको पीएमजेवाई के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसको प्यार से मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर डिलीवरी योजना है। भारत के आजाद होने के बाद अगर कहीं भी कोई हेल्थ केयर योजना बनी है, तो सबसे बड़ी योजना यही बनी है। इसमें करीब 10 करोड़ परिवार को हर साल पांच लाख रुपये के हेल्थ केयर का पैसा दिया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति जो स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अपना दम तोड़ देता है, उसके लिए यह योजना एक आशीर्वाद साबित होने वाली है। अगर मैं कहूं तो यह योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है।

माननीय सभापति (कलराज मिश्र): अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में एक बात करना चाहूंगा। वर्ष 1999 में उनके लिए जो एट्रोसिटी एक्ट बना था, उसके बाद कांग्रेस की तथा बहुत सारी सरकारें आईं, मगर किसी

भी सरकार ने उस कमजोर एक्ट को मजबूत करने का कार्य नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में जो पहले 22 गुणा था, उसमें 25 गुणा को जोड़कर उस एक्ट को मजबूत करने का कार्य किया गया है। जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी इसमें 10 प्रतिशत का आरक्षण करना है। मैं कन्क्लूड करना चाहता हूं और इन लोगों को कहना चाहता हूं –

‘मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरे से है,
यह हवा बेवजह मुझसे दुश्मनी रखती है,
मेरी हवा से तसरीफ है कि दीपक जलाकर देखो,
बुझाना बहुत आसान होता है।’

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(इति)

माननीय सभापति (कलराज मिश्र): जय प्रकाश जी, आपके पास पांच मिनट का समय है।

1554 बजे

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): सभापति महोदय, आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने के लिए अनुमति दी है, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।
(1555/CP/MMN)

महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण उन्हीं विचारों तथा उन्हीं पुरानी बातों को रखने का काम है, जैसे वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की आवाम, नौजवानों, किसानों और सीमा के जवानों के प्रति वचनबद्धता जाहिर की थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अपने कलेजे पर हाथ रख कर देशवासी सोच रहे हैं, मतदाता सोच रहे हैं, अच्छे दिन को ढूँढ रहे हैं, लेकिन गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार के लिए, गरीबों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए आज अच्छे दिन नहीं मिल रहे हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन जरूर आए। यह सत्रावसान का 5 साल का अंतिम सत्र है। जिस ढंग से आपने वादों से यू-टर्न लिया है, जनता तैयार हो चुकी है और सत्ता का, सत्रावसान का अन्तिम सत्र भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप फिर लौटने वाले नहीं हैं। आपने आवाम के साथ, नौजवानों के साथ और किसान के साथ वादा किया था। हमेशा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते रहे। आज वे कारागार में भले ही हैं, न्याय मिलेगा, उनको तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है। देश की एजेंसियां आज उन पर, उनके परिवार पर, सुश्री मायावती जी पर, श्री अखिलेश यादव जी पर, ममता बनर्जी पर लगी हुई है। कोई परवाह नहीं, न्याय मिलेगा, न्याय मरता नहीं है। आप 200 पाइंट रोस्टर को बहाल कीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, उनके अस्मान को बचाना है, संसदीय लोकतंत्र को बचाना है। जो 13 का प्वाइंट रोस्टर है, यह एससी विरोधी, एसटी विरोधी और ओबीसी विरोधी है। अंदर-अंदर आग लग रही है। अगर इसको नहीं बदलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि भूकम्प आने वाला है। आप देखेंगे कि एक भूचाल आने वाला है। जातीय जनगणना कराओ। आप क्यों जातीय जनगणना नहीं कराते हैं? जिसकी जितनी जाति, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो।

तीन राज्यों में आप चले गए, उसके बावजूद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड बदल चुका है और शेयर मार्केट में जो आपका वर्ष 2014 में उछाल था, शेयर मार्केट में बीजेपी का बाजार भाव लुढ़क गया है, गिर गया है, वह अब आपका नहीं है। आरक्षण को बचाना है, एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को बचाना है और 85 परसेंट गरीबों को उनका हक चाहिए। हम उनकी लड़ाई को लड़ते जा रहे हैं।

न्यू इंडिया, क्या न्यू इंडिया में एससी नहीं रहेंगे, एसटी नहीं रहेंगे, ओबीसी नहीं रहेंगे? जैसे मंदिरों से दलितों को हटाया गया था, पूजा करने नहीं दिया जाता था, आज एससी, एसटी, ओबीसी को विश्वविद्यालय के कैम्पस से हटाया गया है। इसे कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। संसद में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे।

हमारी गंगा-यमुना संस्कृति है। हिंदु, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आपस में भाई-भाई। हमें अमन चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए। हम अमन के पुजारी हैं, आप नफरत के पुजारी हैं। हम तिरंगाधारी हैं, आप भगवाधारी हैं। मेक इन इंडिया, नहीं-नहीं आपने कर दिया पैक इन इंडिया। नोटबंदी की, उद्योगपतियों को माफ किया, गरीबों को साफ किया। दो करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, अब आप कहते हैं कि पकौड़ी की दुकान खोलो। कहां गए 15 लाख रुपये? आज स्विच बैंक का स्विच ऑफ हो गया है। वर्ष 2019 में आपका भी स्विच जनता ऑफ कर देगी, आप बचने वाले नहीं हैं। यह सत्रावसान का अन्त है और आपका भी अन्त है।

(इति)

(1600/SK/VR)

1600 बजे

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनंदपुर साहिब): इस भाषण में पिछले साढ़े चार साल से फ़ैडरलिज्म की बात आई, नीति आयोग द्वारा सारे प्रदेशों की भागीदारी सेंट्रल पालिसी से बनाने की बात आई। 1973 में शिरोमणी अकाली दल ने श्री आनंदपुर साहिब में स्टेट्स को और पावर देने और संघीय ढांचे के मजबूत करने के लिए एक रिजाल्युशन लाया था। मुझे इस बात की खुशी है कि साढ़े चार साल में संघीय ढांचा मजबूत हुआ है। राज्यों के 32 परसेंट शेयर को 42 परसेंट किया गया। इससे राज्यों की भागीदारी हुई।

महोदय, मुझे इस बात की भी खुशी है कि पहली बार इतिहास में किसी महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के किसानों को अन्नदाता के तौर पर पुकारा। यह बहुत बड़ी बात है। एमएसपी का फार्मूला लेकर आए, नीम कोटिड यूरिया लाए, फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाए। मैं समझता हूँ कि बहुत से इश्यूज हैं जो किसानों की उबल इनकम के लिए लाए गए हैं।

महोदय, छः करोड़ लोगों को गैस के चूल्हे दिए गए। जिन लोगों ने घुटने चेंज कराने थे उनके लिए 1500 करोड़ रुपये सेव हो गए। 460 करोड़ रुपये स्टंट्स सस्ता करने में लोगों के बच गए। 98 प्रतिशत लोगों के लिए टाएलेट्स बने। 1 करोड़ 30 लाख लोगों को घर बनाकर देना बहुत बड़ी बात है।

मैं सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में करतारपुर तक सड़क बनाने की बात कही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि करतारपुर साहिब का यह रास्ता केवल गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान के दर्शन आसानी से ही नहीं कराएगा बल्कि दो देशों के आपसी रिश्ते जोड़ने के लिए, दो देशों के अवाम के दिल जोड़ने के लिए और सरहद पर जो कड़वापन आया है, उसे खत्म करने का एक माध्यम बनेगा। यह देश और दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज देगा। यह इस देश की सरकार की बहुत बड़ी प्राप्ति है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु नानक देव

जी का 550वां प्रकाश उत्सव दुनिया भर में मनाने जा रहे हैं। मैं यह बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर इस देश में गुरु नानक देव जी की फिलॉसिफी पर अमल किया जाता तो किसी दलित का शोषण न होता। गुरु नानक देव साहब ने कहा-

जे रत लगे कपड़े, जामा होए पलीत,
जो रत पीवे मानसा, तिन कियों निर्मल चीता

गुरु नानक देव जी ने वर्क कल्चर पर जोर दिया - किरत करो, नाम जपो, वंड छोको। गुरु नानक देव साहब ने जातपात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए सरबत का भला मांगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक होता है। इन साढ़े चार सालों में केवल गुरु नानक देव साहब जी का प्रकाश उत्सव ही नहीं मना रहे हैं बल्कि उस पर अमल करने के लिए गरीबों के लिए पालिसी भी लाए हैं।

गुरु नानक देव साहब जी ने कहा था –

नीचां अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच
नानक तिन के संग साथ, वडियां सो किए रीसा

देश में माइनारिटी को असुरक्षित कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाम पर सिक्का जारी किया गया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अब हम सिक्का जारी नहीं कर रहे हैं, देश के लोगों के दिल पर गुरु गोबिंद सिंह जी का सिक्का है। गुरु गोबिंद जी ने कहा था- मानस की जात सबे एक ही पहचानबो। अगर हम पाठ्य पुस्तकों में इसे रख दें तो मैं समझता हूँ कि सब झगड़े खत्म हो जाएंगे।

शहीद भगत सिंह और शहीद ऊधम सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। हम जलियां वाले बाग के 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं। शहीद ऊधम सिंह जी सही मायने में भारत रत्न के हकदार हैं। इनकी कुर्बानी से देश 100 साले पहले आजाद हो गया। शहीद ऊधम सिंह नौजवानों के लिए मॉडल है। शहीद ऊधम सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए।

(इति)

(1605/MK/SAN)

1605 बजे

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया गया था, उसके ऊपर उनका धन्यवाद करने के लिए मुझे समय दिया है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह समझता हूँ कि यह अभिभाषण एक ऐतिहासिक अभिभाषण रहा है। केवल गत वर्षों की भांति अभिभाषण नहीं दिया गया। इस अभिभाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि चार वर्षों में सरकार ने क्या किया है, उसका लेखा-जोखा आंकड़ों सहित रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस अभिभाषण में एक नई बात देखने को मिली है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन साढ़े चार वर्षों में मोदी सरकार ने जो किया है वह गरीबों के हित की, किसानों के हित की, दलितों के हित की, महिलाओं के हित की, गांव के हित की ये सरकार लगातार जितनी भी योजनाएं आयी हैं, वे सब-की-सब योजनाएं कहीं-न-कहीं गरीबों के साथ जुड़ी हुई योजनाएं हैं। जब हम गरीब की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस देश में, जहां हम कहते हैं कि 20-22 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उनकी उस गरीबी को दूर करने का भी काम इन योजनाओं के माध्यम से हुआ है। ऐसा मेरा मानना है। प्रैक्टिकली जमीन पर भी इसका प्रभाव नजर आया है।

अभी हम आयुष्मान भारत की चर्चा कर रहे हैं। इस देश में जहां हम कह रहे हैं कि इस देश में लगभग 20-22 करोड़ वे लोग हैं, जिनके पेट में रात में अन्न नहीं जाता है, जिन्होंने कभी अपने तन पर कपड़ा नहीं देखा है, जिन्होंने अपने पैरों में जूते नहीं देखे हैं, वे कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, तो कभी सोच नहीं सकता है कि कब मेरा इलाज होगा? वह केवल भगवान को याद करता है कि भगवान मेरे को कब बुला लो। यानी वह अपने मरने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करता है। परन्तु, आज हम नरेन्द्र मोदी जी का, उनकी सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आयुष्मान भारत के माध्यम से इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये परिवार हैं, केवल आबादी नहीं हैं। 10 करोड़ परिवार का

मतलब, अगर हम 5 का एवरेज लेते हैं, तो 50 करोड़ आबादी को हमने कहा कि 5 लाख रुपये उनके परिवार के प्रति सदस्यों को हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 23 सितम्बर को यह स्कीम शुरू हुई और तीन-चार महीनों के अंदर आज जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, लगभग 11 लाख लोगों ने अरबों रुपये का इसका लाभ उठा लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अपने जिला के हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में गया था। मैं उन लाभार्थियों से मिला जो परेशान थे, जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। वहां पर आज उनका फ्री में इलाज हो रहा है और इलाज के बाद वे सीधे घर अच्छे होकर निकल रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं से लगता है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बहुत ही संवेदनशील है और गरीबों के लिए काम कर रही है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत चर्चा करते हैं, खासकर के हमारे कांग्रेस के साथी और दूसरे हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, वे रोजगार के बारे में कहते हैं। मैं मोदी जी की वह बात याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि इस देश का युवा केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न करे। He should not be a job-seeker; he should be a job-creator. आज प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लाखों नौजवनों को रोजगार दिया है और उस रोजगार के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूँ कि हमने लगभग 7 लाख करोड़ रुपये इसमें निवेश किया है और हमने 15 करोड़ लोगों को आज इसकी सुविधा दी है।

(इति)

*SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR):

*Laid on the Table

(1610/RBN/RPS)

1610 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to take part in the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

The hon. President's Address to the Joint Session of Parliament was deeply disappointing. The Address is full of so-called achievements of the Government during the last five years. But if you critically examine those so-called achievements, you will realise that all those achievements are not real or contrary to the ground reality and known facts.

The President's Address is a summary of lame excuses for the Government's non-performance during the last five years. The President's Address begins with the vision of three eminent stalwarts of Indian history, that is Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Ram Manohar Lohia. It says that our country is following the dreams of Gandhiji to build an inclusive society based on ethics and principles. It also says that our nation is moving ahead guided by the ideals of social and economic justice as enshrined in the Constitution by Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar and it further says that the efforts of this Government clearly reflect a belief in an egalitarian society as espoused by Dr. Ram Manohar Lohia. The Address ends with a promise of building a new India. This is the crux of the Address of the hon. President.

Let us examine whether the Government, during its five years, is able to achieve any of the dreams or visions of the luminaries or the national leaders

or the forefathers of our country. I would like to know from the Government as to what it has done during the last five years to realise the dreams and visions of these eminent leaders or those eminent personalities of our country. BJP had a golden opportunity to do many things as it has got an absolute majority to rule the country after 30 years. But what have you done for the country during the last five years except eloquent extempore speeches, impressive slogans, promises and diplomatic appearances? So, according to me these five years were a loss to this country.

This is a speech prepared by an out-going Government. So, in a way this is an assessment of the Government's performance during the last five years. What have you promised before five years and what have you delivered after five years? This Government is a Government of broken promises. That is the point which I would like to make.

I am confining my speech to two points. The first one is unemployment and the second one is NITI Aayog. Regarding the unemployment, most of the hon. Members have already mentioned facts and figures. It is known that 6.1 per cent is the unemployment rate today, which is the highest during the last four and half decades. Why has it happened? It happened because of the policies pursued by the Government. I would like to say that the National Sample Survey Organisation and the National Statistical Commission approved a Report. But unfortunately the Government is not able to approve the Report and they are saying that this is only a draft Report. How can the data collected by the NSSO considered as draft? These are all facts and they

speak the truth about the situation which is prevailing in our country. If it is approved and published by the Government of India, all the claims and propaganda of the Government will be contradicted. That is why the Government is not ready to approve and publish the Report which has been prepared by the National Sample Survey Organisation. The Government has totally failed in providing job opportunities. It has also totally failed to create a conducive atmosphere to create jobs. For this, two things are required. One is the policy initiative and the other thing is to create a social infrastructure. In all these things the Government has failed.

In the case of demonetisation the Government has failed. In the case of implementation of the GST also the Government has totally failed. The GST was implemented in an unscientific manner. ...(*Interruptions*) I am very grateful to you. Along with the policy initiatives stated earlier, the Government should create a social infrastructure to attract investment and to create jobs. During the last five years of NDA's rule, they have vitiated the social atmosphere in the country. I am not going into the mob lynching. About 36 people have been killed and minorities are feeling very insecure.

One question I would like to pose regarding the NITI Aayog. What is the concrete and tangible contribution of the NITI Aayog during the last five years? The Planning Commission was dismantled. You have constituted the NITI Aayog. What is its contribution? The BJP Government, during its five years of rule, has been a complete failure in all spheres. The President's Address is only to give credence to its false promises.

The people of India has no other option but to change the Government in the immediate Lok Sabha elections to build a new India, a secular, democratic and vibrant India, as envisaged by His Excellency the President of India. Thank you.

(ends)

(1615/SM/RAJ)

1615 hours (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

1615 hours

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Chairperson, Sir, I remember my last speech on 20th July, 2004. Why I would like to say that that was my last speech? Of course, I had made a bitter criticism on the issue of the farmers. Then the allotment of time was taken by the then Government on the numerical basis. My Party had got only three Members. According to numerical strengths, I was given three minutes time and I was called as twelfth man. The same thing is being continued till today as 13th man to be called according to the numerical strength of the Party.

The hon. Prime Minister was present here. I would like to express some of the points which are concerning the State, not any issue relating to my Party. I am not going to say that every Member of this House is not committed to farming sector, irrespective of the party.

I came to this House in 1991. It was also an unexpected event. My full political carrier was nearly 30 years in Karnataka Legislative Assembly. I was the Leader of Opposition. I was the Minister for PWD & Irrigation. I resigned two times, not for my personal problem but on the issue of allotment of money for irrigation. Because of defeat in 1989, people persuaded me to contest the Parliament election and I came to this House.

I have been watching the deliberation of this august House since 1991 till today. Prior to 2004, the date which I have mentioned, there was some time restriction to speak because I was only one Member at that time.

On several occasions, the Chair used to give me some more time. It is not the question of this ranking – 13th rank or 14th rank. Three days back, I requested the Hon. Speaker personally. I went to her chamber. This may be my last speech.

I have been in public life since 1962 as a legislator. During the last 57 years, I have served the people of my State and my country. ...(*Interruptions*). There is no need to laugh. I am telling with all seriousness. You have got age and bright future. You are also one of my close friends. There are several friends even in Karnataka on both sides who are with me.

(1620/AK/IND)

I do not want to hurt anybody.

My only point, the hon. Prime Minister, is mentioned there that : "... Prior to the 2014 General Election, the country was passing through a phase of uncertainty. After the elections, my Government assumed charge and vowed to build a new India...". I do not dispute it.

1621 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

I have congratulated him when he got 282 seats for the first time. I went to his residence, 7 RCR, and I congratulated the Prime Minister. There was some occasion when my bitterness was there on the issue of Godhra. I had a bitter attack on that day when this had happened, but after he became the

Prime Minister with full majority, Yes, I admit the defeat of all the parties including the Congress.

The occasion was the Auditor General of India -- whether right or wrong -- in the Report that he gave, there were several scams. Subsequently, what had happened? The decision has been taken by the judiciary, and then the matter ends. The Prime Minister's dream was to build a corrupt-free India; to accomplish all achievements; and to eradicate poverty and gap between poor and rich. He had got so many ideas / programmes, which he has framed, and I am not going to dispute all those things. His dream may be to build the strongest India because the people have given him the mandate.

Madam, I never spoke a word either inside the House or outside the House to denigrate the office of the Prime Minister. I have got the highest respect for that Chair. The only thing that hurts me is that when it is said that the coalition Governments have not done anything; the achievements of the previous Governments are not given any respect; or respect those people, who were occupying some place after Independence like Pandit Jawahar Lal Nehru. I am not going to say what contribution he has made, and I would not repeat what Mr. Kharge has said here. They also fought for freedom, and they knew the value of freedom and the leadership of Mahatma Gandhi.

Today, we are enjoying the fruits of freedom that they brought sitting in this House or Dr. Ambedkar who gave the Constitution. Everybody remembers all these things and nobody forgets about it, but in the Budget Speech or the President's Address whose name is going to be highlighted; at what time; at

what period; and under what leadership, I do not want to talk about all these things. This time, Guru Nanak Devji is mentioned in this speech.

(1625/SPR/PC)

I don't know what persuaded the Prime Minister to bring in the name of Guru Nanak. I remember Guru Nanak. Barnala was the Chief Minister. He had done some small mistake. What was the decision taken by religious leaders? The whole day, he should polish the shoes of those who visited the Golden Temple. Can you find such leaders? Who are we? We have to compare ourselves. Are we free from corruption? How much money are we going to spend?

Madam, in this very august House when I came first, I mentioned about the type of accounts we are going to provide to the Election Commission. As an Opposition leader, I came across the Wanchoo Committee recommendations which had revealed that that there was more than Rs.7,000 crore black money. Our Prime Minister wants to remove corruption; he talks of cashless society, new India. In this country, everybody's aspiration is to free the country from corruption. I do agree. But unless we bring in radical changes in the existing system, how can we achieve our aspiration? I am sitting in this chair; I am on the last leg of my life. I am watched. Let us not deceive our conscience.

Now, I come to my own Government. I had 10 and a half months tenure. What had Vajpayee done? I can spell several things. In my 10 and a half

months tenure, I must say that the credit goes to 13 regional parties and to the Congress Party, which had supported my Government from outside.

I come from rural areas. Whatever decisions we had taken, I have compared the President's Address and the Budget speech of my friend. I am not going to read all these details. What have we done? We had taken the decisions. We had the Common Minimum Programme (CMP) of the United Front Government. We had priorities. I would like to bring to the knowledge of the august House the details of our priorities. Farming sector was a major issue. We had given more priority to rural development, poverty alleviation. I would read out some details of our experience in the last eight months on the CMP.

My first Budget was articulated on seven broad objectives – minimum services, employment, micro economic stability, investment, particularly on infrastructure, rural development, and on balance of payments position. These are the seven areas we had given priorities. On 1st June 1996, my oath taking ceremony was held. Vote of Confidence debate took place on 11th June, 1996. Our Budget was presented in this House on 24th July, 1996.

(1630/UB/SPS)

On 14th June, I called the Finance Secretary and the Agriculture Secretary and took a decision to reduce the fertilizer price, be it potassium or phosphate, by Rs. 1000 per tonne. It was not for Karnataka. There was a huge positive response that the production in agriculture went up to 7.8 per cent.

The Economic Survey Report is not present in this House. The Budget was presented by the hon. Finance Minister.

HON. SPEAKER: I am asking you to conclude. We also have crunch of time. I have given you ten minutes and you have taken more than fifteen minutes. I am sorry.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): The people who are sitting on the other side do not want to mention Devegowda's name in this House. What initiative have they taken on the issue of Northeastern States? Who met the Naga leaders in Geneva? This House must know and the people of this country must know that even with a coalition Government, what we can do and achieve.

In September 1996, my Principal Secretary and myself, met the two leaders in Geneva. Afterwards, a ceasefire was decided by both the sides. I went to Northeastern States, I gave a special grant of Rs. 6,100 crore for the works which still have not been completed. In our Budget, we provided Rs. 400 crore for Bogibheel Bridge and for the international airport in Guwahati. Subsequently, Shri Vajpayee ji went there and increased it to Rs. 700 crore, Shri Gujral went there and increased Rs. 100 crore. My first support was of Rs. 6,100 crore for all those works that are still going on – highways, railways, airports.

My decision was that the problems should be solved in these seven States. At that time, too many people were killed, Kukis were killed and Bodos were killed. All the figures are here with me. This was one of the worst

situations. I went there to meet all the leaders belonging to various groups. Before we came to the ceasefire agreement, I had met them in Geneva.

(1635/KMR/MM)

What was the situation in Kashmir? No Prime Minister had gone there for ten years. As the Prime Minister of the coalition government with outside support of the Congress, I went there five times. When I went there, Gen. Krishna Rao was the Governor. Leaders from all sections irrespective of their affiliations met me, including the Hurriyat leaders. Their demand was this. For ten years there was no tourism. Their loans got accumulated. Banks had seized their properties. They pleaded with me to help them by waiving off the loans. When I came back, I took that decision first to create confidence in the people of Jammu and Kashmir.

When I went there second time, we provided jobs. The railway line between Katra and the valley was treated as a national project and Rs.1,500 crore was sanctioned. I cleared two power projects including the Uri power project. Let the Prime Minister during his reply tell this august House whether I had done it or not. Let the country know about this. Not only that, I gave the sanction for Jammu University. Leh Ladakh highway project, to connect it to the mainstream, was sanctioned by me. Allocation was made. In the Supplementary Demands we cleared all these programmes and projects by providing money. That is one thing.

I now come to Delhi Metro. I was sitting here then. There was a quarrel going on between the Chief Minister of Delhi and the previous Chief Minister

who was also a Minister, as to who should preside over the function. I think neither of them is alive now. A tussle was going on. I was sitting here. Nobody mentioned Deve Gowda's name! Time schedules and all other things were fixed. I got the brochure and everything. How the funding should be done and all those things were fixed. Financial allocation and time schedule were fixed. Till today nobody knows that it was done by Deve Gowda heading the 13-party coalition with outside support from the Congress.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We know, Sir, that you started it.
...(Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Vajpayee Government was gone in 13 days. Who asked him to go and take the oath? Can you answer that? He was one of the tallest leaders. He had suffered in those 13 days. Why do you unnecessarily try to provoke me?

I was not anxious to become the Prime Minister. The situation was such. After the fall of Vajpayee Government all secular leaders met. That discussion went on for one week. V.P. Singh's name was mentioned. He declined. Jyoti Basu was the tallest leader. He agreed, but his party Politburo differed. Then, he mentioned my name. I did not want to accept it. It went on for two days. I know the difficulty of running a coalition government.

(1640/SNT/SJN)

Delhi Metro was kept in cold storage for 10 years. We introduced the Public Distribution System. 36 crores people below poverty line got 10kg rice at Rs.3 and 5kg wheat at Rs.2.

Respected Speaker, I have earlier told about the humiliation I suffered. Rs.3 was the rate of kerosene oil. Nobody objected. How to find resources? The issue was that the World Bank's President Wolfensohn came to India. I hosted him a dinner. He asked me that you have violated all the conditions of the IMF and the World Bank. You cannot get any further assistance from the World Bank. Then, I took a decision that when the black money is there why we should go to the World Bank.

I proposed two programs. One was Voluntary Disclosure of Income Scheme. Whatever may be the problem today, I must compliment my colleague Chidambaram. Let me be very frank. He said he would not do it; Indira Gandhi took this decision and there was no achievement; there was no progress; even Morarji Desai had to take a decision. There was no positive response. The actual tax payer blamed the Government. He said he did not want to take such a blame. Then, how to generate the money?

When I took charge, Rs.17,800 crore was the oil pool account deficit. I wanted to make up that. I come from a poor family, farming family. I know the difficulty. How to generate the resources? This is a big dispute. I did not want to go for any funding from outside. So, this Voluntary Disclosure of Income Scheme was proposed.

Another scheme I proposed was that the black money should come for the nation building activities. There should be voluntary building with the black money from those people who come forward to build the highways, tourism activities, investment and infrastructure. It should come from our own Indians

who have got broad minds. The only thing was that Jyoti Basu was aggrieved. He said that we should first announce the Voluntary Disclosure of Income Scheme. If it is going to be useful then we would think of the next item.

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): We got Rs.10,800 crores of revenue generated from the first Voluntary Disclosure of Income Scheme. That had been used for the Public Distribution System.

HON. SPEAKER: Now, please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam, I am not going to take much of your time. I can understand your feelings. If you give some time on the Budget, I would like to participate. I am only saying that do not unnecessarily talk about the *Mahagathbandhan*, the coalition governments. *Vajpayeeji* started with the coalition government. Earlier, there was a minority government. *Narasimha Raoji* also suffered. I do not want to go into all those points. Coalition governments can also do something if proper understanding is there. No person in my Government had any differences, though there may have been differences anywhere outside. We cooperated so much with each other. Ultimately, what has happened, it is not an issue for me.

(1645/GM/BKS)

You have got your turn too. Now people are talking that there may be a coalition government again. It is not my version, but media version. We are watching all these things. That is why I said that whichever coalition governments were there in the past, they have also done something for the

States. Pension for farmers and poor people, eradication of poverty and all those things are a concern of not only the present Government. Maybe a new India is his dream. I am not going to say all those promises which he has made in the first Presidential speech. I do not want to hurt his feelings. I would only say one thing. A full House is not here. We are all committed to farming sector, *annadaata*. There is no difference party-wise. I would like to reiterate what the Father of the Nation Mahatma Gandhi said: "Remember that dark brown starved man bending under a scorching sun, scratching a little plot of land to eke out a living. Anything you do, do for his benefit."

You announced Rs. 6000. That is only Rs. 17 per day. Please think over it. How much benefit are you going to give the industrialists? ...*(Interruptions)* It is not a question of telling any names. It is a question of searching our hearts. Has Modi ji gone for election campaign without this corporate money? How much money has been spent? We can also understand. The people of this country are not fools; they are well-awakened. All this progress may not bring so much of euphoria. They will take their own decision. You are giving Rs. 6000. Telangana is giving Rs. 10,000. How much is Mamata Banerjee giving? There are various States. I think even Odisha is providing more than Rs. 10,000. The Prime Minister announced Rs. 6,000, out of which Rs. 2,000 is in this Financial Year. By that time, election will be over. ...*(Interruptions)* Is it going to clear the difference between the rural and urban sectors, between farmers and other sectors? If it is going to give them at least a certain living standard, we will be happy. I only request the hon. Prime Minister that at least

in this session he should declare a minimum of Rs. 15,000 for farmers who are suffering. So many farmers have committed suicide. This is my last request. With folded hands, I make an appeal to the Prime Minister and all the leaders of the ruling party to cooperate and help the farmers.

With these words, I express my sincere thanks to you, hon. Speaker, for giving me time to at least express my feelings through this August House to my countrymen.

(ends)

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):**

*Laid on the table

*प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन):

*Laid on the table

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):

*Laid on the Table

***श्री हरिनरायन राजभर (घोसी):**

*Laid on the table

***DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH):** Respected Speaker Madam, I may kindly be allowed to lay the following few lines on Hon'ble President's Address on 31.01.2019 to both the Houses of Parliament on the eve of Interim Budget. Hon'ble President spoke on different issues and achievements of the government specially on M.S.P., Rafale Jet deal, surgical strike, demonetisation, 10 per cent reservation of general category poor, tripple talaq, etc. based on government's commitment for a new India, but practically the outcome is not up to the mark.

About doubling farmer's income, attempting a permanent solution faced by farmers and minimum support price of 22 crops is not correct. All are false promises, lame excuses and government's non-performance. While the government is making false promises and claiming about employment generation, the President's Address do not have data or figure on jobs created between 2014-18. The government also failed on demonetisation and black money. RBI figures shows that 99.6 per cent of the demonetised notes had returned to the banking system just 0.01 per cent notes perhaps did not return.

In his speech, Hon'ble President spoke about opening of new airport at Jharsuguda on 22.10.2018, but unfortunately no flights are operational yet. Therefore, there is need to focus on making New India. A new India, based on fare federal structure, committed to execute all the election promises, and many more challenges facing India to be solved and making vibrant all fronts.

(ends)

***डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):** मैं हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के भाषण का समर्थन करता हूँ। 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 70 साल में 70 साल मिलाकर जितना काम नहीं हुआ इससे ज्यादा साढ़े चार साल में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना में करीब 56,000 घरों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से लातूर जिले में 92,000 परिवारों को इसका लाभ हुआ है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने लातूर में केंद्र सरकार की ओर से सारी विकास की योजनाएं दी हैं। लातूर में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल जो 200 बैड का है, 160 करोड़ रुपये की लागत से दो साल में पूरा किया है। यहां एनईईटी का सेंटर दिया है, जो लातूर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा काम हो गया है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र और उस्मानाबाद के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की है, पोस्टल बैंक की शुरुआत भी की है। रेलवे स्टेशन सी कैटेगिरी का था जो ए कैटेगिरी में आया है। भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक उदयगीर लातूर रोड पर एक ही प्लेटफार्म था। मैंने उदयगीर और लातूर रोड पर दूसरे प्लेटफार्म का निर्माण करवाया है। यहां लातूर रेलवे स्टेशन पर दूसरा प्लेटफार्म और एक बड़ा वेटिंग हॉल, हिंदी की लाइब्रेरी, वीआईपी लांज का निर्माण करवाया है। इतना ही नहीं, लातूर में एक ही रेल चलती थी। मैं 2014 में सांसद बना हूँ, अब इसी स्टेशन से 29 ट्रेन शुरू हो गई हैं। पांच मालगाड़ियां और 16 पैसेंजर ट्रेन की यह उपलब्धि हमारी सरकार ने प्राप्त की है।

माननीय मंत्री गडकरी जी द्वारा नेशनल हाइवे के रास्ते के लिए 7 हजार करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे की सड़कों का निर्माण लातूर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। 700 गांवों में सांसद निधि देने का काम किया गया है।

लातूर कोर्ट में वकीलों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, 24 लाख रुपये की निधि देकर लातूर कोर्ट में एक बड़ा एसी हॉल बनवाया गया है। भारत में ऐसा पहली बार एमपी फंड कोर्ट के काम के लिए दिया गया है।

इसके अलावा मोदी सरकार ने देश में विकास के बहुत काम किए हैं। रेल बोगी का कारखाना लातूर में शुरू किया गया है। यह पहली सरकार है जिसने इतने सारे काम किए हैं। जनधन योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा योजना, बीमा योजना, इस तरह की कई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :** अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हमारी सरकार ने देशवासियों की ढेरों चिंता की है। गरीब किसान और मजदूर की चिंता को प्राथमिकता दी है। देश के सदन में प्रस्तावित अंतरिम बजट के माध्यम से यह साबित हो गया है कि आम आदमी आज आम नहीं रहा है बल्कि हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति खास हो गया है। आज देश में किसानों के सपनों को सार्थक और सजीव रूप देने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने ही किया है। वह किसान जो सिर्फ राजनैतिक रूप से बड़े दलों के द्वारा अपने वक्तव्य में ही उपयोग किया जाता था, उसके सम्मान की चिंता हमारी सरकार ने की है। किसानों के लिए डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम हो, 75 हजार करोड़ रुपये कृषि के क्षेत्र में बजट में अलग से देने का कार्य हो या किसानों के खाते में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का कार्य यह बताता है कि हमारे अन्नदाता को सिर उठाकर जीवन जीने की प्रेरणा प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। आज देश में 34 करोड़ लोगों के जन-धन योजना के माध्यम से खाते खोले गए हैं। ये सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि आम जन के जीवन को सुरक्षित कर देने वाली (प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना) योजना से जुड़ी हुई एक कड़ी है। आज देश में 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाकर उस दशा की बात करनी है जब अंधेरे में व्यक्ति का जन्म और मृत्यु की अवस्था होती थी। आज देश के प्रधान मंत्री के द्वारा जिस तरह से देश के गरीब परिवारों को पक्का मकान एवं उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया गया है, यह इस बात को दर्शाता है कि यह दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना जो इस दल के लिए थी, पार्टी के सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। यही इस दल की विशेषता है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और उनके सहयोगी मंत्रिगण के माध्यम से देश की सेवा की जा रही है।

*Laid on the table

इस अभिभाषण की खास बात है प्रधान मंत्री जनऔषिधि योजना जिसके माध्यम से हमारे देश के 600 से ज्यादा जिलों में लगभग पांच हजार जनऔषिधि केन्द्र खोले जा चुके हैं और 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर गरीबों व सामान्य वर्ग को उपलब्ध करायी गयी है। अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारी सरकार में एक ऐसा भारत बनाने का प्रयास है जिसमें सभी के लिए सम्मान तथा आगे बढ़ने के अवसर हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत है जिसका सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था। आज हमारा देश मेक इन इंडिया की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश के सैनिकों के सम्मान की रक्षा करने हेतु बजट में बड़ा हिस्सा उनके सैन्य बल को मजबूत बनाने के लिए रखा गया है। स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए देश में नई संस्थाओं की स्थापना की गई है। खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाया गया। आज हमारा देश रोड और रेल के नेटवर्क के साथ वायु मार्ग से भी जुड़ रहा है। छोटे शहरों को जोड़ने का काम उड़ान के माध्यम से किया गया है। इसलिए यह तय है कि यदि देश को सशक्त बनाना है और स्वावलंबी बनाना है तो आगे आने वाले समय में सर्वजन हिताय हेतु ऐसे नेतृत्व का साथ देना भारत माता के प्रति समर्पण देना होगा। जय हिंद।

(इति)

(1650/RK/GG)

1650 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Respected Madam, I am grateful to you for giving me a chance to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I pay my respect to his Excellency, the President of India but with great respect I disagree with the contents of his speech as it lacks the foundational values and facts. I, therefore, cannot support the contents of his Address.

The country is passing through a phase of uncertainty which is the result of demonetisation. Immediately after demonetisation there was an announcement of GST due to which the country is passing through a phase of uncertainty. The undecided stance on regulation of the cryptocurrency core system, India's security competition with other countries like China, USA, etc., rising unemployment and crisis of farmers have resulted in worsening social inequalities throughout the BJP-led NDA Government regime.

Madam, Nobel Prize winner, economist Amartya Sen considered the act of demonetisation as deprivation of the freedom of the people of India. I would quote Prof. Sen:

“Demonetisation is despotic action that has struck at the root of our economy based on trust.”

It has been said in the President's Address: “The moving goal of my Government is to improve the life of every Indian”. My question is, what

actually has improved the life of every Indian during the last five years and how.

When the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched, it was aimed to provide 50 crore free gas connections by 2019. They have now achieved only 26 per cent of their target. The C&AG Report notes that in 2015-16, households with LPG connections were using on an average 6.27 crore cylinders in a year. But after the scheme was launched, the number of cylinders used on an average came down to 5.6 crore. In many cases BPL households have transferred their LPG connections under the Scheme but that has not been counted.

As on 1st April 2018, there were an estimated 27.72 crore households in the country and 25.68 crore households had LPG connections. It comes to almost 93 per cent coverage. Only 80 per cent of households, that is 22.43 crore households had an active LPG connection as on 1st April, 2018. In simple words, 3.25 crore or nearly 13 per cent domestic LPG consumers were inactive.

West Bengal State Government, under the guidance of hon. Mamata Banerjee has started low cost Fair Price Medicine Shops in 2011 when she came into power. Swasthya Sathi Health Insurance Scheme, which was started in 2016, is covering all the districts of West Bengal and nearly 65 lakh families of the Self-Help Group members, ICDS workers and helpers, contractual employees etc. are covered under this Scheme. Almost 3 crore people are the beneficiaries of this Scheme.

In 2014, our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee declared that all patients will get free treatment in all Government hospitals and health centres across the State including all medical colleges. Almost 2.5 crore patients have already been covered under this scheme while the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was started by the Central Government on 23rd September, 2018 only.

(1655/PS/KN)

There has been a 2.1 per cent decline in the allocation for the National Health Mission, a national health programme that funds infrastructure for primary healthcare from Rs. 31,292 crore in 2017-18 to Rs. 30,638 crore B.E.

Madam, Shri Gopal Krishna Gokhale of Maharashtra said and I quote:

“What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.”

Today, नारा चेंज हो गया। In Indian politics, आज यह नारा है: “What Mamata Didi thinks today, Modiji thinks tomorrow.” अभी आज के देश का यह नारा है। As per the available central data, to alleviate the challenge of malnutrition and proper immunisation, West Bengal performs better than the national average. The coverage of food supplementation in past ten years has improved considerably for all the beneficiary groups from 23.1 per cent to 50.6 per cent for pregnant women; from 19.3 per cent to 46.5 per cent for lactating women; and from 33.3 per cent to 71.9 per cent for children.

I am to inform this House that the hon. Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, has already adopted a multi-sectional strategy to zero tolerance for under-nutrition and anaemia among women and children in a

targeted manner by 2020. The national statistics on under-nutrition for children below five years of age is 38.4 per cent.

Madam, despite several financial burdens, our hon. Chief Minister and our beloved Didi, Ms. Mamata Banerjee has started two new schemes in West Bengal. Just now our very senior leader, the ex-Prime Minister, has referred to that. The waiving of tax on agricultural land and bringing up a scheme like Krishak Bandhu Scheme, helped in rooting out the basic problems of farmers and farm labourers in the State and also helped them in getting rid of private lenders.

Madam, over 12,000 suicides have been reported in the agricultural sector every year since 2013. Farmer suicides account for approximately 10 per cent of all suicides in India. The NCRB data points out that about 2,474 suicides, out of studied 3000 farmer suicides in 2015, the victims had unpaid loans from local banks. The States of Maharashtra and Karnataka had 1,293 and 946 suicides respectively for indebtedness. It is to be noted that both these States have one of the highest incidents of farmer suicides as well as indebtedness. When suicide was committed in Karnataka, the BJP Government was ruling there. As per the recent reports of the National Crime Records Bureau, about 2,372 women farmers have committed suicide. The suicide list is very high. If I will go through it, it will take time. My time is very limited as you have already told me. I will, of course, keep my commitment.

Madam, today the question is this. Today, the constitutional institutions have been destroyed by this Government. All of us and the people of India

repose confidence in the Central Bureau of Investigation. But, because of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji's interference, the CBI has become a circus. We are seeing this circus for the last two months. We have seen this circus when one CBI officer was initiating a criminal case by lodging an FIR against another CBI officer and another CBI officer was initiating a case against the other. What is the fun? This is because of mishandling and because you want to use CBI as your handmade tool and that the CBI has to be dictated by the Government.

We have also seen the case of the RBI. One after another Governor is leaving the institution like the Reserve Bank of India.

(1700/RC/CS)

During Emergency, there were interruptions and interferences in the independence of the judiciary. We have taken 30 years to 40 years' time for repairing the judicial system itself. But during the last 2-3 years, the Indian judiciary has been interfered with by the present ruling Government. During 1975, for one supersession case, the judiciary was interfered with. Now what has happened today? Madam, I would tell you the tragedy of this thing. Justice H.R. Khanna was second in seniority in the Supreme Court. He was superseded and he resigned. He was one of the them. Today's mischief is this. Today's pathetic condition is that 33 persons are being superseded in all India seniority and same is the case with three persons in Delhi High Court. This is the biggest tragedy of the Indian judicial system. Therefore, interference in the judiciary has increased.

As regards freedom of speech, it has gone. It is not that only I am saying it. All the big actors and celebrities are saying that freedom of speech has gone. It is being interfered with. Today, we are living in this system.

Indira Gandhi declared Emergency in writing but today Narendra Modi Ji has declared Emergency without any writing. Today, there is undeclared Emergency. The entire country is under undeclared Emergency. The CBI is being used to throttle the voice of the Opposition. This situation has come today. The ED official is being sent for throttling the voice of the Opposition. But this way, the voice of the Opposition cannot be throttled. People are watching it. People have understood what is going on in this country. They know that emergency is there in the country.

Our respected senior leader and the ex-hon. Prime Minister has just now said how the coalition Government can run on the basis of mutual understanding. We have to learn it from him. He has told these things to this august House today. Now that day is not far off when such coalition Government will run the country. But we will not take any revenge the way revenge is being taken by Shri Narendra Modi. We will not throttle the voice of the Opposition leaders.

In the 15th Lok Sabha when the BJP used to sit on this side, I have seen them. I paid respect to those leaders who used to sit here. I used to see how they were opposing and how they were delivering their speeches. But today, when Modi Ji delivers his speech, they shout – Modi Ji, Modi Ji, Modi Ji, Modi Ji. It becomes a big circus. There is no comparison between the BJP Members

of the 15th Lok Sabha and the BJP Members of the 16th Lok Sabha. They are all creating circus in this House. आप क्या सर्कस बनाते हैं?... (व्यवधान) कुछ नहीं होगा... (व्यवधान) आपको जाना है... (व्यवधान) आप लोग जायेंगे... (व्यवधान) आपको जाना होगा... (व्यवधान) हर घर में, हर स्टेट में नारा है, बीजेपी तुमको जाना है... (व्यवधान) हर घर में नारा है, मोदी तुमको जाना है... (व्यवधान) याद रखना, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वेस्ट बंगाल में जो बैठी है, वह माँ दुर्गा है... (व्यवधान)

(इति)

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):

*Laid on the Table

*DR. A. SAMPATH (ATTINGAL):

*Laid on the Table

*KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):

*Laid on the Table

(1705/RV/SNB)

1705 बजे

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदया, आपने सदन के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए अभिभाषण पर सदन में चर्चा करने का अवसर मुझे प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ...(व्यवधान)

महोदया, इस संबोधन के माध्यम से सरकार अपनी रीति-नीति से देश के आम नागरिक को अवगत करा देती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की कार्य प्रणाली का आईना होता है। किन्तु, खेद है कि वर्तमान अभिभाषण वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने के बजाए महज सरकार का यशोगान करता हुआ दिख रहा था।

मैडम, मैं वर्ष 2019 में उन वायदों की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया था कि हमें बदलाव के लिए आशीर्वाद दीजिए। आज यह बदलाव भूलने का क्या कारण है?

महोदया, हमारे देश में कृषि की क्या स्थिति है? आज कृषि की चर्चा होती है, किसानों की आय को दोगुना करने की बात होती है, लेकिन यह वास्तविकता से परे है। कहीं पर भी किसान की जो उपज है, उसके लिए मंडी उपलब्ध नहीं है। मंडी उपलब्ध न होने के कारण किसान अपने द्वारा उपजाए हुए सामानों को सड़कों पर बिखेर देते हैं। आए दिन अखबारों और टेलिविजन पर यह समाचार आता है कि किसान टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि चीजों को मंडी के अभाव में सड़कों पर बिखेर देते हैं। इसलिए जब तक मंडी की पूर्णरूपेण व्यवस्था नहीं की जाएगी, कृषि आधारित कारखाना नहीं लगाया जाएगा, तब तक किसानों की आय को दोगुना करना सिर्फ एक नारा तक ही रह जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि यदि आप किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, देश में किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से कृषि आधारित कारखाने लगाने की जरूरत है।

महोदया, अन्त में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और एक बिन्दु आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने सवर्ण वर्गों के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। मैं

इसका स्वागत करता हूं, किन्तु इसके साथ-साथ मैं सचेत भी करना चाहता हूं कि इससे समाज के पिछड़े वर्गों को जो हानि हो रही है, वह अधिक घातक है। पूर्व में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन आज तक इसका लाभ मात्र सात से आठ प्रतिशत लोगों को ही मिल सका है जबकि पहले 50 प्रतिशत सीट्स अनारक्षित थे। अब जब मात्र 40 प्रतिशत सीट्स ही अनारक्षित रह जाएंगे तब पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यथास्थिति ही बनी रह जाएगी और उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जातीय जनगणना के आधार पर पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। तब पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति को उचित लाभ मिल सकेगा।

जय हिन्द।

(इति)

1708 hours

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

The hon. President in his speech said that this Government has infused a new hope and confidence amongst the people of this country. I do not understand as to what is the hope that has been infused amongst the people of this country. What is the single most achievement of this Government in the last four and a half years? Nobody knows that. Today in the morning, Shri Kharge ji, with statistics from each Department, has shown that the performance of this Government is not much during the last five years when compared to the performance of the consecutive UPA Governments. What hope can a Government, which itself has no hope, infuse in the minds of the people?

Madam, this Government came to power with 282 seats but since then whenever bye-elections have taken place, the party in power has lost almost every election and their strength in the Lok Sabha has been reduced to 268. The Government knows very well that they would not be coming back to power again. This is a party which itself has lost hope and how can they claim to have infused hope in the minds of the people? Shri Kharge ji has established with statistics that the Government does not have much to say here on its achievements. I am sitting in the House since morning.

(1710/NKL/MY)

I did not hear anybody opposing Khargeji or saying anything otherwise. People are saying many things but they do not have anything to say as their achievements. That is why, now, they are banging on and targeting the Opposition Leaders, and dividing the nation. Legislations like Triple Talaq and Citizenship Bill recently came to this House. The thing in your mind is to divide the people. You have pinned all your hope on dividing the people on religious grounds. You are trying to divide the nation. Your entire hope is on doing that. You do not have anything to show as your achievements in the last five years. That is what I want to say. You are targeting all the Opposition Leaders. How can it be? There are your Governments in many States; there are Chief Ministers; there are Ministers. There is no allegation or enquiry against anybody. But you are having investigations against almost all the Opposition Leaders and the Leaders of the nation, and that too towards the end of your tenure. Is it a matter of pride? You should be ashamed of yourself. I am of the opinion that you have lost confidence in yourself. A person or a movement, which has lost confidence in itself is dangerous. That is why, I say that you are not only hopeless but also are dangerous for the nation. With these words, I conclude.

(ends)

1712 बजे

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़): मैडम स्पीकर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

मैडम, मैं अभी अमेरिका गया था। वहाँ के लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने पूछा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको क्या मिला है, तो उन्होंने कहा कि हमें पहचान मिल गई, हमें सम्मान मिल गया। पैसा तो हमारे पास है... (व्यवधान) यह मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि लोगों ने जो मुझे बताया, वही बता रहा हूँ... (व्यवधान)

मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे-से जिले प्रतापगढ़ से आता हूँ। वहाँ पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। पहले लोग दो सौ किलोमीटर दूर लखनऊ जाते थे और पचास हजार रुपये खर्च करते थे, लेकिन आज दस दिन के अंदर एक हजार रुपये में पासपोर्ट इश्यू हो जाता है, जो पहले छह महीने में होता था। वहाँ सेन्ट्रल स्कूल आ गया है। वहाँ तीन-तीन ट्रॉमा सेन्टर्स बन गए हैं, पहले कभी नहीं बने थे। वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है... (व्यवधान) आप लोग जरा दूसरों की बात भी सुना कीजिए। आप लोग अपोजिशन में इतना ... (Not recorded) हो गए हैं।

मैडम, मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि पांच वर्ष में जो हुआ है, जो साठ महीने में हो रहा है, वह साठ साल में हमारे यहाँ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ से बहुत बड़े-बड़े मंत्री होते रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। रोड में तो इतना बढ़िया काम हुआ है कि आज भी गडकरी साहब को पूरा हाउस धन्यवाद देता है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं।

मैडम, अभी हमारे यहाँ नितिन गडकरी साहब का नाम रोडकरी हो गया है। लोगों ने उन्हें रोडकरी बोलना शुरू कर दिया है। रेलवे में बहुत अच्छा काम हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साढ़े 12 सौ करोड़ रुपये हमें दिया गया, हमारे सिन्हा साहब बैठे हैं और बहुत अच्छा विकास हो रहा है... (व्यवधान) हमारे यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है, आपके यहाँ भी बढ़िया बनेगा। बाकी तो एलपीजी के ऊपर तमाम बातें हुई हैं और काफी सदस्य बोल चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं राष्ट्रपति जी

के अभिभाषण का समर्थन करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने जो बोला है, वह फैक्ट बोला है।
धन्यवाद।

(इति)

1714 hours

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Madam Speaker, Vanakkam. On behalf of AIAIDMK Party, I thank you for giving me an opportunity to take part in the discussion on Motion of Thanks to the Hon. President's Address. Generally, Hon. President's Address highlights the achievements and the importance of future programmes of the present Government. This Address includes the measures undertaken by the Union Government during the last four years besides the views on development achieved so far in different fields. Therefore, this Address assumes significance as Hon. President address took place during the last Session of the 16th Lok Sabha. During the last four and half years, the economic growth on an average remained at 7.3%. Among the developing countries of the world, India occupies the sixth place which makes us to feel pride-filled. Along with that the contribution of India to the gross domestic product ratio has increased to 3.3% as compared to the year 2014. I place on record my appreciation to present Government for taking such path breaking initiatives. We should look into the fact that whether this growth rate has reached the common man. The Programme Implementation and Statistics Department in its report for the year 2017 has stated that the unemployment ratio in India has increased to 6.1%. Therefore, importance should be given to industrial development combined with employment opportunities. I hope that the project proposals will be created by this Government in future.

*Original in Tamil

When we think of employment generation, we need to think about skill development training programmes of the Union Government. Similarly under the Prime Minister's Skill Development Programme till last year 3.16 lakh beneficiaries got employment. If we compare with the unemployment ratio among youth, the employment generation is very less. I urge upon the Union Government to take necessary measures to provide jobs to at least 1Crore youth of our country before the year 2020.I request the Union Government to go for expansion of Skill Development Training Programmes to achieve this target. Hon. President in his Address said that further development of higher educational institutions throughout the country is on cards besides ensuring development activities in 103 KendriyaVidyalayas. The infrastructure development activities are being undertaken in a fast pace in 103 KendriyaVidyalayas of the country. On behalf of Tamil Nadu Government, I appreciate the Union Government for this laudable action. In my Thanjavur constituency, as a result my persistent demand, the Union Government has allocated Rs.18.25 Crore to construct anew school premises for the KendriyaVidyalaya operating from a land belonging to the Ministry of Defence. Out of this allocated amount of Rs 18.25 crore, an advance amount of Rs. 25 lakh have been released so far. Even though funds were allotted, because of the delay in action by the Engineering Department of the Ministry of Defence, the construction activities have come to a halt. I therefore urge upon the Union Government to expedite the construction activities of the KendriyaVidyalaya in Thanjavur. I am happy to say that while accepting my demand, the Union

Government accorded permission to open a new Kendriya Vidyalaya in my Thanjavur constituency. In the Pillaiyarpatti village of Thanjavur District 8.5 acres of land was allocated for the purpose. The State Government has also made necessary arrangements to execute expansion activities as regards the Kendriya Vidyalaya in my Thanjavur Constituency with a fund allocation of Rs.1 Crore and at a place where a College of Education was functional. Even the Commissioner of Kendriya Vidhyala has also visited this place. I therefore urge that the Union Government should support the State Government of Tamil Nadu.

(ends)

(1715/CP/SRG)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सदर-ए-जम्हूरिया के खुतबे के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूँ। मैं सिर्फ 5 पाइंट्स आपके सामने रखूंगा और बिल्कुल कम से कम वक्त में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हिंदुस्तान के आईन के ऊपर ओथ लेती है, तो वजीरे आजम और उनके काबिनी वज़रा ने शेड्यूल 3 के तहत हल्फ लिया, ओथ ली और वजीरे आजम और उनकी पूरी काबिना ने इस ओथ के खिलाफ काम किया। मिसाल के तौर पर वजीरे आजम ने 9 दिसम्बर, 2017 को अपनी तकरीर में कहा कि आपको मस्जिद चाहिए या मंदिर चाहिए। यह उस ओथ के खिलाफ है, क्योंकि इस मुल्क का वजीरे आजम एक मज़हब की तार्ईद में खड़ा नहीं हो सकता। वतन ए अज़ीज़ का आईन साफ और वाज़ह तौर पर कहता है।

(1720/SK/RP)

दूसरी बात है, इस हकूमत ने अपनी ओथ के खिलाफ काम किया, एक्सेस लैंड रिसीवर हैं ये लोग, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिसीवर के तौर पर हकूमत ने कहा कि जमीन एक मज़हब के फिरके को दिया जाए। यह ओथ के खिलाफ है।

मेरा अगला प्वाइंट है कि आर्टिकल 49 में खास तौर से सैपेरेशन आफ पावर का जिक्र है। इस सरकार की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों के बारे में प्रैस कांफ्रेंस की दुनिया जानती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उस लिफाफे में क्या लिखकर दिया कि आज अदलिया आपसे डर रही है? यह हमारी जमूरियत के लिए बड़ा खतरनाक है।

वजीर-ए-आज़म कश्मीर गए। डल लेक में माशाअल्ला उन्होंने हाथ हिलाया, लेकिन नहीं मालूम किसको हाथ हिलाया? शायद जिन्नात को हाथ हिलाकर अपनी मौजूदगी का अहसास दिलाया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान के नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। यह आपकी गलती की वजह से है, आपके पास कोई कश्मीर के लिए पालिसी नहीं है।

चौथी बात, मैं खारज़ा पालिसी के बारे में बताना चाहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ट्रम्प से एक बार नहीं 25 बार बगलगीर हुए, गले मिले। ट्रम्प ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान तालिबान से बात कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या यह हमारे मुल्क की सालिमियत और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रम्प ने आपको धोखा नहीं दिया? आप इतने बगलगीर हुए, इतने चुम्मे दिए लेकिन उन्होंने आपको छोड़ दिया। हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, हम सार्क में आइसोलेट हो चुके हैं। बताइए, बांग्ला देश में, भूटान में, नेपाल में आपकी मस्कुलर पॉलिसी कहां गई? ये सब हमसे दूर हो गए।

मुझे पांचवीं बात का जिक्र करना है कि राइट टू लाइफ हमारे मुल्क का फंडामेंटल राइट है। क्या यह सरकार को ज़ेब देता है? मेरे शहर में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों के खिलाफ केस था कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, आप अपील भी नहीं करते। आप हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर भरोसा करते हैं, हिन्दत्व के नज़रिए पर भरोसा करते हैं। जो लोग मक्का मस्जिद में मर गए, उनके लिए अपील नहीं करते। यह आपकी दहशतगर्दी की पालिसी है कि आप नरम रवैया अख्तियार करते हैं।

मेरा आखिरी प्वाइंट है, मोदी जी को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है, उनको लगता है कि हर तलाकशुदा औरत का साथ देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास सर्वे है, नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं। एनुअल हाउसहोल्ड इनकम इंडियन न्यू डैवलपमेंट सोसाइटी में एससी और एसटी के बाद मुसलमान हैं। आपकी सरकार हर साल, साढ़े चार साल से 25 लाख अखिलियती बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप से महरूम करती रही है, सिर्फ 1000 करोड़ का सवाल था, लेकिन आप नहीं देते हैं। तलाकशुदा औरतों से आपको इतनी मोहब्बत है लेकिन जो बेसहारा हैं उनकी फिक्र नहीं है। यह इनकी पालिसी रही है।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर जेनरेशन मोबिलिटी का डाटा है, जब दलित और अपर कास्ट सब लोगों की इंटर जनरेशन मोबिलिटी हुई तो मुसलमानों की नहीं हुई। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को आइंदा चौकीदारों की जरूरत नहीं है, एक खादिम की जरूरत है, जो इस मुल्क को यरगमाल नहीं बनाएगा, जो इस मुल्क को अपनी अना और तकब्बुर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जो इस मुल्क में खौफ नहीं पैदा करेगा बल्कि मुल्क में लोग आजाद तौर पर हिंदुस्तान के वजीर-ए-आज़म और हकूमत के खिलाफ बोलेंगे। आपने खौफ का माहौल पैदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब हकूमत आएगी, वह कम्पोजिट कल्चर को फरोग देगी, आपने हिंदुत्व नज़रिए को फरोग दिया।

मैडम, मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूँ कि मुझे इन लोगों से बहुत तकलीफ है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ कि चन्द्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट लाइब्रेरी से उठाकर पढ़िए, चन्द्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट ने जिस पर परज्युरी का इल्ज़ाम लगाया, आपने उसको भारत रत्न दिया। यह आपकी मोहब्बत पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी से है। मैं इसीलिए इसकी मुखालिफर करता हूँ। भारत रत्न सिर्फ अपर कास्ट और ब्राहमणों का एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। धन्यवाद।

(इति)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): میڈم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے صدر جمہوریہ کے خطبہ کے اوپر بولنے کا موقع دیا۔ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں صرف 5 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور بالکل کم سے کم وقت میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار ہندوستان کے آئین کے اوپر اوتھ لیتی ہے تو وزیر اعظم اور ان کے کابینہ وزراء نے شیڈیول 3 کے تحت حلف لیا، اوتھ لی اور وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ نے اس اوتھ کے خلاف کام کیا۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نے 9 دسمبر 2017 کو اپنی تقریر میں کہا کہ آپ کو مسجد چاہئے یا مندر؟ یہ اس اوتھ کے خلاف ہے کیونکہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک مذہب کی تائید میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وطن عزیز کا آئین صاف اور واضح طور پر کہتا ہے۔

دوسری بات ہے، اس حکومت نے اپنی اوتھ کے خلاف کام کیا، ایکسیس لینڈ ریسیور ہے یہ لوگ، جب سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک ریسیور کے طور پر حکومت نے کہا کہ زمین ایک مذہب کے فرقہ کو دیا جائے۔ یہ اوتھ کے خلاف ہے۔

میرا اگلا پوائنٹ ہے آرٹیکل 49 میں خاص طور سے سپیریشن آف پاور کا ذکر ہے۔ اس سرکار کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے چار ججوں کے بارے میں پریس کانفرنس کی دنیا جانتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس لفافے میں کیا لکھ کر دیا کہ آج عدلیہ آپ سے ڈر رہی ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کے لئے بڑا خطرناک ہے۔

وزیر اعظم کشمیر گئے، ڈل لیک میں ما شا اللہ انہوں نے ہاتھ ہلایا، لیکن نہیں معلوم کس کو ہاتھ ہلایا؟ شاید جنّات کو ہاتھ ہلایا اور اپنی موجودگی کا احساس

دلایا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان کے نہیں بلکہ کشمیر کے نوجوان آج ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے، آپ کے پاس کشمیر کے لئے پالیسی نہیں ہے۔

چوتھی بات میں خارجہ پالیسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم ٹرمپ سے ایک بار نہیں 25 بار بغلگیر ہوئے، گلی ملے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری ساوتھ ایشیا پالیسی ہندوستان کے ساتھ رہے گی۔ آج ماسکوں میں ہندوستان کو چھوڑ کر امریکہ، پاکستان، طالبان سے بات کر رہے ہیں۔ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے ملک کی سالمیت اور ملک کے لئے خطرہ نہیں ہے؟ کیا ٹرمپ نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا؟ آپ اتنے بغلگیر ہوئے، اتنے چمے دئے، لیکن انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ہم نے پاکستان کو آئیسولٹ کرنے کے لئے سارک کی پالیسی کو چھوڑ دیا، لیکن پاکستان آئیسولٹ نہیں ہوا، ہم سارک میں آئیسولٹ ہو چکے ہیں۔ بتائیے بنگلادیش میں، بھوٹان میں، نیپال میں آپ کی مسکیولر پالیسی کہاں گئی؟ یہ سب ہم سے دور ہو گئے

مجھے پانچویں بات کا ذکر کرنا ہے کہ رائٹ ٹو لائف ہمارے ملک کا فنڈا مینٹل رائٹ ہے۔ کیا یہ سرکار کو زیب دیتا ہے؟ میرے شہر میں مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا، جن لوگوں کے خلاف کیس تھا کورٹ نے ان کو بری کر دیا، آپ اپیل بھی نہیں کرتے۔ آپ ہندوستان کے نیشنلزم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہندوتتو کے نظریہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ مکہ مسجد میں مر گئے، ان کے لئے اپیل نہیں کرتے۔ یہ آپ کی دہشت گردی کی پالیسی ہے کہ آپ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔

میرا آخری پوائنٹ ہے، مودی جی کو مسلمانوں سے بڑی محبت ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہر طلاق شدہ عورت کا ساتھ دیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں

کہ آپ کے پاس سروے ہے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے میں سب سے زیادہ غریب مسلمان ہیں۔ اینول ہاوس ہولڈ انکم انڈیا نیو ڈیولپمنٹ سوسائٹی میں ایس۔سی۔ اور ایس۔ٹی۔ کے بعد مسلمان ہیں۔ آپ کی سرکار ہر سال ساڑھے چار سال سے 25 لاکھ اقلیتی بچے اور بچیوں کو اسکارشپ سے محروم کرتی رہے ہے، صرف 1000 کروڑ کا سوال تھا، لیکن آپ نہیں دیتے ہیں۔ طلاق شدہ عورتوں سے آپ کو اتنی محبت ہے لیکن جو بے سہارہ ہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ان کی پالیسی رہے ہے۔

میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انٹر جنریشن موہلیٹی کا ڈاٹا ہے، جب دلت اور اپر کاسٹ سب لوگوں کی انٹر جنریشن موہلیٹی ہوئی تو مسلمانوں کی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو آئیندہ چوکیداروں کی نہیں ایک خادم کی ضرورت ہے، جو اس ملک کو یرغمال نہیں بنائے گا، جو اس ملک کو اپنی انا اور تقبر کے لئے استعمال نہیں کرے گا، جو اس ملک میں خوف نہیں پیدا کرے گا، بلکہ ملک میں لوگ آزاد طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف بولیں گے۔ آپ نے خوف کا ماحول پیدا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئیندہ جب حکومت آئے گے، وہ کمپوسٹ کلچر کو فروغ دی گی، آپ نے ہندوتتو کے نظریہ کو فروغ دیا۔

میڈم، میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں سے بہت تکلیف ہے، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کہ چندرچوڑ کمیشن کی رپورٹ لائبریری سے اٹھا کر پڑھئے، چندرچوڑ کمیشن کی رپورٹ نے جس پر فرزری کا الزام لگایا، آپ نے اس کو بھارت رتن دیا۔ یہ آپ کی محبت ہے پنڈت دین دیال اُپادھیائے جی سے۔ میں اس لئے اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ بھارت رتن صرف اپر کاسٹ اور براہمنوں کا ایکسکلوسیو کلب بنا ہوا ہے۔ شکریہ۔۔۔ (ختم شد)

(1725/MK/RCP)

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदया, मोहतरम ओवैसी साहब ने कुछ बातें खारिजा पॉलिसी के बारे में बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कही हैं। इसलिए मैं ओवैसी साहब को मुख़ातिब करके आपकी इजाजत से कहना चाहती हूँ कि जितनी बातें आपने खारिजा पॉलिसी के बारे में कहीं, मैं सारी-की-सारी को खारिज करती हूँ। आपका यह कहना कि पाकिस्तान अलग-थलग नहीं हुआ, हम अलग-थलग हुए हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की हिमायत करने के लिए जिस तरह से अलग-थलग करके ग्रे-लिस्ट में रखा गया है, वह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए ओवैसी साहब आपकी तमाम बातों को पूरी तरह से मैं इस सदन में खारिज करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

*KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR):

*Laid on the Table

***श्री राहुल कस्वां (चुरु):**

***Laid on the table**

1726 hours

*SHRI SAUMITRA KHAN (BISHNUPUR): Madam, kindly allow me to speak from this seat. Today I will speak in Bengali because this speech of mine will reach lakhs of people of West Bengal through Lok Sabha television, they will hear me speak. First, I thank you Hon. Madam, I thank Hon. Modiji and I thank you all. We are aware that three things are absolutely required for our survival; these are shelter, food and clothing. Today Modiji has done commendable job. No person dies in starvation, everybody has food to eat.

In as far as shelter is concerned, we have seen that Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme has been implemented. Toilets have been constructed in large numbers. But we have witnessed that surprisingly, whenever any development work is undertaken under the auspices of the Central Government the State Government of West Bengal pastes a sticker of its own name. Like when Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana work is undertaken, Bengal Gram Sadak Yojana banner is displayed. It is very unfortunate and shameful The Beti Bachao Beti Parao programme is being implemented throughout the country. It is a unique programme.

*Original in Bengali.

We all were witness to the previous regime of UPA. Though I was not a member of Parliament at that time, I still remember that the tenure was riddled with coal scam, 2G scam and all such major scams. But today, I feel very proud to declare that I am an Indian. Because of the border fencing, people of India are happy, safe and secure; the army is protecting them. And the army is also happy and content because Hon. Modiji has kept them happy. But it is very unfortunate that helipad is not offered to the Prime Minister's chopper to land whereas the anti-socials of Bangladesh are offered a free-run to organize a Khagragarh incident. Permissions for rallies are not given to Hon. Home Minister or other Central Ministers like Smriti Irani but the bomb factories are sponsored by the State Government. Even yesterday, a bomb blast occurred in Ilambazar. This is the latest industry in West Bengal. There is no job in the state. The youths of Bengal are shifting base in search of jobs. They are moving out to other states. I thank the Chief Ministers of those states who are offering jobs to the Bengal youths. I also thank Hon. Prime Minister for arranging jobs for them. Bengal is on the verge of collapse. A group of anti-social elements is ruling the roost there. This is a dangerous situation for the entire country. In Bengal now new jobs are created through SSC, Government employees are not given DA. You can achieve nothing by trying to malign the image of Modiji. Youths of Bengal are getting jobs in other states because there are newer jobs opportunities in the country.

No Chief Minister can advise people to not deposit their money in the banks. For the first time I have seen that 16-17 leaders had come together in the Brigade Parade Ground Rally and from that forum, the Bengal Chief Minister urged upon the people to refrain from saving money in the banks. So, what do you propose? Where should the common people deposit their hard earned money? Should they invest in the chit funds? Should they invest in the Sarada chit fund? Or to the Narada fund? Though I respect all police personnel, I am compelled to say that the CBI officers should never be manhandled. They had gone to perform their duties. We are staying in a civilized country. When a Police Commissioner is summoned for questioning, he does not cooperate, he does not appear before the CBI, instead he sits on dharna with political leaders. This is not acceptable. People of Bengal are under threat. Today BGBS is being organized for inviting investments. In the year 2015, the proposed investment was Rs.2,43,100 cores but the actual investment was of Rs.983 crores. In 2016, the expected investment was Rs.2,50,253 crores, whereas the actual investment was of Rs.3433 crores only. The investment today is to the tune of Rs.2503 crores only.

We are sorry to say that by attacking Hon. Prime Minister's image, nothing can be achieved. Religious tensions should not be created in the state. It is a very dangerous trend. I would urge upon the Government that please ensure free and fair election in West Bengal. Allow the people of Bengal to cast their votes freely and fearlessly. They are never allowed to vote as per their wishes, they are threatened. In the last Panchayat election 70 persons were killed. This

should be stopped. I request you again to ensure free and fair Lok Sabha election in the interest of democracy. With this request, I conclude my speech.

Thank you.

(ends)

(1730/RPS/SMN)

1731 hours

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. Madam, this was a fresh reminder of all the welfare schemes that our Government has indulged in for the past quarter to five years. It is a time to give our report card for all the work that we have done and seek report card from others as well. Amongst the comity of nations, India deserves its place and that is what the purpose of this Government has been to give due place to India in the comity of nations.

It was very rightly pointed by the President that our country was treading towards the path of uncertainty before 2014. Lethargic and impassive governance is what was ruling in those days. From those times to present time, we have worked on every aspect. Every Ministry has done an immense task to uplift those who were in need of help.

अभी ओवैसी जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी की बात की, सरकार जिनकी थी, वे किसी को भी मार गिरा सकते थे। अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली होती तो शायद इनको पता चलता कि सरकारी तंत्र कैसे चलता था, इनको पता होता कि आज भी सरकारी तंत्र कैसे चल रहा है। आज सरकारी तंत्र ऐसे चल रहा है कि भले ही कुछ लोग सरकार में न हों, लेकिन कुछ सरकारी लोग उनके वहां जरूर बैठे हैं। यह उससे साबित होता है जिस तरीके की हरकतें तमाम संवैधानिक इंस्टीट्यूशन्स के अन्दर हुईं, जहां पर अधिकारियों को अधिकार नहीं होता, पार्टी-ए हो या पार्टी-बी हो, उनको अपना काम करना होता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। इस सरकारी तंत्र के तहत एनएसएसओ की रिपोर्ट, जो कि ड्राफ्ट

रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट नहीं है, वह लीक हो जाती है। सीबीआई के अन्दर जो कुछ चल रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट के सामने है, हाउस के सामने है और बाकी सभी के सामने भी है। यही तंत्र आज भी चल रहा है। यह तंत्र सरकारी कर्मचारी न होकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने साठ-सत्तर साल राज किया है, उन्होंने अपने तंत्र को बिछा रखा है, एक जाल बिछा रखा है।

My friends have already talked about all kinds of schemes by way of which we have tried to touch the lives of all Indians and all citizens. Fifteen crore MUDRA loans have been sanctioned. Seventy-three per cent of those loans has been given to women क्योंकि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति कोई और नहीं, एक महिला ही है। राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे से यह बात कही कि महिलाओं को इस सरकार का सबसे अधिक लाभ हुआ है। जब वह ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए इस्तेमाल होता है तो ओवैसी जी जैसे लोगों को तकलीफ होती है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं केवल पत्नी हैं, बेटियां नहीं हैं? उनके जीवन में क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनके पिता नहीं हैं, उनके भाई नहीं हैं? जब किसी भी औरत को तकलीफ होती है तो उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। अगर उसका जीवन सुधरता है तो मुस्लिम समाज का जीवन सुधरता है, इसमें इनको क्या तकलीफ थी?

(1735/RAJ/MMN)

खड़गे जी ने बहुत सारी योजनाएं गिनवाई थी, उन सारी योजनाओं के बारे में कहा कि इन्होंने केवल नाम बदला है, नाम नहीं बदला है बल्कि क्रियान्वयन का काम बदला है। क्रियान्वयन का काम ऐसे बदला है कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी होती और ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) से बचा जाता तो उन आंकड़ों को दिखाया जाता कि 'इन्द्रधनुष' नाम की योजना के अंदर पहले कितनी कवरेज थी। यह बताया जाता कि 'स्वच्छ भारत योजना' के अंदर जितना काम हुआ, पहले आपके यहां जो स्वच्छ ग्राम योजना चलती थी, उसमें कितनी कवरेज थी? आपने कौन-कौन से इलाके डीमार्केट किए थे। क्रियान्वयन का अंतर सब के सामने है। डिजिटल इंडिया, पोस्ट पेमेंट

बैंक्स, ऐसी तमाम सुविधाएं देश को दी गई हैं। सुषमा जी यहां बैठी हैं तो इसलिए मैं यह भी बताना चाहती हूं कि जो पोस्ट ऑफिसेज ईमेल के जमाने में बंद हो रहे थे तो पोस्ट ऑफिसेज को पासपोर्ट से लेकर सरकारी तंत्र में उनका बैंकिंग के लिए कैसे लाभ उठाया जा सकता है, वह इस सरकार ने करके दिखाया है। आज तीन हजार दो सौ पचास पोस्ट ऑफिसेज ग्रामीण सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और देश के हर जन को छू रहे हैं। ... (व्यवधान) मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने हमें सही आंकड़ा बता दिया कि वह एक लाख तीस हजार हो गया है।

गांव में किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, यह फाइलों में जरूर था, लेकिन उन फाइलों के ऊपर जो काम होना था, वह काम नहीं हुआ। जिस तरह का भ्रमित वातावरण किसानों को लेकर पैदा किया गया, वह एक ऐसा ही तंत्र है, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी। किसानों के लिए पिछले दस सालों में मात्र 54 हजार करोड़ रुपये यूपीए की सरकार ने खर्चा किया था। अभी छः हजार रुपये की कीमत को, जो कह रहे हैं कि छः हजार सभी के खातों में जा रहा है, एक किसान सम्मान योजना के तहत उसका कोई लाभ नहीं है, यह इन-एडीशन है, यानी यह टॉप-अप रीचार्ज है और जो अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है, वह तो मिला ही है। वह एमएसपी दोगुना का फायदा हो या खरीफ की फसलें हों या रबी की फसलें हों, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, प्रधान मंत्री आवास योजना हो, मुद्रा लोन हो या बटाई का काम कहीं और कर रहे हों, वे सभी लाभ हैं। उनके साथ यह अधिकार भी उनको प्राप्त हुआ है। 'ई-नाम' के द्वारा बाजार और खरीदार, दोनों को लाभ दिया गया है ताकि किसानों को सही कीमत उपलब्ध हो सके।

स्पीकर मैडम, कुछ दिन पहले कर्नाटक के किसान आए हुए थे। वे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बात हुई। मैंने कहा कि ग्राउंड पर यह छः हजार रुपये का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मैडम एमएसपी 1860 रुपये हैं और 1860 रुपये में खरीदारी के लिए सरकारी तंत्र के लोग हमारे पास नहीं आये हैं। मैं कर्नाटक सरकार की बात कर रही हूँ। खड़गे जी कर्नाटक से हैं, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ... (व्यवधान) उन्होंने 1460 रुपये में बाजरा बेचा है। यानी एमएसपी से कम में बाजरा बिका है। उनको यह छः हजार रुपये की कीमत बहुत अच्छी कीमत दिखाई दे रही है।

भले ही, उनकी सभी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन यह बहुत बड़ा सहारा और सम्मान है।... (व्यवधान)

टर्शरी हेल्थ केयर के मामले में बिजली हो, शेल्टर हो या हेल्थ केयर हो, उन सभी विषयों पर इस सरकार ने काम किया है और हर उस क्षेत्र को छूने का काम किया है, अब तक जिसको कोई छू नहीं पा रहा था। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत एक करोड़ तीस लाख मकान दिये जा चुके हैं और पिछले सितम्बर में छः लाख, 26 हजार, चार सौ अठासी अफोर्डेबल यूनिट्स बनाने का काम भी शुरू हो चुका है।

इलेक्ट्रिकेशन का मजाक उड़ाया गया था। आज मैं इन सभी को बताना चाहती हूँ कि 'सौभाग्य योजना' के तहत हर गांव को बिजली देने का प्रोग्राम था, जो कि हर गांव को दिया जा चुका है। 25 राज्यों में यह काम पूरी तरह से क्रियान्वित हो गया है। लगभग साढ़े दस लाख परिवार हैं, उन घरों को यह नहीं मिला है, जिसमें मुख्य तौर पर चार राज्य, असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़ हैं, जहां यह काम चल रहा है। जो विकास की यात्रा है, वह लगातार होने वाली यात्रा है। आप किसी भी विकास की यात्रा को यह नहीं कह सकते कि हम अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। आगे कुछ न कुछ शिखर तो रहेंगे, जो आपको अचीव करने होते हैं लेकिन पिछले पौने पांच साल में चरखे से चंद्रयान की यात्रा हमने पूरी की है।

(1740/IND/VR)

आदरणीय अध्यक्षा जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे कार्यकाल के पौने पांच साल के एक ऐसे भारत के निर्माण के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का परिचायक है, जहां पहले के मुकाबले अब अधिक पारदर्शिता है, अधिक सुचिता है, अधिक रोजगार है, अधिक स्वच्छता है, स्वास्थ्य में लाभ हुआ है, किसानों के लिए समृद्धि है और व्यापारियों के लिए अभिवृद्धि है। गरीबों के लिए खुशहाली है, महिलाओं के लिए सम्मान है और अल्पसंख्यकों के लिए 'सबका साथ, सबका विकास' के तहत अवसर भी उपलब्ध हैं। यह सोच से सृजन तक का रास्ता हमने पौने पांच साल में पूरा किया है और यह एक समर्पित यात्रा रही है। समर्पण इस मातृभूमि को, समर्पण इस भारत के समाज को।

एक ऐसी कठिन यात्रा जिसमें संघर्ष थे, चुनौतियां थीं, परीक्षाएं थीं, लेकिन सबसे अधिक संभावनाएं थीं और उन संभावनाओं के रहते हमने इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है और यही हमारा परिचायक है। यह यात्रा असंभव से संभव की ओर थी। क्या कोई सोच सकता था कि भारत में हर जन स्वच्छता के प्रति काम करने को जागरूक होगा? क्या कोई सोच सकता था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ या फीमेल फोइटीसाइड ऐसे तमाम राज्यों के अंदर जहां महिलाओं की संख्या खत्म हो रही थी और जेंडर इंजस्टिस हो रहा था, वहां आज आंकड़ा बताता है कि आपके यहां कितनी बेटियां पैदा हुई हैं और किस तरीके से लोग सैलिब्रेट कर रहे हैं। आज संकल्प से सिद्धि तक यदि हम पहुंचे हैं, तो वह पिछले पौने पांच साल की एक अभूतपूर्व आनंद की यात्रा रही है और इसका वृत्तांत मैं कुछ लाइनों के माध्यम से आपसे साझा करना चाहती हूं। पहली लाइन अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर है। अव्यवस्था – कालाधन कमाओ, रखो और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी अव्यवस्था इस देश में थी। पैसा देश से बाहर ले जाने के लिए कोई रोक नहीं थी। किसी दूसरे के नाम पर प्रापर्टी खरीदने पर कोई रोक नहीं थी। काला धन चाहे बेनामी हो, उस पर कोई कानून नहीं था। जितनी मर्जी फर्जी कम्पनियां खोलो, कोई कानून नहीं था। हमने उस अव्यवस्था को ठीक किया है और इसलिए अव्यवस्था से व्यवस्था की बात मैं कह रही हूं...(व्यवधान)

महोदया, इनकी तकलीफ मुझे समझ आ रही है। चाहे रोज वैली हो, 15 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हो। दो-ढाई हजार रुपये, दो सौ या ढाई सौ रुपये की बात नहीं है, कई करोड़ों रुपयों के घोटाले की बात है और इन्हें रोकने वाला कोई कानून नहीं था। बेनामी संपत्ति का कोई कानून नहीं था। हमने आकर वह व्यवस्था खड़ी की है। असमानता से समानता की ओर, इस देश में मात्र 120 परिवार पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे और वे 120 परिवार सौ करोड़ लोगों का पैसा संभालते थे। हम इसे समानता की तरफ लेकर आए, क्योंकि लोगों ने बात की कि गरीबी हटाओ। मेरा बचपन ये नारे सुन-सुनकर बीता है, लेकिन गरीबी कैसे हटे, इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे नेता गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन यदि गरीब को शौचालय चाहिए, तो नहीं मिलेगा, सड़क चाहिए तो नहीं मिलेगी, पैसा चाहिए तो नहीं मिलेगा। इस देश की 52 प्रतिशत जीडीपी

असंगठित वर्ग से आती है, लेकिन उसके लिए वर्ष 2014 से पहले कोई पॉलिसी नहीं थी और यह बात मैं ढंके की चोट पर कहती हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं थी कि उसे मुद्रा मिले, उसे पैसा मिले और वह अपना काम कर सके। असमानता से समानता की तरफ हमारी सरकार ने देश को ले जाने का काम किया है। नकारात्मकता से ऊर्जा की ओर, ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि इस देश का हर घर कभी बिजली से रौशन होगा। हर बच्चा रात को भी पढ़ पाएगा। हर महिला शाम के अंधेरे का या सुबह के अंधेरे का इंतजार शौच जाने के लिए नहीं करेगी। हमारी सरकार ने यह नई ऊर्जा का संदेश पिछले पौने पांच साल में दिया है। सोच से क्रियान्वयन की बात कही है। खड़गे जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा यह भी प्लान था, हमारा यह भी प्लान था, हमारी यह भी योजना थी, हमारी वह भी योजना थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ये सभी योजनाएं थीं, लेकिन फाइलों के अंदर थीं।

(1745/PC/SAN)

काम कैसे होता है, क्रियान्वयन कैसे होता है, वह इनको नहीं पता था। वह क्रियान्वयन हमने कर के दिखाया है। ... (व्यवधान) एक-एक योजना ये लें, एक-एक डेटा हम देंगे। ... (व्यवधान) इनकी तो वैसे - मेरे पीछे से मेरे भाई-बहन आवाज़ लगा रहे हैं - स्पैक्ट्रम योजना भी थी। ... (व्यवधान) मैंने कहा कि ऐसे तो सी.डब्ल्यू.जी. भी थी और बहुत सारी योजनाएं थीं। ... (व्यवधान) उनका डिस्कशन किसी और दिन के लिए। ... (व्यवधान) अकर्मण्यता से पराक्रम की ओर - ये वही लोग हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न-चिन्ह लगाते थे। ये वही लोग हैं, जिनके समय हमारे सैनिकों के सिर काटकर ले जाए जाते थे। ... (व्यवधान) उन्हीं सैनिकों के पराक्रम का जवाब हमने दिया है। ... (व्यवधान) यह असमंजसता से निश्चय की यात्रा है, क्योंकि हर बार हर प्रोग्राम, हर प्रोजेक्ट के गोल डिसाइडेड हैं। ... (व्यवधान) तीन महीनों के अंदर आपको यह काम खत्म करना है, छः महीनों में यह काम करना है, आपका बजट क्या होगा और अन्य चीज़ें क्या होंगी, यह सब तय है। ... (व्यवधान) इसी के रहते असमंजसता से निश्चय की और कृपणता से हृदय की यात्रा है। ... (व्यवधान) ये वे लोग हैं, जिनको भूखे बच्चों का भूखा पेट नहीं दिखाई देता था, क्योंकि खाने की और बहुत चीज़ें थीं। ... (व्यवधान)

ये वे लोग हैं, जिनको अकेले अंधेरे में जाते हुए महिला नहीं दिखाई देती थी। ... (व्यवधान) अंधेरा खाती हुई वह महिला नहीं दिखाई देती थी। ... (व्यवधान)

उज्ज्वला पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं उसे सिर्फ मेंशन नहीं करूंगी और ज़्यादा नहीं कहूंगी। ... (व्यवधान) यह ठहराव से बदलाव की यात्रा है। ... (व्यवधान) पॉलिसी पैरालेसिस ने इस देश को खत्म किया। ... (व्यवधान) 2014 तक यह सामान आना है, यह विमान आना है, पर कहां आना है, कब आना है, क्या होना है, किसी को नहीं पता था। ... (व्यवधान) यह ठहराव से बदलाव की और बिखराव से जुड़ाव की लड़ाई है। ... (व्यवधान) कभी धर्म के नाम पर बांटो, कभी क्षेत्र के नाम पर बांटो, कभी जेंडर के नाम पर बांटो, कभी जाति के नाम पर बांटो - बस बांटते रहो। ... (व्यवधान) भारत की और भारत की जनता की कौन बात करेगा, इसका कोई संदेशा नहीं था। ... (व्यवधान) आज हमने जुड़ाव की बात की है, निराशा से उत्साह से बात की है। ... (व्यवधान) आज हम सब लोग उत्साहित हैं कि भारत अपने संकल्प की यात्रा पूरी कर सकता है और पूरी कर के रहेगा। ... (व्यवधान) विनाश से सृजन की - एक ऐसा समय था, जब हम फ्रेजाइल-5 में थे। ... (व्यवधान) 2014 में आने से पहले हमारा आकलन फ्रेजाइल-5 में होता था कि हमारी अर्थव्यवस्था इस देश को खत्म कर देगी, इस देश के पास कुछ नहीं रहेगा, हम डेब्ट में रहेंगे। ... (व्यवधान) इन पिछले पांच सालों में एक भी कर नहीं बढ़ाया गया। ... (व्यवधान) पिछले पांच सालों के अंदर, जी.डी.पी. के तहत जो हमारी पोजीशन ग्यारहवीं होती थी, उसमें आज हम छठे नंबर पर हैं। ... (व्यवधान) आज वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम देश हमारी प्रशंसा करते हैं और हमने एक भी रुपया उधार नहीं लिया है। ... (व्यवधान) यह है हमारी विनाश से सृजन की यात्रा, अन्याय से न्याय की यात्रा। ... (व्यवधान) जो भी पैसा लेकर भागा है, जिसको भी जेल के पीछे होना चाहिए, जिसको भी ई.डी. के सामने जाना चाहिए, जिसको भी 1,600 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स पे करना चाहिए, उसको पे करना पड़ेगा। ... (व्यवधान) वह उससे बचेगा नहीं। ... (व्यवधान) यह अन्याय से न्याय की यात्रा है। ... (व्यवधान) अवरोध से गतिशीलता की यात्रा है। ... (व्यवधान) चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, वे अवरोध पैदा करना जानते हैं, लेकिन हम गति प्राप्त करना जानते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यह यात्रा रही है सोच से प्रयास की और यही यात्रा आगे चलकर पिछड़ेपन से विकास की बनी। ... (व्यवधान) मैंने पहले भी कहा कि पिछड़ापन या विकास कभी भी मुकाम नहीं होता। ... (व्यवधान) वह एक यात्रा है, जो आगे बढ़ती जाती है। ... (व्यवधान) 2014 के आंकड़े और आज के आंकड़े हमको देखने होंगे। महोदया, यह यात्रा रही है शून्य से वृद्धि की और संकल्प से सिद्धी की। ... (व्यवधान) पौने पांच सालों में वहां से यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं, यह सब के सामने है और एक-एक आकलन सबके बीच में है। ... (व्यवधान) यह उन्मुक्त प्रशस्त रास्ता हम दृणता के साथ पूरा कर पाए हैं, जिसकी वजह से आज सिर्फ विकास और विकास और विकास - यही हमारी यात्रा का मार्ग है और यही सृजन में, जुड़ाव में, विजय में, विश्वास में, संभाव में और सर्वस्व में हो चुकी है और यही क्रियान्वयन का अंतर है। ... (व्यवधान)

Madam, I want to tell you that there is no place for imperfect, corrupt and inertia-ridden systems. We are here to destroy those systems and we shall destroy those systems so that we can have a Government and we can have systems of governance which are efficient systems to serve the mother nation. That is exactly what the plan of Modi Government has been and that is why, such a mention is there even in the Presidential Address.

I am grateful to the President for rightly mentioning that we were sensitive to the needs of the countless helpless people. That is why, we worked for them and tried to ensure that there is life beyond darkness.

(1750/SPS/RBN)

अध्यक्ष जी, दो बातें मुख्यतः मैं कहना चाहती हूं कि ढलते सूरज की बात की है और पिछले पांच साल से हम वह ढलता हुआ सूरज ही देख रहे हैं। वक्त बदलता है और इन्होंने कहा कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है, यह बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग भागते फिरते थे, इस देश के अमीर, इस देश के करप्ट, आज वे सब ई.डी. से लेकर पुलिस के आगे जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है और

जितने भी लोगों ने ऐसे काम किए हैं, उनको पता होना चाहिए कि वक्त के आगे कोई भी नहीं है। आज मुझे याद आ रहा है कि चाहे भ्रष्टाचार के नियंत्रण का मुद्दा हो, चाहे काले धन का, इस देश में लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र की दुहाई तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन वह दुहाई असलियत में लूटतंत्र की थी। लूटतंत्र को वेबकास्ट किया गया था, जिसके माध्यम से सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आ जाते हैं। एक ही मंच के ऊपर और मैं यह कहती हूँ कि महत्वाकांक्षाएं होते हुए सब इकट्ठे हो जाते हैं। किसी के नाम हजार करोड़ हैं, किसी के नाम पर पंद्रह हजार करोड़ हैं। ये सब घोटालों के आरोपी हैं। इसलिए 1600 करोड़ का जो आयकर है, उसको पूरा करें तो उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक लाइन याद आ रही है “We must, indeed, all hang together or, most assuredly, we shall all hang separately.” यही कारण है कि all these people are hanging together.

महोदया, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको आज लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। असलियत में लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र खतरे में है। अध्यक्ष जी, लूटतंत्र के रहते खलबली मचना जायज़ है, इसलिए मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। इन्होंने संवैधानिक तंत्र को किस प्रकार से असंवैधानिक किया है, वह भी सबके सामने है। यह सब देश की जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है और अपने वक्त का इंतजार कर रही है। उनका जवाब भी ठीक सुनने को मिलेगा। विपक्ष की जो प्रीति है, वह ... *(Not recorded)* असत्य, मिथ्या और भ्रम से प्रीति है। सत्यनिष्ठा, विकास और शुचिता, ये हमारी मोदी सरकार की नीति है। लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र के लिए अगला हथियार है, ... *(Not recorded)* रिपोर्ट में यह लिखा है। पूछो कौन सी रिपोर्ट, तो उसको सत्यापित करना आवश्यक नहीं है। राफेल के मामले में तो ... *(Not recorded)* मिराज-2000, हमारे एक पायलट अबरोल जी का देहांत हुआ, लेकिन किसी ने उस विषय पर बात नहीं की, क्योंकि कफन बनाने के लिए 3.9 बिलियन रुपये खर्च किए गए थे। क्योंकि 20-25 साल पुराना जो जहाज है, उसको रीवैम्प करने के लिए 3.9 बिलियन रुपये खर्च किए थे। जो राफेल के सौदे की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके समय में मैट्रो रेल के अंदर, जिसको बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फाईल करनी पड़ रही हैं,

उसको 70 हजार करोड़ लोन आपने दिया था। उसका हिसाब दीजिए। इसलिए जो भ्रष्टाचार है, ये ... *(Not recorded)* भ्रम का माहौल इस देश में फैलाया जा रहा है। जब 45 हजार करोड़ का बैंकरोप्सी केस फाईल होता है तो समझिए कि बैंकरोप्सी कोड ने ये केस फाईल करवा दिया। ये अव्यवस्था से व्यवस्था का नतीजा है। ई.वी.एम. पर नई साजिश कर दो। सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए गए सवाल, इनटॉलरेंस पर खड़ा किया गया विवाद, अभी कुछ भी हो, कभी कहा कि रॉइट्स नहीं, नम्बर्स इनके बिल्कुल अलग थे। रॉइट्स सबसे अधिक पहले के समय में हुए हैं। आंकड़े कुछ और कहते हैं, ये यहां पर कुछ और कहते हैं। ये ... *(Not recorded)* की शासकीय नीतियां हैं और इसीलिए ये ... *(Not recorded)* को फैला रहे हैं। अंत में मैं लाईन खत्म करना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)* अगर ये लोग ई.वी.एम. को नहीं कोसेंगे तो अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ... *(Not recorded)* के पापी हैं। इसलिए अभी कुम्भ चल रहा है, जाकर स्नान कर लो।

(1755/MM/SM)

अर्थव्यवस्था का जिन्होंने पटरा बनाया, उनको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार उसको पटरी पर लेकर आयी है। हमारी सरकार ने देश को क्या दिया है, यह पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। आर्थिक नीति के तहत जो दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, उससे विपक्ष भी उभरा नहीं था कि अत्यंत लोकप्रिय बजट लाकर मोदी जी की सरकार ने इनकी बाकी बची हिम्मत भी तहस-नहस कर दी है। बिच्छु का डंक अभी तक इनको त्रास रहा है। अब तक इनको दर्द है कि इतना बढ़िया बजट कैसे आ गया? वर्ष 2014 में जनता का नारा था 'अब की बार मोदी सरकार', इस बार जनता कह रही है 'इस बार 300 पार' और 400 पार एनडीए के इन्हीं शब्दों के साथ, I just want to say one line, Madam. "The Government of the people, by the people, for the people needs to be sensitive to the needs and necessities of the people" and that is what our Government has done. I support the Presidential Address. I am very grateful to you and I am

very grateful to my Government. There, every Minister has done a fantastic job.

Thank you very much.

(ends)

***श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):**

***Laid on the table**

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):

*Laid on the Table

*SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR):

*Laid on the Table

***श्री रोड़मल नागर (राजगढ़):**

***Laid on the table**

*SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG):

*Laid on the Table

***कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया,

मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, देश का गौरव, मान-सम्मान, क्षमता, शक्ति, कृषि उपज, गरीब को सुविधाएं बढ़ी हैं। ईमानदारी से कैसे कार्य किया जा सकता है, शून्य से समृद्धि की ओर सदभाव से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नागरिकों के जीवन स्तर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में देश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर देशवासियों को गर्व की अनुभूति कराई कि किस प्रकार देश के निर्धन संसाधन हीन नागरिकों को दर्जनों लोकहितकारी योजनाओं से सरकार ने लाभांशित किया है। दुनिया ने माना है कि दुनिया की सब से बड़ी-बड़ी योजनाएं वंचितों के लिए भारत की सरकार ने बनाई हैं।

आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों का निःशुल्क इलाज करवाने की व्यवस्था भी है, जो कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अविश्वसनीय लगती थी। करोड़ों गैस कनेक्शन, करोड़ों शौचालय, करोड़ों आवास आदि-आदि बनाए गए। करोड़ों लोगों के खाते खोले गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि पहुंच रही है। बिना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के लाभार्थी निश्चित होकर खर्च कर पा रहे हैं। किसान सम्मान योजना के द्वारा प्रत्येक लघु व सीमांत किसान को आर्थिक सहायता दिए जाने का बड़ा प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, समय बहुत कम है, विषय बहुत ज्यादा है। अतः अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। देश की आबादी निश्चितता के साथ तरक्की कर रही है। माननीय मोदी जी के प्रयास से देश मजबूती के साथ बढ़ रहा है। यही नेतृत्व देश को परम प्रभावशाली बनाने में लगा है। निश्चित ही हमारा सपना पूरा होगा।

(ends)

***Laid on the table**

***श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** माननीय अध्यक्ष जी मैं 31 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी के दिये अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

हमारी सरकार ने न केवल 2014 की चुनौतियों का समर्थन करते हुए योजनाओं पर काम किया परिणाम भी दिए।

गरीब कल्याण, बुनियादी ढाँचे के निर्माण, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए, महंगाई, भ्रष्टाचार व आतंकवाद पर नियंत्रण करते हुए दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ाया है। आज देश में अनुकूल वातावरण है व देश आगे बढ़ रहा है।

(इति)

***Laid on the table**

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बाँदा):** माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन में श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी के द्वारा प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी केन्द्र सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कार्य पिछले साढ़े चार वर्षों में किए हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए जहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया है, वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देकर उक्त वर्गों के गरीब लोगों के साथ न्याय करने का कार्य किया है। आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लाकर देश के करोड़ों गरीब परिवारों को लाभ देने का व उनका जीवन बचाने का कार्य किया है। इस योजना से 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। उज्ज्वला योजना से 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, करोड़ों परिवार को शौचालय निर्माण हेतु सहायता दी गयी। किसानों की आमदनी को दुगुना करने हेतु तमाम योजनाएँ लागू की गयी। लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरों से गरीबों को छत देने का काम किया गया है और 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने का कार्य किया गया है। चाहे केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, या रक्षा कॉरीडोर का निर्माण या झांसी-मानिकपुर एवं खैराड़-कानपुर लाइन का दोहरीकरण या विद्युतीकरण चित्रकूट जनपद को आकांक्षा जनपद घोषित कर विकास करना। बाँदा में पासपोर्ट आफिस खुला। चित्रकूटधाम को रामायण सर्किट में लेकर विकास। भारत माता प्रोजेक्ट एवं राम वन गमन मार्ग का निर्माण। मैं इसी के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(इति)

1756 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : अध्यक्ष महोदया,

“तोड़कर कांग्रेस वालों का बंधन
करता हूं मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिनंदना
मोदी जी करेंगे 2019 में विरोधियों का रणकंदन
और बांट देंगे 130 करोड़ लोगों को विकास का सुगंधी चंदना”

अध्यक्ष महोदया,

“राहुल जी को लग गई है एक चाहूल
2019 का नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया है माहौला
राहुल जी बोलते हैं यह है जुमला,
लेकिन उनको मालूम नहीं है, यह है बीजेपी की कमला।
यह नहीं है असली जुमला,
नरेन्द्र मोदी जी करेंगे कांग्रेस पर 2019 में हमला”

महोदया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत अच्छा है। लोगों को सक्षम बनाने के लिए सरकार की भूमिका राष्ट्रपति जी ने रखी है। कांग्रेस वाले राह देख रहे हैं कि हम यहां कब आएंगे? लेकिन आपके पास और 10-15 साल यहां आने के चांस नहीं हैं। आप कोशिश करो, लेकिन लोकतंत्र को खतरा पैदा करने का काम मत कीजिए। बंगाल में अभी जो हुआ है, अगर चिट फंड में कोई इनक्वायरी करनी है तो सीबीआई को अधिकार है। हमारे महाराष्ट्र में तेलगी के केस में मुम्बई के कमिश्नर अंदर थे। तेलगी केस में जब हमारे पुलिस कमिश्नर का नाम आया था तो कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे मंत्री हो, एमएलए हो या कोई लीडर हो, कानून सबसे बड़ा है। अगर सीबीआई को जानकारी मिली थी कि चिट फंड की कुछ फाइल्स गायब हो गयी हैं और कमिश्नर से जानकारी लेने का अधिकार उनके पास है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम हुआ है और वहां उनको रोकने का काम हुआ

है। अगर ऐसा हो जाएगा। ... (व्यवधान) सीबीआई को इनक्वायरी करने का अधिकार है। ... (व्यवधान)
हमें बंगाल की जनता को जगाना है और ममता जी को वहां से भगाना है। ... (व्यवधान)

(1800/SJN/AK)

... (व्यवधान) ममता जी के लिए हमारे दिल में आदर है। ममता जी एनडीए में थीं। ममता जी वहां की मुख्य मंत्री हैं, उनके बारे में हमारे दिल में आदर है। वह एक बहुत ही एक्टिव लेडी हैं। वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री थीं। ... (व्यवधान) तब मैं उधर था, लेकिन अब मैं इधर आ गया हूँ। ... (व्यवधान) ममता जी एनडीए में थीं, उनके लिए हमारे दिल में आदर है। ... (व्यवधान) वह बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी मुख्य मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने जो पुलिस कमिश्नर को सपोर्ट करने का काम किया है, वह बात अच्छी नहीं थी। ... (व्यवधान) पुलिस कमिश्नर कोई भी आदमी हो, सीबीआई को उसकी इनक्वायरी करने का अधिकार है। ऐसा हो जाएगा और वहां पुलिस पकड़कर रखेगी, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ... (व्यवधान) इसीलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है। ... (व्यवधान) राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में हमारी सरकार ने साढ़े चार-पाँचे पाँच साल में बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहेब अंबेडकर जी की स्मारक, बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत अच्छी भूमिका ले ली है। मैं यह याद करना चाहता हूँ कि दामोदर वैली नाम की एक वैली है, वहां बाबा साहेब अंबेडकर जी ने चार डैम बनाए थे, जब वह पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। ... (व्यवधान) मेरा एक निवेदन यह है कि दामोदर वैली को बाबा साहेब का नाम देना चाहिए। मैथन डैम में बाबा साहेब का स्टैचू खड़ा होना चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी जरूर इसके संबंध में विचार करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ... (व्यवधान) यहां मैं बताना चाहता हूँ कि-

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार खोल रही है विकास के द्वार,

जहां-जहां हो रहा है भ्रष्टाचार वहां करेंगे नरेन्द्र मोदी जी करेंगे वारा। ... (व्यवधान)

हम यह काम करते रहेंगे और इसीलिए आप लोगों का सहयोग हमें मिलना चाहिए...(व्यवधान) वर्ष 2019 की चिंता मत करिए। आप लोगों में बिल्कुल भी एकता नहीं है...(व्यवधान) आप लोगों में एकता नहीं है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अठावले जी, प्लीज मुझे समय बढ़ाने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास अठावले : प्रधान मंत्री जी के वे कैंडिडेट हैं, वहां राहुल जी हैं, ममता जी हैं, बहुत सारे लोग वहां प्रधान मंत्री के लिए कैंडिडेट हैं...(व्यवधान) हमारे यहां एक ही उम्मीदवार है, श्री नरेन्द्र मोदी जी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय प्रधान मंत्री जी का रिप्लाइं पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री रामदास अठावले : नरेन्द्र मोदी जी की सरकार फिर 2019 में आएगी। जय भीम, जय भारता।

(इति)

***श्री जुगल किशोर (जम्मू):**

***Laid on the table**

***SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH):**

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**

*Laid on the Table

1803 बजे

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस बार के संबोधन में राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार से देश को दिशा दी है, सरकार के विज्ञान की व्याख्या की है, सरकार के मुखिया के नाते मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इस सरकार की पहचान ईमानदारी के लिए है। इस सरकार की पहचान पारदर्शिता के लिए है, गरीबों के लिए है, संवेदना के लिए है, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए है।... (व्यवधान) और तेज गति से काम करने के लिए है।... (व्यवधान) वह टीवी का दृश्य अभी भी याद है, जब नोट ऐसे-ऐसे जेबों में रखे जाते थे।... (व्यवधान)

आज इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री भर्तृहरि जी, श्री वेणुगोपाल जी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, श्री दिनेश त्रिवेदी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमान् सौमित्र खान जी, ऐसे अनेक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी राय रखी है।

(1805/BKS/SPR)

एक सार्थक चर्चा का प्रयास हुआ है और सदन ने इन सबको जिस प्रकार से सुना, उनकी बातों को प्रोत्साहित किया, इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति वाले भी और विचारों को प्रोत्साहन देने वाले इस पूरे सदन का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ आलोचनाएं भी हुईं, कुछ सिर-पैर के बिना की बातें भी हुईं, कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है, वह भी यहां बार-बार बोलने की आदत वालों ने बोल भी लिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह चुनाव का वर्ष है तो स्वाभाविक है, हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ तो बोलना ही पड़ता है। इसलिए वह प्रभाव रहना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन यह भी सही है कि हम लोग यहां से जाने के बाद जनता जनार्दन को अपने काम-काज का लेखा-जोखा देने वाले हैं। क्योंकि चुनाव का वर्ष है तो हमको जनता को जाकर अपना हिसाब देना है। मैं आप सभी को आगामी चुनाव में हैल्दी कम्पिटिशन के लिए अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। करोड़ों युवाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो इस शताब्दी में पहली बार इस चुनाव में पार्लियामेंट के लिए वोट देने वाले हैं, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। क्योंकि वोट डालना या

मताधिकार प्राप्त करना एक छोटी घटना नहीं है। हमें भी हमारी इस नई पीढ़ी को, जो पहली बार 21वीं शताब्दी के पार्लियामेंट के चुनाव के वोटर बनने वाले हैं, उनका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि वे एक प्रकार से देश के नीति-निर्धारक उस प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं उन नये मतदाताओं को, उन युवाओं को अनेक-अनेक बधाइयां देता हूँ और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी राष्ट्र को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं और यह भी सही है कि निराशा के गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति या समाज न खुद के लिए कुछ करता है, न उस पीढ़ी के लिए कुछ कर पाता है। कर वे ही सकते हैं, जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं। रोना रोने वालों को 5-10 अगल-बगल के लोग आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास कभी फटकते नहीं हैं। जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्धृत करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ... (व्यवधान) हो गया? ... (व्यवधान) अतीत में जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा, वे सभी आवश्यक थे, क्योंकि विनाश का जो काल बीच-बीच में आया, उससे निकलकर ही भविष्य का भारत आ रहा है।

(1810/KN/UB)

वह अंकुरित हो चुका है। उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली वृक्ष, विशालकाय वृक्ष का उगना शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में विकास की आस, विश्वास यही देश को आगे ले जाता है। चुनौतियों को चुनौती देना, यह देश का स्वभाव होता है। देश चुनौतियों को परास्त करता है। जो चुनौतियों से डर कर भागते हैं, वे नई-नई चुनौतियों को मोल लेते हैं। इसलिए चुनौतियों को ही चुनौती देना सामान्य मानवी की देश की आशा-अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज यहाँ 1947 से कुछ बातें बताई गईं। अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो दो पीरियड्स की चर्चा करते हैं- बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 1947 से 2014 तक तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की

उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है- बिफोर कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में। सब तबाह था, गर्त में था और एडी का मतलब है- आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ, वह उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर किसी काम को कम्पेरेटिव देखना ही पड़ता है और वह बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हमें इतना विचलित क्यों होना चाहिए? साढ़े चार साल पहले क्या होता था और आज क्या है। साढ़े चार सालों में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत साढ़े चार सालों में 10वें, 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था से आज छठे नम्बर पर पहुँच गया है और यह भूलिए मत कि जब 11 नम्बर पर पहुँचे थे तब इसी सदन में यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहाँ भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुँचने का बड़ा गौरवगान किया था। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जिनको 11 पर पहुँचने पर गौरव दिखता था, उनको 6 पर पहुँचने में पीड़ा क्यों होती है, दर्द क्यों होता है। पहले की तुलना में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट आज भारत में आ रहा है।

मेक इन इंडिया की ताकत, मैन्यूफेक्चरिंग के नए प्रतिमान प्रस्थापित कर रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चरर आज हिंदुस्तान है। फसलों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन आज भारत कर रहा है। इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज़्यादा कन्जम्प्शन अगर दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान में है। स्टार्टअप इको सिस्टम ने जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई है, अपनी जड़ें जमाई हैं आज बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स को भी वह चुनौती दे रहे हैं। एविएशन सेक्टर सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ा रहा है लेकिन विपक्ष में हैं, विरोध करना ज़रूरी है। विरोध करना चाहिए। मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम मोदी की आलोचना करते-करते, बीजेपी की आलोचना करते-करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं। इससे देश का हित नहीं होगा।

(1815/RV/KMR)

हममें से किसी को भी, गलती से भी, देश की बुराई हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ... (व्यवधान) बहुत-सी बातें हैं। ... (व्यवधान) लंदन में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर-करके देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो? झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज मुझसे पूछ रहे हो कि कुछ नहीं कहा? मैं अपनी मर्यादा में रहूँ, वही ज्यादा अच्छा है। ... (व्यवधान)

आज हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने भी वही बात सदन में कही। इसका मतलब कि यह सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा कुछ बोलना, अन्दर अलग बोलना, ऐसा नहीं है। जो सच बोलता है, वह बाहर भी वही बोलता है, अन्दर भी वही बोलता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जन सभा में भी सच बोलते हैं, लोक सभा में भी सच बोलते हैं। प्रधान मंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गयी है। आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गयी है।

आपने कहा कि मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है - 'उलटा चोर चौकीदार को डाँटे।' आप जरा बताइए। मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा काँग्रेस ने, लेकिन कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया काँग्रेस ने और कहते हैं कि मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, कहने वाले काँग्रेस के, और कहते हैं कि मोदी इंस्टीट्यूशंस बर्बाद कर रहा है। कहानियाँ गढ़ी जाती हैं तख्ता पलट करने की और हिन्दुस्तान की सेना की इज्जत को कितना बड़ा गहरा घाव लगा है! आपको मालूम नहीं है। आपने हफ्ते, दो हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी। लेकिन, यह जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे, आज़ादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हों, बुरे दिन आए हों, वीक प्रधान मंत्री रहे हों, वीक गवर्नमेंट्स रही हों, एक

सरकार रही हो, मिली-जुली सरकार रही हो, पर कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया। हम ये बातें कह दें, जस्ट अपनी राजनीति के लिए! मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने बहुत बुरा किया है। हम जिम्मेदार लोग हैं। शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हों और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं?

इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केन्द्र बन सकता है। छोटी-मोटी शिकायतें रहने के बावजूद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के निर्णयों को मान कर चल रहे हैं। क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? आज हम उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या हम उस दिशा में कुछ सोच सकते हैं?

उसी प्रकार से, अपनी विफलता ई.वी.एम. पर, मैं तो हैरान हूँ! देश बजट की चर्चा करता है और ये ई.वी.एम. का रोना रो रहे थे। आप इतने डरे हुए, यह हो क्या गया है आप लोगों को?
...(व्यवधान)

(1820/MY/SNT)

न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। न्यायपालिका के निर्णयों पर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। न्यायपालिका का निर्णय अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी। लेकिन हमें पसंद न हो इसलिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें? आप पूरी ज्यूडिशिएरी को डराने के लिए महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हो?

यह कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को 'जोकरों का समूह' कहा था, मालूम है न किसने कहा था। आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने 'जोकरों का समूह' कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान होना चाहिए। एक शब्द पकड़ लिया, लेकिन बाकी जरा अपना करोबार भी तो देखो।

धारा 356 का दुरुपयोग करीब-करीब सौ बार आपने किया। चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया और अकेली श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार उसका उपयोग किया। 50 बार सरकारों को गिराया। यह 2019 किस चीज की एनीवर्सरी है, याद करें, जरा मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) 1959 में जब नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थीं, वह केरल गई थीं। पता नहीं क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना, आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह 2019 एनीवर्सरी है। आप संस्थाओं के मान-सम्मान की बातें करते हो? किस प्रकार से आपने देश के साथ क्या किया, आपने एन.टी.आर. के साथ किया? आपने एम.जी.आर. के साथ क्या किया? इतना ही नहीं, बल्कि आप मंत्रिमंडल के निर्णय तथा कैबिनेट के डिसेजन को प्रेस कांफ्रेंस में जाकर कैसे काट रहे हैं! कौन-सी सैंक्टिटी, कौन-सी संस्थाओं का सम्मान? इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी चार उंगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। खड़े जी एक डीसेन्ट व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मज़बूरी है, किस मुसीबत में फंसे हैं। ... (व्यवधान) एक डीसेन्ट व्यक्ति हर बार डिसेन्ट, हर बार डिसेन्ट, हर बार डिसेन्ट... (व्यवधान) लेकिन आप डीसेन्ट हैं, इस बात को तो मैं इस सदन के सामने कहूँगा। यह बात सही है कि आज उन्होंने कहा कि मैं जरा फर्स्ट एड ले लूँ, लेकिन करीब 36 घंटे के बाद वह पूछ रहे थे कि फर्स्ट एड की जरूरत है क्या। आप एक सीनियर व्यक्ति के नाते, हम जैसे लोगों की चिंता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया जी, इन सारी मुसीबतों के मूल में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एक गरीबी से उठा हुआ इंसान, जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वे पचा नहीं पा रहे हैं। वे तो यह मान कर चलते हैं कि इस देश की गद्दी हमारे मालिकी की है। एक कोने में पड़ा हुआ ऐसा इंसान यहां आ गया, यह बात इनके दिमाग से जाती नहीं है। वह जो नशा है, वह नशा परेशानी कर रहा है।

(1825/CP/GM)

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, अब जरा हिसाब की बातें चल रही हैं कि हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, तो मैं भी बता दूँ। 55 साल, मेरे 55 महीने। देखिए स्वच्छता का दायरा, 55 साल में 2014 का 40 पर्सेंट था, आज साढ़े चार साल में, 55 महीने के अंदर 98 पर्सेंट क्रॉस कर गया है। साढ़े 4 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। जो लोग कहते हैं कि यह सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया है। वही मेरे अमीर हैं, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है, उन्हीं के लिए जीता हूँ, उन्हीं के लिए यहां आया हूँ। 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन और 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन और उसमें 6 करोड़ उज्ज्वला। काम किस गति से होता है और किसके लिए होता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। गरीबों के नाम पर बातें कीं, राजनीति की, चुनाव जीतते गए, वोट बटोरते गए, लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50 प्रतिशत लोगों के बैंक के खाते थे, 55 महीने में अब वह शत-प्रतिशत करने में हम यशस्वी हुए हैं। आपको तकलीफ होती है 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई। आप आंकड़ा देते हैं, यानी 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी। 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी, वहीं से शुरू कर रहे हैं आप, वह बी.सी. और ए.डी. वाली बात है। अगर सचमुच में जिस गति से पिछले 55 महीने में सरकार चली है, आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थीं, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था, अगर आप उस समय काम करना चाहते, तो पहले दो दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। यह काम जो बीस साल में होना चाहिए था, वह मुझे आकर पूरा करना पड़ा है। इतना ही नहीं आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में यह कहा है कि हम 3 साल के भीतर, आपने 2004 में कहा 3 साल के भीतर, आपने 2009 में कहा 3 साल के भीतर, 2014 में कहा 3 साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे।

आपके मैनिफेस्टो में है कि बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूँ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ तो आप एक्सटेंड करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 2014 में भी 3 साल और आज घरों में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे रात-दिन मेहनत करनी पड़ रही है। ढाई करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया है और आने वाले दिनों में शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे, मैं आपको विश्वास से कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं... (व्यवधान)

2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी।

(1830/SK/RK)

देश अनुभव करता है, जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आपका शुक्रिया, धन्यवाद।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं हैं। यह महामिलावट, आप कोलकाता में इकट्ठा करो, देख लो, यह महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का... (व्यवधान) महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश ने बाहर कर दिया। ... (व्यवधान) महामिलावट देखने वालों को ... (व्यवधान) यह महामिलावट का खेल ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, अब हो गया।

... (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): अस्थिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण यह महामिलावट... (व्यवधान) देश ने 30 साल यह स्थिति देखी है... (व्यवधान) अब तो जो हैल्थ कांशियस सोसाइटी है, वह भी मिलावट से दूर रहती है। हैल्दी डेमोक्रेसी वाले भी महामिलावट से दूर रहने वाले हैं... (व्यवधान)

जब बहुमत वाली सरकार होती है, देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है तो काम कैसे होता है? वर्ष 2014 से पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए, 1947 से हर सरकार ने इस पर विचार किया है। 2014 से पहले पांच साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने में 1 करोड़ 30 लाख घर बनाकर चाबी दे दी। घर भी ऐसे जिसमें शौचालय है, बिजली है, गैस का कनेक्शन है। ऐसे ही चार दीवारी बनाकर काम पूरा नहीं कर रहे हैं। आज आप के लोग भी आकर कहते हैं कि हमारे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए, पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं हैं।

आपके 2004 के घोषणापत्र में था, 2009 में था और 2014 में भी था। आप तीन साल की बात कहां से ले आए, मुझे मालूम नहीं, तीन साल की आपकी क्या डेफिनेशन है, यह भी मुझे मालूम नहीं। आपने 2004 में भी कहा कि तीन साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह 2004 में कहा था। वही बात 2009 में कही, वही बात 2014 में कही। जब हम आए, तब 59 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था, यानी आइडिया नया है। अब आप कहेंगे कि हमारी योजना थी। आपकी योजना थी, मेनिफैस्टो में लिखा है कि करेंगे, लिख दिया। 2004 से आपने काम शुरू किया, 2014 में पहुंचते-पहुंचते 59 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो थी, वह 55 महीने की हमारी सरकार में 1 लाख 16 हजार गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे।

आज खड़गे साहब का शेर-ओ-शायरी का मिजाज़ था, हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी, उस पर उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई। आप जिस परिवेश में पैदा होकर आए हैं, आपका परिवार जिस संघर्ष से निकला है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर।

(1835/MK/PS)

अगर वे चीजें आपको याद रहती हैं, तो इस हुस्न वाली पंक्ति की तरफ आपकी नज़र नहीं जाती। अगर वह होता, तो आपकी नज़र इस पर जाती और मुझे तो आप लोगों के कारण बराबर यह बात दिन-रात याद रहती।...(व्यवधान) उस कविता में लिखा है-

“जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है,
तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा है।”

आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है, यह कविता में आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन वह नहीं देख पाए।...(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): यह कांग्रेस वालों का धोखा है।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी: उसी कविता में आगे लिखा है अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वह छूट गया होगा। अगर वह बचा होता, तो उसके आगे की पंक्ति आपके दिल को जरूर छू जाती। आगे की पंक्ति है –

“अपने घर की चारदीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है,
जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है।”

इसके लिए जब संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर यह बात बनती है।...(व्यवधान) कांग्रेस के 55 साल -- सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने -- सेवा भाव के 55 महीने। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव और जब नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हों, निष्ठा अटल हो तो हम चौबीसों घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने-आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं।...(व्यवधान) आप किस प्रकार से काम करते हैं? मैं 21वीं सदी के मतदाताओं को जरूर याद कराना चाहूंगा कि किस नीयत से 55 साल तक सत्ता भोग चला है।...(व्यवधान) आप देखिए, जब कॉमनवैलथ गेम्स हुए, तब देश की आन, बान, शान पूरे विश्व में पहुंचाने का एक स्वर्ण अवसर था, लेकिन उस समय

एक तरफ हमारे खिलाड़ी पदक जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और ये कॉमनवैल्थ में अपनी वैल्थ को जिताने में लगे थे। 2-जी स्पैक्ट्रम का आबंटन, आप देख लीजिए, 2-जी स्पैक्ट्रम में क्या हुआ। ... (व्यवधान) यह सत्ता भोग का परिणाम था और इनकी नीयत यही -- अपना और अपनों का फायदा करना, हमारी नीयत -- लोगों को सस्ता डेटा, फोन पर बात करने का खर्च कम हो। और इसके लिए स्पैक्ट्रम की नीलामी की व्यवस्था हमने विकसित की। बैंकिंग व्यवस्था -- क्या करके रखा था? फोन बैंकिंग करता था। नामदार को पता चले कि इसको मदद की जरूरत है, बैंक को फोन चला जाता था, रुपये निकल जाते थे, पहुंच जाते थे। किस काम के लिए, कौन ले जाएगा, कहां ले जाएगा, अब सब निकल रहा है, तो परेशानियां बढ़ रही हैं। ... (व्यवधान)

(1840/RPS/RC)

एक बात को नहीं भूल सकते कि स्वतंत्रता के बाद, 2008 तक बैंकों ने कुल 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया, लोन दिया, लेकिन सत्ता भोग की जो राजनीति चलती थी, जो देश चलाने का तरीका था, उस सत्ता भोग के 55 साल का परिणाम देखिए। वर्ष 2008 से 2014 तक, छः साल में यह 18 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गए। यह फोन बैंकिंग का परिणाम था, लोगों के पैसे थे, लूटे जा रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। यह आपका तरीका था। अब 21वीं सदी के मतदाताओं को पता होना चाहिए, तब उनकी उम्र इतनी छोटी रही होगी, जब ये सब खेल चले, अब उनको शिक्षित करना हम लोगों का काम है। ... (व्यवधान) मुद्रा योजना से हमने 7 लाख करोड़ रुपये दिए। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): एनपीए कितना है, बताइए?

श्री नरेन्द्र मोदी: यह वही है जो 2014 में आप छोड़कर गए, यह तो ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है। यह आप छोड़कर गए, उसका ब्याज बढ़ रहा है। हम कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपये वापस आने शुरू हुए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने 7 लाख करोड़ रुपये मुद्रा योजना से दिए। उन लोगों को दिए, जिनके पास कोलैटरल गारन्टी देने की भी कोई ताकत नहीं थी और उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। यह काम हमने किया है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): नीरव मोदी कितना रुपया लेकर भाग गया?

श्री नरेन्द्र मोदी: जो भाग गए हैं, वे ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9 हजार करोड़ रुपये लेकर निकला था, लेकिन मोदी ने मेरे 13 हजार करोड़ रुपये जब्त कर लिए। वे रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि आज मेरी इस सम्पत्ति का पता चल गया और वह भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में सम्पत्ति है तो वह भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाए। यह कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बनाकर उनको वापस लाने की कोशिश की। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी दो दिन पहले मदद की थी तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस ने यह कहा, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। तब कांग्रेस ने कहा कि हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): छः बार हुई थी। क्या मैं डेटवाइज बताऊं?

श्री नरेन्द्र मोदी: हाँ-हाँ, आपके पास सब कुछ है। ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घण्टों तक बोलने दिया है। ... (व्यवधान) उस समय सेना की वह हालत ही नहीं रहने दी थी आपने, सेना को आपने एक प्रकार से निहत्था बना दिया था। वह स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। यह हाल आपने बनाकर रखा था। वे दिन थे, जब बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक उपलब्ध नहीं थीं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की सोच भी कैसे सकते थे और आप हिन्दुस्तान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्यूनिकेशन डिवाइसेस थीं, न हेलमेट थे और न अच्छे प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य व्यवस्थाओं की बात है। 2009 में

भारतीय सेना ने एक लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट्स की मांग की, पांच साल बाद भी, 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं खरीदी गईं। अब वे लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद की।

(1845/RAJ/SNB)

2018 में 1 लाख, 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमने अपने जवानों को पहुंचा दिए। अगर 2014 में, उसके बाद भी देश की जनता ज्यादा समझदार है, इसलिए गलती नहीं करती है, लेकिन 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार बनी होती तो देश का गौरव, तेजस लड़ाकू विमान, आज जमीन पर ही खड़ा होता, वहां पार्किंग में पड़ा होता, वह हवा में नहीं जाता। जुलाई, 2016 में हमने 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया और 83 तेजस विमान खरीदने की स्वीकृति दे दी। आपको इसकी चिंता नहीं थी। सेना ताकतवर हो, आपने यह कभी नहीं सोचा...(व्यवधान) देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आप में इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? कांग्रेस की पिछली सरकार ने पिछले दस सालों में सेना, वायु सेना और नेवी की आवश्यकताओं को नरजअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए, उस समय हमारे दुश्मन देशों ने कोई हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना criminal negligence किया है। देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता है। आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार के वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे यह बताइए कि तीन दशक हो गए, क्या कारण है कि देश ने एक भी next generation fighter planes हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया है। Not a single in 30 years. जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या यह देश की सुरक्षा का यह विषय, देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है...(व्यवधान)

दादा को राफेल के बारे में सुनना है। एक-एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन-गिन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में, हमारी वायु सेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं।

...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि हमारी वायु सेना मजबूत हो।...(व्यवधान) राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे आप किसकी भलाई के लिए लगे हो?...(व्यवधान) आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो?...(व्यवधान) कौन लोग हैं, जिन्होंने आपको लगाया है?...(व्यवधान) आप देश की सेना के साथ यह व्यवहार करते हो? आपने तीस साल तक देश की सेना को निहत्था बना कर रखा था।...(व्यवधान) इतिहास गवाह है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)... (Not recorded)

श्री नरेन्द्र मोदी : इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का काल खंड रक्षा सौदों में 'दलाली' के बिना कभी काम नहीं हुआ।...(व्यवधान) मैं सोच रहा था कि राफेल को लेकर ये 'झूठ' भी इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं। जब मैं डीटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वह यह मान कर चले हैं कि पिछले 55 सालों में, सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना 'दलाली' नहीं हुआ है। कहां से कोई चाचा, कोई मामा ... (व्यवधान) जब पारदर्शिता से, ईमानदारी से देश की वायु सेना को मजबूत करने का काम हो रहा है तो ये कांग्रेस के लोग ज़रा बौखला जाते हैं।

(1850/IND/NKL)

उनको सच सुनने की आदत रही नहीं है और अब परेशानी है। चेहरे उतरे हुए हैं और कारण यही है, क्योंकि अब राज़दार को पकड़कर लाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन राज़दार सामने आए हैं। आपकी चिंता यह है कि ये कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है? छुप-छुपकर चिट्ठियां पकड़ाई जाती हैं और इसलिए आपकी बेचैनी में समझ सकता हूं। जहां तक काले धन का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, हम आज भी जीरो टोलरेंस के साथ प्रतिबद्ध हैं। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो यह नहीं चाहता होगा कि देश से भ्रष्टाचार खत्म न हो। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन किसी न

किसी के हाथ-पैर कहीं फंसे हुए थे, इसलिए चाहते हुए भी कर नहीं पाते थे। हमारा कोई बैगेज नहीं है और न हमें किसी पर एहसान करना है और न किसी के एहसान पर हम जिंदा हैं। हम तो सवा सौ करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से जिंदा हैं और इसलिए जी जान से काला धन हो या भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का माद्दा रखते हैं और अभी तक पीछे नहीं हटे हैं और उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। आठ करोड़ लोगों को जो इस व्यवस्था में थे, जो दलाली लेते थे, आधार की व्यवस्था से आठ करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। क्या किया दादा? यह किया। बेनामी सम्पत्ति का कानून तो कितने साल से बना पड़ा था, संसद में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उस कानून को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसी प्रकार रख लिया, लेकिन हमने आकर उस पर कानून बनाया और बेनामी सम्पत्ति आज जब्त हो रही है। उसी के कारण लोग परेशान हैं और आज प्रॉपर्टी निकल रही है। कहां-कहां, कैसे-कैसे, कौन-कौन, किसके लिए, कब-कब, और इसलिए परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जो संकल्प लेकर चले हैं, इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, रुकावटें अनेक हैं, लेकिन जितनी रुकावटें हैं, उनसे ज्यादा मजबूत हमारा संकल्प है। जितनी रुकावटें हैं, उनसे ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं। आपको नोटबंदी की परेशानी हो रही है। नोटबंदी के बाद तीन लाख फर्जी कम्पनियां जो रुपयों का कारोबार करती थीं, डोनेशन लेना-देना आदि करती थीं, यह सब बंद हो गया। यह कारोबार चलता रहता, यदि पुराना सिस्टम होता। यह 55 महीने वाली सेवा भाव वाली सरकार है, राष्ट्र को समर्पित सरकार है, इसलिए यह संभव हुआ है। आईबीसी कानून के तहत तीन लाख करोड़ रुपये वापस आए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, एक और जानकारी शायद सदन में बहुत लोगों को अचरज करेगी। हमने आकर देश में भिन्न-भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी। हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है। एफसीआरए कानून के तहत आपको परमिशन मिली हुई है।

(1855/PC/SRG)

आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए। विदेशों से पैसा आता है, उसे कहां उपयोग करते हैं? इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है। एक छोटी सी चिट्ठी गई थी। आप हैरान हो जाएंगे कि इस देश में 20 हजार से ज्यादा संगठनों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं, जो विदेशों से धन लेते थे। ... (व्यवधान) ये 20 हजार संस्थाएं क्या करती थीं? सीमावर्ती गांवों से लेकर, संसद से लेकर, न्याय तंत्र और न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था। ... (व्यवधान) उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। ... (व्यवधान) 20 हजार संस्थाएं? क्या आप ये नहीं रोक सकते थे? क्यों चलने दीं? क्या आर्शीवाद थे? आपका क्या भला होता था? ये विदेशी धन लाने के रास्ते किस के लिए थे? ... (व्यवधान) ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली-गलौज सुनने को मिलती है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। ... (व्यवधान) उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है, तो क्या होता है, यह इससे पता चलता है। 20 हजार संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है। ... (व्यवधान) अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत बड़े-बड़े नाम थे, वे ऑफिशियली हिन्दुस्तान में अपना कारोबार बंद कर के नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, यह हाल पैदा हो गया है। ... (व्यवधान) आपने देखा होगा। मुझे याद है गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम है। पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था और अभी मैंने उद्घाटन किया है। ... (व्यवधान) इसके पीछे विदेशी धन से खेलने वाले एन.जी.ओ. थे। किसी ने इनको नहीं रोक। 20 हजार संस्थाएं बंद हुई हैं। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हम पाई-पाई का हिसाब ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, 55 साल के सत्ता भोग ने कुछ दलों के लोगों की आदत ऐसी खराब कर दी है, वे अपने आप को ऐसा शहंशाह मानते हैं और बाकियों को ऐसा निकृष्ट मानते हैं। ... (व्यवधान)

वे हर व्यवस्था को निकृष्ट मानते हैं। ...(व्यवधान) हर किसी का अपमान करना मानो उनके स्वाभाव में है। ...(व्यवधान) हर किसी को अपमानित करना उनके स्वाभाव में है। ...(व्यवधान) इसलिए मुख्य न्यायाधीश को विवाद में घेरना, पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना, न्याय तंत्र का अपमान करना, रिज़र्व बैंक का अपमान करना, सेनाध्यक्ष का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, देश की सब से बड़ी जांच एजेंसी का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना - यह मैं समझता हूँ सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे। उनको यह अंदाज हो गया था कि सारी बीमारियों की रिसेविंग केपेसिटी सब से किसी की ज़्यादा है, तो कांग्रेस की है। इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत - यह मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) 150 साल हो रहे हैं महात्मा गांधी जी के, श्रद्धांजलि के रूप में यह काम करना ही करना है। ...(व्यवधान) कितनी ही मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। ...(व्यवधान) हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग हैं। ...(व्यवधान) हमारे लिए हम से बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा जी, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, भ्रष्टाचार, वंशवाद - एक प्रकार से कांग्रेस के साथियों ने भी यह मिलावट कल्चर स्वीकार कर लिया है। वंशवाद के बाहर उनका एक भी साथी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए यह संस्कार बन गया है, यह उनकी संस्कृति बन गई है। ...(व्यवधान) इसलिए, यह महा-मिलावट का खेल बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सभी वंशवादी हैं। ...(व्यवधान) करीब-करीब थोक में सब बेल पर हैं। ...(व्यवधान)

(1900/SPS/RP)

फिर बड़ा स्वाभाविक है। ... (व्यवधान) मिलना और पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुझसे ज्यादा पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होता। हम जानते हैं और जो आज आपके पास आए हैं, वे उस समय भी हमारे पास थे और उस समय भी उन्होंने ऐसे ही धोखा किया था। ... (व्यवधान) इन धोखेबाज लोगों को लेकर मिलावटी कल्चर से देश का महाविलावट-महाविलावट करते रहो। आज यहां बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हुई। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का उल्लेख हुआ। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था और हो सकता है कि मिलावट के रास्ते पर गए हुए कुछ लोगों को शायद बाबा साहेब अम्बेडकर में श्रद्धा हो तो काम आएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का वाक्य है। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। ... (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि “कांग्रेस एक जलता मकान है” ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): कांग्रेस ने ही उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। क्या आपने बनाया था या मोदी जी ने बनाया था? ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : खड़गे जी, आपका सी.आर. कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सी.आर. की चिंता नहीं है, मैं जो भी जी रहा हूं, मेरा कहना है कि मेरा जो यह जीना है, यह बहुत है। मेरी उम्र साठ साल तक थी, लेकिन मैं 77 साल तक जो जी रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोदी : आपको शतायु होना है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदया जी, आज यहां सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं। हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में सिनेमा में दो गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे। एक था, “बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे” और दूसरा गाना था महंगाई का

जो पॉप्युलर हुआ था, “महंगाई डायन खाए जात है।” अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉप्युलर हुआ था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं और इन्फ्लेशन 20 प्रतिशत से ज्यादा था। दूसरा गाना, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10 प्रतिशत से ज्यादा इन्फ्लेशन था, तब ये गाने लिखे गए हैं, तब ये गाने पॉप्युलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है। इस देश में जब भी कांग्रेस आई है, महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30 परसेंट से प्लस इन्फ्लेशन चला गया था। ये कारोबार आपने किया था। अब आप कल 1947 से शुरू कर रहे थे। मैं खोलकर रखूंगा तो पता नहीं क्या-क्या निकलेगा? इसलिए बीते 4.5 वर्ष में महंगाई की दर को 55 महीने में सेवा भाव से चलने वाली सरकार ने 4 प्रतिशत की मर्यादा में बांधकर रखा है। मध्यम वर्गीय समाज के लिए बहुत सारी मदद करने के काम हमारी सरकार लगातार करती रही है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि आई है, मध्यम वर्ग की आशाएं, अपेक्षा बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ कि किसी भी देश की प्रगति के विकास के लिए बहुत अनिवार्य अंग हैं, जो आज देश 55 महीने में अनुभव कर रहा है।

(1905/MM/RCP)

नई-नई एस्पिरेशंस, नई-नई अपेक्षाएं, नई-नई आकांक्षाएं विकास की सबसे बड़ी निशानी होती है, जो आज देश में नजर आ रहा है। कुछ लोगों को आशाएं-अपेक्षाएं बोझ लग रही हैं, मैं इसको गौरव से देखता हूँ, क्योंकि वे दौड़ने की ताकत देती हैं, न्याय करने की प्रेरणा देती हैं।

जीएसटी के बाद जरूरी सामान को टैक्स के दायरे से बाहर करने का काम हमने किया है। आप याद कीजिए, दूध पर भी आप टैक्स लेते थे, न जाने कैसी-कैसी चीज पर टैक्स लेते थे। आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। एवरेज टैक्स जीएसटी से पहले 30 प्रतिशत से ज्यादा हुआ करता था। आप कैसी बातें बताते हैं? जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है, जिसमें आपके दल के लोग भी होते हैं, आपके दल के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के लोग भी होते हैं। आज 99 परसेंट सामान या उससे ज्यादा सामान पर टैक्स 18 परसेंट या उससे कम आया है। इस बजट में भी इंकम टैक्स के तहत पांच लाख रुपये पर राहत देने का काम हमने किया है। यह मांग हमारे समय में आयी है, ऐसा

नहीं है। जब इकोनॉमिस्ट प्रधान मंत्री थे, तब भी आती थी, वर्ष 1992 में भी ऐसी मांग आती थी, लेकिन इतने सालों तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने इसकी चिंता की है।

एजुकेशन लोन, हमारा मिडिल क्लास का परिवार एजुकेशन लोन लेता है। उस पर ब्याज 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत हमने किया है। उसके कारण अगर एक नौजवान विद्यार्थी दस लाख रुपये का लोन लेता है तो आज उसको लोन भरते-भरते सवा लाख रुपये की बचत होती है। उसी प्रकार से आवास में मध्यम वर्गीय परिवार बैंक से अगर लोन लेता है तो बैंक में पैसा जमा करते-करते उसे 5 से 6 लाख रुपये तक की बचत होती है। यह काम हमने करके दिया है।

इसी प्रकार से एलईडी बल्ब है। मैं हैरान हूँ कि क्या कारण था कि यूपीए की सरकार के समय में एलईडी बल्ब 300, 400 और 450 रुपये में बिकता था? ऐसा क्या कारण है कि हमारे आने के बाद वह 60-70 रुपये पर आ गया है? देश में करोड़ों एलईडी बिक बल्ब गए हैं। कितने करोड़ों रुपये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बचा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस एलईडी बल्ब के कारण देश में 50 हजार करोड़ रुपये की बिजली का बिल लोगों का कम हुआ है। 50 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब में बचा है। यह बहुत बड़ा काम एक एलईडी बल्ब के माध्यम से हुआ है। अगर मैं 50 हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित करता तो मीडिया में चौबीसों घंटे चर्चा चलती, हर अखबार की हेडलाइन होती। यह 50 हजार करोड़ रुपये बचाकर के देश के मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

दिल की बीमारी के स्टेंट कितने महंगे थे, हमने सस्ते कर दिए। नी-इम्प्लांट का काम कितना सस्ता हो गया है, यह हमने करके दिखाया। हम मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर गए हैं। पहले गरीब व्यक्ति को डायलिसिस के लिए दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। आज उसको मुफ्त में यह सुविधा देने का काम हमने किया है। पांच हजार से ज्यादा जनऔषधि केन्द्र हमने शुरू किए हैं। उन जनऔषधि केन्द्रों का परिणाम है कि आज गरीब परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार हों, 60 से ऊपर की उम्र के लोग साथ में रहते हों तो उनकी दवा खरीदने का काम होता रहता है। आज सौ रुपये की जेनरिक दवाई 30 रुपये में मिलने लगी है। यह मध्यम वर्ग को सबसे

बड़ा लाभ देने का काम हमने किया है। इसी प्रकार से गरीब के इलाज की हमने चिंता की है। मैं हैरान हूँ कि आयुष्मान भारत में मोदी की चिट्ठी को लेकर लोग परेशान हैं। देश का प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखता है तो एक प्रकार से बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेता है, बहुत बड़ा कमिटमेंट देता है और सामान्य मानवी को विश्वास देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज इस सदन को सचमुच में खुशी होनी चाहिए कि इस देश के गरीब, जो अपनी गरीबी के कारण मौत का इंतजार करते थे, लेकिन अस्पताल की राह जाने की हिम्मत नहीं करते थे और सामान्य जड़ी-बूटी लेकर गुजारा कर लेते थे, गम्भीर से गम्भीर बीमारी में भी दिन काटते थे और परिवार के लोगों की स्थिति भी ऐसी होती थी कि इनके लिए क्या किया जाए? दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल से गम्भीर बीमारी में पड़े हुए लोग, अभी सौ दिन से कुछ ज्यादा दिन ही आयुष्मान भारत योजना को हुए हैं, अब तक करीब-करीब 11 लाख गरीबों ने इसका ऑलरेडी फायदा उठाया है।

(1910/SJN/SMN)

गंभीर प्रकार की बीमारियों में लाभ मिला है। प्रतिदिन 15 हजार से ज्यादा गरीब इस 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत फायदा उठा रहे हैं। यह हम सबका दायित्व है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए हमारे सभी एम.पी. चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी है, फलानी बीमारी है, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे दीजिए और प्रधानमंत्री राहत कोष से हम इस काम को लगातार करते रहते हैं, मेरे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन इस 'आयुष्मान भारत' के बाद आज किसी एमपी को इस प्रकार की चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आ रही है। उसको गोल्ड कार्ड मिल गया, उसका काम तुरंत हो जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष से तो कुछ सीमा तक पैसे दिए जाते थे, इसमें पूरा का पूरा खर्चा दिया जा रहा है। हर एम.पी. प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले पैसों के संबंध में मुझसे हमेशा मिलते थे और संतोष व्यक्त करते थे कि मेरे इलाके में इतने लोगों का फायदा हो गया है। पहले सप्ताह में हो गया है, तीसरे सप्ताह में हो गया है। मैं उनको भी चिट्ठी लिखता हूँ। प्रधानमंत्री राहत कोष में से जिनको भी पैसा मिलता है, मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि पक्का होना चाहिए कि वह सचमुच में बीमार था या नहीं था।

मैं जब गुजरात में था, तब हमने एक प्रयोग किया था। सर्किट हाउस में लोग रहते थे। नेता लोग हैं, तो उन्हें कन्सेशन से सर्किट हाउस मिल जाता है। हमारे सर्किट हाउस के एक मैनेजर थे, जितने लोग रहते थे, उनको फिर चिट्ठी लिखते थे कि आप और आपकी पत्नी फलानी तारीख को आए थे, आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई होगी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोगों ने आना ही बंद कर दिया... (व्यवधान) मैं चिट्ठी लिखता था... (व्यवधान) कि आपको इस बीमारी के नाते मैंने इतना पैसा भेजा है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहा होगा। उसको फिर आधार से भी जोड़ दिया, एक नये पैसे का लीकेज नहीं, 'दलाल' नहीं। लेकिन 'आयुष्मान भारत' से मैं सभी एमपी से आग्रह करता हूँ कि आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने गरीबों को आप अपने क्षेत्रों में 'आयुष्मान भारत' का लाभ दिला सकते हैं, दिलाइए। मैं आपको स्वस्थ स्पर्धा के लिए निमंत्रित करता हूँ। गरीबों का भला होगा, चुनाव तो आएंगे और जाएंगे। अभी दो-तीन महीने हैं, कुछ काम कर लीजिए। आपके लिए मौका है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया जी, मैं एक विषय को जरा विस्तार से बताना चाहता हूँ। विस्तार से बताने की बात अब शुरू कर रहा हूँ... (व्यवधान) संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाल्यूट कर सकते हैं, उस रास्ते को हमने चुना है। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10 प्रतिशत गरीबों को आरक्षण दिया है। यह विषय कोई हमारे आने के बाद आया है, ऐसा नहीं है। यह पहले से था। हमने हिम्मत दिखाई है और मैं इस सदन का आभारी हूँ, सबका आभारी हूँ कि सबने सर्वसम्मति से इस पर साथ दिया है। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हरेक का आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ बाकी के साथ अन्याय न हो, इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है, ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है, उसको कोई तकलीफ न हो। 55 साल के शासन के बावजूद... (व्यवधान) अब मैं जरा सत्ता भोग का हाल क्या है... (व्यवधान) जॉब के संबंध में 55 सालों तक कोई स्टैंडर्ड व्यवस्था विकसित ही नहीं हुई थी। पुरानी सरकारों के लिए वह

कोई एजेंडा ही नहीं था कि रोजगार को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सत्ता भोग में डूबे हुए लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हमने आकर कोशिश की है। अगर 100 सेक्टरों में नई नौकरियां बन रही हैं, तो सिर्फ उसमें 7-8 सेक्टर को गिनकर एक मोटा-मोटा अनुमान लगाया है। आज जो पद्धति है कि 100 सेक्टर में रोजगार है, तो 7 या 8 सेक्टर में टोकन सर्वे होता है और उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है।

(1915/BKS/MMN)

अब आज वक्त बदल चुका है, सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं, रोजगार के प्रकार बदल चुके हैं। इसलिए मैं आज इस सदन को सच्चाई बताना चाहता हूं और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, हकीकतों के आधार पर बताना चाहता हूं और मैं देशवासी जो टी.वी. पर देखते हैं, उनको विशेष रूप से कहता हूं कि मेरे आगे के भाषण के बजाय इसको गंभीरता से सुनिये, ताकि जिस प्रकार से सत्य को कहीं जगह नहीं, ऐसे सत्ताभोगी लोग जो बातें कर रहे हैं, उनको जरा सीधा-सीधा जवाब देश की जनता दे सकती है।

अब देखिये, देश में असंगठित क्षेत्र करीब-करीब 85 से 90 परसेंट नौकरियां देता है। जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10 से 15 परसेंट ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में 80 से 90 परसेंट है, जब कि आर्गेनाइज्ड सैक्टर में ऑनली 10 से 15 परसेंट है। जो सैक्टर नौकरियों का सिर्फ 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जरा वह 10 परसेंट वाला हिसाब देना चाहता हूं। 90 परसेंट वाला हिसाब बाद में देखते हैं। सितम्बर, 2017 से लेकर नवम्बर, 2018 तक यानी करीब-करीब 15 महीने में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। क्या यह बिना रोजगार होता है? इनमें से 64 परसेंट लोग हैं, जिनकी उम्र 28 साल से कम है। इसलिए खड़गे जी आज जो सुबह आर्थ्यूमेंट दे रहे थे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। 28 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब नया जॉब प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है।

इसके अलावा एक और तथ्य मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश में मार्च, 2014 में करीब-करीब 65 लाख लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई। क्या यह भी बिना नौकरी के हुआ होगा, क्या कोई ऐसे ही कर देता होगा? ...(व्यवधान)

इसलिए एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो अपनी आय घोषित करते हैं, उन्हें खुद सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग अपने यहां जिन लोगों को नियुक्त करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। पिछले चार वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6 लाख 35 हजार नये प्रोफेशनल्स जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डाक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा? कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है तो क्या वह किसी को रोजगार नहीं देता होगा? क्या वह एक, दो या तीन लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा? 6 लाख 35 हजार प्रोफेशनल्स ने जिन लोगों को काम पर रखा होगा। मैं फिर कहूंगा कि यह फॉर्मल सैक्टर का आंकड़ा है, जो सिर्फ 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है, उसके आधार पर मैंने बताया है।

अब मैं आपको जरा इनफॉर्मल सैक्टर का आंकड़ा देता हूँ। इनफॉर्मल सैक्टर में ट्रांसपोर्ट सैक्टर, जो असंगठित कामगार होते हैं, ट्रांसपोर्ट सैक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर होता है। बीते चार वर्षों में ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): पानी पीजिए सर।

श्री नरेन्द्र मोदी: थैंक यू, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। ...(व्यवधान) सदन में आप जैसे लोग रहने चाहिए, ताकि चिंता रहती है। बीते चार वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक या कमर्शियल व्हीकल्स बिके हैं, करीब डेढ़ करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं।

(1920/KN/VR)

27 लाख से ज़्यादा नए ऑटों की बिक्री हुई हैं। ये सारी गाड़ियाँ, जिन्होंने भी खरीदी हैं क्या उन्होंने पार्किंग करके रखी है, शोभा के लिए रखी है क्या? उनको चलाने वाला नहीं होगा क्या? उनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती होगी क्या? क्या उनके मेन्टीनेंस के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता होगा? एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते साढ़े चार वर्षों में करीब-करीब सवा करोड़ लोगों को नए अवसर मिले होंगे।

इसी तरह अगर मैं होटल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो अप्रूव्ड होटलों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या ये होटल खाली पड़े हैं? क्या वे किसी को जॉब नहीं दे रहे हैं? अनुमान यह भी हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर में करीब-करीब डेढ़ करोड़ नई नौकरियों का निर्माण हुआ है। देश में टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस का इतना विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष के मेरे साथियों को लगता है कि तमाम ऐप बेस कम्पनियाँ, यह कर रही है। यह ऐप बेस कर रही है, क्या ड्राइवरलैस कार चल रही है? ऐप बेस हो रहा है तो क्या ड्राइवरलैस कार है? उसमें भी कोई न कोई गाड़ी चलाता है। उसमें भी कोई न कोई रोज़गार पाता है।...(व्यवधान)

मुद्रा योजना के तहत पहली बार लोन पाने वाले लोगों की संख्या सवा चार करोड़ से ज़्यादा है। फर्स्ट टाइमर यानी इन सवा चार करोड़ लोगों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये लोग जॉब डेटा के अंदर नहीं होते हैं।...(व्यवधान)

इसी तरह हमारी सरकार के दौरान दो लाख से ज़्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी? एक जमाना था, एसटीडी का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोज़गार के आँकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज दो लाख कॉमन सर्विस सेंटर करीब-करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक-एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएँ दे रही हैं।

उसी प्रकार से देश में दुगुनी गति से हाइवे बन रहे हैं। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। करोड़ों-करोड़ों नए घर बन रहे हैं। क्या यह भी किसी को रोज़गार के

अवसर नहीं देते हैं? हमारे देश का नौजवान आज अपने दम पर खड़ा हुआ है। रिकल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना इत्यादि। ये स्वरोजगार के ऐसे मजबूत हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो देश में...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हमारे देश का युवा, हमारे देश के भविष्य के साथ सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी के साथ-साथ हमारे देश के किसानों की चिंता भी जिस प्रकार से की गई है, ज़रा बजट देख लीजिए, आपके समय में कितना बजट खर्च होता था और हमारे समय में कितना खर्च होता है। आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ आपकी सरकारें थीं, एमएसपी में कितनी खरीदी करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करती हैं, ज़रा आँकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग 55 महीने का सेवा भाव, यह आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नज़र आएगा। आपने दस साल में चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया है। यह आपने अपना खेल शुरू किया है। दस साल हवा बनाते चलो और आँख में धूल झाँको। फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो...(व्यवधान) यह आपकी 10 वार्षिक योजना है। वर्ष 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था। इतना बड़ा उन्होंने ताम-झाम, होहल्ला किया और उनकी इको-सिटी में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है। वह भी गाजे-बाजे बजाने लग जाते हैं।

(1925/RV/SAN)

6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था और आपने माफ कितना किया, 52,000 करोड़ रुपये...(व्यवधान) यह क्या है और यह किसको जाता है? बैंक में जो बड़े लोग पैसे ले जाते हैं, यह उनको जाता है। जो गरीब किसान है, उस बेचारे को तो अगर कोई जरूरत हो तो उसे साहूकार के पास जाना पड़ता है। वह ब्याज देने में मर जाता है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। उस समय जो सी. एण्ड ए.जी. की रिपोर्ट है, वह इसी सदन में रखी गयी थी। लेकिन, उस समय इतना बड़े-बड़े करप्शन का कारोबार चलता था कि बहुत-सी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था। 2-जी चलता था,

कोयला चलता था, न जाने क्या-क्या चलता था और कैसे-कैसे लोग चलाते थे? किस-किस समय चलाते थे? लेकिन, उस समय की सी. एण्ड ए.जी. रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ रुपये के लोन में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए, जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वे पैसे ले रहे थे...(व्यवधान) इसमें भी 'दलाली', इसमें भी खेल! इतना ही नहीं, जब हम इस योजना को लाए हैं तो हमारा साफ मत है कि हम कैसे भला करेंगे। किसान के लिए हमारी सोच क्या रही है? हम भी कर्ज माफी के रास्ते पर जा सकते थे। लेकिन, एम्पावरमेंट-ऑफ-किसान, उसकी समस्या का कायम समाधान, 99 सिंचाई की योजनाएं थीं। आज आपको 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' से तकलीफ हो रही थी। 99 सिंचाई योजनाएं थीं। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां नेहरू जी ने एक पत्थर डाला था और मैंने जाकर उसका उद्घाटन किया। 99 ऐसी योजनाएं, जो लटकी पड़ी थीं, हजारों करोड़ रुपये खर्च करके उन योजनाओं को पूरा करने का काम हमने किया है...(व्यवधान)

हमने नए मेगा फूड पार्क, नए कोल्ड स्टोरेज पर बल दिया है। 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने e-NAM के माध्यम से किसानों को अपने माल बेचने की ऑनलाइन व्यवस्था मुहैया की है, ताकि किसानों को पूरा दाम मिल सके...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस योजना में, किसानों के लिए इस बार के बजट में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से देना तय किया है। यह निर्णय आने वाले समय में दूरगामी परिणाम देने वाला है। 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी बनेंगे। आपकी अब तक की योजनाएं एक करोड़, डेढ़ करोड़, दो करोड़ किसानों तक ही सीमित थीं। वे ऊपरी सतह के लोगों के लिए थीं। एक एकड़, दो एकड़ भूमि वाले किसानों तक वे कभी पहुंची नहीं थीं। पर, यह योजना ऐसी है, जो एक एकड़, दो एकड़ वाले छोटे किसानों के लिए है। इस देश के 85% किसान ऐसे हैं। इन्हें यह लाभ मिलने वाला है और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ उनके बैंक खातों में जाएगा और उसमें कोई दलाल नहीं होगा। मैं हैरान हूँ। कुछ राज्य बड़ा सीना तानकर कह रहे हैं कि हम मोदी की किसान योजना को नहीं लेंगे। अरे, जरा वहां के किसानों से तो पूछो कि 6,000 रुपये आने हैं, उसे यह लेना है या नहीं। आपको तो एक रुपया देना नहीं है। यह तो सीधा जाने वाला है। लेकिन, राजनीति में कुछ लोगों को

ऐसा 'पागलपन' हो जाता है कि वे घोषणा कर देते हैं कि इस योजना का लाभ नहीं लेना। अरे, अपने किसानों की चिंता करो। हम 'आयुष्मान योजना' नहीं लेंगे। अरे, अपने यहां के गरीबों की चिंता कीजिए। यह राजनीति चलती रहेगी, यह खेल करना बंद करो और अपने गरीबों, किसानों की चिंता करो...(व्यवधान)

साहूकारों से लोन लेने वाले छोटे किसानों की कोई कर्जमाफी नहीं होती है...(व्यवधान) मैं जरा कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं...(व्यवधान) आप कर्नाटक से हैं और किसान नेता स्वयं यहां बैठे हैं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी अपने आपको एक किसान-पुत्र के रूप में लोगों को हमेशा बताते रहते हैं...(व्यवधान) आपकी सरकार, आपने बड़ी घोषणाएं की थीं और हमें कहते हैं कि मोदी ने घोषणाएं करके वोट ले लिया। आपने कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने को कहा था। इसके लाभार्थी 43 लाख हैं। According to Government's record of Karnataka, 43 लाख लोग इसके हितकारी हैं और अभी तक सिर्फ 60 हजार लोगों को लाभ मिला है...(व्यवधान) यह मैं आपके सरकार की बात बताता हूं। 43 लाख लोगों में से सिर्फ 60 हजार का किया और आप दुनिया को कर्ज माफी के नाम पर बता रहे हैं - 'दस दिनों में कर्ज माफी, दस दिनों में कर्ज माफी।' राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर आइए। वहां अभी तो कागज पर चिट्ठियां नहीं बन पा रही हैं। आप बातें बड़ी-बड़ी करते थे।

(1930/MY/RBN)

मैं बताता हूं कि आप अपने दस वर्ष के खेल में एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपये माफ करते थे। आप दस साल में एक बार करते थे और ऊपर के जो दो-तीन करोड़ किसान होते हैं, वही उनके हितकारी होते थे। सभी के पास लाभ पहुंचता तो था नहीं, लेकिन हमारी योजना प्रतिवर्ष है। अगर मैं दस साल का हिसाब लगाऊं, तो किसानों के खाते में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। कहां 50-52 हजार करोड़ रुपये का खेल और कहां साढ़े सात लाख करोड़ रुपये देश के किसानों के हाथ में जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि हमने इस बजट में 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग', के तहत मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है और पशुपालन करने वालों

के लिए भी व्यवस्था की है। जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का बैनिफिट मिलता था, वह बेनिफिट पशुपालक और मछलीपालन करने वालों को भी मिलने वाला है। अब इसका फायदा होने वाला है। हमने उन लोगों के विषय में सोचा। एक संवेदनशील सरकार कैसे काम कर सकती है? आप कहेंगे कि हमारे समय में भी था, हमारे समय में भी था। भाई, सब कुछ आपके समय में था, लेकिन मेरी काफी ताकत तो आपके किए हुए चीजों को पूरा करने में ही जा रही है, क्योंकि आपने ऐसे-ऐसे कामों में हाथ लगाकर छोड़ दिया है कि जिसको अब हमें पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उसको भी खुशी-खुशी पूरा करूंगा।

अब मुझे टीकाकरण के बारे में बताइए। यह मोदी के आने के बाद आया है क्या? टीकाकरण पहले भी था, लेकिन टीकाकरण होना चाहिए था। उस बच्चे तथा माँ को उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वह काम नहीं होता था। हमारे गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित छूट जाते थे। हमने 'मिशन इन्द्रधनुष' चलाया, आज हमने टीकाकरण का दायरा चौड़ा कर दिया और इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण आपके जमाने में भी था, लेकिन वह टीका किसी के टीके के लिए रह जाता था। वह टीका गरीब के घर तक नहीं पहुंचता था। इस काम को हमने करने का काम किया है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों के लिए हमने स्किल डेवलपमेन्ट का काम, स्वरोजगार का काम तथा उसके लिए कौशल विकास का एक बड़ा अभियान चलाया है। हमने 'स्किल इंडिया अभियान' के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है। 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना', कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की कई वर्षों से अन-ऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए मांग रहती थी। 40-42 करोड़ अन-ऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं। पहली बार हमने उनके लिए हाथ लगाया और तीन हजार रुपये की पेंशन की व्यवस्था अन-ऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए लेकर आये। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जो सोती रही, वह नहीं कर पायी। लेकिन, वह काम करने का काम हमने किया है। हमारे देश में मछुआरों की एक मांग रहती थी कि हमारे लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हमारी

सरकार ने इस बार बजट में कहा है। हमने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

उसी प्रकार से देश की आर्थिक गतिविधि में ट्रेडर्स का रोल है, लेकिन उनकी चिंता करने वाला कोई मालिक नहीं था। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार ने डी.आई.पी.पी. को बदलकर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्डस्ट्री इन्टरनल ट्रेड के साथ जोड़ दिया है, ताकि ट्रेडर्स की देखभाल करने वाला भारत सरकार में भी एक विभाग होना चाहिए।

घुमंतू समुदाय, ये समुदाय कोई मेरे आने के बाद घुमंतू नहीं हुए, बल्कि सदियों से ये समुदाय हैं। आप तो गरीबों के लिए नारे लगाते थे, लेकिन घुमंतू समुदाय के लिए, जो सांप-सपेरे वाले लोग हैं, आप किसी विदेशी मेहमान को दिखाने लिए सपेरे वालों को बैठा देते थे। लेकिन, आपको उनकी चिंता करने की फुर्सत नहीं थी। हमने पहली बार घुमंतू समुदाय के वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाने का निर्णय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के उस वर्ग को भी मिले। मेरा अनुभव है और जब मैं गुजरात में था, तो मैं घुमंतू जाति के लोगों के मकान के लिए काम कर रहा था। मेरी इच्छा थी कि उनके बच्चे भी पढ़ें। लेकिन वे कह रहे थे कि साहब हमारा तो घर ही नहीं है, हम रहेंगे कहां, हम स्कूलों में क्या जाएंगे। मैंने उनको घर दिया, इसलिए आज मैं गर्व से कहता हूं कि आज उनके बच्चों कम्प्यूटर चला रहे हैं और बड़े शान से जीवन जी रहे हैं। अगर इन समाजों में शक्ति है तो हम उन समाजों की भलाई के लिए काम करें और इसे हम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया जी, विदेश के संबंध में हमारी सुषमा जी कई बार कई बातें कह चुकी हैं, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं, लेकिन यह एक बात नहीं है। यह निश्चित है कि आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, आज यह दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। आज जब विश्व में कोई निर्णय होता है तो निर्णय के पहले, आप पेरिस एग्रीमेन्ट देख लीजिए, पेरिस एग्रीमेन्ट के फाइनल होने से पहले लगातार दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ टेलीफोन पर भारत से बात करती थी कि यह शब्द रखें या न रखें।

(1935/CP/SM)

यानी आज भारत ने अपनी जगह बना ली है। फिलीस्तीन और इजरायल के बीच में तनाव होगा, लेकिन फिलीस्तीन और इजरायल दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच में तनाव होगा, लेकिन सऊदी अरब और ईरान दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं।

हमारा विदेश में रहने वाला जो भारतीय समुदाय है, हमने कभी उसकी अहमियत नहीं मानी। मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों की भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। विदेश में रहने वाले भारतीय हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत हैं। हमने इसको पहचाना है और आज इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वे हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस बनारस में हुआ, वह अब तक के प्रवासी भारतीय दिवसों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला था।

यह खुशी की बात है कि कुंभ को विश्व ने हैरिटेज में रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम ऐसी मानसिक बीमारी में फंस गए थे कि कुंभ की बात आए, तो भागते थे कि कहीं साम्प्रदायिकता का दाग न लग जाए। लेकिन आज दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि कुंभ के मेले में आ रहे हैं। दुनिया की एंबेसी के सारे लोग कुंभ में गए और अपने देश का झंडा गाड़ कर आए। यह भारत की ताकत है, भारत की साफ्ट पॉवर है। इसको भी हमने पहले नजरअंदाज किया। अब हम उन चीजों पर भी बल दे रहे हैं, इसलिए उस दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने जितने भी विचार रखे होंगे, आलोचना की होगी, तथ्यों के अभाव के साथ भी बोल दिए होंगे, रिकार्ड पर भी चला जाएगा, लेकिन अध्यक्ष महोदया जी, मैं आज इस सदन को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में जिस मंजिल को लेकर हम निकले हैं, देश के सपनों को पूरा करने के लिए हमने जो ठानी है, जिसके लिए दिन-रात हम मेहनत कर रहे हैं, देश जिन बीमारियों में फंसा हुआ है, इनसे बाहर निकालने का काम, देश जिन सपनों को लेकर चल रहा है, इन सपनों को लेकर योजनापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास, देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पल-पल देश के विकास के लिए काम आए, पाई-पाई देश की भलाई के

लिए काम आए, इसके लिए हम लगातार लड़े हैं। हम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोटने का भरपूर प्रयास किया गया था। डेढ़-पौने दो घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी, यह ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। उस समय मैंने आपको एक शुभकामना दी थी, वह शुभकामना मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ... (व्यवधान) यह समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है, 400 से 40 हो गए। ... (व्यवधान) अहंकार का परिणाम है, 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर बैठ गए, 2 से निकल करके यहां आकर बैठ गए। ... (व्यवधान) आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे! मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लम्बी बात करोगे, तो शोभा नहीं देगी।

जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा, जैसे आंकड़े बता रहे थे, मैं कहता हूं कि खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो, 1947 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 1947 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की है, यह लेखा-जोखा लोगे, तो पता चलेगा कि हर डगर-डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएंगी। दुनिया के देशों ने इसी कालखण्ड में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली विषमताओं को पार किया है। हमारे पास सम्भावनाएं थीं, आपकी गति में दम नहीं था, आपकी नीति नहीं थी, आपके पास विजन नहीं था और इसी के कारण 5, 15 संस्थाओं का नाम देकर आप गीत गाते रहते हैं।

(1940/SK/AK)

अगर उसी गति से चलते, देश को समस्याओं से मुक्त किया होता, अरे, किसान को पानी पहुंचा दिया होता, लोगों को घरों में बिजली पहुंचा दी होती। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): क्या आपने पहुंचा दी?

श्री नरेन्द्र मोदी: हां, हमने 55 महीने में कर दिया है और आने वाले दिनों में देश में हम यही काम करने वाले हैं, हम करके रहने वाले हैं।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूँ, आज सुबह बसवन्ना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आपने पढ़े थे इसलिए पढ़ रहा था।

श्री नरेन्द्र मोदी: खड़गे साहब, आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल बाद क्यों पढ़ा? अगर यही 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए, वह नहीं जाता। जो गलत काम पर चले गए, नहीं जाते। ... (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि हर कांग्रेसी के घर में बसवन्ना के वचन, जो आज आपने पढ़ा न, उसे टंगवा कर रखिए। ... (व्यवधान) अभी जहां सरकार है, जहां मौका मिला है, वहां तो बड़े अक्षरों में लगाकर रखिए ताकि ये बीमारियां जो आपके यहां फलीफूली हैं, थोड़े लोग उरने लगे। इसलिए भी, वहां एक फोटो मोदी की मत रखना वरना बेचारे उर जाएंगे कि मुसीबत आएगी। ... (व्यवधान) जी हां, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी उरा कर रहेगा। उरा कर रहेगा, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। ... (व्यवधान) देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। ... (व्यवधान) जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको उरना ही होगा। ... (व्यवधान) उनको उरना ही होगा। ... (व्यवधान) इसीलिए तो जिंदगी खपाई है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सब उराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी: बिल्कुल, इस देश में 'चोर', 'लुटेरे', 'बदमाशों' का उर बिल्कुल खत्म हो गया था, उसी के कारण देश बर्बाद हुआ है, उनके लिए उर पैदा करने के लिए देश ने मुझे यहां बिठाया है। ... (व्यवधान) इसलिए हम इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आखिर में, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा,

सूरज जाएगा भी तो कहां, सूरज जाएगा भी तो कहां।
उसे यहीं रहना होगा, यहीं हमारी सांसों में,
हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रतजगों में।
तुम उदास मत हो, तुम उदास मत हो,
अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा।

बहुत, बहुत धन्यवाद।

(इति)

SHRI V.S. UGRAPPA (BELLARY): Madam, today we have seen the '*Adhunika Duryodhana*' in this House! ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: A number of amendments have been moved by Members to the Motion of Thanks.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall put all the amendments to the vote of the House together.

The amendments were put and negatived.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Motion to the vote of the House.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2019'."

The motion was adopted.

- - -

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Friday, the 8th February, 2019 at 11.00 am.

1945 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, February 08, 2019 / Magha 19, 1940 (Saka).